रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 28, 1985/अश्विन 6, 1907

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 28, 1985/ASIVAN 6, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1985

सूचनाएं

का०आ० 4564.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है, कि मिस गुरदीप खेरा, एडवोकेट, सुभाष नगर, नई दिल्ली ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे केन्द्र शासित दिल्ली व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर भी किसी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं० 5/34/85/न्या०]

MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 10th September, 1985

NOTICES

S.O. 4564.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Miss Gurdeep Khera, advocate, Subhash Nagar, New Delhi for appointment as a Notary to practise in the Union Territory of Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(34)|85-Judl.]

का०आ० 4565.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री बी०बी०नन्निहा, एडवोकेट, वीराजपेत टाऊन, कर्नाटका ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे विराजपेत टाउन व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं० 5/33/85/न्या०]

S.O. 4565.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri B. B. Nanaiah, advocate, Virajpet Town, Karnataka for appointment as a Notary to practise in Virajpet Town.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(33)|85-Judl.]

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1985

का. आ. 4566.—नोटरीज नियम 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री एम. एस. उथापा, एडवोकेट, अमेठी पोस्ट, कोडागु कर्नाटका ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे विराजपेत टाउन व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5/28/85-न्या.]

New Delhi, the 11th September, 1985

S.O. 4566.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri M. S. Uthappa, advocate, Ammathi Post, Kodagu Karnataka for appointment as a Notary to practise in Virajpet Town.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(28)|85-Judl.]

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1985

सूचना

का. आ. 4567.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री दुर्गादास बैनर्जी सालिसिटर एण्ड एडवोकेट, 1/1 भीम घोष बाय, लेन कलकत्ता-6 ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया जाता है कि उसे बुरतौला कलकत्ता व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(35)/85-न्या.]

एस. गुप्तु, सक्षम प्राधिकारी

New Delhi, the 13th September, 1985

S.O. 4567.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Durgadas Banerjee Solicitor & Advocate, 1|1, Bhim Ghose Bye Lane, Calcutta-6 for appointment as a Notary to practise in Burtolla areas of Calcutta City.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(35)|85-Judl]

S. GOOPTU, Competent Authority

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1985

आदेश

का०आ० 4568.—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 7 के साथ पठित, धारा 5 की की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अपराधों के अन्वेषण के लिए, राजस्थान सरकार की सहमति से, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण उतने क्षेत्र पर करती है जो राजस्थान राज्य में 22 सीमावर्ती पुलिस थानों में, अर्थात गंगानगर जिले मे, थाना (1) हिन्दुमलकोट, (2) मतीली स्थान, (3) केसरी सिंहपुर, (4) करनपुर, (5) गजसिंहपुर, (6) रायसिंहनगर, (7) अनूपगढ़, और (8) घरसाना– बीकानेर जिले में में थाना (1) छतरगढ़, (2) पूगल और (3) बज्जू– जैसलमेर जिले में थाना (1) नचाना, (2) मोहनगढ़, (3) रामगढ़, (4) साम तथा (5) भिनभियाली– तथा बाड़मेर जिले में थाना (1) गिरब, (2) गजरा रोड, (3) रामसार, (4) बिजराड़, (5) सेदवा, तथा (6) बकासर, में समाविष्ट है, अर्थात :

(i) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धाराओं 121, 121क, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 153क, 153ख, 189, 190, 212, 216, 216क, 224, 225, 225ख, 295, 295क, 302, 304, 307, 308, 326, 332, 333, 342, 343, 344, 346, 347, 353, 363, 364, 365, 367, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 436, 506, और 507, के अधीन दण्डनीय अपराध–

(ii) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1984 (1984 का 4) की धारा 9ख के अधीन दण्डनीय अपराध।

(iii) भारतीय तार अधिनियम, 1985 (1985 की 13) की धारा 20 और धारा 25 के अधीन दण्डनीय अपराध।

(iv) भारतीय रेल अधिनियम 1890 (1890 का 9) की धाराएं 126, 126क, 127 और 128 के अधीन दण्डनीय अपराध।

(v) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) की धाराएं 3, 4, 5 और 6 के अधीन दण्डनीय अपराध।

(vi) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 25, 26 और 27 के अधीन दण्डनीय अपराध।

(vii) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के अधीन दण्डनीय अपराध।

(viii) सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन अधिनियम 1982 (1982 का 66) की धारा 3 और धारा 4 के अधीन दण्डनीय अपराध।

(ix) यान-हरण निवारण अधिनियम, 1982 (1982 का 65) की धारा 4 और धारा 5 के अधीन दण्डनीय अपराध।

(x) लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 (1984 का 3) की धारा 3 और धारा 4 के अधीन दण्डनीय अपराध।

(xi) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1985 (1985 का 31) के अधीन दण्डनीय अपराध और

(xii) उपर खण्ड (i) से (xi) उल्लिखित किसी अपराध या किन्हीं अपराधों और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के संबंध में या उनके संसक्त प्रयत्न दुष्प्रेरण और षडयन्त्र।

[सं० 228/24/85-ए०वी०डी०-(II)]
के० जी० गोयल, उप सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL & TRAINING, ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 10th September, 1985

ORDER

S.O. 4568.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, read with section 6, of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government, with the consent of the Government of Rajasthan, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to so much of the area comprised within jurisdiction of the 22 border Police Stations of the State of Rajasthan, namely, Police Stations (1) Hindumallkot, (2) Matili Rathan, (3) Kesrisinghpur, (4) Karanpur, (5) Gaj Singh Pur, (6) Raisinghnagar, (7) Anupgarh, and (8) Gharsana, in Ganganagar District; Police Stations (1) Chatargarh, (2) Pugal and (3) Bajju, in Bikaner District, Police Stations (1) Nachana, (2) Mohangarh (3) Ramgarh, (4) Sam, and (5) Jhunjhunyali, in Jaisalmer District and Police Stations (1) Girab, (2) Gadra Road, (3) Ramsar, (4) Bijrad, (5) Sedwa, and (6) Bakasar, in Barmer District, for investigation of the following offences namely :—

(i) Offences punishable under Sections 121, 121A, 122, 123, 124, 12B, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 153A, 153B, 189, 190, 212, 216, 216A, 224, 225, 255B, 295, 295A, 302, 304, 307, 308, 326, 332, 333, 342, 343, 344, 346, 347, 353, 363, 364, 365, 367, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 399, 436, 506 and 507 of the Indian Penal Code (45 of 1860);

(ii) offences punishable under section 9B of the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884);

(iii) offences punishable under sections 20 and 25 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

(iv) offences punishable under sections 126, 126A, 127 and 128 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890);

(v) offences punishable under sectons 3, 4, 5 and 6 of the Explosive Substances Act, 1908 (6 of 1908);

(vi) offences punishable under sections 25, 26 and 27 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959);

(vii) offences punishable under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967);

(viii) Offiences punishable under sections 3 and 4 of the Suppression of Unlawful Acts against Safety of Civil Aviation Act, 1982 (66 of 1982);

(ix) offences punishable under sections 4 and 5 of the Anti Hijacking Act, 1982 (65 of 1982);

(xx) offences punishable under sections 3 and 4 of the Prevention of Damage to Public Property Act, 1984 (3 of 1984);

(xi) offences punishable under the Terrorists and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985 (31 of 1985); and

(xii) attempts, abetments and conspiracies in relration to or in connection with one or more of the effences mentioned in clauses (i) to (xi) above and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228|24|85-AVD.II]
K. G. GOEL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1985

आदेश

का. आ. 4569:—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित, धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अपराधों के अन्वेषण के लिए, पंजाब सरकार की सहमति से, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण भारत की सीमा से लगे हुए उतने क्षेत्र पर करती है जो पंजाब राज्य में 15 किलोमीटर की बैल्ट के भीतर समाविष्ट है, अर्थात् :—

(i) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धाराओं 121, 121क, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 153क, 153ख 189, 190, 212, 216, 216क, 224, 225, 225ख, 295, 295क, 302, 304, 307, 308, 326, 332, 333, 342, 343, 344, 346, 347, 353, 363, 364, 365, 367, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 436, 506, और 507 के अधीन दंडनीय अपराध;

(ii) भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 (1884 का 4) की धारा 9-ख के अधीन दंडनीय अपराध;

(iii) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 20 और धारा 25 के अधीन दंडनीय अपराध;

(iv) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धाराएं 126, 126क, 127 और 128 के अधीन दंडनीय अपराध;

(v) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) की धाराएं 3, 4, 5 और 6 के अधीन दंडनीय अपराध;

(vi) आयुद्ध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 25, 26 और 27 के अधीन दंडनीय अपराध;

(vii) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के अधीन दंडनीय अपराध;

(viii) सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन दमन अधिनियम 1982 (1982 का 66) की धारा 3 और धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध;

(ix) यान-हरण निवारण अधिनियम, 1982 (1982 का 65) की धारा 4 और धारा 5 के अधीन दंडनीय अपराध;

(x) लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 (1984 का 3) की धारा 3 और धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध;

(xi) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1985 (1985 का 31) के अधीन दंडनीय अपराध; और

(xii) ऊपर खंड (i) से (xi) में उल्लिखित किसी अपराध या किन्हीं अपराधों और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के संबंध में या उनसे संसक्त प्रयत्न, दुष्प्रेरण और षड्यंत्र।

[सं. 228/24/85-ए. वा. डी.-II]

New Delhi, the 12th September, 1985

ORDER

S.O. 4569.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, read with section 6, of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government, with the consent of the Government of Punjab, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to so much of the area comprised within the belt of 15 Kilometres in the State of Punjab running along the borders of India, for the investigation of the following offences namely :—

(i) Offences punishable under sections 121, 121A, 122, 123, 124, 124A, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 153A, 153B, 189, 190, 212, 216, 216A, 224, 225, 225B, 295, 295A, 302, 304, 307, 308, 326, 332, 333, 342, 343, 344, 346, 347, 353, 363, 364, 365, 367, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 436, 505, 506 and 507 of the Indian Penal Code (45 of 1860);

(ii) offences punishable under section 9B of the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884);

(iii) offences punishable under section 20 and 25 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885).

(iv) offences punishable under sections 126, 126A, 127 and 128 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890);

(v) offences punishable under sections 3, 4, 5 and 6 of the Explosive Substances Act, 1908 (6 of 1908);

(vi) offences punishable under sections 25 and 26 and 27 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959);

(vii) offences punishable under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967);

(viii) offences punishable under sections 3 and 4 of the Suppression of Unlawful Acts against Safety of Civil Aviation Act, 1982 (66 of 1982);

(ix) offences punishable under sections 4 and 5 of the Anti-Hijacking Act, 1982 (65 of 1982);

(x) offences punishable under sections 3 and 4 of the Prevention of Damage to Public Property Act, 1984 (3 of 1984);

(xi) offences punishable under the Terrorists and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985 (31 of 1985); and

(xii) attempts, abetments and comspiracies in relation to or in connection with one or more of the offences mentioned in clauses (i) to (xi) above and any other offence arising out of the same facts.

[No. 228/24/85-AVD.II]

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1985

आदेश

का. आ. 4570 :—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित, धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के पूर्व में खुले समुद्र में तारीख 21 जून, 1985 को या उसके लगभग भारतीय पोत "मो. ज. नित्य नानक" और "मो. ज. नित्य राम" के डूबने की बाबत जिसके फलस्वरुप पोत के कर्मी दल के 44 सदस्यों की, उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा, मृत्यु कारित हुई, भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 304क के अधीन दंडनीय अपराध और उसी अपराध, और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध, के संबंध में या उनसे संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षडयंत्रों के अन्वेषण के लिए, महाराष्ट्र सरकार की सहमति से, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य पर करती है।

[संख्या 228/23/85-ए. वी. डी. (II)]

एम. एस. प्रसाद, अवर सचिव

New Delhi, the 13th September, 1985

ORDER

S.O. 4570.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of Maharashtra, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Maharashtra for the investigation of offences punishable under section 304A of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and attempts, abetments and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts, in regard to the sinking of the Indian Ships Nitya Nanak and Nitya Ram sometime on or about the 21st June, 1985 in the High Seas to the east of India, resulting in the death of 44 crew members on board, caused by rash or negligent act.

[No. 228/23/85-AVD-II]

M. S. PRASAD, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1985

(आय-कर)

का. आ. 4571 :—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 80-छ की उपधारा (2ख) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा संपूर्ण तमिलनाडु राज्य में प्रख्यात "अरुलमिगु सेंगलम्मन तिरुक्कोइल, सेंबालिवरम्, सोलवरम्" सार्वजनिक पूजा-स्थल के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 6347/फा. सं. 176/73/84-आ. क. (नि.-I)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 31st July, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 4571.—In exercise of the powers conferred by sub-section 2(b) of Section 80-C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Arulmigu Sengalamman Thirukkoil, Sembulivaram, Sulavaram" as a place of public worship renown throughout the State of Tamil Nadu.

[No. 6347/F. No. 176/73/84-IT(AI)]

का. आ. 4572 : आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-छ की उपधारा 2(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "सेठ कवासजी बैरामजी आतश बेहराम ट्रस्ट" को अधिसूचित करती है।

[सं. 6348/फा.स. 176/19/85-आ.क. (नि.-I)]
आर. के. तिवारी, अवर सचिव

S.O. 4572.—In exercise of the powers conferred by sub-section 2(b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Seth Cawasjee Byramjee Atash Behram Trust".

[No. 6348|F. No. 176|19|85-IT(AI)]
R. K. TEWARI, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अगस्त 1985

प्रधान कार्यालय संस्थापन

का०आ० 4573 :-केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का संख्यांक 54) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) के अधिकारी श्री ए० सी० सल्डाना को, जो पिछले दिनों निरीक्षण निदेशालय में महानिदेशक के रूप में तैनात थे, 9 अगस्त, 1985 पूर्वाह्न से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है।

[फा० सं० ए-19011/7/85-प्रशा० I]

New Delhi, the 21st August, 1985

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

S.O. 4573.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Central Boards of Revenue Act, 1963 (54 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri A. C. Saldanha, an officer of the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise) and formerly posted as Director General, Directorate of Inspection, Customs and Central Excise, New Delhi, as Member of the Central Board of Excise & Customs with effect from the forenoon of the 9th August, 1985.

[F. No. A. 19011/7/85-Ad. I]

नई दिल्ली, 22 अगस्त 1985

प्रधान कार्यालय संस्थापन

का०आ० 4574 केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का संख्यांक 54) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क) के अधिकारी श्री बी०आर० रेड्डी को, जो पिछले दिनों प्रधान समाहर्ता, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, मद्रास के रूप में तैनात थे, 19 अगस्त, 1985 पूर्वाह्न से केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है।

[फा०सं० ए-19011/8/85-प्रशा० I]
जे० एम० त्रेहन, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd August, 1985

HEADQUARTERS ESTABISHMENT

S.O. 4574.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Central Boards of Revenue Act, 1963 (54 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri B. R. Reddy, an officer of the Indian Revenue Service (Customs & Central Excise) and formerly posted as Principal Collector of Customs & Central Excise, Madras, as Member of the Central Board of Excise & Customs with effect from the forenoon of the 19th August, 1985.

[F. No. A. 19011|8|85-Ad.I]
J. M. TREHAN, Under Secy.

(समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण)

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1985

का. आ. 4575 समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 12 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण) नियम, 1970 में, जो भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं. का. आ. 179(अ), तारीख 18 फरवरी, 1977 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 18 फरवरी, 1970 में, पृष्ठ 563 से 569 पर प्रकाशित हुए थे, आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण) संशोधन नियम, 1985 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण) नियम 1977 के नियम 22 में, —

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे अर्थात् :—

"(1) प्रतियों के प्रदाय के लिए नकल फीस दो रुपये प्रति पृष्ठ या उसका भाग होगी।

(1क) फोटोस्टेट प्रतियों के प्रदाय के लिए नकल फीस अधिकरण द्वारा ऐसी प्रतियों पर उपगत वास्तविक व्यय होगी।"

(ख) उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(5) जब प्रति डाक द्वारा भेजी जाती है तब आवेदक पर वास्तविक डाक-व्यय भी प्रभारित किया जाएगा जो नकद में अग्रिम रूप से वसूल किया जाएगा।"।

अधिकरण के आदेश से।

[फा. सं. 91/सामान्य/स. स. अ. अ./85]

बी. चक्रवर्ती, रजिस्ट्रार

(Appellate Tribunal for Forfeited Property)

New Delhi, the 11th September, 1985

S.O. 4575.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 12 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Appellate Tribunal for Forfeited Property, hereby makes the following rules further to amend he Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Appellate Tribunal for Forefeited Property) Rules, 1977, published with the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking S.O. No. 179(E), dated the 18th February, 1977 at page 563 to 569 of the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 18th February, 1977, namely :—

1. (1) These rules may be called the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Appellate Tribunal for Forfeited Property) Amendment Rules, 1985.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Appellate Tribunal for Forfeited Property) Rules, 1977, in rule 22—

(a) for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely :—

"(1) Copying fees for supply of copies shall be rupees two per page or part thereof.

(1A) Copying fees for supply of photostat copies shall, however, be the actual expanses incurred by the Tribunal for such copies";

(b) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

which shall be recovered in advance in cash.".
also be charged with the actual postal charges which shall be recovered in advance in cash.".

By order of the Tribunal.

[F. No. 91|Genl|ATFP|85]

B. CHAKRAVATRY, Registrar

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1985

(आयकर)

का. आ. 4576.--आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा दिनांक 12-10-1982 की अपनी अधिसूचना सं. 4944/फा. सं. 188/8/82-आ. क. (नि० I) के साथ संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है :--

(1) क्रम सं. 9 के सम्मुख कालम सं. 2, 3, 4, 5, और 6 के सम्मुख आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

(2) क्र० संख्या 9 के सम्मुख कालम सं. 2, 3, 4, 5 और 6 में आने वाली प्रविष्टियों का लोप कर दिया गया है।

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
9.	उत्तर-पूर्वी फ्रंटियर रेलवे के वे सभी कर्मचारी जो वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, उत्तर फ्रंटियर रेलवे, मालीगांव, गोहाटी के अधीन आते हैं और उत्तर-फ्रंटियर रेलवे के कर्मचारी जो मुख्य लेखा-परीक्षक, उत्तर-पूर्वी फ्रंटियर रेलवे, मालीगांव के अधीन आते हैं। इनमें वकीलों, चिकित्सकों, वास्तुविदों, इंजीनियरों और चार्टर्ड अकाउंटेंटों की हैसियत वाले कर्मचारी भी शामिल हैं।	आयकर अधिकारी डीवार्ड जिला-II, गोहाटी	निरीक्षी सहायक आयुक्त, रेंज II, गोहाटी	सहायक अपीलीय सहायक आयुक्त, गोहाटी रेंज, गोहाटी	आयकर आयुक्त (अपील) गोहाटी	आयकर आयुक्त उत्तर-पूर्वी रेलवे, शिलांग

यह अधिसूचना 16 अगस्त, 1985 से लागू होगी।

[सं. 6374/फा. स. 188/1/85-आ. क. (नि.-I)]

आर. के. तिवारी, अवर सचिव,
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, 21st August, 1985

INCOME-TAX

S.O. 4576:—In exercise of the powers conferred by section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment to the Schedule annexed to its Notification No. 4944/F. No. 188/8/82-IT(AI) dated 12-10-1982.

1. The entries appearing in Col. Nos. 2, 3, 4, 5 & 6 against S. No. 9 shall be substituted by following entries.

2. The entries appearing in Col. Nos. 2, 3, 4, 5 & 6 against Sl. No. 9-A are deleted.

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7
9.	All employees of North East Frontier Railway who are under the Audit control, of the Financial Adviser and the Chief Accounts Officer, N.F. Railway, Maligaon, Gauhati and the employees of N.F. Railway under the Chief Auditor, North-East Frontier Railway, Maligaon, including the cases of the employees in the capacity of Lawyers, physicians, Architects, Engineers and Chartered Accountants.	I.T.O., D-Ward, Distt.II, Gauhati	I.A.C., Range-II, Gauhati	A.A.C., Range Gauhati	CIT (Appeals), Gauhati.	CIT NER Shillong.

This notification shall take effect from 16th August, 1985.

[No. 6374, /F.No. 188/1/85-IT (AI)]

R.K. TEWARI, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1985

का. आ. 4577 :—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबंध अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के वास्ते यूनाइटेड इंडस्ट्रीयल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे वहां तक इनका संबंध गिरवीदार के रूप में बैंक का मैसर्स सुरेन्द्र इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के शेयरों की धारिता से है।

[संख्या एफ० 15/क/83-बी० ओ. III]

एम० के० एम० कुट्टी, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 9th September, 1985

S.O. 4577.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India hereby declares that the provisions of sub-section (2) of Section 19 of the said Act shall not apply to the United Industrial Bank Ltd., Calcutta for a period of two years the date of notification insofar as they relates to its holding of shares of M|s. Surendra Engineering Works Pvt. Ltd., Calcutta as pledgee.

[No. 15|7|83-B.O.III]

M. K. M. KUTTY, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1985

का. आ. 4578:—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खंड 3 के उपखंड (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एम. सी. सत्यवादी, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली को नीचे दिए गये राष्ट्रीयकृत बैंकों में श्री पी. जी. मांकड के स्थान पर निदेशक के रूप में नियुक्त करती है:—

1. बैंक आफ इण्डिया
2. केनरा बैंक
3. इण्डियन ओवरसीज बैंक

[संख्या एफ. 9/24/85-बी. ओ. I(1)]

New Delhi, the 13th September, 1985

S.O. 4578.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri M. C. Satyawadi, Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) New Delhi as Director of the nationalised bank mentioned below in place of Shri P. G. Mankad :—

1. Bank of India
2. Canara Bank
3. Indian Overseas Bank

[No. F. 9|24|85-BO. I(1)]

का. आ 4579 :—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1980 के खंड 3 के उप खंड (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे की सारणी के कालम (2) में उल्लिखित व्यक्तियों को उनमें से प्रत्येक के सामने उसी सारणी के कालम (3) में उल्लिखित व्यक्तियों

के स्थान पर सारणी के कालम (1) में दिये गये राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है:—

सारणी

1	2	3
1. न्यु बैंक आफ इण्डिया	श्रीमती ताजवर रहमान साहनी, उपसचिव वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।	श्री ना. बालसुब्रह्मण्यम
2. ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	श्री ना. बालसुब्रह्मण्यन, निदेशक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।	श्री एस. एस. हसूरकर

[संख्या एफ. 9/24/85-बी. ओ.-I(2)]

एम. एस. सीतारामन, अवर सचिव

S.O.4579.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby appoints the persons specified in column (2) of the Table below as Directors of the nationalised banks specified in column (1) thereof in place of the persons specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
1. New Bank of India	Smt. Tajwar Rahman Sahni, Deputy Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi.	Shri N. Balasubramanian
2. Oriental Bank of Commerce	Shri N. Balasubramanian, Director, Ministry of Finance, Department of Economic affairs (Banking Division), New Delhi.	Shri S.S. Hasurkar.

[No. F. 9/24/85-BO I(2)]

M.S. SEETHARAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1985

(सं० 298/85-सीमा शुल्क)

का० आ० 4580.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं० 51/85 सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में, मद (vii) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:—

"(vii) मध्य प्रदेश राज्य में राजगढ़ जिले के पीलूखेरी को ;"

[फा० सं० 473/510/84-सी०शु०VII]

आर०, के० कपूर अवर सचिव

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

New Delhi, the 28th September, 1985

NO. 298/85-CUSTOMS

S.O. 4580.—In exercise of the powers confered by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following amendment in the notification of the Central Board of Excise and Customs No. 51/85-Customs, dated the 28th February, 1985, namely:—

In the said notification, for item (vii) and the entry relating thereto, the following item and entry shall be substituted, namely :—

"(vii) Pilukheri in Rajgarh District in the State of Madhya Pradesh;".

[F. No. 473/510/84-Cus.VII]

R. K. KAPUR, Under Secy.

Central Board of Excise and Customs

वाणिज्य मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

(एम. एल. अनुभाग)

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1985

का. आ. 4581:—होटल मौर्य शेराटन (वैलकम ग्रुप), डिप्लोमेटिक एन्कलेव, नई दिल्ली-110021 को पनीर (चीज) के आयात के लिए 1,50,000/- रु. मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं. पी./पी./2032512/सी./एक्स/एक्स/94/एच./84/एम. एल. एस., दिनांक 12-3-85 दिया गया था जो जारी होने की तिथि से 18 मास के लिए वैध था। अब पार्टी ने उपर्युक्त आयात लाइसेंस की अनुलिपि प्रति देने

के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस खो गया है। लाइसेंसधारी ने आवश्यक शपथ-पत्र दिया है जिसके अनुसार उपर्युक्त आयात लाइसेंस किसी भी सीमा-शुल्क कार्यालय के पास पंजीकृत नहीं किया गया था और उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है एवं लाइसेंस के मुद्दे शेष धनराशि 1,50,000 रुपए है। इस संबंध में शपथ-पत्र में एक घोषणा भी शामिल की गई है कि यदि उक्त आयात लाइसेंस बाद में मिल गया या पाया गया तो उसे जारी करने वाले प्राधिकारी को लौटा देंगे। इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि मूल आयात लाइसेंस खो गया है, अधोहस्ताक्षरी निदेश देता है कि आवेदक को एक अनुलिपि लाइसेंस (दोनों सीमा-शुल्क एवं मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां) जारी किया जाना चाहिए। मैं, भी आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के खंड 9 के उप-खण्ड (घ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क एवं मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां रद्द करता हूं।

[फा. सं. 18/208/84-85/एम. एल. एस./599]

एन. एस. कृष्णामूर्ति, उप-मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात,

कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

(M. L. Section)

New Delhi, the 16th September, 1985

S.O. 4581.—Hotel Maurya Sherton (Welcomgroup), Diplomatic Enclave, New Delhi-110021, were granted an Import Licence No. P|P|2032512|C|XX|94|H|84|MLS dated 12-3-85 for Import of Cheese valuing at Rs. 1,50,000 with a validity of 18 months from the date of issue. Now the party have applied for grant of a Duplicate Copy of the aforesaid Import Licence on the ground that the subject licence has been lost. The licensee has furnished necessary affidavit according to which the aforesaid Import Licence was not registered with any Customs House and was not utilised at all and the balance against the licence is Rs. 1,50,000. A declaration has also been incorporated in the affidavit to the effect that if the said Import Licence is traced or found later on, it will be returned to the issuing authority. On being satisfied that the original Import Licence has been lost, the undersigned directs that a Duplicate licence (both Custom as well as Exchange Control Purposes Copies) should be issued to the applicant. I also in exercise of the powers conferred in Sub-Clause (d) of Clause 9 of the Imports (Control) Order 1955, hereby cancel the original Customs as well as Exchange Control Purpose Copies of the above licence.

[F. No. 18|208|84-85|MLS|599]

N. S. KRISHNA MURTHY, Dy. Chief Controller of Imports & Exports

For Chief Controller of Imports & Exports

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1985

का०आ० 4582 :—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के अनुलग्नक में उल्लिखित उपक्रमों के पंजीकरण को उक्त उपक्रमों के वह उपक्रम होने पर, जिन पर उक्त अधिनियम के अध्याय III के भाग-क के उपबन्ध अब लागू नहीं होते हैं के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

अधिसूचना सं. 16/12/85; एम-3 का अनुलग्नक

क्रम सं.	उपक्रमों के नाम	पंजीकृत पता	पंजीकरण संख्या
1	2	3	4
1.	हिन्दुस्तान स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड	सर विट्ठलदास चैम्बर्स 16, बम्बई समाचार मार्ग, फोर्ट, बम्बई; 400023	1303/76
2.	निर्मल क्लरेन्ट्स एंड कैमिकल्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि.	–यथोपरि–	1310/76
3.	सरदार कार्बनिक गैस कंपनी लि.	–यथोपरि–	1317/76
4.	एक हाउसहोल्ड एंड लक्ष्मी लि०	–यथोपरि–	1305/3
5.	फैन्सी नेटस प्राइवेट लि.	–यथोपरि–	1322/77
6.	प्रभात इन्वेस्टमैन्टस लि०	–यथोपरि–	1319/76
7.	मोर केमीकल्स एंड प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	–यथोपरि–	1328/77
8.	स्मार्ट लेदर लिमिटेड	–यथोपरि–	1323/77
9.	एलोरा इन्वेस्टमैन्ट कंपनी लि.	–यथोपरि–	1318/76
10.	काटन एंड टैक्सटाइल ट्रेडर्स	–यथोपरि–	1321/77
11.	लक्ष्मी वेयरहाउसिंग एजेन्सी	–यथोपरि–	1325/ 7
12.	इंडियन फाउण्ड्रीज	–यथोपरि–	1329/77
13.	बल्कोटैक्स	–यथोपरि–	1326/77
14.	जेट मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी	–यथोपरि–	1334/77
15.	निर्मल वेयरहाउसिंग एजेन्सी	–यथोपरि–	1331/77
16.	नागार्जुन स्टील्स लिमिटेड	नागार्जुन हिल्स पंजागुट्टा, हैदराबाद; 500482	1946/84

1	2	3	4
17.	रेस्पोंसिव हायर परचेज एण्ड क्रेडिट लिमिटेड	749, माउन्ट रोड, मद्रास; 600002	1736/84
18.	फाइजर लिमिटेड	एक्सप्रेस टावर्स नारीमन पाइन्ट बैकबे रिक्लेमेशन, बम्बई; 400021	1444/79
19.	सेन्दूर मैंगनीज एंड आयरन ओरेज लिमिटेड	"लुहादरी भवन" यशवन्त नगर; 583124 बेल्लारी जिला (कर्नाटक)	1572/82
20.	डावी आशमोर इंडिया लि.	6-ए, मिडलटन स्ट्रीट, कलकत्ता ; 700071	1596/82
21.	अमृत बनासपति कंपनी लि.	अमृत नगर, जी. टी. रोड, गाजियाबाद ; 202012 (यू. पी)	1735/84

[सं० 16/12/85-एम०-3]

MINISTRY OF INDUSTRY AND CO. AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 9th September, 1985

S.O. 4582.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of the undertakings mentioned in the Annexure to this notification, the said undertakings being undertakings to which the provisions of Part A Chapter III of the said Act no longer apply.

Annexure to the Notification No. 16-12-84-M-III

S.No.	Names of the Undertakings	Registered Address	Registration No.
1	2	3	4
1.	Hindustan Spinning & Weaving Mills Ltd.	Sir Vithaldas Chambers, 16, Bombay Samachar Marg, Fort, Bombay-400023.	1303/76
2.	Nirmal Colorants & Chemicals Manufacturing Company Limited.	—do—	1310/76
3.	Sirdar Carbonic Gas Company Limited	—do—	1317/76
4.	Eck Haubold & Laxmi Ltd.	—do—	1305/76
5.	Fancy Nets Private Ltd.	—do—	1322/77
6.	Prabhat Investments Ltd.	—do—	1319/76
7.	Bhor Chemicals and Plastics Private Ltd.	—do—	1328/77
8.	Art Leather Ltd.	—do—	1323/77
9.	Ellora Investment Company Ltd.	—do—	1318/76
10.	Cotton & Textile Traders	—do—	1321/77
11.	Laxmi Warehousing Agency	—do—	1325/77
12.	Indian Foundries	—do—	1329/77
13.	Buffotex	—do—	1326/77
14.	Jet Manufacturing Company	—do—	1334/77
15.	Nirmal Warehousing Agency	—do—	1331/77
16.	Nagarjuna Steel Ltd.	Nagarjuna Hills Panjagutta Hyderabad-500482.	1945/84
17.	Responsive Hire Purchase & Credit Ltd.	749-Mount Road Madras-600002.	1736/84
18.	Pfizer Ltd.	Express Towers Nariman Point Backbay Reclamation, Bombay-400021.	1444/79
19.	Sandur Manganese & Iron Ores Ltd.	'Lohadri Bhawan' Yeswant Nagar-583124 Bellary Distt. (Karnataka).	1572/82
20.	Davy Ashmore India Ltd.	6-A, Middleton Street Calcutta-700071.	1596/82
21.	Amrit Banaspati Co. Ltd.	Amrit Nagar, G.T. Road, Ghaziabad-202012 (U.P.)	1735/84

[No. 16|12|85.M-III]

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1985

का. आ. 4583.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

एतद्द्वारा इस अधिसूचना के अनुलग्नक में उल्लिखित उपक्रमों के पंजीकरण को, उक्त उपक्रमों के वह उपक्रम होने पर, जिन पर उक्त अधिनियम के अध्याय-III के भाग-क के उपबन्ध अब लागू नहीं होते हैं, के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

अधिसूचना सं. 16/12/85- एम.- 3 का अनुलग्नक

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	पंजीकृत पते	पंजीकरण संख्या
1.	ज्योति लिमिटेड	इंडस्ट्रियल एरिया, पो. ओ. केमिकल्स इंडस्ट्रीज, बड़ोदरा- 390003 (गुजरात)	1562/82
2.	भारत लिंडर प्रा. लि.	सी-2/19, इंडस्ट्रीयल स्टेट गोरवा रोड, बड़ोदरा- 390016	1566/82
3.	थाना इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लि.	एसियन बिल्डिंग (प्रथम मंजिल) 17-आर. कंपनी मार्ग, बेलार्ड स्टेट, बम्बई -400038	1889/84
4.	एसियाटिक आक्सीजन लि.	8, बी. बी. डी. बेग (स्टेट) कलकत्ता- 700001	519/70
5.	एसियाटिक इंडस्ट्रियल गैसेज लि.	- यथोपरि -	1722/84
6.	अजय ट्रेडर्स	श्री अंबिका मिल्स लि. के सामने नं. 1 प्रीमिजेज कनकरिया अहमदाबाद - 380008	1311/76
7.	उषा स्माल लि.	14, प्रिंसेप स्ट्रीट, कलकत्ता- 700072	1457/79
8.	हिन्दुस्तान ब्रोन बोवरी लि.	ब्रोन बोवरी हाउस, 264, 265 डा. एनीबेसेन्ट रोड, बम्बई-400025	1101/75

[सं. 16/12/85-एम.-3]

एल. सी. गोयल, अवर सचिव

New Delhi, the 13th September, 1985

S.O. 4583.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of the undertakings mentioned in the annexure to this notification, the said undertakings being undertakings to which the provisions of part A Chapter III of the said Act no longer apply.

Annexure to the Notification No. 16/12/84 M-III

Sl. No.	Names of the undertakings	Registered Address	Registration No.
1.	Jyoti Limited	Industrial Area, P.O. Chemical Industries, Vadodara-390003. (Gujarat)	1562/82
2.	Bharat Lindner Private Limited	C-2/19, Industrial Estate, Gorwa Road, Vadodara-390016. (Gujarat)	1566/82
3.	Thana Electric Supply Company Limited	Asian Building (Ist Floor), 17-R. Kamani Marg, Bllalard Estate, Bombay-400038.	1889/84
4.	Asiatic Oxygen Limited	8-B.B.D. Bag (East) Calcutta-700001.	519/70
5.	Asiatic Industrial Gases Limited	-do-	1722/84
6.	Ajay Traders	Opp. Shri Ambica Mills Ltd., No. 1 Premises, Kankaria, Ahmedabad-380008.	1311/76
7.	Usha Ismal Limited	14-Princep Street, Calcutta-700072	1457/79
8.	Hindustan Brown Boveri Limited.	Brown Boveri House, 264/265, Dr. Annie Besant Road' Bombay-400025.	1101/75

[No. 16|12|85-M-III]

L. C. GOYAL, Under Secy.

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1985

शुद्धि-पत्र

का. आ. 4584 :—भारत के राजपत्र तारीख 23 मार्च, 1985 के भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में पृष्ठ 1457 से 1458 पर प्रकाशित भारत सरकार के इस्पात खान और कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 1247 तारीख 2 मार्च 1985 में :—

पृष्ठ 1458 पर— अनुसूची में :—

1. "पुलिस चौकी सं." के स्थान पर "पटवारी सर्कल सं." पढ़िए।

2. क्रम सं. 5 में ग्राम स्तम्भ के नीचे "बोगडोना" के स्थान पर "बगडोना" पढ़िए और जहां कहीं यह शब्द

प्रयुक्त हुआ हो वहां "बगडोना" पढ़िए ।

सीमा वर्णन में :—

3. रेखा "ख—ग" में "बंदु" के स्थान पर "बिन्दु" पढ़िए ।

4. रेखा "झ—ञ" के स्थान पर "झ— " पढ़िए ।

5. रेखा "क—ट—ठ—ड" के स्थान पर "—ट—ठ—क" पढ़िए ।

[सं. 19/79/82— सी. एल. /सी ए]
समय सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF STEEL, MINES & COAL

(Department of Coal)

New Delhi, the 9th September, 1985

CORRIGENDUM

S.O. 4584.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Coal) No. S.O. 1247 dated the 2nd March, 1985, published at pages 1458 to 1459 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 23rd March, 1985.—

At page 1459, in the boundary description—for "P-J" read "I-J".

[No. 19|79-82-CL|CA]
SAMAY SINGH, Under Secy.

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1985

का. आ. 4585 :—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालयों, जिनके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है :

1. भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली
(मुख्यालय)
2. अन्न सुरक्षा अभियान, चण्डीगढ़
3. भारतीय अनाज संचयन संस्थान, हापुड़
4. भारतीय अनाज संचयन संस्थान, उदयपुर
5. अन्न सुरक्षा अभियान, भोपाल
6. लेखा नियंत्रक, नई दिल्ली
7. अन्न सुरक्षा अभियान, पटना
8. अन्न सुरक्षा अभियान, रायपुर
9. वेतन तथा लेखा कार्यालय, बम्बई
10. अन्न सुरक्षा अभियान, पुणे
11. अन्न सुरक्षा अभियान, लखनऊ
12. भारतीय अनाज संचयन संस्थान, लुधियाना
13. अन्न सुरक्षा अभियान, जयपुर
14. अन्न सुरक्षा अभियान, वाराणसी
15. अन्न सुरक्षा अभियान, गाजियाबाद

[संख्या ई-11017/4/84-हिन्दी]
निर्मल झाला, निदेशक (पी)

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

New Delhi, the 6th September, 1985

S.O. 4585.—In pursuance of Sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices under the administrative control of the Ministry of Food & Civil Supplies (Department of Food), the Staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :

1. Food Corporation of India, New Delhi.
(Headquarter)
2. Save Gram Campaign, Chandigarh
3. Indian Grain Storage Institute, Hapur
4. Save Grain Campaign, Udaipur
5. Save Grain Campaign, Bhopal
6. Controller of Accounts, New Delhi
7. Save Grain Campaign, Patna
8. Save Grain Campaign, Raipur
9. Pay & Accounts office, Bombay,
10. Save Grain Campaign, Pune
11. Save Grain Campaign, Lucknow,
12. Indian Grain Storage Institute, Ludhiana
13. Save Grain Campaign, Jaipur
14. Save Grain Campaign, Varanasi,
15. Save Grain Campaign, Ghaziabad.

[No. E-11017|4|84-Hindi]
N. K. S. JHALA, Director (P)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1985

का. आ. 4586 :—सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का. 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 870 दिनांक 3 मार्च, 1972 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात :—

उक्त अधिसूचना के नीचे सारणी में क्र. सं. 9 के सामने स्तम्भ (1) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :—

"मुख्य प्रबन्धक अधिकारी, सिन्दरी एकक, भारतीय उर्वरक निगम लि."

[फा. सं. 76/11/84—एफडीसी]
अकील अहमद, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

New Delhi, the 21st August, 1985

S.O. 4586.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Works and Housing No. S.O. 870, dated the 3rd March, 1972, namely :—

In the Table below the said notification, against serial No. 9, for the entry in column (1), the following entry shall be substituted, namely :—

"Chief Executive Officer, Sindri Unit, Fertilizer Corporation of India, Limited."

[F. No. 76|11|84-FDC]
AQEEL AHMAD, Desk Officer

पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1985

का. आ. 4587.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2579 तारीख 30-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा एकड़ में
1	2	3	4	5	6
शाहजहांपुर	सदर	जमौर	जमौर	141	—94
				142	—16
				143	—42

[सं. ओ-14016/351/85-जी. पी.]

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 12th September, 1985

S.O. 4587.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2579 dated 30-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	plot No.	Area in Acres
1	2	3	4	5	6
Shahjahanpur	Sadar	Jamaur	Jamaur	141	—94
				142	—16
				143	—42

[No. O-14016/351/85—GP]

का.आ. 4588 :—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 998 तारीख 9-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली- जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	दातागंज	सलेमपुर	चटमूरी	540	0-1-16
				541	0-3-10
				542	0-1-16
				539	0-7-5
				538	0-1-16
				537	1-4-0
				471	0-0-6
				498	0-3-6
				497	1-12-0
				496	0-10-8
				495	0-16-0
				501	0-1-0
				452	1-15-15
				451	0-6-12
				448	0-3-12
				437	2-18-0
				436	1-6-15
				435	0-5-0
				433	0-7-10
				392	0-6-16
				393	0-1-5
				394	0-17-0
				395	1-5-5
				373	0-7-15
				372	0-8-0
				381	1-5-5
				369	0-14-5
				368	0-15-0
				367	0-16-15
				351	0-9-0
				352	0-12-0
				353	0-11-0
				354	0-3-15
				316	1-9-15
				315	1-19-15
				311	0-0-13
				306	0-10-17
				305	0-10-10
				304	0-1-5
				285	1-1-0
				290	0-18-10
				289	0-18-0
				292	0-0-15
				294	0-16-10
				295	0-0-7
				296	0-15-0

[सं. ओ-14016/124/85-जी. पी.]

S.O. 4588.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 998 dated 9-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline:

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Data-ganj	Salam-pur	Chat-mury	540	0-1-16
				541	0-3-10
				542	0-1-16
				539	0-7-5
				538	0-1-16
				537	1-4-0
				471	0-0-6
				498	0-3-6
				497	1-12-0
				496	0-10-8
				495	0-15-0
				501	0-1-0
				452	1-15-15

1	2	3	4	5	6
				451	0-6-12
				448	0-3-12
				437	2-18-0
				436	1-6-15
				435	0-5-0
				433	0-7-10
				392	0-6-16
				393	0-1-5
				394	0-17-0
				395	1-5-5
				373	0-7-15
				372	0-8-0
				381	1-5-5
				369	0-14-5
				368	0-15-0
				367	0-16-15
				351	0-9-0
				352	0-12-0
				353	0-11-0
				354	0-3-15
				316	1-9-15
				315	1-19-15
				311	0-0-13
				306	0-10-17
				305	0-10-10
				304	0-1-5
				285	1-1-0
				290	0-18-10
				289	0-18-0
				292	0-0-15
				294	0-16-10
				295	0-0-7
				296	0-15-

[No. O—14016/124/85—GP]

का. आ. 4589:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1005 तारीख 9-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमि उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	दातागंज	स्लेमपुर	खुर्वी	8	2-4-10
				59	0-1-5
				56	1-6-8
				35	0-11-15
				36	1-5-5
				24	0-1-16
				98	0-2-8
				99	2-1-10
				102	1-18-0
				103	0-14-8
				105	0-1-5
				109	0-0-5
				110	1-1-0
				157	0-6-7
				158	0-2-5
				111	0-0-5
				112	0-16-5
				113	0-15-5
				146	0-1-0
				126	0-18-5
				130	2-8-0
				140	0-7-10
				141	0-0-10
				139	0-13-12

[सं. ओ-14016/131/85 जी. पी.]

S.O. 4589.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. No. 1005 dated 9-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central

Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Datеganj	Slampur	Khurdi	8	2-4-10
				59	0-1-5
				56	1-6-8
				35	0-11-15
				36	1-5-5
				24	0-1-16
				98	0-2-8
				99	2-1-10
				102	1-18-0
				103	0-14-8
				105	0-1-5
				109	0-0-5
				110	1-1-0
				157	0-6-7
				158	0-2-5
				111	0-0-5
				112	0-16-5
				113	0-15-5
				146	0-1-0
				126	0-18-5
				130	2-8-0
				140	0-7-10
				141	0-0-10
				139	0-13-12

[No. O—14016/131/85—GP]

का. आ. 4590.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1106 तारीख 9-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया या रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	दातागंज	स्लेमपुर	पडेली बमेड़ा	745	0-10-0
				744	0-16-15
				740	0-12-10
				738	0-0-15
				706	1-1-15
				707	1-17-5
				716	0-19-0
				717	0-13-5
				718	0-12-0
				720	0-7-15
				722	
				357	1-16-0
				338	1-12-10
				335	0-0-15
				310	2-4-10
				306	0-3-5

[सं. औ-14016/132/85-जी. पी.]

S.O. 4590.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1106 dated 9-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said

lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Data-ganj	Salem-pur	Padeli Bajheda	745	0-10-0
				744	0-16-15
				740	0-12-10
				738	0-0-15
				706	1-1-15
				707	1-17-5
				716	0-19-0
				717	0-13-5
				718	0-12-0
				720	0-7-15
				720	0-7-15
				722	
				357	1-16-0
				358	0-16-0
				338	1-12-10
				335	0-0-15
				310	2-4-10
				306	0-3-5

[No. O-14016/132/85-GP]

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	दाता गंज	सलेम पुर	बिहारीपुर हंसराज	1	0-3-8
				6	0-5-0
				7	0-4-5
				5	0-7-10
				8	0-10-10
			Chakmarg		0-0-15
				21	0-6-0
				22	1-12-8
				23	0-4-10
				24	0-9-10
				25	0-7-10
				28	0-9-0
				27	0-1-5
				30	0-2-4
				31	0-4-19
				32	0-4-19
				33	0-1-2
				36	0-2-5
				37	0-1-16

[सं. ओ-14016/133/85-जी. पी.]

का. आ. 4591.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 1007 तारीख 9-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

S.O. 4591.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Deptt. of Petroleum) S.O. 1007 dated 9-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central

Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Data-ganj	Salam-pur	Behari-pur Hans Raj	1	0-3-8
				6	0-5-0
				7	0-4-5
				5	0-7-10
				8	0-10-10
				Chak-marg	0-0-15
				21	0-6-0
				22	1-12-8
				23	0-4-10
				24	0-9-10
				25	0-7-10
				28	0-9-0
				27	0-1-5
				30	0-2-4
				31	0-4-19
				32	0-4-19
				33	0-1-2
				36	0-2-5
				37	0-1-16

[No. O—14016/133/85—GP]

का. आ. 4592.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 1008 तारीख 9-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजक्ट ।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	दाता-गंज	सलेम-पुर	लहडरी पोखता	168	0-15-8
				170	2-8-0
				172	0-1-2
				171	0-1-2

[सं. O-14016/134/85-जी. पी.]

S.O. 4592.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Deptt. of Petroleum) S.O. 1008 dated 9-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdispur Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Data-ganj	Salam-pur	Lohdari Pokhta	168	0-15-8
				170	2-8-0
				172	0-1-2
				171	0-1-2

[No. O—14016/134/85—GP]

का. आ. 4593.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 1257 तारीख 23-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजक्ट।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकवा
1	2	3	4	5	6
बरेली	फरीदपुर	फरीदपुर	सैदपुर एदतमाली	1	1—8—10
				2	0—3—0
				3	0—10—0
				4	0—3—5

[सं. O—14016/150/85—जी. पी.]

S.O. 4593.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Deptt. of Petroleum) S.O. 1257 dated dated 23-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Rihgt of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acqqire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Fareed-pur	Fareed-pur	Said-pur Ahat-mali	1	1–8–10
				2	0–3–0
				3	0–10–0
				4	0–3–5

[No. O—14016/150/85—GP]

का० आ० 4594.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० आ० सं० 1258 तारीख 23-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार

में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आवला	बल्लिया	गहुरी	282	0-1-10
				281	0-8-8
				280	0-12-0
				278	0-4-11
				277	0-0-10
				276	0-0-8
				261	0-4-16
				44	0-1-10
				42	0-0-16
				41	0-2-16
				40	0-2-8
				18	0-12-12
				19	0-6-12
				20	0-8-0
				21	0-9-12
				22	0-8-16
				23	0-2-0
				24	0-1-16
				25	0-2-8
				26	0-3-4
				30	0-2-8
				31	0-3-0
				32	0-5-12
				35	0-6-0
				36	0-1-4
				38	0-15-12

[सं. O-14016/151/85-जी. पी.]

S.O. 4594.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Deptt. of Petroleum) S.O. 1258 dated 23-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government:

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Baliya	Gahavva	282	0-1-10
				280	0-8-8
				280	0-12-0
				278	0-4-16
				277	0-0-10
				276	0-0-8
				261	0-4-16
				44	0-1-10
				42	0-0-16
				41	0-2-16
				40	0--2--8
				18	0-12-12
				19	0-6-12
				20	0-8-0
				21	0-9-12
				22	0-8-16
				23	0-2-0
				24	0-1-16
				25	0-2-8
				26	0-3-4
				30	0-2-8
				31	0-3-0
				32	0-5-12
				35	0-6-0
				36	0-1-4
				38	0-15-12

[No. O-14016/151/85-G.P.]

का०आ० 4595.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 1244 तारीख 23-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजक्ट।

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकवा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	बलिया	डण्टा-श्याम पुर	788	0-4-16
				787	0-6-0
				785	0-10-16
				784	0-0-6
				778	0-0-10
				775	0-1-4
				773	0-12-0
				767	0-4-4
				766	0-16-16
				765	0-1-5
				764	0-1-10
				763	0-3-12

[सं. O-14016/152/85- जी. पी.]

S.O. 4595.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1244 dated 23-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Balliya	Danta Shyam pur	788	0-4-16
				787	0-6-0
				785	0-10-16
				784	0-0-6
				778	0-0-10
				775	0-1-4
				773	0-12-0
				767	0-4-4
				766	0-16-16
				765	0-1-5
				764	0-1-10
				763	0-3-12

[No. O—14016/152/85GP]

का० आ० 4596.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनिय 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 1259 तारीख 23-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधि यम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची

में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा में प्रकाशन को इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट ।

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आवला	बल्लिया	रामपुर कांकर	18	0-1-5
				24	0-4-10
				25	0-1-5
				48	0-9-0
				49	0-12-0
				52	0-7-5
				50	0-9-0
				55	0-1-5
				58	0-1-15
				54	0-12-0
				59	0-18-5
				70	0-19-5
				68	0-1-15
				69	0-12-5
				67	0-2-2
				72	0-1-5
				549	0-5-10
				550	0-17-0
				543	0-1-5
				545	0-12-15
				66	0-0-15
				548	0-0-15
				544	0-1-5
				521	0-16-8
				522	0-2-6
				520	0-1-0
				513	0-9-5
				511	0-5-10
				515	0-0-10
				514	0-14-0
				516	1-2-15
				510	0-0-5
				506	0-0-5
				508	0-1-8
				466	0-4-0
				611	0-1-5
				467	0-4-5
				468	0-1-5
				482	0-0-15
				488	1-4-0
				487	0-15-0
				486	0-1-2
				485	0-6-0
				481	0-0-15
				479	0-6-0
				463	0-7-0
				345/835	0-9-5
				345/836	0-7-10
				345/841	0-0-10
				385	0-7-0
				391	0-1-15
				386	0-2-15
				384	0-0-10
				379	0-12-0
				378	0-0-5
				377	0-0-15
				354	0-5-5
				353	0-15-10
				347	0-10-2
				346	0-4-0
				304	0-0-10
				303	0-5-15
				302	0-7-15
				301	0-2-5
				306	1-11-4
				307	0-15-12

[सं. 0-14016/153/85-जी. पी.]

S.O. 4596.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1259 dated 23-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdispur Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Ballia	Ram-	18	0-1-5
			pur	24	0-4-0
			Karhker	25	0-1-5
				48	0-9-0
				49	0-12-0
				52	0-7-5
				50	0-9-0
				55	0-1-5
				58	0-1-15
				54	0-12-0
				59	0-18-5
				70	0-19-5
				68	0-1-15
				69	0-12-5
				67	0-2-2
				72	0-1-5
				549	0-5-10
				550	0-17-0
				543	0-1-5
				545	0-12-15
				66	0-0-15
				548	0-0-15
				544	0-1-5
				521	0-16-8
				522	0-2-6
				520	0-1-0
				513	0-9-5
				511	0-5-10
				515	0-0-10
				514	0-14-0
				516	1-2-15
				510	0-0-5
				506	0-0-5
				508	0-1-8
				466	0-4-0
				611	0-1-5
				467	0-4-5
				468	0-1-5
				482	0-0-15
				488	1-4-0
				487	0-15-0
				486	0-1-2
				485	0-6-0
				481	0-0-15
				479	0-6-0
				463	0-7-0
				345/835	0-9-5
				345/836	0-7-10
				345/841	0-0-10
				385	0-7-0
				391	0-1-15
				386	0-2-15
				384	0-0-10
				379	0-12-0
				378	0-0-5
				377	0-0-15
				354	0-5-5
				353	0-15-10
				347	0-10-2
				346	0-4-0
				304	0-0-10
				303	0-5-15
				302	0-7-15
				301	0-2-5
				306	1-11-4
				307	0-15-12

[No. O—14016/153/85—GP]

का. आ. 4597.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 1260 तारीख 23-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाईप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	बलिया	नौरंगपुर	764	1-8-0
				765	0-12-16
				766	0-1-15
				761	1-4-9
				762	0-1-4
				769	0-1-11
				770	0-1-4
				775	0-13-16
				776	0-0-18
				1005	0-0-18
				1006	0-0-10
				1007	0-0-10
				1004	1-5-8
				1003	0-18-10
				1001	0-13-16
				1002	0-1-4
				1027	0-0-12
				1028	0-7-14
				1029	0-0-15
				1030	0-0-12
				1031	0-9-15
				1035	1-10-0
				1050	0-9-12
				1091	0-13-16
				1100	1-0-8
				1096	0-7-4
				1099	0-0-6
				1097	0-10-16
				1116	0-2-8
				1136	0-13-8
				1136/	
				1134	0-7-2
				1138	0-1-10

[सं. O-14016/154/85-जी. पी.]

S.O. 4597.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1260 dated 23-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Ballia	Naur-angpur	764	1-8-0
				765	0-12-16
				766	0-1-15
				761	1-4-9
				762	0-1-4
				769	0-1-11
				770	0-1-4
				775	0-13-16
				776	0-0-18
				1005	0-0-18
				1006	0-0-10
				1007	0-0-10
				1004	1-5-8
				1003	0-18-10
				1001	0-13-16
				1002	0-1-4
				1027	0-0-12
				1028	0-7-14
				1029	0-0-5
				1030	0-0-12
				1031	0-9-15
				1035	1-10-0
				1050	0-9-12
				1091	0-13-16
				1100	1-0-8
				1096	0-7-4
				1099	0-0-6
				1097	0-10-16
				1116	0-2-8
				1136	0-13-8

1	2	3	4	5	6
				1134	0-7-2
				1138	0-1-10

[No. O-14016/154/85-GP]

का आ. 4598.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1261 तारीख 23-3-1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	सन्हा	नौगवां ठाकुरान	950	0-1-7
				958	0-2-12
				959	0-15-0
				984	0-1-4
				983	0-11-4
				982	0-10-0
				981	0-1-0
				995	1-13-0
				991	0-0-12
				1003	0-19-4
				1009	1-5-15
				1011	0-1-12
				1010	0-14-16
				1008	0-18-0
				1016	0-1-4
				1032	0-10-16
				1023	0-6-15
				1024	0-10-0
				1025	0-2-5
				1028	0-3-0
				1029	0-5-0
				1032	0-2-0

[सं. O-14016/155/85-जीपी]

S.O. 4598.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1261 dated 23-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said repoort, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of thi declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Aquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Sanha	Nauga-wa Thaku-ran	950	0-1-7
				958	0-2-12
				959	0-15-0
				984	0-1-4
				983	0-11-4
				982	0-10-0
				981	0-1-0
				995	1-13-0

1	2	3	4	5	6
				991	0-0-12
				1003	0-19-4
				1009	1-5-15
				1011	0-1-12
				1010	0-14-16
				1008	0-18-0
				1016	0-1-4
				1031	0-10-16
				1023	0-6-15
				1024	0-10-0
				1025	0-2-5
				1028	0-3-0
				1029	0-5-0
				1032	0-2-0

[No. O-14016/155/85-GP]

का. आ. 4599.—यत: पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1262 तारीख 23-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	सन्हा	जमालपुर	2	0-4-0
				3	0-1-16
				14	0-4-0
				15	0-5-10
				20/2	0-1-15
				21	0-3-10
				19	0-11-16
				23	0-3-0
				105	0-5-0
				106	0-3-15
				107	0-19-0
				109	0-12-0
				110	0-10-16
				111	0-9-12
				112	0-0-2
				114	0-1-12
				22	0-0-10
				120	1-4-0
				121	0-8-0
				125	0-2-0
				155	1-0-8
				156	0-9-18
				158	0-16-4
				159	0-16-0
				162	0-3-0

[सं. O-14016/156/85-जी पी]

S.O. 4599.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1262 dated 23-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awlah	Sanha	Jamal-pur	2	0-4-0
				3	0-1-16
				14	0-4-0
				15	0-5-10
				20/2	0-1-15
				21	0-3-10
				19	0-11-16
				23	0-3-0
				105	0-5-0
				106	0-3-15
				107	0-19-0
				109	0-12-0
				110	0-0-16
				111	0-7-12
				112	0-0-2
				114	0-1-12
				22	0-0-10
				120	1-4-0
				121	0-8-0
				125	0-2-0
				155	1-0-8
				156	0-9-18
				158	0-16-4
				159	0-16-0
				162	0-3-0

[No. O-14016/156/85-GP]

का॰ आ॰ 4600.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का॰आ॰ सं॰ 1264 तारीख 23-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि॰ में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाट संख्या	लिया गया रकबा
	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	सन्हा	देवीपुर	1	0-10-4
				2	0-12-0
				3	0-1-12
				4	0-0-18
				5	0-12-0

[सं. O-14016/158/85-जीपी]

S.O. 4600.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1264 dated 23-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awlah	Sanha	Devipur	1	0-10-4
				2	0-12-0
				3	0-1-12
				4	0-0-18
				5	0-12-0

[No. O-14016/158/85-GP]

का. आ. 4601.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1265 तारीख 23-3-1985 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	फरीदपुर	फरीदपुर	चठिया		
			चटनपुर	89	0-17-10
			मुस्तकिल	90	0-5-15
				91	0-9-0
				93	0-6-0
				94	0-6-0
				96	0-16-0
				97	1-0-0
				99	2-10-0
				95	0-1-0
				122	0-1-5
				127	0-16-5
				128	0-16-15
				133	0-1-5
				137	1-1-0
				134	0-1-0
				136	0-4-0
				135	0-9-10
				142	0-17-10
				143	0-5-0
				147	0-1-10
				324	1-8-15
				325	0-11-0
				326	0-1-10
				339	0-9-0
				144	0-0-10
				100	0-0-10
				327	0-0-5

[सं. O-14016/159/85-जीपी]

S.O. 4601.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1265 dated 23-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdispur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Fareed-pur	Fareed-pur	Chotia	89	0-17-10
			Chotan-pur	90	0-5-15
				91	0-9-10
			Musat-kil	93	0-6-0
				94	0-6-0
				96	0-16-0
				97	1-0-0
				99	2-10-0
				95	0-1-0
				122	0-1-5
				127	0-16-5

1	2	3	4	5	6
Chatira	Chatan	Mustakil-(Contd.)		128	0-16-15
				133	0-1-5
				137	1-1-0
				134	0-1-0
				136	0-4-0
				135	0-9-10
				142	0-17-10
				143	0-5-0
				147	0-1-10
				324	1-8-15
				325	0-11-0
				326	0-1-10
				339	0-9-0
				144	0-0-10
				100	0-0-10
				327	0-0-5

[No. O-14016/159/85-GP]

का. आ. 4602.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1266 तारीख 23-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आवला	सन्हा	खेड़ा	1	0-1-16
				10	0-18-10
			खेड़ा—(जारी)	13	0-4-16
				14	0-9-12
				18	0-0-16
				19	0-0-12
				20	0-12-16
					0-1-14
					0-1-5
				23	0-9-12
				118	0-1-15
				119	0-1-15
				516	0-2-10
				522	0-7-4
				524	0-1-12
				525	0-0-12
				526	1-1-0

[सं. O-14016/160/85-जी पी]

S.O. 4602.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1266 dated 23-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Sanha	Kherha	1	0-1-16
				10	0-18-10
				13	0-4-16
				14	0-9-12
				18	0-0-16
				19	0-0-12
				20	0-12-16

1	2	3	4	5	6
			Kherha—(concld.)		0-1-14
					0-1-5
				23	0-9-12
				118	0-1-15
				119	0-1-15
				516	0-2-10
				522	0-7-4
				524	0-1-12
				525	0-0-12
				526	1-1-0

[No. O-14016/160/85-G.P.]

का. आ. 4603.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1267 तारीख 23-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	फरीदपुर	फरीदपुर	सैदपुर मुस्तकिल	3	1-4-10
				4	0-19-0
				143	0-0-15
				160	3-7-0
				161	0-1-10
				162	0-3-5
				163	0-1-10
			सैदपुर मुस्तकिल (जारी)	164	0-11-0
				165	0-14-15
				167	0-9-0
				168	0-6-0
				1	0-0-10

[सं. O-14016/161/85-जीपी]

S.O. 4603.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1267 dated 23-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira—Bareilly—Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Fareed-Pur	Fareed-pur	Saidpur Musta-kil	3	1-4-10
				4	0-19-0
				143	0-0-15
				160	3-7-0
				161	0-1-10
				162	0-3-5
				163	0-1-10
				164	0-11-0
				165	0-14-15
				167	0-9-0
				168	0-6-0
				1	0-0-10

[No. O-14016/161/85-GP]

का. आ. 4604.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत

सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1268 तारीख 23-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर–पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	फरीदपुर	फरीदपुर	चटिया		
			चटनपुर	97	0-3-0
			एतमाली	99	0-19-10
				113	0-9-0
				112	0-3-0
				105	0-1-0
				104	0-0-10
				100	0-2-5
				102	0-3-0
				101	0-0-5
				164	0-10-0
				161	3-0-0
				163	0-0-5
				162	0-10-0

[सं. O-14016/162/85-जी पी]

S.O. 4604.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1268 dated 23-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira—Bareilly—Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Fareedpur	Fareedpur	Chatia Chatan	97	0-3-0
			Ahatmali	99	0-19-10
				113	0-9-0
				112	0-3-0
				105	0-1-0
				104	0-0-10
				100	0-2-5
				102	0-3-0
				101	0-0-5
				164	0-10-0
				161	3-0-0
				163	0-0-5
				162	0-10-0

[No. O-14016/162/85-GP]

का. आ. 4605.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1269 तारीख 23-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में

विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	फ़रीदपुर	फ़रीदपुर	बरेंदा	84	0-2-12
				85	0-4-10

[सं. O 14016/163/85-जी पी]

S.O. 4605.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1269 dated 23-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report, to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira—Bareilly—Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Fareed-Pur	Fareed-Pur		84	0-2-12
			Barenda	85	0-4-10

[No. O-14016/163/85-GP]

का. आ. 4606.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1654 तारीख 20-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	बिसौली	सादनगर	9	0-7-10
				10	1-7-0
				11	0-0-5
				12	0-3-0
				13	0-3-15
				36	0-1-5
				64	0-13-4
				62	0-1-10
				61	0-1-10
				66	0-13-8
				67	0-7-0
				60	0-0-10
				105	2-2-0
				113	0-7-16
				--	0-1-10
				115	1-8-8
				118	0-12-0
				119	0-4-0
				120	0-1-0
				121	0-1-0
				122	0-10-0
				114	0-11-14

[सं. O-14016/214/85-जी पी]

S.O. 4606.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O No. 1654 dated 20-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Bisauli	Sohan-pur	9	0–7–10
				10	1–7–0
				11	0–0–5
				12	0–3–0
				13	0–3–15
				36	0–1–5
				64	0–13–4
				62	0–1–10
				61	0–1–10
				66	0–13–8
				67	0–7–0
				60	0–0–10
				105	2–2–0
				113	0–7–16
				—	0–1–10
				115	1–8–8
				118	0–12–0
				119	0–4–0
				120	0–1–0
				121	0–1–0
				122	0–10–0
				114	0–11–14

[No. O-14016/214/85-GP]

का. आ. 4607.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1656 तारीख 20-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	बिसौली	कमाल-पुर	13	0-1-10
				14	0-8-8
				15	0-12-14
				16	0-0-15
				22	0-5-10
				23	0-13-14
				26	0-19-16
				55	0-0-5
				56	0-0-6
				57	0-2-5
				72	0-4-6
				113	0-4-0
				112	0-10-0
				95	0-18-12
				78	0-5-10
				77	0-2-0
				79	0-1-5
				80	0-18-0
				82	0-8-0
				83	1-4-17
				84	7-0-5
				85	0-3-10

[सं. O- 14016/216/85- जी०पी०]

S.O. 4607.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1656 dated 20-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declared that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira—Bareilly—Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Besuli	Besuli	Kamal-pur	13	0-1-10
				14	0-8-8
				15	0-12-14
				16	0-0-15
				22	0-5-10
				23	0-13-14
				25	0-19-16
				55	0-0-5
				56	0-0-6
				57	0-2-5
				72	0-4-6
				113	0-4-0
				112	0-10-0
				95	0-18-12
				78	0-5-10
				77	0-2-0
				79	0-1-5
				80	0-18-0
				82	0-8-0
				83	1-4-17
				84	0-0-5
				85	0-3-10

[No. O-14016/216/85-GP]

का. आ. 4608.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1658 तारीख 20-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	बिसौली	अन्तहिपुर	1/1	0-0/10

[सं. O-14016/218/85-जी०पी०]

S.O. 4608.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1658 dated 20-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Besali	Besali	Antaiypur	1/1	0-0-10

[No. O-14016/218/85-GP]

का०आ० 4609.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 1660 तारीख 20-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त नियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	बिसौली	सिद्धपुर		
			कैथोली	676	0-7-18
				677	0-18-15

[सं. O-14016/220/85-जी०पी०]

S.O. 4609.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1660, dated 20-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Projec.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisouli	Bisouli	Siddpur	676	0-7-18
			Katholi	677	0-18-15

[No. O-14016/220/85-GP]

का० आ० 4610.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 1661 तारीख 20-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम के धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची

में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	सतासी	बिसौली	नवादा	1	0-15-12
				2	0-10-16
				3	0-18-0
				9	0-2-15
				7	0-0-10

[सं. O-14016/221/85-जी०पी०]

S.O. 4610.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1661 dated 20-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Pargana	Tehsil	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Satasi	Bisauli	Navada	1	0-15-12
				2	0-10-16
				3	0-18-0
				9	0-2-15
				7	0-0-10

[No. O-14016/221/85-GP]

का०आ० 4611:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 1662 तारीख 20-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	बिसौली	निभरा-सखनपुर	4	0-1-4
				5	0-14-10
				7	0-3-0
				10	0-1-10
				26	1-3-10
				28	0-3-18
				29	0-1-5
				31	0-12-2
				36/2	0-19-9
				36/3	1-18-18
				41	0-1-10
				42	0-3-15

[सं. O-14016/222/85-जी०पी०]

S.O. 4611.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1662 dated 20-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaartion in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Bisauli	Nibhara Sardin-pur	4	0-1-4
				5	0-14-10
				7	0-3-0
				10	0-1-10
				26	1-3-10
				28	0-3-18
				29	0-1-5
				31	0-12-2
				36/2	0-19-9
				36/3	1-18-18
				41	0-1-10
				42	0-3-15

[No. O-14016/222/85-GP]

का. आ. 4612 :—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1672 तारीख 20-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं०	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	बिसौली	कालूपुर	204	0-1-15
				206	0-19-16
				271	0-13-16
				272	1-0-0
				273	0-11-2
				274	0-1-10
				277	0-1-5
				283	0-10-16
				284	1-1-12
				285	0-12-10
				266	0-2-0
				265	0-15-12
				254	0-9-0
				264	0-15-0
				263	0-9-10
				253	0-1-10

[सं. O-14016/232/85-जी पी]

S.O. 612.—Wheeras by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1672 dated 20-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Bisauli	Kalupur	204	0-1-15
				206	0-19-16
				271	0-13-16

				272	1-0-0
				273	0-11-2
				274	0-1-10
				277	0-1-5
				283	0-10-16
				284	1-1-12
				285	0-12-10
				266	0-2-0
				265	0-15-12
				254	0-9-0
				264	0-15-0
				263	0-9-10
				253	0-1-10

[No. O-14016/232/85-GP]

का. आ. 4613 :—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं० 1673 ता० 20-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम को धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन लिए के एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	बिसौली	बेगरेन	922	0-13-4
				919	0-13-0
				918	1-2-4
				917	0-8-6
				915	0-1-4
				916	0-8-8
				902	0-3-0

[सं. O-14016/233/85-जी.पी.]

S.O. 4613.—Whereas by notifiaction of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1673 dated 20-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Bisauli	Begren	922	0-13-4
				919	0-13-0
				918	1-2-4
				917	0-8-6
				915	0-1-4
				916	0-8-8
				902	0-3-0

[No. O-14016/233/85-GP]

का०आ० 4614.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 1793 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप, में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लाट संख्या	अर्जित रकबा वि.बि.बि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	शाहाबाद	पछोहा	जल्पापुर	7	0-9-0
				8	0-19-10
				9	0-10-15
				10	0-2-0
				18	0-2-10
				17	1-5-10
				44	0-6-0
				45	0-10-0
				46	1-1-0
				117	0-1-10
				125	0-4-0
				126	1-1-0
				127	0-1-10
				124	0-8-10
				123	1-0-0
				122	0-1-10
				141	0-4-10
				140	0-8-10
				139	0-10-10
				138	0-7-0
				137	0-1-10
				185	0-6-0
				186	0-3-10
				187	0-14-15
				188	0-1-5
				189	0-8-10
				190	0-10-10
				184	0-0-10
				47	0-0-5

[सं. O-14016/239/85-जी.पी.]

S.O. 4614.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 793 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in B.B B.
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Shaha-bad	Pac-hhoha	Jalpa-pur	7	0-9-0
				8	0-19-10
				9	0-10-15
				10	0-2-0
				18	0-2-10
				17	1-5-10
				44	0-6-0
				45	0-10-0
				46	1-1-0
				117	0-1-10
				125	0-4-0
				126	1-1-0
				127	0-1-10
				124	0-8-10
				123	1-0-0
				122	0-1-10
				141	0-4-10
				140	0-8-10
				139	0-10-10
				138	0-7-0
				137	0-1-10
				185	0-6-0
				186	0-3-10
				187	0 14-15
				188	0-1-5
				189	0-8-10
				190	0-10-10
				184	0-0-10
				47	0-0-5

[No. O-14016/239/85-GP]

का. आ. 4615—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के (पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1762 तारीख 16-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा बी.बि.बि.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	शाहाबाद	पठोहा	ज्यूरा	475	1-16-10
				474	0-0-10
				478	0-7-5
				479	1-16-0
				486	1-17-0
				488	0-8-0
				422	0-12-0
				421	0-12-0
				420	0-2-10
				418	0-5-10
				419	0-1-10
				416	0-6-0
				417	0-12-0
				414	0-18-0
				413	0-9-0
				412	0-4-0
				411	0-3-0
				633	0-14-0
				766	1-19-0
				769	0-4-0
				779	0-6-0
				780/1220	0-1-5
				780	0-5-0
				778	0-12-0
				774	0-1-0
				775	0-13-0
				814	0-16-10
				815	0-9-10
				817	0-7-10
				820	0-1-10
				836	0-0-10
				837	0-7-5
				838	0-8-10
				842	0-10-10
				843	0-3-0
				844	1-2-10
				845	0-2-10
				899	0-1-10
				898	0-13-0
				897	0-14-10
				896	0-9-0
				894	0-7-0
				874	0-4-0
				875	0-12-10
				890	1-3-0
				889	0-12-0
				886	0-2-10
				887	0-10-0
				876	0-0-5
				622	0-3-0

[सं. O-14016/248/85-जी.पी.]

S.O. 4615.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S. O. 1762 dated 16-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declares its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of lay'ng pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted reprot to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd., free from all encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in B B B
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Shahabad	Pachhoha	Juira	475	1-16-10
				474	0-0-10
				478	0-7-5
				479	1-16-0
				486	1-17-0
				488	0-8-0
				422	0-12-0
				421	0-12-0
				420	0-2-10
				418	0-5-10
				419	0-1-10
				416	0-6-0
				417	0-12-0
				414	0-18-0
				413	0-9-0
				412	0-4-0
				411	0-3-0
				633	0-14-0
				766	1-19-0
				769	0-4-0
				779	0-6-0
				780/1220	0-1-5
				780	0-5-0
				778	0-12-0
				774	0-1-0
				775	0-13-0
				814	0-16-10
				815	0-9-10
				817	0-7-10
				820	0-1-10
				836	0-0-10
				837	0-7-5
				838	0-8-10
				842	0-10-10
				843	0-3-0
				844	1-2-10
				845	0-2-10
				899	0-1-10
				898	0-13-0
				897	0-14-10
				896	0-9-0
				894	0-7-0
				874	0-4-0
				875	0-12-10
				890	1-3-0
				889	0-12-0
				886	0-2-10
				887	0-10-0
				876	0-0-5
				622	0-3-0

[No. O-14016/248/85-GP]

का. आ. 4616:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के (पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1772 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	आंवला	मनौना	811	1-1-0
				810	0-2-2
				806/1	1-8-16
				808	0-1-3

1	2	3	4	5	6
				803	0-1-10
				805	0-6-18
				804	0-0-14
				800	0-6-16
				799	0-6-16
				798	1-13-6
				797	0-8-2
				796	0-1-4
				766	0-10-5
				765	0-5-5
				764	0-3-10
				763	1-9-0
				762	0-10-12
				761	0-18-10

[सं. O-14016/258/85-जी.पी.]

S.O. 4616.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1755 dated 27-4-85 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said and specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Awala	Mana-una	811	1-1-0
				810	0-2-2
				806/1	1-8-16
				808	0-1-3
				803	0-1-10
				805	0-6-18
				804	0-0-14
				800	0-6-16
				799	0-6-16
				798	1-13-6
				797	0-8-2
				796	0-1-4
				766	0-10-5
				765	0-5-5
				764	0-3-10
				763	1-9-0
				762	0-10-12
				761	0-18-10

[No. O-14016/258/85-GP]

का. आ. 4617.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1778 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	इस्लाम-नगर	दजराम-पुर	75	0-9-9
				76	0-10-4
				67	0-10-5
				68	0-7-10
				69	0-3-18
				29	0-19-0
				30	0-0-5

1	2	3	4	5	6
				27	0–7–0
				32	0–5–10
				21	0–13–15
				33	0–9–12
				19	0–2–10
				20	0–3–0
				18	0–10–0
				15	1–1–0
				16	0–1–15
				14	0–8–2
				5	0–10–15
				6	0–7–4
				7	0–6–0
				8	0–0–15
				9	0–1–0
				77	0–0–10
				74	0–0–10
				4	0–1–5

[सं. O-14016/264/85–जी.पी.]

S.O. 4617.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1778 dated 27-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Islam Nagar	Daja-ram pur	75	0–9–9
				76	0–10–4
				67	0–10–5

1	2	3	4	5	6
				68	0–7–10
				69	0–3–18
				29	0–19–0
				30	0–0–5
				27	0–7–0
				32	0–5–10
				21	0–13–15
				33	0–9–12
				19	0–2–10
				20	0–3–0
				18	0–10–0
				15	1–1–0
				16	0–1–15
				14	0–8–2
				5	0–10–15
				6	0–7–4
				7	0–6–0
				8	0–0–15
				9	0–1–0
				77	0–0–10
				74	0–0–10
				4	0–1–5

[No. O-14016/264/85-GP]

का.आ. 4618:—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1752 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	इस्लाम-नगर	मोहसन-पुर	401	0–2–5
				402	1–13–0
				403	0–7–15

[सं. O–14016/269/85–जीपी.]

S.O. 4618.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1752 dated 27-4-1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (i) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Islam Nagar	Mohsan Pur	401	0–2–5
				402	1–13–0
				403	0–7–15

[No. O-14016/269/85-GP]

का.आ. 4619.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1732 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची निर्दश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	इस्लाम-नगर	विक्रमपुर चरसौरा	180	1–5–4
				46	1–1–12
				47	0–6–0
				48	0–1–4
				49	1–6–4
				58	0–3–12
				60	0–6–0
				59	0–2–8
				61m.	0–9–13
				62	0–6–0
				63	0–3–0
				64	0–1–4
				65	0–1–0
				135m.	0–10–16
				132	0–4–0
				133	0–13–16
				134	0–4–16
				135m.	0–10–16
				138	0–19–0
				139	0–1–0
				125	0–1–10

1	2	3	4	5	6
				126	0-17-8
				123	0-0-12
				141	0-19-4
				168	0-3-0
				137	0-0-5
				140	0-0-5
				56	0-0-10
				120	0-4-0
				119	0-18-0
				118	0-1-4
				390	0-8-8
				391	0-16-6
				392	0-2-8
				393	0-13-4
				412m.	1-10-0
				405	0-8-8
				406	0-12-0
				412m.	1-2-16
				433	0-1-4
				434	0-6-0
				441	0-4-4
				456	0-1-0
				457	0-0-12
				458	1-3-0
				459m.	1-6-8
				460	0-14-10
				461	0-15-10
				485	0-1-0
				486	0-15-12
				487	0-6-16

[सं. O-14016/277/85-जी.पी.]

S.O. 4619.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Deptt. of Petroleum) S.O. 1732 dated 27-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appeanded to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, threfore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Islam-Nagar	Vikram-pur Char-sawra	180	1-5-4
				46	1-1-12
				47	0-6-0
				48	0-1-4
				49	1-6-4
				58	0-3-12
				60	0-6-0
				59	0-2-8
				61m.	0-9-13
				62	0-6-0
				63	0-3-0
				64	0-1-4
				65	0-1-0
				135m.	0-10-16
				132	0-4-0
				133	0-13-16
				134	0-4-16
				135m.	0-10-16
				138	0-19-0
				139	0-1-0
				125	0-1-10
				126	0-17-8
				123	0-0-12
				141	0-19-4
				168	0-3-0
				137	0-0-5
				140	0-0-5
				56	0-0-10
				120	0-4-0
				119	0-18-0
				118	0-1-4
				390	0-8-8
				391	0-16-6
				392	0-2-8
				393	0-13-4
				412m.	1-10-0
				405	0-8-8
				406	0-12-0
				412m.	1-2-16
				433	0-1-4
				434	0-6-0
				441	0-4-4
				456	0-1-0
				457	0-0-12
				458	1-3-0
				459m.	1-6-8

1	2	3	4	5	6
				460	0–14–10
				461	0–15–10
				485	0–1–0
				486	0–15–12
				487	0–6–16

[No. O-14016/277/85-GP]

का. आ. 4620.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना स. का. आ. 1736 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	इस्लाम-नगर	चन्नी	5	3–0–12
				6	0–3–19
				16	0–0–5
				25	0–2–8
				26	2–15–0
				27	0–11–0
				28	0–0–10
				29	0–0–10

[सं. O-14016/281/85-जी.पी.]

S.O. 4620.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum) S.O. 1736 dated 27-4-85 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira–Bareilly–Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Islam-Nagar	Chani	5	3–0–12
				6	0–3–19
				16	0–0–5
				25	0–2–8
				26	2–15–0
				27	0–11–0
				28	0–0–10
				29	0–0–10

[No. O-14016/281/85-GP]

का० आ० 4621.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 1738 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार

एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस ता० में निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	इस्लाम-नगर	अतमाद-पुर उर्फ रामपुर	500	0–7–4
				501	0–6–0
				499	0–9–0
				498	0–1–4
				497	0–3–12
				459	0–18–0
				458	0–3–10
				457	0–0–10
				456	0–18–0
				443	0–12–0
				446	0–9–0
				447	1–7–0
				227	0–12–0
				228	0–16–16
				238	0–7–0
				239	0–16–16
				224	0–0–16
				214	0–1–4
				244	0–12–0
				216	0–4–19
				245	0–10–16
				251	1–8–0
				250	0–1–16
				254	0–8–0
				271	0–7–0
				253	0–2–0
				276	0–12–0
				165	0–10–5
				166	0–8–10
				163	1–6–8
				160	0–3–0
				119	0–7–16
				122	1–15–4
				123	0–0–10
				121	0–2–8
				120	0–2–10
				494	0–1–4
				460	0–1–8
				461	0–11–0
				212	0–1–10
				243	0–1–8
				246	0–0–18
				275	0–13–16
				195	0–2–8
				184	0–3–5
				167	0–0–10
				162	0–1–0
				118	0–5–0
				272	0–1–10

[सं. O–14016/283/85–जी.पी.]

S.O. 4621.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Petroleum) S.O. 1738 dated 27-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Islam-Nagar	Atamad-pur urf Rampur	500	0-7-4
				501	0-6-0
				499	0-9-0
				498	0-1-4

1	2	3	4	5	6
				497	0-3-12
				459	0-18-0
				458	0-3-10
				457	0-0-10
				456	0-18-0
				443	0-12-0
				446	0-9-0
				447	1-7-0
				227	0-12-0
				228	0-16-16
				238	0-7-0
				239	0-16-16
				224	0-0-16
				214	0-1-4
				244	0-12-0
				216	0-4-19
				245	0-10-16
				251	1-8-0
				250	0-1-16
				254	0-8-0
				271	0-7-0
				253	0-2-0
				276	0-12-0
				165	0-10-5
				166	0-8-10
				163	1-6-8
				160	0-3-0
				119	0-7-16
				122	1-15-4
				123	0-0-10
				121	0-2-8
				120	0-2-10
				494	0-1-4
				460	0-1-8
				461	0-11-0
				212	0-1-10
				243	0-1-8
				246	0-0-18
				275	0-13-16
				195	0-2-8
				184	0-3-5
				167	0-0-10
				162	0-1-0
				118	0-5-0
				272	0-1-10

[No. O-14016/283/85-GP]

का० आ० 4622.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 1741 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	आंवला	मनपुरा	155	0-4-4
				152	0-6-12
				151	0-11-7
				153	0-0-13
				132	0-5-0
				131	0-17-8
				130	0-2-14
				154	0-1-3
				164	0-4-8
				165	0-6-0
				174	0-15-5
				175	0-0-5
				166	0-1-13
				172	0-12-12
				173	0-0-14
				171	0-10-3
				179	0-0-16
				178	0-1-12
				180	0-0-16
				192	1-8-0

1	2	3	4	5	6
			मनपुरा (जारी)	187	0–0–14
				184	0–9–4
				185	0–8–8
				95	0–0–12
				88	0–18–0
				87	0–1–8
				61	0–4–10
				60	1–10–0
				42	0–7–0
				44	1–0–0

[सं. O-14016/286/85-जी.पी.]

S.O. 4622.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1741 dated 27-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Awala	Man-pura	155	0–4–4
				152	0–6–12
				151	0 11–7
				153	0–0–13
				132	0–5–0
				131	0–17–8
				130	0–2–14
				154	0–1–3
				164	0–4 8
				165	0-6–0
				174	0-15–5
				175	0–0–5
				166	0–1–13
				172	0–12–12
				173	0–0–14
				171	0–10–3
				179	0–0–16
				178	0–1–12
				180	0–0–16
				192	1–8–0
				187	0–0–14
				184	0–9–4
				185	0–8–8
				95	0–0–12
				88	0–18–0
				87	0–1–8
				61	0–4–10
				60	1–10–0
				42	0–7–0
				44	1–0–0

[No. O-14016/286/85-G.P.]

का. आ. 4623.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 1744 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	आंवला	आसपुर	337	0–2–14
				338	0–1–4
				339	0–5–14
				356	0–18–0

1	2	3	4	5	6
				355	0–14–8
				354	0–1–4
				353	0–17–4
				350	0–6–0
				361	0–7–0
				363	0–1–4
				364	0–9–0
				365	2–0–0
				370	0–1–0
				367	0–4–10
				366	0–5–8
				248	0–4–4
				247	0–7–14
				249	0–5–0
				250	0–2–0
				246	0–0–10
				120	0–8–0
				121	0–1–0
				119	0–19–0
				122	0–5–5
				109	0–13–15
				123	0–1–10
				131	0–2–0
				130	0–11–16
				128	0–0–1
				129	1–4–12
				127	0–11–12
				140	0–2–8
				141	0–16–4
				101	0–1–4
				97	0–16–0
				98	0–14–8
				94	1–2–16
				93	0–9–0
				359	0–0–2
				360	0–0–5
				349	0–0–10

[सं. O-14016/289/85- जी.पी.]

S.O. 4623.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, (Deptt. of Petroleum) S.O. 1744 dated 27-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira–Bareilly–Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Awala	Aspur	337	0-2-14
				338	0-1-4
				339	0-5-14
				356	0-18-0
				355	0-14-8
				354	0-1-4
				353	0-17-4
				350	0-6-0
				361	0-7-0
				363	0-1-4
				364	0-9-0
				365	2-0-0
				370	0-1-0
				367	0-4-10
				366	0-5-8
				248	0-4-4
				247	0-7-14
				249	0-5-0
				250	0-2-0
				246	0-0-10
				120	0-8-0
				121	0-1-0
				119	0-19-0
				122	0-5-5
				109	0-13-15
				123	0 1-10
				131	0-2-0
				130	0-11-16
				128	0-0-1
				129	1-4-12
				127	0-11-12
				140	0 2 8
				141	0-16-4
				101	0-1-4
				97	0-16-0
				98	0-14-8
				94	1-2-16

1	2	3	4	5	6
			Aspur—(Contd.)	93	0–9–0
				359	0-0–2
				360	0–0-5
				349	0–0–10

[No. O—14016/289/85-G.P.]

का. आ. 4624.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के उर्जा मन्त्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का.आ. सं. 2027 तारीख 1-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5	6
हरदोई	बिलग्राम	कटियारी	श्यामपुर		बी. वि. वि.
				190	2–5–0
				169/860	0–4–0
				169	0–12–0
				170	0–9–0
				186	0–1–0
				185	0–5–0
				221	2–0–0
				222	1–0–0
				223	0–6–10
				226	0–2–10
				228	1–0–0
				229	1–0–0

1	2	3	4	5	6
			श्यामपुर (जारी)	230	0–8–0
				231	0–11–0
				232	0–19–0
				233	0–12–0
				234	0–16–0
				235	0–15–0
				236	0–19–0
				237	0–9–0
				238	0–6–0
				216एम	3–2–0
				217एम	0–5–0
				345	1–0–0
				355	1–3–0
				354	0–15–0
				353	0–0–10
				352	1–0–0
				350	2–7–0

[सं. O-14016/306/85-जी.पी.]

S.O. 4624.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2027 dated 1-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Vill.	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
					B.V.V.
Hardoi	Bilg-gram	Kati-yari	Shyam-pur.	190	2-5-0
				169/860	0-4-0
				169	0-12-0
				170	0-9-0

1	2	3	4	5	6
		Shyampur (contd.)		186	0–1–0
				185	0–5–0
				221	2–0–0
				222	1–0 0
				223	0–6–10
				226	0-2–10
				228	1–0–0
				229	1–0–0
				230	0–8–0
				231	0–11–0
				232	0–19–0
				233	0–12–0
				234	0-16–0
				235	0–15–0
				236	0–19–0
				237	0–9–0
				238	0–6–0
				216m	3-2–0
				217m.	0–5–0
				345	1–0–0
				355	1–3–0
				354	0–15–0
				353	0–0–10
				352	1–0–0
				350	2–7–0

[No. O-14016/306/85-G.P.]

का. आ. 4625 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 2579 तारीख 30-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा एकड़ में
1	2	3	4	5	6
शाहजहांपुर	सदर	ददरौल	जाजलपुर	220	— 18
				221	— 65
				223	— 03
				224	— 45
				225	— 38
				226	— 15
				165	— 07

[सं. ओ.-14016/352/85-जी.पी.]

S.O. 4625.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2579 dated 30-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipe Line Project

Distt.	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acres
1	2	3	4	5	6
Shahjhanpur	Sadar	Dadroul	Jajalpur	220	18
				221	65
				223	03
				224	45
				225	38
				226	15
				165	07

[No. O-14016/352/85-G.P

का०आ० 4626.– यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 2576 तारीख 30-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा एकड़ में
1	2	3	4	5	6
शाहजहांपुर	सदर	कान्ट	धनुवा खिड़ा	41	— 18
				42	— 18
				43	— 84
				44	— 35
				47	— 42
				52	— 02
				53	— 13

[सं. ओ-14016/354/85-जी. पी.]

S.O. 4626.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2576 dated 30-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acres
1	2	3	4	5	6
Shahjhanpur	Sadar	Kant	Dhanuwa Khera	41	— 18
				42	— 18
				43	— 84
				44	— 35
				47	— 42
				52	— 02
				53	13

[No. O—14016/354/85-G.P.]

का. आ. 4627 :— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2577 तारीख 30-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	तहसील	गाटा संख्या	अर्जित रकबा एकड़ में	
1	2	3	4	5	6	
शाहजहां-पुर	सदर	कांट	बरनावा	87	—	30
				94	—	30
				95	—	10
				98	—	68
				99	—	45
				100	—	04
				101	—	50
				102	—	55
				88	—	02

[सं. ओ-14016/355/85-जी. पी.]

S.O. 4627.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2577 dated 30-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Aceres	
1	2	3	4	5	6	
Shah-jahan-pur	Sadar	Kant	Bar-nawa	87	—	30
				94	—	30
				95	—	10
				98	—	68
				99	—	45
				100	—	04
				101	—	50
				102	—	55
				88	—	02

[No. O-14016/355/85-G.P.]

का. आ. 4628.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2587 तारीख 30-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा एकड़ में
1	2	3	4	5	6
शाहजहांपुर	सदर	कांट	अलियापुर	2	—83
				3	—30
				4	—66
				5	—45
				14	—15
				15	—10
				16	—21
				53	—15
				157	—10
				158	—14
				159	—48
				160	—09
				170	—58
				171	—02
				172	—10
				173	—20
				224	—38
				226	—29
				227	—24
				156	—05

[सं. ओ-14016/356/85-जी. पी.]

S.O. 4628.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2587 dated 30-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Cenral Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipe line Project

Distt.	Tehsil	Porgana	Village	Plot No.	Area in Acers
1	2	3	4	5	6
Shahjhanpur	Sadar	Kant	Aliyapur	2	—83
				3	—30
				4	—66
				5	—45
				14	—15
				15	—10
				16	—21
				53	—15
				157	—10
				158	—14
				159	—48
				160	—09
				170	—58
				171	—02
				172	—10
				173	—20
				224	—38
				226	—29
				227	—24
				156	—05

[No. O-14016/356/85-.G.P.]

का. आ. 4629:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2588 तारीख 30-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा एकड़ में
1	2	3	4	5	6
शाहजहाँपुर	सदर	कांट	हसरामऊ	56	—18
				57	—15
				58	—06
				59	—06
				78	—65
				73	—02
				75	—02
				76	—03

[सं. ओ-14016/357/85-जी. पी.]

S.O. 4629.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2588 dated 30-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals, Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acers
1	2	3	4	5	6
Shah-Jahan-pur	Sadar	Kant	Hasra Mau	56	—18
				57	—15
				58	—06
				59	—06
				78	—65
				73	—02
				75	—02
				76	—03

[No. O -14016/357/85-G.P.]

का. आ. 4630.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2590 तारीख 30-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा एकड़ में
1	2	3	4	5	6
शाहजहाँपुर	सदर	कांट	महमदपुर अजमाबाद	249	—06

[सं. O 14016/358/85 जी. पी.]

S.O. 4630.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2590 dated 30-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the

right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acres
1	2	3	4	5	6
Shah-jhan-pur	Sadar	Kant	Mah-mad-pur Ajma-bad	249	... 06

[No. O-14016/358/85-G.P.]

का. आ. 4631.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 2585 तारीख 30-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देदी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा—बरेली—जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा एकड़ में
1	2	3	4	5	6
शाहजहांपुर	सदर	कांट	रतनापुरा	54	0-04

[सं. O-14016/359/85-जी. पी.]

S.O. 4631.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2585 dated 30-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notificfiation;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acres
1	2	3	4	5	6
Shah-jhan-pur	Sadar	Kant	Ratna-pur	54	0 — 04

[No. O-14016/359/85-G.P.]

का. आ. 4632.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 का (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 2585 तारीख 30-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित रकबा बी.वि.बी.
1	2	3	4	5	6
हरदोई	शाहाबाद	पछोहा	मानपारा	353	0-1-10
				354	0-0-5
				355	0-13-0
				373	0-11-10
				372	0-0-5
				371	0-3-0
				419	0-6-0
				418	0-9-0
				417	0-8-10
				416	0-6-0
				420	0-6-10
				516	0-0-5
				515	0-5-5
				514	0-17-0
				547	0-13-10
				548	0-18-0
				549	0-7-5
				564	0-2-0
				565	0-3-10
				566	1-3-10
				567	0-4-5
				568	0-9-0

[सं. O-14016/361/85-जी. पी.]

S.O. 4632.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2585 dated 30-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submited report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication, of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acquired B. V. V.
1	2	3	4	5	6
Hardoi	Shahbad	Pachhoha	Manpara	353	0-1-10
				354	0-0-5
				355	0-13-0
				373	0-11-10
				372	0-0-5
				371	0-3-0
				419	0-6-0
				418	0-9-0
				417	0-8-10
				416	0-6-0
				420	0-6-10
				516	0-0-5
				515	0-5-5
				514	0-17-0
				547	0-13-10
				548	0-18-0
				549	0-7-5
				564	0-2-0
				565	0-3-10
				566	1-3-10
				567	0-4-5
				568	0-9-0

[No. O-14016/361/85-G.P.]

का. आ. 4633.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3043 तारीख 29-6-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	आंवला	कन्यरी जाफर-पुर	312	1-7-0
				287	0-12-10
				286	0-3-0
				237	0-2-5
				236	0-16-15
				239	0-14-2
				240	1-2-10
				233	0-0-15
				232	0-19-4
				231	0-0-12
				230	0-10-16
				228	0-10-0
				226	1-13-16
				243	0-0-16
				223	0-0-2
				224	2-1-0
				242	0-0-14
				198	0-0-6
				195	1-0-8
				192	0-1-0
				134	0-15-0
				139	0-1-9
				153	0-1-12
				152	0-7-15
				151	0-9-4
				150	0-6-10
				146	0-1-2
				149	0-17-6
				148	0-1-5
				147	1-6-16
				32	0-0-12
				25	1-0-14
				26	0-1-10
				24	1-14-8
				28	0-0-10
				27	1-8-0
				36	0-2-8
				314	0-0-2
				234	0-0-10
				22	0-0-2

[सं. O-14016/368/85-ओ. पी.]

S.O. 4633.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3043 dated 29-6-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in

Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipeline Project

Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Awala	Kanth-	312	1-7-0
			ari	287	0-12-10
			Jafarpur	286	0-3-0
				237	0-2-5
				236	0-16-15
				239	0-14-2
				240	1-2-10
				233	0-0-15
				232	0-19-4
				231	0-0-12
				230	0-10-16
				228	0-10-0
				226	1-13-16
				243	0-0-16
				223	0-0-2
				224	2-1-0
				242	0-0-14
				198	0-0-6
				195	1-0-8
				192	0-1-0
				134	0-15-0
				139	0-1-9
				153	0-1-12
				152	0-7-15
				151	0-9-4
				150	0-16-10
				146	0-1-2
				149	0-17-6
				148	0-1-5
				147	1-6-16
				32	0-0-12
				25	1-0-14
				26	0-1-10
				24	1-14-8
				28	0-0-10
				27	1-8-0
				36	0-2-8
				314	0-0-2
				234	0-0-10
				22	0-0-2

[No. O-14016/368/85-G.P.]

का० आ० 4634.--यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, नियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के (विभाग) पैट्रोलियम मंत्रालय, की अधिसूचना का. आ. सं. 3041 तारीख 24-6-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकरी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा--बरेली--जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	आंवला	गुलैली	495	0-1-0
				544	0-3-10
				543	0-11-12
				542	1-7-12
				496	0-0-12
				497	0-0-18
				498	0-9-17
				535	0-19-16
				533	2-7-16
				534	0-0-10
				523	0-1-4
				524	0-1-4
				510	1-0-0
				511	1-5-8
				512	0-13-10
				514	0-1-0
				515	0-2-0
				516	0-3-10
				494	1-18-0

[सं. O--14016/370/85--जी.पी.]

S.O. 4634.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3041 dated 29-6-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands, shall instead of vesting in Central Government, vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Awala	Gulaibi	495	0-1-0
				544	0-3-10
				543	0-11-12
				542	1-7-12
				496	0-0-12
				497	0-0-18
				498	0-9-17
				535	0-19-16
				533	2-7-16
				534	0-0-10
				523	0-1-4
				524	0-1-4
				510	1-0-0
				511	1-5-8
				512	0-13-10
				514	0-1-0
				515	0-2-0
				516	0-3-10
				494	1-18-0

[No. O-14016/370/85-G.P.]

का. आ. 4635.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. सं 3353 तारीख 20-7-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट

भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
कानपुर देहात	अकबरपुर	अकबरपुर	पुर	305	0-5-0
				303	1-3-0
				293	0-18-0
				296	2-3-0
				16	0-6-0
				24	1-1-0
				23	0-11-0
				25	1-8-0
				28	0-17-0
				19	0-2-0
				280	2-2-0
				22	0-2-0

[सं. O-14016/393/85-जी.पी.]

S.O. 4635.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3353 dated 20-7-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central

Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Barcilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acquired
1	2	3	4	5	6
Kanpur Dehat	Akbarpur	Akbarpur	Pur	305	0–5–0
				303	1–3–0
				293	0–18–0
				296	2–3–0
				16	0–6–0
				24	1–1–0
				23	0–11–0
				25	1–8–0
				28	0–17–0
				19	0–2–0
				280	0–2–0
				22	0–2–0

[No. O-14016/393/85-G.P.]

का०आ० 4636.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. 1263 तारीख 23-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लाट संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	सन्हा	नकटपुर	12	0-1-8
				13	0-13-9
				14	0-14-8
				15	0-12-0
				16	0-16-4
				17	0-0-16
				21	2-0-17
				24	0-1-12
				19	0-7-0
				20	0-0-9
				98	0-10-19
				76	0-1-2
				96	0-16-5
				95	0-3-5
				97	0-3-12
				96/184	0-0-18
				105	2-0-10
				100	0-2-15
				101	1-6-10
				102	0-6-0
				104	0-0-5
				103	0-11-0
				176	0-0-12
				178	0-10-18

[सं. O-14016/157/85-जी. पी.]

एम. एस. श्रीनिवासन, उप सचिव

S.O. 4636.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1263 dated 23-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the

said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Teshil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Sanha	Nikatpur	12	0-1-8
				13	0-13-9
				14	0-14-8
				15	0-12-0
				16	0-16-4
				17	0-0-16
				21	2-0-17
				24	0-1-12
				19	0-7-0
				20	0-0-9
				98	0-10-19
				76	0-1-2
				97	0-16-5
				95	0-3-5
				97	0-3-12
				96/184	0-0-13
				105	2-0-10
				100	0-2-15
				101	1-6-10
				102	0-6-0
				104	0-0-5
				103	0-11-0
				176	0-0-12
				178	0-10-18

[No. O-14016/157/85-G.P.]

M.S. SRINIVASAN, Dy. Secy.

का. आ. 4637.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गजरात राज्य में सोभासन सी. टी. एफ. से जी. जी. एस. I पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

सोभासन सी. टी. एफ. से जी. जी. एस. I

राज्य गुजरात जिला व तालुका :— मेहसाना

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
हेदुवा	96	0	06	35
	100	0	01	50
	97	0	00	25
	कार्टट्रेक	0	00	40
	99	0	06	20
	106	0	03	75
	कार्टट्रेक	0	00	25
	109	0	08	55
	112	0	03	50
	116	0	05	00
	117	0	02	90
	कार्टट्रेक	0	00	25
	167	0	01	15
	166	0	04	85
	कार्टट्रेक	0	00	25
	165	0	01	90
	160	0	03	60
	178	0	01	15

[सं. O-12016/101/85-ओ एन जी-डी 4]

S.O. 4637.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Sobhasan C.T.F. to G.G.S.I. in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009) ;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Sobhasan CTF to GGS I.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Hebuva	96	0	06	35
	100	0	01	50
	97	0	00	25
	Cart track	0	00	40
	99	0	06	20
	106	0	03	75
	Cart track	0	00	25
	109	0	08	55
	112	0	03	50
	116	0	05	00
	117	0	02	90
	Cart track	0	00	25
	167	0	01	15
	166	0	04	85
	Cart track	0	00	25
	165	0	04	90
	160	0	03	60
	178	0	01	15

[No. O-12016/101/85-ONG- D-4]

का०आ० 4638-यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सोभासन सी. टी. एफ. से जी. जी. एस. I तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयो द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

सोभासन सी. टी. एफ. से जी. जी. ऐस– I

राज्यः– गुजरात जिला व तालुकाः– मेहसाना

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
कुकस	276	0	02	75
	283	0	13	40
	289	0	08	90
	303	0	05	00
	300	0	06	45
	299	0	07	75
	307	0	00	25
	309	0	04	20
	310	0	17	00
	311	0	05	70
	312	0	01	90
	313	0	08	75
	314	0	04	05
	कार्ट ट्रेक	0	00	25
	320	0	06	23

[सं. O–12016/100/85–ओ एन जी- डी-4]

पी. के. राजगोपालन, डैस्क अधिकारी

S.O. 4638.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Sobhasan CTF to G.G.S.I. in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the scheduled annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Sobhasan CTF to GGS I

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Kukas	276	0	02	75
	283	0	13	40
	289	0	08	90
	303	0	05	00
	300	0	06	45
	299	0	07	75
	307	0	00	25
	309	0	04	20
	310	0	17	00
	311	0	05	70
	312	0	01	90
	313	0	08	75
	314	0	04	05
	Cart track	0	00	25
	320	0	06	30

[No. O-12016/100/85-ONG- D-4]

P.K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

भारत मौसम विभाग

(मौसम विज्ञान महानिदेशक का कार्यालय)

नई दिल्ली, 10 सितम्बर 1985

का० आ० 4639.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1955, तारीख 14 जून, 1973 को, अधिक्रांत करते हुए, यह निदेश देते है कि इस आदेश की अनुसूची के भाग 1 और भाग 2 के स्तम्भ 1 मे विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" और साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ" के पदों की बाबत स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होगा तथा स्तम्भ 3 और स्तम्भ 5 मे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट शक्तियों के संबंध में क्रमश: अनुशासन प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी होंगे।

अनुसूची

भाग 1—साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग"

पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां आरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और वे शास्तियां जिन्हें वह (नियम 11 मे पद संख्याकों के प्रति निदेश से) अधिरोपित कर सकेगा। प्राधिकारी	शास्तियां	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
भारत मौसम-विज्ञान विभाग : वैज्ञानिक सहायक, आशुलिपिक (श्रेणी 2), पुस्तकालयाध्यक्ष, अधीक्षक (कलकत्ता), प्रधान लिपिक, हिन्दी अनुवादक श्रेणी-1 और हिन्दी अनुवादक श्रेणी-2	मौसम-विज्ञान उपमहानिदेशक (प्रशासन और भंडार)	मौसम-विज्ञान उपमहानिदेशक (प्रशासन और भण्डार)	सभी	मौसम विज्ञान महानिदेशक
		मौसम विज्ञान उपमहानिदेशक (मौसम विज्ञान और भू-भौतिकी); मौसम विज्ञान अपर महानिदेशक (अनुसंधान) का कार्यालय, पुणे, मौसम विज्ञान उपमहानिदेशक उपकरण उत्पादन, नई दिल्ली (मौ० पू० पुणे); (उपकरण निरीक्षण और सेवा) पुणे और सभी प्रादेशिक निदेशक कृषि मौसम-विज्ञान निदेशक, पुणे, मौसम-विज्ञानी (स्थापना) मुख्यालय, मौसम-विज्ञान महानिदेशक का कार्यालय, नई दिल्ली।	(i) से (iv)	
यांत्रिक सहायक, मुख्य मैकेनिक	मौसम-विज्ञान उप-महानिदेशक (प्रशासन और भण्डार)	मौसम-विज्ञान उपमहानिदेशक (प्रशासन और भण्डार)	सभी (i) से (iv)	मौसम-विज्ञान महानिदेशक
		मौसम विज्ञान उपमहानिदेशक (उपकरण उत्पादन), नई दिल्ली उपकरण निरीक्षण और सेवाएं, पुणे; प्रादेशिक निदेशक बम्बई।		मौसम विज्ञान महानिदेशक
अन्य पद :				
(क) मौसम विज्ञान महानिदेशक का कार्यालय, भूकम्प विज्ञान वेधशालाओं, नागर विमान प्रशिक्षण केन्द्र, बामरौली से संलग्न मौसम-विज्ञान एकक और जल मौसम विज्ञान वेधशालाओं में जो मौसम-विज्ञान महानिदेशक, केन्द्रीय भूकम्प विज्ञान वेधशाला, शिलांग, स्थितीय खगोलविज्ञान केन्द्र कलकत्ता के स्थापन द्वारा धारित है।	मौसम-विज्ञान उप-महानिदेशक (प्रशासन और भंडार)	मौसम-विज्ञान उपमहानिदेशक (प्रशासन और भंडार)	सभी (i) से (iv)	मौसम-विज्ञान महानिदेशक
		भारसाधक मौसम-विज्ञानी केन्द्रीय भूकम्प-विज्ञान वेधशाला शिलांग, उस कार्यालय के पदों के लिए और अन्य के लिए मौसम-विज्ञानी (स्थापना) मौसम-विज्ञान महानिदेशक का कार्यालय		मौसम-विज्ञान उप महानिदेशक (प्रशासन और भंडार)
(ख) अन्य कार्यालयों के स्थापन में	मौसम-विज्ञान उप-महानिदेशक (प्रशासन और भंडार)	मौसम-विज्ञान उप महानिदेशक प्रादेशिक निदेशक या संबंधित निदेशक।	सभी (i) से (iv)	मौसम-विज्ञान महानिदेशक
		अन्य कार्यालयों में प्रशासन का भारसाधक सहायक मौसम विज्ञानी		मौसम विज्ञान उप-महानिदेशक या प्रादेशिक निदेशक या संबंधित निदेशक।

भाग 2—साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ"

1	2	3	4	5
(1) मौसम-विज्ञान महानिदेशक के स्थापन द्वारा धारित और जल-मौसम विज्ञान तथा भूकम्प-विज्ञान एककों के स्थापन द्वारा धारित सभी पद।	मौसम-विज्ञान महानिदेशक के कार्यालय में मौसम-विज्ञानी (प्रशासन)	मौसम-विज्ञान महानिदेशक के कार्यालय में मौसम-विज्ञानी (प्रशासन)	सभी	मौसम-विज्ञान उप-महानिदेशक (प्रशासन और भंडार)।
(2) केन्द्रीय भूकम्प-विज्ञान वेधशाला, शिलांग के सभी पद।	भारसाधक मौसम-विज्ञानी, केन्द्रीय भूकम्प वेधशाला शिलांग	भारसाधक मौसम-विज्ञानी केन्द्रीय भूकम्प-वेधशाला शिलांग	सभी	मौसम-विज्ञान उप-महानिदेशक (प्रशासन और भंडार)।

1	2	3	4	5
(3) अन्य कार्यालयों (जिसके अंतर्गत स्थितीय खगोल-विज्ञान केन्द्र, कलकत्ता भी है) के सभी पद।	प्रशासन का भारसाधक सहायक मौसम-विज्ञान	प्रशासन का भारसाधक सहायक मौसम-विज्ञानी	सभी	मौसम-विज्ञान उप-महानिदेशक या प्रादेशिक निदेशक या संबंधित कार्यालय का भारसाधक निदेशक।

[सं. बी-00101 भाग 2/ बी]

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

(Office of the Director General of Meteorology)

New Delhi, the 10th September, 1985

S.O.4639.—In exercise of the power conferred by sub-rule (2) of rule 9 and clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of Rule 24 of the Central Civil Services (Cclassification Control and Appeal) Rules, 1965, and is supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Tourism and Civil Aviation No. S.O. 1955 dated the 14th June, 1973, the President hereby directs that in respect of the posts in the General Central Services, Group C, and General Central Services, Group D, specified in column 1 of Parts I and II of the Schedule to this order, the authority specified in column 2 shall be the Appointing Authority and the authorities specified in columns 3 and 5 shall be the Disciplinary Authority and the Appellate Authority respectively in regard to the penalties specified in column 4.

SCHEDULE

Part I—General Central Service Group "C"

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in rule 11)		Appellate Authority
		Authority	Penalties	
1	2	3	4	5
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT:				
Scientific Assistant, Stenographer (Grade-II), Librarian, Superintendent (Calcutta), Head Clerks, Hindi Translator Grade-I and Hindi Translator Grade-II.	Deputy Director General of Meteorology (Administration and Stores).	Deputy Director General of Meteorology (Administration and Stores).	All	Director General of Meteorology.
		Deputy Director General of Meteorology (Climatology and Geophysics), Office of the Additional Director General of Meteorology (Research), Pune; Deputy Directors General of Meteorology (Instrument Production), New Delhi; (Weather Forecasting), Pune; (Instrument Inspection and Servicing), Pune; and all Regional Directors, Director Agricultural Meteorology, Pune; Meteorologist (Establishment) Headquartres, Offic· of the Director General of Meteorology, New Delhi.	(i) to (iv)	Director General of Meteorolcgy
Mechanical Assistant, Chief Mechanic.	Deputy Director General of Meteorology (Administration and Stores).	Deputy Director General of Meteorology (Administration and Stores).	All	Director General of Meteorology.
		Deputy Directors General of Meteorology (Instrument Production) New Delhi; (Instrument Inspection and Servicing), Pune; Regional Director, Bombay.	(i) to (iv)	Director General of Meteorology.
Other posts:				
(a) In the Office of the Director General of Meteorology, Seismologic al Observatories, Meteorological	Deputy Director General of Meteorology (Administration and Stores).	Deputy Director General of Meteorology (Administration and Stores).	All	Director General of Meteorology.

1	2	3	4	5
Unit attached to the Civil Aviation Training Centre, Bamrauli and Hydro-Meteorological Observatories which are borne on the establishment of the Director General of Meteorology, Central Seismological Observatory, Shillong; Positional Astronomy Centre, Calcutta.		Meterologist-in-Charge, Central Seismological observatory, Shillong for posts in that office and Meteorologist (Establishment), Office of the Director General of Meteorology for others.	(i) to (iv)	Deputy Director General of Meteorology (Administaration and Stores).
(b) In the establishment of other offices.	Deputy Directors General of Meteorology or Regional Directors or Director concerned.	Deputy Directors General of Meteorology or Regional Directors or Director concerned.	All	Director General of Meteorology.
		Assistant Meteorologist Incharge of Administration in other offices.	(i) to (iv)	Deputy Directors General of Meteorology or Regional Directors or Director concerned.

Part II—General Central Service Group D

Description of posts	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in rule 11)		Appellate Authority
		Authority	Penalties	
1	2	3	4	5
(1) All posts borne on the establishment of the Director General of Meteorology and Hydro-Meteorological and Seismological Units borne on his establishment.	Meteorologist (Administration) in the office of the Director General of Meteorology.	Meteorologist (Administration) in the office of the Director General of Meteorology.	All	Deputy Director General of Meteorology (Administration and Stores).
(2) All posts in the Central Seismological Observatory, Shillong.	Meteorologist Incharge, Central Seismological Observatory, Shillong	Meteorologist Incharge, Central Seismological Observatory, Shillong.	All	Deputy Director General of Meteorology (Administration and Stores).
(3) All posts in other offices (including Positional Astronomy Centre, Calcutta).	Assistant Meteorologist-in-Charge of Administration.	Assistant Meteorologist Incharge of Administration.	All	Deputy Director General of Meteorology or Regional Director or Director-in-Charge of the office concerned.

[No. V-00101 Part II/B]

का. आ. 4640:—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उपनियम (1), और नियम 12 के उपनियम (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1954, तारीख 14 जून, 1973 को अधिक्रान्त करते हुए, यह निदेश देते है कि इस आदेश की अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट भारतीय मौसम विज्ञान सेवा, समूह "ख" के पदों की बाबत, स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होंगे और स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट शास्तियों के संबंध में अनुशासन प्राधिकारी होगा।

अनुसूची

पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और वे शास्तियां जिन्हें वह (नियम 11 में मद संख्यांकों के प्रति निर्देश से) अधिरोपित कर सकेगा।	
		प्राधिकारी	शास्तियां
1	2	3	4
भारत मौसम विज्ञान विभाग भारतीय मौसम विज्ञान सेवा समूह "ख" राजपत्रित			
सहायक मौसम विज्ञानी या सहायक कृषि मौसम विज्ञानी या सहायक भूकंप विज्ञानी	मौसम विज्ञान महा-निदेशक	मौसम विज्ञान महानिदेशक	सभी
अराजपत्रित			
(1) यान्त्रिक सहायक [जिसके अन्तर्गत यान्त्रिक सहायक (फोरमैन) और आशुलिपिक श्रेणी-1 भी है]	मौसम विज्ञान महा-निदेशक	पुणे स्थित मौसम विज्ञान अपर महानिदेशक अनुसंधान के स्थापन द्वारा धारित पदों के लिए मौसम विज्ञान उपमहानिदेशक (जलवायुविज्ञान और भूभौतिकी), मौसम विज्ञान महानिदेशक, केन्द्रीय भूकंप विज्ञान वेधशाला, शिलांग और स्थितीय खगोल विज्ञान केन्द्र, कलकत्ता के स्थापन द्वारा धारित पदों के लिए मौसम विज्ञान उपमहानिदेशक (प्रशासन और भंडार), मौसम विज्ञान उपमहानिदेशक (उपकरण उत्पादन), (मौसम पूर्वानुमान) और (उपकरण निरीक्षण और सर्विसिंग), प्रादेशिक निदेशक, कृषि मौसम विज्ञान निदेशक, उनके अपने अपने स्थापन द्वारा धारित पदों के लिए।	सभी 1 से 4
(2) अधीक्षक, मौसम विज्ञान महानिदेशक का कार्यालय, मुख्यालय, नई दिल्ली	मौसम विज्ञान महा-निदेशक	मौसम विज्ञान महानिदेशक मौसम विज्ञान उपमहानिदेशक (प्रशासन और भण्डार)	सभी 1 से 4
(3) अधीक्षक, मौसम विज्ञान अपरमहानिदेशक (अनुसंधान) का कार्यालय, पुणे	मौसम विज्ञान महा-निदेशक	मौसम विज्ञान महानिदेशक मौसम विज्ञान उपमहानिदेशक (जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी), पुणे	सभी 1 से 4
(4) अधीक्षक, मौसम विज्ञान उपमहानिदेशक (उपकरण उत्पादन) का कार्यालय, नई दिल्ली	मौसम विज्ञान महा-निदेशक	मौसम विज्ञान महानिदेशक मौसम विज्ञान उपमहानिदेशक (उपकरण उत्पादन)	सभी 1 से 4

[सं. बी-00101 भाग 2/ग]

एम. के. दास, मौसम विज्ञान महानिदेशक

S.O. 4640.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9 and clause (2) of sub-rule (2) of rule 12 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and in superession of the notification of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation No. S.O. 1954 dated the 14th June, 1973, the President hereby directs that in respect of the posts in the Indian Meteorological Service, Group 'B', specified in column 1 of the schedule to this order, the authority specified in column 2 shall be the Appointing Authority and the authority specified in column 3 shall be the Disciplinary Authority in regard to the penalties specified in column 4.

SCHEDULE

Description of the post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in rule 11).	
		Authority	Penalties
1	2	3	4
INDIAN METEOROLOGICAL DEPARTMENT Indian Meteorological Service Group 'B' GAZETTED			
Assistant Meteorologist or Assistant Agricultural Meteorologist or Assistant Seismologist.	Director General of Meteorology	Director General of Meteorology	All
NON-GAZETTED			

1	2	3	4
(1) Professional Assistant [Including Professional Assistant (Foreman) and Stenographer Grade-II	Director General of Meteorology	Director General of Meteorology	All
		Deputy Director General of Meteorology (Climatology and Geophysics) for the posts borne in the establishment of Additional Director General of Meteorology (Research) Pune, Deputy Director General of Meteorology (Administration & Stores) for the posts borne in the establishment of Director General of Meteorology, Central Seismological Observatory Shillong and Positional Astronomy Centre, Calcutta, Deputy Directors General of Meteorology, (Instrument Production) (Wheather Forecasting) and Instrument Inspection Servicing), Regional Directors, Director Agricultural Meteorology for posts borne in their respective establishment.	(i) to (iv)
(2) Superintendent, Headquarters Office of Director General of Meteorology, New Delhi.	Director General of Meteorology.	Director General of Meteorology	All
		Dy. Director General of Meteorology (Admn. and Stores).	(i) to (iv)
(3) Superintendent, Office of the Additional Director General of Meteorology (Research) Pune.	Director General of Meteorology	Director General of Meteorology	All
		Dy. Director General of Meteorology Climatology and Geophysics, Pune).	(i) to (iv)
(4) Superintendent, Office of the Deputy Director General of Meteorology (Instrument Production) New Delhi.	Director General of Meteorology.	Director General of Meteorology	All
		Dy. Director General of Meteorology (Instrument Production).	(i) to (iv)

[No. V—00101 Part II(A)]
S. K. DAS, Director General of Meteorology

कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1985

का. आ. 4641:—हल्दी श्रेणीकरण और और चिह्नांकन नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिये, हल्दी श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 1983 के प्रारुप नियम, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ. 10-2/82-ए. एम., तारीख 27 जून, 1983 के साथ का. आ. 2965 के रुप में, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 23 जुलाई, 1983 के पृष्ठ 3041 पर प्रकाशित किये गये थे। इसके द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे,

नियमों के उक्त प्रारुप को, उन सभी व्यक्तियों की जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना, है, जानकारी के लिए कतिपय उपांतरणों सहित पुनः प्रकाशित किया जाना वांछनीय समझा गया है।

अतः अब हल्दी श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम 1985 का निम्नलिखित प्रारुप जिसे केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हल्दी श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम 1964 का और संशोधन करने के लिए बनाना चाहती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती है; पैंतालीस दिन की समाप्ति पर या इसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर जो, ऊपर ऐसे विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारुप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हल्दी श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 1985 है।

2. हल्दी श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1964 में, अनुसूची 4 और अनुसूची 4-क के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचित रखी जाएगी, अर्थात

अनुसूची IV

(नियम 3 और 4 देखें)

विभिन्न किस्म के हल्दी चूर्ण का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	विशेष लक्षण							साधारण लक्षण
	आर्द्रता प्रतिशत भार के आधार पर अधिकतम	भस्म का कुल प्रतिशत भार के अनुसार (अधिकतम)	अम्ल अविलेय भस्म का प्रतिशत भार के अनुसार (अधिकतम)	सीसा (पी. बी. के अनुसार) भाग प्रति दस लाख (अधिकतम)	स्टार्च प्रतिशत भार के अनुसार (अधिकतम)	टुकड़े का आकार*	क्रोमेट परीक्षण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मानक	10.0	7.0	1.5	2.5	60.0	सभी चूर्ण 300 माइक्रोन वाली छलनी से निकाले जाएंगे।	नकारात्मक	1. हल्दी चूर्ण साफ सूखी हल्दी (करकुमा लोंगा एल.) (हिन्दी हरिदा) प्रकंद को पीसकर निर्मित किया जाएगा।
साधारण	10.0	8.0	1.5	2.5	60.0	सभी चूर्ण 500 माइक्रोन वाली छलनी से निकाले जाएंगे।	नकारात्मक	2. इसका अपना लाक्षणिक स्वाद, सुगंध होगी और वह फफूंदी गंध से रहित होगी 3. यह धूल, फफूंदी उत्पत्ति और कीट; अंतर्ग्रसन से रहित होगी। 4. यह किसी प्रकार के रंजक पदार्थ जैसे सीसा क्रोमेट परिरक्षकों और विजातीय पदार्थों जैसे अनाज या दालों के आटे या किसी अतिरिक्त स्टार्च से रहित होगी।

X निर्यात के लिए आशयित परेषणों के लिए वृहदाकार टुकड़ों के लिए भार के अनुसार 5 प्रतिशत सहायता अनुज्ञात होगी।

[सं. 10-4/85-एम. I]

बी. के. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : 1. मूल नियम भारत के राजपत्र तारीख 2-5-64 में का. आ. 1463 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

2. पहला संशोधन भारत के राजपत्र, तारीख 8-1-1966 में का. आ. 123 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

3. दूसरा संशोधन भारत के राजपत्र, तारीख 8-1-66 में का. आ. 3189 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

4. तीसरा संशोधन भारत के राजपत्र तारीख 6-1-1968 में का. आ. 35 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 10th September, 1985

S.O. 4641.—Whereas the draft rules of the Turmeric Grading and Marking (Amendment) Rules, 1983 further to amend the Turmeric Grading and Marking Rules, 1964 were published as S.O. 2965 at page 3041 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 23rd July, 1983 with the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development No. F. 10-2|82-AM dated the 27th June, 1983 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected;

And whereas, it is considered desirable to publish the said draft rules again with certain modifications for the information of all persons likely to be affected thereby;

Now, therefore, the following draft rules of the Turmeric Grading and Marking (Amendment) Rules, 1985, which the Central Government proposes to make in exercise of powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) further to amend the Turmeric Grading and Marking Rules, 1964, are hereby published as required by the said section for information of all

persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period so specified above will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Turmeric Grading and Marking (Amendment) Rules, 1985.
2. In the Turmeric Grading and Marking Rules, 1984 for Schedule IV and Schedule IV-A. the following Schedule shall be substitued, namely :—

"SCHEDULE IV"

(*See* rules 3 and 4)

Grade designations and definitions of quality of different types of Turmeric Powder

Grade designation	Special characteristics							General Characteristics
	Moisture percentage by weight (Max.)	Total ash percentage by weight (Max.)	Acid insoluable ash percentage by weight (Max.)	Lead (as Pb) parts per million (Max.)	Starch percentage by weight (Max.)	Particle size @	Chromate test	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Standard	10.0	7.0	1.5	2.5	60.0	all of the powder shall pass through 300 micron sieve.	negative	1. The turmeric powder shall be prepared by grinding clean, dry turmeric (Curouma longa L.) rhizomes
General	10.0	8.0	1.5	2.5	60.0	all of the powder shall pass through 500 micron sieve	negative	2. It shall have its characteristic taste, flavour and be free from musty odour 3. It shall be free from dirt, mould growth and insect infestation. 4. It shall be free from any colouring matter such as lead chromate, preservatives and extraneous matter such as cereal or pulse flour or any added starch.

@ A tolerance upto 5 per cent by weight for oversized particles shall be allowed for the consignments meant for export.

[No. 10—4/85—M I]

B. K. BAJAJ, Under Secy.

Note : (1) Principal rules published vide S.O. 1463 of the Gazette of India dated 2-5-1964.
(2) 1st Amendment published vide S. O. 123 of the Gazette of India dated 8-1-1966
(3) 2nd Amendment published vide S. O. 3189 of the Gazette of India dated 29-10-1966
(4) 3rd Amendment published vide S. O. 35 of the Gazette of India dated 6-1-1968.

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1985

का. आ. 4642.—बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (1984 का 51) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के मुख्य निदेशक (सहकारिता) श्री के. सुन्दरराजुलु को आगामी आदेशों तक सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीकार के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. एल. 11012/1/85– एल. एंड एम.]

ए. आर. सुब्बैया, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

(Department of Agriculture & Cooperation)

New Delhi, the 16th September, 1985

S.O. 4642.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Multi State Co-operative Societies Act, 1984 (51 of 1984), the Central Government hereby appoints Shri K. Sundarajulu, Chief Director (Co-operation) in the Ministry of Agriculture and Rural Development (Department of Agriculture and Cooperation) as the Central Registrar of Co-operative Societies, until further orders.

[No. L-11012|1|85-L&M]
A. R. SUBBIAH, Under Secy.

(युवा कार्य और खेल विभाग)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1985

का. आ. 4643—समय-समय पर संशोधित के अनुसार 25 मार्च, 1982 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग—II, खंड 3, उपखंड 3(ii) में प्रकाशित शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय की अधिसूचना एस. ओ. संख्या 166 (ई) दिनांक 22 मार्च, 1982 के क्रम में, केन्द्रीय सरकार, धमार्थ अक्षयनिधि अधिनियम 1890 की धारा 4 (1) के अंतर्गत, प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, और खिलाड़ियों के लिए प्रशासन के प्रयोजनार्थ सामान्य समिति की सहमति से, एतद्द्वारा आदेश देती है कि 15 लाख रुपए (केवल पन्द्रह लाख रुपये) की राशि, भारत के धमार्थ अक्षयनिधि के कोषाध्यक्ष और न्यास के पद पर उनके उत्तराधिकारी को, उक्त राशि और उनसे होने वाली आय को, डाकघर की समय जमा योजना में 5 वर्ष की अवधि के लिए जमा करने हेतु सौंपी जायेगी।

[सं. एफ 13-1/81 डी.-1 (एस. पी.)]
आर. एन. गुप्ता, उप सचिव (खेल)

DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi, the 22nd August, 1985

S.O. 4643.—In continuation of the Ministry of Education and Culture Notification S.O. No. 166(E) dated 22nd March, 1982 published in the Gazette of India (extraordinary) Part II Section 3 Sub-Section 3(ii) dated 25th March, 1982, as modified from time to time, the Central Government in exercise of the powers conferred under section 4(1) of the Charitable Endowments Act 1890 and with the concurrence of the General Committee for the purpose of Management and Administration of the National Welfare Fund for Sportsmen do hereby order that an amount of Rs. 15 lakhs (Rupees Fifteen lakhs only) be vested in the Treasurer of Charitable Endowments for India to be held by him and his successors in office upon trust to hold the said monies and the income thereof for a period of five years for deposit in the Post Office Time Deposit scheme.

[No. F. 13-1|81 DI(Sp)]
R. N. GUPTA, Dy. Secy. (Sports)

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(हिन्दी अनुभाग)

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1985

का. आ. 4644:—राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में भारत सरकार (नौवहन और परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली को एक ऐसे कार्यालय के रूप में अधिसूचित करती है, जहां 80 प्रतिशत कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

[सं. एच पी यू/ 147/85]
योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Hindi Section)

New Delhi, the 9th September, 1985

S.O. 4644.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official language (use for the Official purposes of the Union) Rules, 1976 the Govt. of India hereby notifies the Delhi Transport Corporation, New Delhi (under the administrative Control of the Ministry of Shipping and Transport) as an Office where 80 per cent of staff have acquired working knowledge in Hindi.

[No. HPU|147|85]
YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1985

का. आ. 4645—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकारी, नागार्जुन ग्रामीण बैंक, के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-9-85 को प्राप्त हुआ था।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 12th September, 1985

S.O. 4645.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th September, 1985.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (C) AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 26 of 1982

BETWEEN

The workman of Nagarjuna Grameena Bank, Khammam.

AND

The Management of Nagarjuna Grameena Bank, Khammam. ......

APPERANCES:

Sri C Venkata Krishuna, Advocate and Sri M. Ravinder, Reddy, President, Nagarjuna Grameena Bank Officers' Association for Nagarjuna Garmeena Bank Officers' Union and Sri K. Venkata Reddy, Advocate for the Nagarjuna Grameena Bank Employees Union for the Workmen.

Sarvasri K. Srinivasa Murthy and K. Satyananrayana Rao Advocates for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-12011/8/81-D. II (A) dated June, 1982 referred the following dispute under Section 7A and 10 (1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the Management of Nagarjuna Grameena Bank, Khammam, Andhra Pradesh and their workmen to this Tribunal for adjudication.

"Whether the demand of the workmen of Nagarjuna Grameena Bank, Khammam (A.P.) for payment of Bonus at a rate higher than 8.33 per cent is justified ? If so, at what rate should the Bonus be paid for accounting year 1979?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 26 of 1982 and notices were issued to both the parties.

2. In the Claims Statement filed by the workmen, it is mentioned that Nagarjuna Grameena Bank after all deductions during the year 1979 had surplus amount to the tune of Rs. 21,39,564.82 and he made a representation to the Board of Directors for payment of 20 per cent bonus for the accounting year 1979 and that they assuerd 20 per cent bonus and that the said bonus would be paid soon. It is further mentioned that to their dismay that Chairman has announced bonus of 8.33 per cent for the accounting year 1979 vide Circular No. 201 dt. 9-12-1980 stating that he was directed to do so by the Central Government. It is mentioned that under the provisions of Reserve Bank Act the Board of Directors are vested with General Superintendent to give directions and to manage the affairs of the Bank and that what they decided is final. According to them under Section 22 of the R.R.B. Act, this Bank is treated as Cooperative Society for purpose of Income Tax and therefore it is exempted from the payment of Income Tax under Section 80P of Income Tax Act 1961 and the deduction of Rs. 13 lakhs towards the National Income on the profits earned is available for purpose of granting bonus. According to them the Labour Enforcement Officer, Kothagudem instructed the Management of the Bank Books to pay 20 per cent bonus within 15 days but the Management failed to comply with the direction so far. It is further maintained that as per Section 17 (1) of B.R. Act 1949 only 20 per cent of the profit shall be transferred to the Statutory Reserves, while the Management deducted 25 per cent to arrive at the surplus for payment of Bonus which is irregular. It is also mentioned that keeping the provisions for dividend at 7.5 per cent at share capital of Rs. 25 lakhs is incorrect, and thus as per the calculation shown in the Claims Statement they are entitled for 20 percent bonus for the year 1979 and the same should be ordered under the Bonus Act.

3. In the counter filed by the Management, it is denied that after permissible deduction to the surplus available with the Grameena Bank is Rs. 18,14,976.22 for the year 1979. It is asserted that the allocable surplus available undert the payment of Bonus Act is only Rs. 1,33,775.00. It is also mentioned that under Section 24 of the Reginoal Rural Bank Act any directions given by the Central Bank to the Respondent Bank are final. The Respondent also filed the work statement to show how the allocable surplus is arrived at. The Respondent denied all other allegations mentioned and it is also denied that only 20 per cent of the profit shall be transferred to the Statutory Reserve. It is maintained by the Respondent that as per Section 4 (a) read with second Schedule for Payment of Bonus Act the Respondent Bank is entitled to deduct 7.5 per cent under share capital towards the dividends for arriving at the allocable surplus and finally it is mentioned that on the available surplus the payment for bonus at 8.33 per cent were worked out payable to be claimants and therefore any excess bonus claimed by them is not maintainable.

4. On behalf of the Nagarjuna Grameena Bank Officers Union and the Nagarjuna Grameena Bank Employees Union no witnesses have been examined even after taking sufficient time. The Management on the other hand examined one witness P. Ravi Kumar who was Assistant District Manager, Nalgonda who worked as Head of the Department, Khammam in the year 1979. In the said Nagarjuna Garmeena Bank he filed Ex. M1 as the balance sheet for the year 1979 and mentioned that the accounts were audited. Further he filed the photo state copy of the instructions under Ex. M2 received by them from the Government of India instructing them not to declare dividend for the year 1979. He deposed that Government of India and State Bank of India, State Government are share holders of these Banks and Nagarjuna Grameena Bank is also governed by Banking Regulations Act 1949. He marked Ex. M3 instructions issued by the Government of India for deducting income tax by them and they have deducted the same as per the Bonus Act while Preparing the balance sheet. He marked Ex. M4 as the instructions received by the State Bank of India regarding payment of bonus and further marked that they received instructions from the State Bank of India on 24-1-1981 with regard to Section 17 of the Banking Regulations Act and marked it as Ex. M5. According to him the statement prepared by them following these instructions indicated the available allocable surplus as shown therein under Ex. M6. According to him various deductions were made before arriving at the allocable surplus for declaring bonus. He mentioned that 25 per cent of the net profits were deducted as per the Banking Regulations Act and 7.5 per cent of dividend on share capital and 5 per cent reserve at the beginning of the year and they also deducted income tax notionally and depreciation reserve. He relied upon Ex. M7 instructions for notional income tax deductions and Ex. M8 letter informnig them that bonus should be declared at 8.33 per cent. He declared that the Bank has no sufficient allocable surplus to give 20 per cent bonus has claimed by Union. He maintained that Rs. 1,33,000 was the surplus available as per the statement prepared by them under the instructions of the authorities as marked above and this is not sufficient to declare even 8.33 per cent bonus but the Minimum Bonus Act makes it mandatory to declare bonus at 8.33 per cent and the same therefore declared. He admitted in the cross-examination under Ex. W1 as the copy of the letter dt. 20-10-1978 issued by the Ministry of Finance to all Regional Rural Banks Showing that they are deemed as Cooperative Society for the purpose of Income Tax. The witness denied the suggestion that for the purpose of Bonus Act there should be no deduction of Income Tax and he maintained that Bonus cannot be given at 20 per cent even if they are treated as cooperative society for the purpose of Income Tax.

5. The admitted facts are that Government of India enacted a legislation entitled the Regional Rural Banks Act 1976 (21 of 1976), and that the said Act came into force on 25th September, 1975. In the preamble of the Act it is mentioned that an Act to provide for "the incorporation, regulation and winding up of Regional Rural Banks with a view to developing the rural economy by providing, for the purpose of development of agriculture, trade, commerce, industry and other productive activities in the rural areas, credit and other facilities, particularly to the small and marginal farmers, agricultural labourers, artisans and small entrepreneure, and for matters connected therwith and incidental therto." The Regional Rural Banks in short are R.R. Bs established by Central Government when requested to do so by a sponsored Bank shall by a Nationalised Bank with the specification of jurisdiction of operation. The State Government where the R.R.B. established will have the power to exercise to a limited extent in the functioning of the Banks by having a representative on the Board of Directors.

6. In the instant case the Nagarjuna Grameena Bank is sponsoered as a Regional Rural Bank by notification of the Central Government with the cooperation of the Nationalised Bank namely State Bank of India with certain jursidiction to function in the areas specified and the Government of Andhra Pradesh is also having its Directors on the said Bank to see that the provisions of the R.R.Bs. are properly imulemented and regulated. Under Section 22 of the R.R.Bs. Act the nstitutions are classified as cooperative society as follows:

> "For the purpose of the Income Tax Act 1961 or any other enactment for the time being in force relating to any tax on income, profits or fains a Regional Rural Bank shall be deemed to be a Co- operative Society."

Under Section 23 of the said Act it is mentioned as follows:

> "Notwithstanding anything contained in the Interest Tax Act, 1974, no Regional Rural Bank shall be liable to pay tax under that Act."

7. The Counsel for the workman a written argument contending that on the basis of Sections 22 and 23 that the R.R.B. is defined as Co-operative society and as they are governed by Service Staff Regulations 1980 under Regulation 39 and that the employees and workers are entitled for bonus. According to him the authorities of the R.R.B. are not required to pay any income tax and as such any deduction on the national value of payable tax is not warranted. He mentioned that all deductions while calculating and arriving at allocable surplus have to be done only under the provisions of the law guided by Banking Regulations Act of 1949 or the Income Tax of 1961 and therefore when the R.R.B. are treated as cooperative society and when Section 80 p of the Income Tax Act exempts the cooperative Societies from payment of income tax the same rational has to be applied to R.R.Bs. which are in the nature of cooperative society serving the needs of the rural agricultural people by giving exemptions from the payment of Income Tax. So it

is vehemently contended that the Bank is not entitled to calculate notional tax payable under the income Tax Act as such any deductions made towards the same is illegal. Incidentally to support their case the worker counsel relied upon the decision reported in ORIENTA METAL PRESSING WORKS (P) LTD. vs. WORKMEN AND ANOTHER (S.C. Labour Judgements 1950-83 Volume II revised edition at page 129) wherein it was held any employer claiming deduction for Income Tax under Section 23-A of the Income Tax Act must show thaton actual facts that Income Tax levied. It is pointed out that Income Tax on the basis of Section 23-A cannot be allowed even notionally, for Income Tax under the Section may and may not be leviable at all.

8. In the instant case it is not the case of the Management that there was any loss sustained by the Bank for the previous year. The Bank did not show any loss in the previous year.

9. On the other hand the Management's counsel contended in their written arguments which they filed Balance Sheet Ex. M6 to show the available surplus is only Rs. 2,22,954.71 and as per Section 2 (4) of payment of Bonus Act 1965 the allocable surplus (60 per cent of the available surplus) will come to Rs. 1,32,775.00 only. Regarding the point argued by the Workers Counsel that no Income Tax deductions is peprmissible, it is contended that Income Tax is sought to be deducted by virtue of Section 6 (b) of the Payment of Bonus Act and that it is not necessary that the Income Tax should actually be paid or become payable. It is argued that Section 6 (b) does not warrant such an interpretation. It is asserted that even if it is ultimately not found payable, the Management can claim the amount as deduction for the purpose of work sheet and relied upon the decision reported in METAL BOX CO. OF INDIA vs. THEIR WORKMEN 1969 (I) LLJ, page 785) The Division Bench of the Supreme Court held in the said judgement that Section 6 of the Bonus Act Provides that having arrived at the gross profit under Section 4 read with Schedule 2 the Company is entitled to deduct therefrom depreciation admissible under Section 32 (1) of the Income Tax Act, i.e. such precentage on the written-down value as may in the case of each of the classes of assets be prescribed. Further the Suppreme Court laid down that a mere production of the auditors' certificate in this respect would not amount to proof of the correctness of the amount so claimed, and it is laid down that it should, however insist on some reasonable proof of the correctness of the ✓snutes of depreciation claimed by the emplover either by examining the auditor who calculated and certified it or by some other persons and it is mentioned that fairness therefore requires that an opportunity must be given to the employees to verify such figures by cross examination of the employer or the witness who have calculated depreciation amount. In the instant case the auditor who filed this Ex. M1 Annual Report are not examined by the management. The mere production of the Auditors certificate under Ex. M1 without proof of correctness of the same amount claimed will not give a presumption of accurancy about the profit and loss account of the Company. Moreover as laid down by the Supreme Court presided by three Judges in Oriental Metal Pressing (P) Ltd., vs. Workman for the purpose of Income Tax under Section 23-A unless it is shown that the actual facts such Income Tax was levied on the management for the year in dispute, it cannot be allowed even notionally to deduct. Therefore it is not correct to say that the judgement relied upon the Management will come in the way of following the judgement relied upon by the Workers Counsel.

10. The Management then relied upon the decision reported in WORKMEN OF WILLIAM JACKS vs. MANAGEMENT OF WILLIAM JACKS (1971 (I) LLJ, page 503). It is laid down in the said judgement that the rule in 1969 (I) LLJ Page 785 is not altered by the amendment act 8 of 1969 with reference to the formula of working out the bonus or calculating the income tax deductable. It was a case where a foreign company charging interest for an advance made by the Head Office in London to the Branch Office in Madras in the profit and loss account which was not objected by the Auditors of the Company is held that the said amount of interest could not be debited as an expenditure for the purpose of calculation of available surplus under the provisions of the Payment of Bonus Act. Thus such facts are not here in the present case. There is nothing like debiting interest made bythe Head Office to the Branch Office towards the profit and loss account. The Judgement only reiterated the position settled is not altered as mentioned in 1969 (I) LLJ Page 785. Therefore it was no application to the present facts.

11. The Management relied upon the decision reported in DELHI CLOTH & GENERAL MILLS CO. LTD. Vs. WORKMEN (1971 (II) LLJ, Page 539). In that case the Delhi Cloth Mills and Swatantra Bharat Mills were the two units run by a public limited Company. A dispute arose regarding the quantum of direct tax deductible under Section 6 (c) of the Act and the rate of bonus payable to each employee. In that context it was held that the notional liability of a venture of which gross profits are known and the prior charges by way of depreciation rebate and developed allowances commuted should be taken into consideration. In that case it was held that the Tribunal went wrong in assessing the liability on the basis of workers memo, Awarded bonus at 7.31 per cent of their annual wage bill. The contention of the Management that Section 6 (c) does not warrant that Income Tax should actually to be paid or become payable is not laid down as a proposition in this case. On the other hand the citation relied upon by the workers counsel clearly laid down that unless the Income Tax is shown to be payable as a matter of fact and that it was livied for the year in dispute, no deduction can be allowed even notionally for income tax as the same may or may not levy at all so it had no application.

12. The Management relied upon the decision reported in INDIAN OXYGEN LTD. Vs. THEIR WORKMEN (1972 (1) LLJ Page 627) and contended that the Management was entitled to deduct notionally the income tax even without actually paying or the same becoming payable. The said judgement merely showed that the employer is entitled to compute its tax liability without deducting the first amount of bonus he would be liable to pay from and out of the amount computed under Sections 4 and 6. Incidentally it is mentioned that the return on reserve at 6 per cent and payment of divident for the year ending; deduction for the reserve shown thereon were correct and in that case actually award was modified so far claimed for direct tax is concerned. Even in this case in the statement of account, the statement that they have deducted notionally Rs. 13.11.140.00 under Section 6 (b) of the payment of Bonus Act for the purpose of Income Tax is liable to be struck down as not maintainable. The workers are challenging deduction of Rs. 13,11,140.00 towards the notional income tax. In other words the judgement in 1972 (1) LLJ, Page 627 is not applicable to the present facts and the workers judgement relied upon would aptly show that notional deduction under Section 6(b) of the Payment of Bonus Act 1965 for the purpose of income tax to an extent of Rs. 13.11,140.00 is not according to Law. Moreover under Section 22 of the Act it is clearly specified that R.R. Bs are functioning as cooperative society and when Sections 22 and 23 read together with, it is clearly laid down that notwithstanding anything contained in the interest Act 1974 also no. R.R.B. is liable for any tax under that act and when the Section 22 of the Act also specified that it is only a cooperative society there cannot be any income tax on a cooperative society for the profits or gains. Thus looking from any angle it is clear that apart from Rs. 1,33,775.00 shown as available allocable surplus there is an amount of Rs. 13.11,140.00 and granting of Bonus on the basis of the instructions that in case the allocable surplus exceeds the amount of minimum bonus of 8.33 per cent they are bound to pay to every employee in proportionate to the salary or wages earned by the employees during the accounting year subject to the maximum of 20 per cent of such salary or wages as mentioned in Ex. M3 should have been followed instead of limiting it to 8.33 per cent as is done in the instant case. At any rate it is quite clear if the item of Rs. 13,11,140.00 deducted on the notional income tax payable is to be added to calculation of allocable surplus for determining the bonus payable to the employee, Then it becomes much more than what is shown under Ex. M6 and it cannot be as mentioned in Ex. M8 or Ex. M7.

13. In fact Ex. W1 which is admitted by M.W.1 would show that under Section 22 of the R.R.B. Act 1976 the Regional, Rural Bank is treated as specifically cooperative Society and the provision of Section 80P of the Income Tax Act 1961 are not applicable to the Regional Rural Bank and thus the Income earned by the cooperative society in carrying on business of banking providing credit facilities to its employees, is not deductable in computing its taxable income.

Thus it is established that none of the documents replied on by the Management will show that they are quite right in fixing the bonus at 8.33 per cent. On the other hand it is clearly established by the workers that the employees shall under Section 10 of the R.R.B. Act are entilted to receive in respect of the accounting year bonus which shall be an amount in proportionate to the salary or wages earned by the employees during the accounting year subject to a maximum of 20 per cent or such salary or wage. I therefore hold that the Management is not justified in fixing the rate of bonus at 8.33 per cent in the given circumstances and the workmen and staff are entitled for higher rate of bonus for the year 1979 limiting it upto 20 per cent and the same should be calculated proportionately in accordinace with the Payment of Bonus Act 1965 in proportion to the salaries or wages earned by employees during the said accounting year, he said percentage which must be evidently beyond 8.33 fixed by the Management when the total amount comes to Rs. 14,44,915.00 or even more if worked out carefully.

14. With reference to the Statutory Reserves under Section 17(1) of the Banking Regulations Act 1949 only 20 per cent of the profit shall be transferred to the Statutory Reserve. It is alleged now that 25 per cent of the profits are calculated and deducted to arrive at the available surplus for payment of bonus. In other words they tried to get 5 per cent in excess of the Statutory Reserves as required under Section 17(1) of the Banking Regulations Act 1949. This also must be corrected properly and the excess of 5 per cent transferred to statutory reserves is also available as profits for the purpose of calculating Bonus payable to staff and workers.

15. The arguments of the Workers counsel that 7.5 per cent paid on the share capital of .25 lakhs should not have been done is not tenable. There are number of share holders other than Government of India namely, the Nationalised Bank i.e. State Bank of India as well as State Government of Andhra Pradesh who are share holders. Therefore it is not correct to say that there should be no provision for dividend of 7.5 per cent on the share capital of Rs. 25 lakhs as per third schedule. Thus the computation must be done on the available allocable surplus which should be arrived at after excluding the notional income tax shown at item 5 of Ex. M6 and also after making the statutory reserves limited at 20 per cent of the profits under Item 8 of Annexure I and arrive at allocable surplus and it must naturally be beyond what is shown in the Ex. M6 for the purpose of granting Bonus under Section 2(4) of the Payment of Bonus Act. The payable bonus is thus to be worked out proportionately with reference to their salaries and wages as there are sufficient allocable surplus funds for payment of bonus at 20 per cent as claimed by them for the accounting year 1979 and hence the same should be calculated and the Bonus should be paid at 20 per cent for the accounting year 1979 to all the staff and workers by the Management.

Award is accordingly passed.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 14th day of August, 1985.

Industrial Tribunal

Sd./-

Illegible

Appendix of Evidence

Witnesses examined on behalf of the Nagarjuna Grameena Bank Officers Union.	Witness examined on behalf of the Nagarjuna Grameena Bank Employees' Union.
NIL	NIL

Witness examined for the Management

M.W. 1 P. Ravi Kumar.

Documents marked for Nagarjuna Grameena Bank Officers' Union

NIL

Documents marked for Nagarjuna Grameena Bank Employees' Union

Ex. W1—Letter No. F. 2-22/77-RRB dt. 20-10-78 addressed by the Deputy Secretary to Government of India, New Delhi to the Chairman, All Regional Rural Banks with regard to payment of Income ax Documents marked for the Management

Ex. M1—Fourth annual report of Nagarjuna Grameena Bank.

Ex. M2—Photo stat copy of the letter No. F. 2-3/80-RRB dt. 1-3-80 addressed by Director, Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi to the Chairman, All Regional Rural Banks, with regard to apporpriation of net profits in Regional Rural Banks and declaration of Dividends.

Ex. M3—Photo stat copy of the letter No. F. 2-50/80-RRB dt. 22-7-81 from the Director, Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic of Affairs (Banking Division) New Delhi), with regard to payment of Bonus to the Employees of Regional Rural Banks.

Ex. M4—Photo Stat copy of the letter dt. 9-1-81 addressed by the Additional Chief Officer (Regional Rural Banks) State Bank of India, to Agricultural Banking, Regional Rural Banks, with regard to payment of Bonus Act, 1965.

Ex. M5—Photo stat copy of the letter No. ABD-RRB. 0311 dt. 24-1-81 addressed by Additional Chief Officer (Regional Rural Banks) State Bank of India to Agricultural Banking, Regional Rural Banks with regard to Reserve Fund.

Ex. M6—Statement showing available/applicable surplus with regard to payment of Bonus.

Ex.M7—Photo stat Copy of the letter No. F.2/50/80-RRB dt. 1-4-81 addressed by Deputy Secretary to Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) to the Chairman, Nagarjuna Grameena Bank, Station Road, Khammam (AP) with regard to payment of Bonus for the accounting year ended 31-12-1979.

Ex. M8—Photo stat copy of the D.O. No. F.2-10/79-RRB dt. 5-12-80 addressed by S.L. DUTT, Deputy Secretary, Ministry of Finance, New Delhi to the Chairman, Nagarjuna Grameena Bank, Station Road, Khammam, with regard to payment of Bonus for the year 1979.

J. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal

[No. L-12011/8/81-D. II(A)]

का. आ. 4646.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकारी, बैंक आफ महाराष्ट्रा के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29-8-85 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 4646.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Maharashtra and their workmen, which was received by the Central Government on the 29th August, 1985.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL. NEW DELHI

I.D.No. 9/84.

In the matter of dispute between Shri Baldev Singh represented by Deputy General Secretary, Union of Maharashtra Bank Employees.

Versus

Bank of Maharashtra, New Delhi.

APPEARANCES :

Shri Ramesh Kadam, Dy. General Secretary—for the workman.

Shri S. V. Kulkarni—for the Management.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour on 14th January, 1984 vide order No. L-12012(197)|83-D.II.(A) made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Management of Bank of Maharashtra, New Delhi, in relation to their Divisional Office, Delhi in denying posting as Special Assistant to Shri Baldev Singh, Clerk with effect from 1-4-82 is justified? If not, to what relief it the workman concerned entitled ?"

2. Mr. Baldev Singh, a Clerk in the Divisional Office, Delhi, was not appointed Special Assistant by the Bank of Maharashtra and the workman's Union asserts that he was entitled to the Special Assistant's post which carried allowance of Rs. 283 p.m. for discharging higher type of duties. It is asserted that such posts are filled on service seniority basis as per rules of Bank of Maharashtra and the Management declared such posts through a circular and list of eligible hands before posting them as Special Assistants.

3. Reliance is placed on memorandum of settlement between the employees and the Management dated 8-7-78 especially paras 4 and 5 which are as under :

"4. ELIGIBILITY :

(a) An employee having completed five years of service of securing minimum seven marks will be eligible to be selected as Special Assistant.

(b) In case of staff member who is eligible in not found suitable by the management for considering him for the post of Special Assistant, the management shall inform the concerned candidate in writing, stating the reason therefor and if such staff member feels agrieved, he shall represent his case to the management through his Union representatives. Refusal to accept rotation of jobs or change of tables by the staff members would weigh adversely against them at the time of consideration for postings as Special Assistant.

5. METHOD OF SELECTION : The post Special Assistants shall be filled in, in accordance with aggregate marks obtained by the individual eligible candidate under the heads of service and qualification.

MARKS : (1) For each completed year of service, the eligible candidate will get one mark.

(2) For the educational qualification, additional marks will be allotted as under :—

(a) Graduates	2 Marks
(b) C.A.I.I.B. (Part II)	1 Marks
(c) C.A.I.I.B. (Part II)	2 Marks

In case there is a tie i.e. candidates securing equal marks under the above clause, final selection shall be made in terms of following provisions :—

(a) Candidate who has joined bank's service earlier as probationer amongst the candidates securing equal marks shall be posted as Special Assistant.

(b) If the date of joining the Bank's service as probationer amongst the candidates scoring equal marks the selection shall be made on the basis of alphabatical order, surname being taken first.

(c) If the date of joining the bank's service as probationer and the surname of candidates scoring equal marks are same, the selection will be made on the basis of alphabatical order of first name."

3. The posts of special assistants were declared in the year 1982. Baldev Singh requested that his name was not included in the list of employees, eligible for posting while he was eligible for the same. The Management replied that he was not found suitable for posting since he had been given punishments through Departmental Enquiry for stoppage of two increments falling due in future with cummulative effect and that he had been given warning that the errors of ommission and commission in his working from 30-12-75 should be scrupulously avoided for all times to come and that he had not been paid anything over and above the subsistence allowance paid to him during suspension period from 7-1-76 till 1-9-79.

4 The workman's case is that the punishments aforesaid did not in any way debar him from future posting against any allowance carrying post in the same cadre and Baldev Singh requested the Management to reconsider their decision. It was asserted that Baldev Singh was absolved of the guilt by the Sessions Court and that the Departmental Enquiry conducted against him on the same facts awarded punishment mentioned by the Bank and that denying him the post of Special Assistant was another punishment for him for the same charge. The workman requested that Baldev Singh should be treated as Special Assistant w.e.f 1-4-82 and paid necessary allowance and any other reliefs.

5. The Management contested the claim and asserted that the post of Special Assistant was not filled on seniority basis alone and that suitability was criterion and that the settlement arrived at between the parties in the year 1978 and 1983 provided guideline. Seniority was taken into consideration but it was not the only factor.

The record of the workman was considered and he was not found suitable for promotion as Special Assistant.

6. The matter has been tried. The workman gave his own affidavit and has been cross-examined. He also examined Mrs. Usha Rani, Special Assistant, in his favour who was also punished by being having her four increments stopped with cummulative effect but still she was made Special Assistant vide order dated 4-8-80. The Management filed affidavit of Shri M. T. Mainkar, Officer in the Divisional Office, Bank of Maharashtra and he had been cross-examined by the workman. Written arguments of the parties are on record and have been perused. The Judgment of Shri K. B. Andley, Addl. Sessions Judge, Delhi in Crl. Appeal No. 113|78 Baldev Singh Vs. State decided on 26-3-79 has been filed on record and has been examined.

6. The post of Special Assistant is a different post from the which Mr. Baldev Singh holds. The criminal case in which a person is ultimately acquitted may have no bearing on the post that he holds or even in respect of payment of full pay and allowances for the period of his suspension during the pandency of the criminal case, but it cannot be said that the Management cannot take into account the punishment given to him or the period of his suspension and non-actual functioning for the purpose of the higher post.

7. In this particular case Mr. Baldev Singh not only did not actually function during the period 7-1-76 to 1-9-79 his two increments were stopped with cummulative effect which were due in 1982 and 1983 and the Management could keep these facts in view for denying him the post of Special Assistant for a certain period and the workman has been ignored for the post of Special Assistant only for a certain period and not wholly.

8. It cannot be said that the Management of Bank of Maharashtra could not have denied him the Special Assistant's post when Baldev Singh have been prosecuted, convicted in lower court and acquitted by the Add. Sessions Judge and remained under suspension for a period of more the 3-1|2 years and when he had been given punishment of stoppage of two increments falling due in 1982-83 with cummulative effect, It cannot be accepted that Special Assistant post must go by seniority alone and that suitability and service record is no criterion in the matter.

9. As regard the case of Mrs. Usha Rani, she was removed from service but in appeal the punishment was reduced. There was no police case against her and it is in this situation that she was promoted as Special Assistant in 1980.

10. No two cases are alike and it is not possible to corrolate cases and then decide about discrimination. The fact of absence of a criminal case against Mrs. Usha Rani is distinctive of her case and it cannot be said that her case parallels the case of Baldev Singh. In any case my view is that the Management has a right to take into consideration the service record and conduct of a workman in the matter of grant of Special Assistant's post which carries allowance of Rs. 283 p.m. and mere seniority is not basis for automatic grant of Special Assistant. post. The action of the Bank of Maharashtra in this case does not appear to be otherwise than bonafide. The workman is not entitled to any relief.

Further it is ordered that the requiste number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

AUGUST 23,1985.

O. P. SINGLA, Presiding Officer
[No. L-12012/197/83-D.II(A)]
N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 सितंबर, 1985

का. आ. 4647 .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय, सरकार बैंक आफ बड़ौदा के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-9-85 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 16th September, 1985

S.O. 4647.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th September, 1985.

CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN, JAIPUR

Case No. C.I.T. 33/84.

REFERENCE :

Desk officer, Government of India, Ministry of Labour and Rehabilition, Department of Labour, New Delhi, Order No. L-12012/221/83-D. II (A). dated 6-2-84.

In the matter of an Industrial Dispute

BETWEEN

The General Secertay, Bank of Baroda Karmchari Union, C/o Baroda Bank, M.I. Road, Jaipur.

AND

The Regional Manager, Bank of Baroda, D-38, Ashok Marg, C-Scheme, Jaipur.

PRESENT :

Smt. Mohini Kapur, R.H.J.S.

For the Applicant—Shri Ashok Parihar.

For the Opposite Party—Shri R.C. Sharma.

Shri C.M. Mathur.

Date of Award : 30-4-85

AWARD

The Central Government has referred the following dispute for adjudication.

"Whether the action of the management of Bank of Baroda, Jaipur in relation to their Johari Bazar Branch, Jaipur in terminating the service of Shri Ram Singh, Peon, with effect from 24-6-76 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. The facts as stated in the statement of claim are that the workman Ram Singh was working as a Peon in the Johari Bazar, Jaipur Branch of the Bank of Baroda since 18-1-69. After the completion of his probation period his services were confirmed. As his services were terminated w.e.f. 24-6-76 it may be proper to look into the facts relating to this. The workman applied for leave from 12-5-76 to 18-5-76 on the ground of sickness. According to him he remained under the constant treatment of a doctor till 30-6-76. He himself was very weak and there was no other responsible person to attend on him and also to inform the Bank Authorities about his condition. The Bank's action in terminating the service of the workman on the ground of abandonment of service has been challenged. The termination order dated 24-6-76 read as under:—

1. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-एस.टी.एफ. 14 : 125 दिनांक 8-6-76 के संदर्भ में सूचित करते हुए अत्यन्त खेद है कि आपने अभी तक ड्युटी पर हाजिर नहीं हुए हैं। यह पत्र लिखने की तिथि तक हमें न तो कोई सूचना ही प्राप्त हुई है और न ही अवकाश की बढ़ोत्तरी के लिए आपका पत्र प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही आप द्वारा अनधिकृत रूप से लिए जा रहे अवकाश का स्पष्टीकरण ही प्राप्त हुआ है।

2. इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि हमने आपको स्वेच्छा से बिना किसी पूर्व सूचना के बैंक सेवाओं से मुक्त मान लिया है। यदि आपका कोई वेतन बकाया है तो निम्न हस्ताक्षरकर्ता से कार्यालय के समय में प्राप्त कर सकते हैं।

The workman reported himself on duty on 1-7-76 alongwith the Medical Fitness Certificate and made representations to the Agent and the Bank Authorities, but he was not taken on duty. The Agent recommended his case to the Regional Manager but the higher authorities did not look sympathetically towards the miseries of the workman. It is also pleaded that this was the period of emergency in the nation when all the authorities turned a deaf ear. It is submitted that there are no rules, regulations, or service conditions or tripartite settlement according to which his service could be terminated on the ground of self abandonment. It is pleaded that the service of person, absenting himself on medical ground cannot be terminated without giving him an opportunity to defend himself. The action is said to be highly unreasonable, and untenable, and unjustified, and said to stinking of high headed, adament attitude of the authorities. He was not given any notice or pay in lieu of notice or any compensation and on this ground the termination is said to be illegal. He has prayed for reinstatement with full back wages.

3. The opposite party in its reply has admitted the appointment of the workman as a peon and his application from 12-5-76 to 18-5-76 on the ground of his illness. In the application he has mentioned that he was suffering from fever and dysentry. He did not submit any application after 18-5-76. The Bank wrote the letter dated 23-5-76 asking the workman to submit for examination before the Bank's doctor, but this direction was not complied with. The Bank wrote another letter to this workman on 8-6-76 informing him that if no satisfactory reply was received from him within a period of ten days, he would be treated as absent from duty in an unauthorised manner and it would be presumed that he was not interested to continue in the service of the Bank and has voluntarily abandoned from duty. This letter was issued with a view to provide him with a further opportunity to convince the Bank authorities about the genuineness of his illness, but he failed to avail this opportunity and as such it was presumed that he had voluntarily aband-

oned the service. He remained absent without prior permission of the Bank authorities and failed to give any explanation about his absence inspite of the opportunity given to him. If be was really ill he would not have any objection to getting himself examined by the doctor of the Bank but his conduct shows that he was not prepared for such an examination.

4. It is not the Bank's case that at the time of terminating the service of the workman, he was given any notice or pay in lieu of notice or any compensation. According to the Bank the termination in the present case is not retrenchment as it fails within one of the exceptions provided in section 2(oo) of the Industrial Disputes Act. His services has been determined on the ground of abandonment of service which cannot be said to be retrenchment of service. The workman has admitted that he had submitted an application of leave on the ground of illness from 12-5-76 to 18-5-76 and thereafter did not come for duty till 30-6-76. According to him he was unwell during this period and was under treatment and as he was alone in the house he could not send information to the Bank authorities. In his cross examination he has admitted that he received two letters from the Bank during the period of his absence or illness as stated by him. However, he does not remember whether he was asked to get himself examined by the doctor of the Bank. He wants to take the plea that during his illness there was nobody with him who could take his leave application to the Bank. His father and brother reside away from him and during the days of his illness there was no communication with them. His wife went to her parents house. This means that a person who was so unwell, that he could not walk for a distance, not more-than half a Kilometer to go to the Bank and give his application was without any assistance from his family members. After all a sick man needs attention and also medicines, but this person who has close relations like father, brother, wife was left all alone to suffer during his illness. It appears that this workman did not expect his father, brother and wife to look after him during his illness but wants sympathy from the Bank authorities on account of absence from duty which may or may not be on the ground of illness. He has admitted the receipt of two letters from the Bank during his illness but has not given any explanation why he did not submit to examination by the Bank's doctor. The inference is that either he was not ill at all and did not have the courage to go to the Bank's doctor, or, he was not at Jaipur and got the letters only on his return. It was then that he poined duty but it was too late. The person who remains absent on the ground of sickness has to at least submit an application for leave at the proper time but the workman failed to submit such an application. He was given an opportunity to explain his absence but he did not avail of this opportunity. He has now taken up the case that he was not given any opportunity to show cause before terminating his service but he himself has admitted the receipt of two letters of the Bank which are nothing but a notice to show cause as to why he was absent and why he should not be removed from service. It was for him to remove the doubt of the Bank authorities by getting himself examined by the Bank's doctor. When he failed to avail of this opportunity he cannot take the stand that he was not given any opportunity to show cause. After 1-7-76, the workman wrote two letters to the Bank which are Ex. M2. and Ex. M3. In these letters he has admitted his mistake and begged to be excused. He has even admitted the receipt of the letters sent by the Bank. When he did not comply with the directions given in the letters of the Bank then the only course open to the Bank was to treat this as a case of abandonment from service.

5. In the present case the termination of the workman can also be said to be punishment inflicted by way of disciplinary action. He was absent from duty and was asked to show cause which he failed to do and his absence made him liable to be punished. The termination in this case is both on the ground of abandonment of service as well as punishment by way of disciplinary action and the formalities necessary to be followed at the time of retrenchment of service are not to be done in this case.

6. The learned counnsel for the Bank has relied upon 1974 (3) S.S.C. 601, the Mineral Development Corporation vs. Shri P.H. Brahmbhatt. In this case the employee of the Corporation remained absent on the ground of illness without previously getting his leave sanctioned. He did not care for the rules and was insolent in correspondance. He was directed to get himself examined by Civil Surgeon, Ahemadabad but he preferred to go to Bombay. The medical certificate produced by him did not show that he was seriously ill. He used to remain absent from duty without obtaining prior permission. In this case the workman was a temporary employee. Considering all the facts and circumstances it was held that the workman was always adopting highly unreasonable attitude which was detrimental to the interest of the Corporation and it cannot be said that the action taken by the Corporation in terminating the service was mala fide and not bona fide.

7. The learned counsel for the workman has relied upon 1982 S.C.C. (L&S) 124, L. Robert D'Souza Vs. Executive Engineer, Sourthern Railway and Another, in which it has been held that termination of service for an unauthorised absence from duty amounts to retrenchment and for the misconduct of absence without leave from duty the termination of service cannot be made without complying with the provisions of natural justice. This is a case of termination service on account of absence which was due to the fact that the workman was sitting on fast unto death for redressal of the grievances espoused by the Union. He broke his fast on the intervention of the Asstt. Labour Commissioner and immediately thereafter the authorities issued the impugned order terminating his service for his unauthorised absence from duty. The order was held to be not bona fide as it was passed without giving any opportunity to show cause.

8. In the present case the workman had completed more than six years service but he admittedly remained absent without submitting any application for leave after 18-5-76. The Bank gave him opportunity on two occasions to explain the cause of his absence and also to get himself examined by the Bank's doctor in order to show that his illness was genuine. The Bank did not take action against the workman on account of any mala fides. There was no option but to treat abandonment of service. It is not necessary that there should be any rules as to when absence from duty can be treated as abandonment from service. When the workman concerned was asked to explain the cause and he failed to explain it then the employer is perfectley justifierd, in coming to the conclusion that the workman does not desire to continue in service. The Bank was perfectly justified in asking him to get himself examined by the Bank's doctor. In this country, day by day it has become very easy to obtain medical certificate for some sort of illness in order to remain away from duty. The employer, who wants to confirm the genuiness of the ailment, can be said to be very reasonable The workman cannot be given a free hand to declare that he is ill whenever he finds it convenient. I am unable to agree with the contention of the workman that the termination of his service is not justified.

9. A reference has been made to the fact that this action took place during the days when Emergency was declared in the nation. The workman wants to say that nobody was sympathetic towards the poor in those days and everybody was out to take strong action and victimise. In this connection I can only say that it was a time when the employers as well as employees were all learning discipline and to work according to schedule but the workman failed to catch the lesson of emergency and work according to rules. He failed to submit applications for obtaining leave and failed to get himself examined by the Bank's doctor for clarification of his illness. Now he cannot turn round and blame emergency for the mistakes committed by him.

In the end I would like to make an observation that the termination of the workman was made in the year 1976 and the reference was made on 6-2-84, nearly after eight years. I am not in a position to say whether the workman raised the dispute after a long time or the Government took much time in deciding to refer this dispute but it would be proper to draw the attention of the authorities to the fact that in cases where the termination of service is held to be invalid then normally the workman is allowed full back wages along with the relief of reinstatement. Sometimes a workman, who is in alternative employment delays the raising of the dispute as he stands to gain by way of back wages for a long period as the other employment is not within the knowledge of the employer. No doubt there is no limitation as far the time for raising a dispute is concerned but in cases where there is unreasonable delay, the proper

authority should take this fact into consideration while referring the dispute. If the Tribunal is notified the cause of delay in raising the dispute, or referring the dispute then it will be in the interests of justice.

10. As the termination of the workman Ram Singh is held to be proper the workman is not entitled to any relief. A no dispute award is passed in this reference.

11. The award be sent to the Central Government for publication.

SMT. MOHINI KAPUR, Judge
[No. L-12012/221/83-D.II(A)]

नई दिल्ली, 17 सितंबर, 1985

का. आ. 4648.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 9 सितम्बर 1985 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 17th September, 1985

S.O. 4648.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th September, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL KANPUR

Industrial Dispute No. 238 of 1983

In the matter of dispute

BETWEEN

Shri Amar Kumar Pande, Village Dhuchwa, Swaroopur Post Office Dhemipur, District Pratapgarh, (U.P.).

AND

The Branch Manager, State Bank of India, Kunda Branch, District Pratapgarh, (U.P.).

APPEARANCE :

Shri V. N. Sekhari & B. D. Tewari, representative for the workman.

Shri Mahesh Chandra, representative for the Management.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/135/83/D.II-A dated 17th November, 1983, has referred the following dispute for adjudication;

"Whether the action of the management of State Bank of India in relation to their Kunda Branch (Pratapgarh District) in terminating the services of Shri Amar Kumar Pande Guard with effect from 12-1-1983, is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. It is common ground that the workman was empanneled as BADLI GUARD, at the management's branch at KUNDA, District Pratapgarh, from 27-3-82, and continued to work as such according to requirement. That his services were terminated w.e.f. 12-1-1983, as his services no longer required. According to the management the actual number of days worked by the workman touching the maximum number of days prescribed under rules. It is further admitted that as badli guard he was neither issued appointment letter nor termination letter. The workman alleged that he worked for more than 181 days but according to the management it is only 117 days. The management bank by not giving appointment letter and termination letter has violated para 493 522(4) and 522(5) of the Sastri Award. It is further averred that having worked for 181 days, the workman has acquired the right of the post and taking work from other two guards and not taking work from the workman amounts to victimisation, hence the termination be deemed illegal and viod abinitio and be be held reinstated with full back wages.

3. The management has averred that in the very nature of the terms of the employment, a badli guard is appointed for a particular work on a particular day. His employment comes to an end as soon as his specified work or the period of work is over. A badli guard has no right to claim employment on the next day. Engagement of a badli guard does not amount to termination of service.

4. According to the statement of work done filed by the management, the workman worked for 8 days, 4 days, 20 days and 150 days total 182 days. The management in para 4A has admitted that by way of fair policy and to ensure that badli guards are not misutilised by long term engagement the rules provide that they are in no case shall be employed for a period exceeding 180 days in a calender year.

5. In the rejoinder it is alleged by the workman that he was working against a regular vacancy as a relieving guard which was of a permanent nature in the bank and the petitioner was liable to be regularised in service instead of being retrenched. It is further averred that the termination of the workman infringes provision of sec. 25G, H and J of the I.D. Act, and thus he is entitled to be reinstated. The workman has further averred that he worked for 181 days during the period 27-3-82 to 12-1-83. No notice or notice pay was ever given to the workman.

6. The workman moved an application for production of certain document by the management. The management replied that no document at serial No. 5 of the applicaion dated 10-10-84 was in existence. The management has filed guards allotment register and the statement of bank guards of Kunda Branch. This statement shows that in the said branch i.e. Kunda branch of the management, there were three permanent guards who were all appointed prior to the date when Shri A. K. Pande workman left the job and there were 6 other temporary guards appointed on 14-2-84, 15-2-84, 15-4-84 and 22-4-84 and on 21-5-84 and none of them have been regularised in the bank. The management has further filed statement of emoluments drawn by the workman Shri Amar Kumar Pande, during the period March, 82 to December 82 and that he was paid for total 175 days only. The management has filed copy of staff circular No. 168 of 1976 dated 9th September, 1976 showing that temporary employees who have not completed 240 days in one calender year should be unmediately despenced with. They have filed further Staff circular No. 77 of 78 which lays down that no temporary employee should exceed 90 days of service in a year and no re-engagement should be made.

7. As regards oral evidence the management has examined one Shri Naval Kishore who has testified the case of the management in the affidavit filed by him. In the cross examination he has deposed that badli guard is appointed from the penal list of guard when a permanent guard goes on rest or on leave. He has shown his inability in deposing whether the workman was appointed in a permanent vacancy. He deposed that the workman has availed 28 days of rest. He states that he does not know whether the workman was given salary for 29 days rest but states that normally for rest days badli guards are not paid. Admittedly the workman has been paid for 175 days. If 28 days is added to that it will come to 203 days whereas even according to both the parties the workman has not worked for more than 182 days. This shows that the workman has paid for all 203 days. He has admitted that in the duty register of badli guards at page 391 on 13-9-82 the name of Shri Ambika Prasad Pande was scored out as he was on leave. He has further stated that on 13-9-82 the workman was given duty in place of Dasa Ram who was on rest. On the otherhand Shri A. K. Pande workman has given his testimoney by filing affidavit and incorporating the claim statement. In cross examination he has deposed that he was a temporary guard and was told by the management. He admits that from 27-3-82 to 12-1-83 he was worked when he was deputed to work. He has denied that he knew that he was being put on the penal of badli guard.

8. A perusal of statement of bank guards filed by the management shows that there were only 3 permanent guards, thus daily even if all of them present and they were given

8 hours duty there was recurring shortage of one permanent guard which was filed by employing the workman. It is a matter of common knowledge that round the clock vision by guards had to be done by bank and each guard is required to perform 8 hours duty. Thus it can not be said that Shri Amar Kumar Pande workman was not engaged as temporary guard who could have filled in the permanent vacancy of 4th guard and not the simple guard to be employed in contingency when a permenant guard go on leave or on rest.

9. In this view of the matter it can not be said the Shri Amar Kumar Pande workman was a badli guard. His position is being that of a temporary guard his termination could not thus effected without notice for 14 days as required in para 522(4) of Sastri Award. The statement filed by the management shows that if at all it was necessary to terminate Shri Amar Kumar Pande, workman, the provision of last come first go should have been applied and Shri Sachida Nand should have been terminated first and not the Workman Shri Amar Kumar Pande.

10. Thus to my mind the management has contravened the provision of section 25G of the I.D. Act. The two provision being mandatory the termination of the workman Shri Amar Kumar Pande was illegal and void ubinitio and the result is that he will be entitled to be reinstated with full back wages.

11. I, therefore, hold that the action of the management bank of State Bank of India, in relation to their Kunda (Pratapgarh) in terminating the services of Shri Amar Kumar Pande, Guard w.e.f. 1-1-83 is not justified, and the workman is entitled to be reinstated in the management bank's service with full back wages. Under the circumstances of the case the management shall pay Rs. 200 as cost to the workman. .

12. I, therefore, give my award accordingly

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

13. Let six copies of this Award be sent to the Government for publication.
Dt. 2-9-85.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012|135|83-D.II(A)]
N. K. VERMA, Desk Officer.

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1985

का०आ० 4649.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एन्ड जयपुर के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-9-1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 18th September, 1985

S.O. 4649.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of Bikaner & Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th September, 1985.

CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN, JAIPUR.

Case No. C.I.T. 19/82.

REFERENCE:

Desk Officer, Government of India, Ministry of Labour Order No. L-12012 (168)/81-D. II (A), dated 20-4-82.

In the matter of an industrial dispute.

BETWEEN

Shri Satya Narayan Purohit, S/o Shri Shebi Ramn C/o M/s. K.K. Plastic and polythine Industries, F-58, Industrial Area, Sikar. (Rajasthan).

AND

State Bank of Bikaner and aJipur, S.M., Highway, Jaipur

For the Applicant—Shri Ashok Parihar.

For the Bank—Shri P.C. Jain.

Shri T. N. Tandon.

Date of Award 27-6-85

AWARD

The Central Government has referred the following dispute for adjudication.

"Whether the action of the management of State Bank of Bikaner and Jaipur in relation to its Begun Branch in dismissing Shri S.N. Purohit, Head Cashier with effect from 1-1-79 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled."

2. The workman S.N. Purohit was the Head Cashier at the Begun Branch of the Bank at the relevant time and he has himself raised this dispute. The dispute which lead to the dismissal of the workman is actually betwewen the workman and Shri S.L. Jagani who was an Agent of the Begun Branch at that time. Two incidents are said to have occured on 7-5-74 and 8-5-74 in which according to the workman it was Shri Jagani who beat the workman while according to the Bank it was the workman who attacked Shri Jagani and gave clenched fist blows on his face. On account of these two incidents, the workman was suspended and served a charge sheet on which an enquiry was held. After giving him an opportunity against the proposed punishment he was dismissed from service. The justification of this punishment is to be adjudicated in this reference.

3. It may be mentioned here that the Bank was unable to produce the full record of enquiry proceedings with the result that the enquiry could not be said to be fair and proper. The Bank has been allowed to prove the charges before Tribunal. It will therefore, not be necessary to reproduce the contentions of the workman challenging the fairness of the enquiry.

4. The workman was appointed with the opposite party, Bank, on 1-1-58 and according to him he was an active member of the trade Union movement and in 1972-73 he was the President of the Begun Branch of the Union. Shri S.L. Jagani was the Agent in this Branch during the year 1973-74 and according to the workman he was a very shrewd and notorious, scheming person, involved in numerous illegal and untoward activities. The local news papers and local public made several complaints against Shri Jagani. It was due to the complaints and opposition to him that he started harassing the employees as well as the workman, who was the President of the Union. He was dragged in a criminal case. Peons were made to write complaints against the workman but later on they were withdrawn. According to him, the Bank authorities played in the hands of Shri Jagani against whom no action was taken inspite of numerous complaints. Even the incidents of 7-5-74 and 8-5-74 were immediately intimated to the higher authorities but no action was taken on the complaint of the workman. His dismissal from service is said to be due to adament and unreasonable attitude of the Bank. It is said to be illegal, unjustified mala fide, vindictive amounting to victimisation and unfair labour practice.

5. In reply the Bank has drawn attention to an earlier charge sheet issued to the workman on 25-4-74. This relates to an attack made by the workman on Narayan Das and Nar Singh Gupta, Cashier of the Reserve Bank. After enquiry two increments were with-held. The workman preferred a writ Petition against this and he was not successful before the Single Judge as well as the Division Bench. Actually the

punishment imposed was said to be very lenient for the act of assaulting an official of the R.B.I. This incident is said to be relevant as it shows the conduct of the workman who is said to be in the habit of beating others. The allegations against Shri S.L. Jagani are said to be mischievous, malacious, and motivated and are denied. It is said that the workman used to harass the customers of the Bank in the matter of receiving and paying cash. It is stated that with a view to cover his own defects he has levelled allegations against Shri Jagani. The order of dismissal is said to be justified on basis of the charge sheet dated 17-6-74.

6. Before referring to the evidence in the case it is necessary that the charges against the workman may be perused in detail. The charge sheet enumerates the following charges against the workman.

"(i) On 7-5-1974, Shri V.N. Saxena, Forest Range Officer, Begun tendered a Govt. cheque for Rs. 20,000|- alongwith the details of the denominations of G.C. Notes required by him and same was sent to you duly passed by the authorised official for payment. You thereupon sent the aforesaid cheque to the Agent of your branch through "Cheque Referred and Returned Register" *enquiring* as to what denominations of G.C. Notes be issued to the said tendered. Although ' Cheque Referred and Returned Register is not meant for seeking such directions, necessary instructions were however, given to you by the Agent of your Branch. The Agent of your branch subsequently accompanied you to the strong room at about 12.15 p.m. to take out some currency notes of required denomination from the strong room to effect the payment of the above cheque and while he was filling the vault register, you are reported to have beaten the branch Agent by clenched fist on his face. You were subsequently restrained from doing so by Shri Balu Ram peon.

You have thus not only committed acts of riotous and disorderly behaviour in the premises of the Bank but also committed acts of insubordination which are tantamount to gross misconduct in terms of paragraph 19.5 (c) & 19.5 (e) of the Bipartite settlement dated the 19th October, 1966.

(ii) By your lapses, you prevented the Agent to take out the required cash from the strong room for payment to Shri Saxena as a result of which the payment could not be made to Shri Saxena till about 1.30 p.m.

You thus committed an act highly prejudicial to the interest of the Bank which is an act of gross misconduct in terms of paragraph 19.5 (i) of the Bipartite Settlement dated the 19th October, 1966.

(iii) On 8-5-1974, at about 10.15 a.m. while asking the Agent of your branch to return the office copies of two letters given by you to him earlier, you pounced upon the Agent Shri Jagani and beat him again with clenched fist. You further twisted the the hands of the Agent. During the course of this assault you raised a chair to beat Shri Jagani but Shri Baluram peon caught hold and saved Shri Jagani from its injury.

You have thus committed acts of riotous and disorderly behaviour on the premises of the Bank which is an act of gross-misconduct in terms of paragraph 19.5 (c) of the Bipartite Settlement of the 19th October, 1966.

The evidence, which has been led before this Tribunal to prove these charges is to be perused in order to come to the finding whether the charges have been proved or not. It may be mentioned here that the workman, as well as the Bank have admitted that some incident took place on 7-5-74 and 8-5-74 in which the workman and Shri Jagani were involved. According to the workman it was Shri Jagani who attack him while the cases of Shri Jagani is opposite. This will have to be decide with reference of the statement of the evidence examined before me.

7. The witness for the Bank is Shri Virendra Nath Saxena who is a Ranger in the Forest Department. He brought two cheques for encashment between 10.00 a.m. to 10.30 a.m. on 7-5-74. The cheques were passed at about 11.15 a.m. but he did not receive the cash. He even approched the Manager to expedite the payment. On that day, the workman S.N. Purohit was sitting at the cash counter and instead of making payment of the cheques he entered them in the register of Referred and Returned Cheques and sent to the Manager. The workman asked Mr. Saxena to write the denomination of the notes required by him. He had already written that on the reverse of the cheques and he did it again but it still took time for making the payment. Then he was told that it would take sometime, so he sat down and then the workman as well as the Manager went to the strong room. After opening the strong room the Manager made some entry in the register and at that time the workman hit a blow on the cheek of Shri Jagani. The Manager fell down and the peons ran towards them. The peons caught hold of Shri Purohit and brought him out and then the Manager came out after him. This witness could watch the incident from the hall and he could see one blow given by the workman on Jagani's cheek but could not hear the conversation. This incident occurred at about 12 p.m. and he was able to get the payment only about 1.30 p.m. or 2.00 p.m and during this period the working of the Bank remained suspended.

PW-3, Baluram, was a peon in the Bank, has stated that on 7-5-74, Ranger had come to encash cheques and he demanded notes of specific denominations. The cshier, namely the workman, put the cheques in the Cheques Referred and Returned Register and sent it to the Manager who said that he would have to pay cash. Then the workman told this witness to tell the Manager to open the strong room for taking out notes of the specified denomination. After this the strong room was opened and the workman as well as Shri Jagni both entered in it. The witness, PW-3, went away to the stationary room but had to rush back in a couple of minutes because of the noise and scuffle. When he came back he found that Shri Jagani saying that Purohit was beating him. This witness caught hold of purohit while the Manager came out of the strong room. The next witness is Shri Jagani himself who has stated that Shri V. N. Saxena, Ranger, brought two cheques for Rs. 10,000|- each and the denomination of the notes required by him were already recorded on the reverse of the cheques. He passed the cheques for payment and got them entered in the books through the clerk concerned and sent it to the Head Cashier for making payment. The head cashier instead of making the payment returned the cheques to him after entering them in the Cheques Referred and Returned Register with a note. According to him, this register is not meant for such references and he ordered, 'Pay as per Bank's arrangement.' At about 12.15 p.m. he and Mr. Purohit went in the strong room. He was about to make an entry of the withdrawal register kept in the Vault when Shri Purohit gave three blows with a clenched fist on his face as a result of which he fell down and Shri Purohit continued beating him by kicks. On hearing the noise in the strong room Shri Baluram, peon came in rushing and caught hold of Shri Purohit by waist and took him out of the strong room. Had Baluram not come to his rescue, Shri Purohit would have inflicted grave injuries. Immediately he informed the Head Office about the incident vide telegram. The Asstt. Sub Inspector. Shri Allauddin and Medical Officer Incharge Government Hospital came to see him. This is as regards the incidents which occured on 7-5-74. PW-4. Shri S. N. Masaldan, Administrative Officer has stated that on 7-5-74 he received a telephone call from his Begun Branch informing about the incident which took place in the strong room and the work of the Bank remained suspended till 1.30 p.m. at that day.

9. As against this there is the sole statement of Shri Purohit. He has stated a lot about the activiies and reputation of Shri Jagani. As regards the incident of 7-5-74 he had admitted that he entered the strong room alongwith Shri Jagani and after the latter made entry in the inward register of the Vault and he (Purohit) was about to initial the entry, Jagani abused him and started beating. Shri Balu, peon came intervene. The only witness to support him is Hira Singh Chowdhary who is not an eye witness to the incident but according to him when Purohit and Jagni came out of the strong room on 7-5-74 at 12.15 p.m., Purohit was alleging that Jagani had beaten him. The presence of this witness Hira Singh has not been established by the other witnesses. Even Baluram, peon has stated that there was no one else besides the Ranger.

10. In an incident of this sort which admitted took place, the only question which remains relevant is as to who was the assailant. The circumstances show that Purohit was annoyed by Jagani on account of the charge sheet served upon him by the latter. The beating by Purohit is corroborated by witnesses. The workman Purohit has not been able to satisfy that he had made complaints against Jagani who retaliated against him. It canont be forgotien that once before Purohi had assaulted an Officer of the Reserve Bank for which he was punished departmentlly.

11. Now I come to the incident which occured on 8-5-74. Shri Jagani has stated that on 8-5-74, he was waiting for the arrival of the head-cashier in the cashier's cage in the Bank at about 10.15 a.m. to take out the cash from the strong room. Shri Purohit came and asked for duly signed two office copies of certain letters given to him on 7-5-74. At that time he (Jagani) stated that he will return the same to him in due course. Upon this Shri Purohit twisted Jagani's hand by holding his wrist and gave a blow with clenched fist on his back and raised the chair to full hieght to hurt him. Just at that moment Shri Baluram, peon caught hold of Shri Purohit's waist from behind once again and saved Shri Jagani from getting further injuries. PW-2, Shri Ratan Lal, Watchman, has sated that there was an altercation between the Manager Jagani and Shri Purohit in the hall of the Bank at about 10.15 a.m. and Shri Purohit lifted the chair. At that time Shri Baluram caught hold of Shri Purohit who started shouting and left the Bank premises. He has denied the sugestion that he was not an eye witness. The other witness is Shri Baluram, peon, who has stated that the cashier Shri Purohit had submitted some reply and he wanted a receipt from the Manager, upon which there was some quarrel, and Shri Purohit caught hold of the hand of the Manager and gave a blow and lifted the chair. This witness, Ratanlal, then caught hold of Shri Purohit. He has denied that it was the Manager who gave beating to the Purohit. The story as given by Shri Purohit is also similar. According to him he demanded receipt of his two letters which Shri Jagani gave him and said that he was in habit of making complaints therefore he should be taught a lesson. The Manager then asked Shri Ratanlal Chowkidar to close the door of the Bank and asked Baluram to hold him. After this Shri Jagani started dealing blows and kicks. On hearing his shouts some people started to knock the main gate. which was then opened. He then went to the hospital to get his injuries examined. The story about closing the door of the Bank has not been put to Shri Jagani and he other witnesses, and the workman has not been able to get this version corroborated by any witness. The injury report of Shri Purohit shows bruises on legs, calf area, and the elbows which can be caused in a scuffle. A man who is unable to use his hand may use his feet and may cause bruises on the leg. They cannot be said to be the injuries caused by a person who is opening the attack because in that case there should be some injury or the vital parts namely face, or chest, or back of Shri Purohit.

12. The workman has produced two photostat copies which have been marked as Jagani-I and Jagani-II. According to the workman Jagani used to write complants against the workman and get them signed by peons in order to collect material against him. The original of the documents from which the workman made these photostats are not available. If Jagani had written out the complaints then he could no have signed them. His own explanation is that he had copied some complaints. In absence of the originals of these photostats it is impossible for me to arrive at any firm conclusion or to discredit Jagani on basis of these photostat copies.

13. The workman Purohit instituted a criminal case in respect of the incidents of 7-5-74 and 8-5-74. He has placed reliance on the statement of the witnesses Baluram and Ratanlal in that case. They had denied the incident before the Magistrate but before this Tribunal they have clarified that because of compromise in the Magistrates Court they had not given a correct statement. In view of the statements made by the witness before this Tribunal in which hey have stood the test of cross examination also. The statement made in the criminal Court, in the shadow of compromise, cannot be said to be correct,

14. The Management has been able to prove the incident of both the dates and it is to be seen what punishment should be imposed upon the workman. Because of some incident which took place earlier his two increments were with-hold which were confirmed by the High Court. A person with this type of background cannot be said to be a person suitable for continuation in the service of the Bank. The Banks have to deal with customers and the attitude of its employees may sometimes make the Bank lose customers. Persons responsible for this type of acts cannot be forced upon the Bank and the circumstances in which he has been dismissed from service are appropriate for this punishment and the dismissal is proper and fit to be up held.

15. Accordingly an award is passed that the action of the management of the State Bank of Bikaner and Jaipur in dismissing the workman S. N. Purohit cashier of Begun Branch from 1-1-79 is justified and proper. The workman is not entitled to any relief.

16. Accordingly an award is passed which is to be sent to the Central Government for publication in accordance with law.

SMT. MOHINI KAPUR, Judge

[No. L-12012|168|81-D. II(A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1985

का. आ. 4650—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, बैंक आफ मदुरा लि. (अहमदाबाद) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, गुजरात के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3 सितम्बर, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 13th September, 1985

S.O. 4650.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Gujarat, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Madura Ltd., Ahmedabad and their workmen. which was recived by the Central Government on the 3rd September, 1985.

BEFORE SHRI G. S. BAROT, PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)

Reference (TC) No. 8 of 1982

ADJUDICATION

BETWEEN

Management of Bank of Madura Ltd

AND

Their workmen.

In the mater of termination of services of Shri Vipul Babulal Shah, etc.

INDUSTRY : Banking

APPEARANCES :

Shri P. S. Chari, Advocate—for the Bank.

Shri Y. V. Shah, Advocate—for the workmen.

AWARD

The industrial dispute between the Management of Bank of Madura Ltd. and their workmen regarding termination of services of Shri Vipul Babulal Shah has been referred u/s. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication to me by Government of India, Ministry of Labour,

New Delhi, Order No. L-12012/322/81-D.II(A) dt. 26-3-82.

2. The case of Shri Vipul Babulal Shah, hereinafter referred to as the 'workman concerned' is that he was appointed as a clerk by order dated 9-7-80 passed by the Chief Officer of the Bank of Madura, hereinafter referred to as 'the bank', that he was appointed on probation for a period of six months but thereafter by order dated 6-1-81 his probation period was extended for a further period of 3 months with effect from 21-1-81; that his servic record was quite satisfactory; that his services were then summarily terminated by the Chief Officer of the Bank by order dated 11-4-81 on the ground of unsatisfactory work with effect from 20-4-81; that he has not been given any show cause notice and/or charge sheet or has not been given any compensation; that he has completed continuous service with the bank for more than 240 days; that no inquiry has been held against him; that no adverse remarks, if any, have been communicated to him and therefore the impugned order passed against him is unjustified, illegal and null and void. He should therefore be reinstated on his original post with full back wages.

3. The bank has filed written statement ex. 4 contending inter alia that the workman concerned was upointed by order dated 9-7-80 as a clerk on probation initially for a period of six months; that it was specifically stated in the said appointment letter that his services as a probationer would be confirmed or extended at the time of completion of the probationary period depending upon his performance; that as per the aforesaid term and as his performance was found very poor his probation period was further extended for a period of three months with effect from 21-1-81, i.e., on the expiry of initial period of six months; that this was done to give him a further opportunity to improve himself in his work; that his performance even during the extended period was also not satisfactory and therefore as per the terms of the contract and the letter of appointment as a probationer his services were duly terminated; that it is the discretion of the bank to decide whether the probationer is fit to be confirmed or not on the expiry of the probationary period or the extended probationary period as the case may be; that the workman concerned was not found suitable for being confirmed and hence in bona fide exercise of discretion, the bank, by its order dt. 11-4-81 terminated the services of the workman concerned as he was on probation upto 20-4-81, i.e., the date on which his extended probationary period expired; that in view of the aforesaid circumstances the question of holding inquiry or the order of termination being punitive does not arise. The allegation as to victimisation was also specifically denied. It was also submitted that the instant case is not one of retrenchment and hence the provisions of S. 25F of the I.D. Act would not be attracted.

4. It was also contended by the workman concerned in his statement of claim that the order of his termination of service was passed under political pressure which again amounted to victimization. The bank in its written statement has emphatically denied this allegation.

5. It appears that the bank has also filed additional written statement at ex. 5 on 14-9-82 wherein it has been very specifically stated that the action of the bank is not punitive but if the Tribunal comes to the conclusion that the workman concerned should be afforded adequate opportunity of being heard, the bank reserves its right to substantiate the reasons for termination before the Tribunal. The bank therefore requested the Hon'ble Court to afford opportunity to the bank to inquire into the reasons for termination before the Hon'ble Industrial Tribunal.

6. It is important to note that in this case a purshish on behalf of the workman concerned (Ex. 11) was given on 17-9-84 stating that the workman concerned did not desire to lead any oral evidence. As against that though the bank through its additional written statement ex. 5 had submitted that the bank be given an opportunity to substantiate the reasons for the termination of services of the workman concerned before this Tribunal, further gave an application ex. 12 on 18-12-84 stating that the bank wanted to prove the charges against the workman concerned and desired to lead oral evidence. It further stated that the Deputy Chief Officer, Staff Department, is not in Ahmedabad and therefore time may be granted. Thereafter from ex. 13 another application given by the bank it appears that witness Shri P. M. Venkateswaran, Deputy Chief Officer, Central Office, Madras, is not present in Ahmedabad and therefore adjournment was sought for which was also granted having not been objected on behalf of the workman concerned. From this it clearly appears that the bank wanted to prove the charge inspite of the fact that it was its contention that the order of termination of the services of the workman concerned was not punitive. Pursuant there to the bank examined R. Ramanathan at ex. 14. He is the branch manager in Ahmedabad branch of this bank. He has stated in his deposition that he knew the workman concerned quite well. The workman concerned was appointed with effect from 9-7-80 in Ahmedabad branch. He was appointed as a probationer. The witness further deposed that on 19-8-80, i.e., hardly a month after his appointment on probation the workman concerned was given the work of despatching one cover in which some important papers were there. However, the said papers were misplaced by the workman concerned for which a memo was given to him and explanation was also sought for from the workman concerned to which he had furinshed his explanation. Thereafter the workman concerned had assured to be alert in future. The witness further deposed that as a manager he was keeping a watch on the work of the workman concerned but he had found the work of the workman concerned quite unsatisfatcory. He had also written one letter dt. 9-9-80 wherein he had invited the attention of the central office on six or seven points on which he had found the workman concerned not upto the mark. He had also sent two performance reports in connection with the workman concerned wherein he had graded the workman concerned as below average; that thereafter the period of probation of the workman concerned was extended by a further period of three months during which also the work of the workman concerned was under close scrutiny. The witness further stated that inspite of the probationary period being extended the work of the workman concerned was getting deteriorated day by day. While working in the despatch department and the bill section the workman concerned used to make many mistakes; that the workman concerned was even called in person and shown his mistakes. Not only that the witness i.e. the manager had also instructed him to improve his working. The witness has also pointed out from the registers where entries of bills were made, the mistakes committed by him. Some columns of the registers were also not filled in properly; that it also shows over-writing and errasures. The witness also pointed out one column which is meant for showing as to from which branch the letter was received but according to the witness the said column was kept blank and it was not possible to know from which branch the said letter was received. At times the officer concerned had to fill in the columns kept blank by the workman concerned. In one of the cases the workman concerned had not written the due date which is considered to be the most important matter in bank dealings. According to this witness he had also sent another performance report dt. 1-4-81. The witness has also stated that the workman concerned is at present working as a permanent clerk in Kalupur Commercial Co-operative Bank at Sanand. This witness was cross examined on behalf of the workman concerned and a suggestion was made to him that the workman concerned was appointed on the recomemndation of Shri Prabhudas Patwari the then Governor of Madras. The idea behind putting this question appears to be that as the workman concerned was appointed at the instance of Shri Patwari and now that when he is not in power the bank has victimized him by terminating his services. It appears that another question was put to the witness in cross examination as to the application of the Shops & Establishment Act to this branch of the bank. In reply to the said question it was admitted by the branch manager that at the relevant time the Shops & Establishment Act did apply to the said branch. In reply to another question put on behalf of the workman concerned the branch manager admitted that the services of the concerned workman were terminated because the workman concerned was

not found suitable in his work. The witness also admitted that the concerned workman was paid wages for the period from 9-7-80 to 20-4-81. On another suggestion being made to the witness in cross examination the witness however denied that the services of the workman concerned were terminated by way of punitive action. However the witness admitted that the workman concerned was not given any show cause notice and/or charge sheet. He also admitted that no inquiry was held against him nor any compensation in lieu of notice was given.

7. The bank also examined at ex. 32 one Venkateswaran the Deputy Chief Officer who is working in the personnel department of the bank at Madras. This witness has deposed about the procedure of taking probationer clerks etc. and also about the procedure adopted while terminating the services of such probationers. The witness has stated that the probation period of the workman concerned was extended by a further period of three months. In the cross examination the witness stated clearly that with regard to the workman concerned the branch manager had forwarded his observations in his report.

8. On behalf of the bank by list ex. 15 zerox copies of certain documents have been produced which are exhs. 16 to 23.

9. I have heard Shri Y.V. Shah for the workman concerned and Shri Venkateswaran, the Deputy Chief Officer for the bank. On behalf of the workman concerned Shri Shah argued that the workman concerned was appointed on probation for six months. It was further extended by period of three months and then suddenly without giving any notice or a show cause or conducting any inquiry the bank mala fide terminated the services of the workman concerned. According to Shri Shah the order passed by the bank against the workman concerned is in substance nothing but retrenchment and the bank having not complied with any of the provisions contained in S. 25F of the Act the order in question has had no law i.e. null and void and the workman concerned should therefore be reinstated on his original post with full back wages. Shri Shah also pointed out from the evidence led by the bank that the services of the workman concerned were terminated because his work was not quite satisfactory. Shri Shah for the workman concerned however argued that though the workman concerned was a probationer his services have been terminated with a view to punishing him and as such the order passed by the bank is a punitive order. Shri Shah then argued that the impugned order having been passed without holding any inquiry is null and void and it would attract the provisions of S. 25F of the Act. In support of this contention Shri Shah relied on the case between Management of Karnataka State Road Transport Corporation, Bangalore v/s. M. Boraiah and another reported in A.I.R. 1983 SC 1230=(1984) 1 SCC p. 244. In the aforesaid case decided by the Hon'ble Supreme Court Their Lordships were pleased to hold that—Section 2(oo) covers every case of termination of service except those which have been embodied in the definition. Therefore, discharge from employment or termination of service of a probationer, would also amount to retrenchment. Compliance with the requirements of Section 25-F in case of such termination is essential. I am in respectful agreement with the observations of the Hon'ble Supreme Court as far as the principle laid down therein is concerned. It is true that once a conclusion is reached that retrenchment as defined in S. 2(oo) of the Act covers every case of termination of service except those which have been embodied in the definition, discharge from employment or termination of service of a probationer would also amount to reterenchment. In the present case it is true that the workman concerned was a probationer and his services were terminated by the bank but it is to be seen whether the instant case is one of retrenchment or falls within one of the expected or excluded categories. For this it would be relevant to refer to the definition of 'retrenchment' contained in S. 2(oo) of the Act which says :

'Retrenchment means the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action, but does not include —

(a) voluntary retirement of the workman; or

(b) retirement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract of employment between the employer and the workman concerned contains a stipulation in that behalf; or

(c) termination of the service of a workman on the ground of continued ill health."

Now as Shri Shah has argued that the case in question is one of retrenchment which would attract the provisions of S. 25F as the bank has not held any inquiry. Shri Shah has also in the alternative argued that the branch manager in his cross examination had admitted that Shops & Establishment Act is applicable to the branch of the bank. Shri Shah had therefore drawn my attention to a decision of the Hon'ble High Court of Gujarat in Special Civil Application No. 5519 of 1983 wherein Their Lordships had an occasion to deal with a case of a workman who had completed 240 days with the bank. In the above case decided by Hon'ble High Court of Gujarat, Their Lordships were pleased to hold as under :

"However, it is not necessary for us to decide this question because there is another similar provision in Bombay Shops and Establishments Act, 1948, in section 66 which directs that no employer shall dispense with the service of an employee who is in continuous employment for more than three months without giving such a person atleast 14 days notice in writing or wages in lieu of such notice."

The question before Their Lordships was one of considering completion of 240 days in service by a workman. But there, the question was being considered under the provisions of the Industrial Disputes Act. It was there argued on behalf of the employer that Sundays and holidays should be excluded while counting 240 days. However on the facts of the case Their Lordships were of the view that it was not necessary for Their Lordships to decide the said question as the provisions of Shops & Establishment Act also applied in the said case. In the instant case also Shri Shah for the workman concerned tried to put his case similar to the one decided by Their Lordship in the said above Special Civil Application but in my view it is not necessary to consider the provisions of the Shops & Establishment Act applicable to the branch of the bank herein, inasmuch as there is no question as far as the completion of 240 days is concerned in this case. In my view the provisions of the I.D. Act are hereby applicable in the instant case. It is also not in dispute that the workman concerned has completed 240 days of service in the bank. The only question therefore to be seen is whether the termination of the service of the workman concerned amounts to retrenchment and if it is to be found that it is retrenchment then the provisions of S. 25F are attracted and the bank having not complied with the provisions of the said section the order would be null and void.

10. However in the instant case as stated above the bank had from the very beginning been stating through its additional written statement that though it is the case of the bank that the order passed against the workman concerned is not a punitive order, if the Tribunal thinks otherwise, the bank be allowed to lead evidence in support of the allegation that the work of the workman concerned was not satisfactory. Not only that but an application ex. 12 was also given wherein the bank specifically prayed to allow it to lead oral evidence to prove the charges. Thereafter the bank led evidence to prove the fact about the unsatisfactory work of the workman concerned. As against that it is clear from ex. 11 that the workman concerned did not lead any evidence nor a request was made even after the evidence of the bank was over that the workman concerned be allowed to say anything further in the matter. Thus, whatever evidence is there on record has to be considered and from that one has to reach a conclusion whether the work of the workman concerned was satisfactory or not. Referring back to

the definition of retrenchment contained in the Act it says that retrenchment means termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action. This means that if it is proved by the bank that the order of termination of the service of the workman concerned falls in one of the accepted categories in the definition of retrenchment than the order passed herein would not amount to retrenchment and there would be no question of any violation of the provisions of S. 25F or the said order being null and void. Now let us examine the evidence on record by which the Bank has tried to prove the charge viz. that the work of the workman concerned who was a probationer was not satisfactory and therefore the action of the Bank in terminating his services would not amount to retrenchment but the order is perfectly justified, legal and proper. For this, it would be necessary once again to see the evidence of the Branch Manager wherein he has clearly stated that the workman concerned was given one cover containing very important documents which he has misplaced. He was given a memo and asked for his explanation which was submited by the workman concerned. The Branch Manager has also pointed out that the work of the workman concerned was not satisfactory and therefore his probation period was extended by a period of three months on the reports about his work. He has also categorically stated that even during the first probation period and the extended probation period his work was not satisfactory and the workman concerned was found below average in his work. Nothing worthwhile could be elicited in his cross-examination which would disprove the charge regarding his work being unsatisfactory, nor has the workman concerned led any evidence to rebut this charge. If this is the state of the evidence, the charge regarding his unsatisfactory work is proved through evidence before the Tribunal and as such it amounts to punishment by way of disciplinary action. I do not also think that the order passed by the Bank can be said to be an order passed with ulterior motive or by way of victimization. However, it is to be seen whether it is a camouflage for an action which, in reality, may have been taken with ulterior motive. Scrutinising the evidence on record, I do not think it is so, nor has the allegation regarding any political pressure, any substance whatsoever. In the aforesaid circumstances, I am of the view that the impugned order cannot be termed as retrenchment of the workman concerned but it is an order of punishment by way of discepilinary action. As such, there is no question of any violation of Sec. 25F of the Industrial Disputes Act, 1947. For the aforesaid reasons, it is held that the termination of the services of the workman concerned was legal, proper and justified and he is not entitled to any relief. No order as to costs.

Ahmedabad,
Dated : 16th August, 1985

G. S. BAROT, Presiding Officer
[No. L-12012/322/81-D.II(A)/D.IV(A)]
K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1985

का. आ. 4651:—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे संबंधित विद्यमान सभी अधिसूचनाओं को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रण के अधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कम्पनी महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसकी एक से अधिक राज्यों में विभाग या शाखाएं हैं, उक्त अधिनियम और स्कीम कुटुंब पेंशन स्कीम और उसके अधीन विरचित बीमा स्कीम के प्रयोजनों के लिए, निम्न सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उसके स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

सारणी

अधिकारी	क्षेत्र
(1)	(2)
1. प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आंध्र प्रदेश (हैदराबाद) के कार्यालय के सभी भविष्य निधि अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी	सम्पूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का यनम क्षेत्र
2. प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त बिहार (पटना) के कार्यालय के सभी भविष्य निधि अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी	संपूर्ण बिहार राज्य
3. प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय के सभी भविष्य निधि अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी	संपूर्ण दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र
4. प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात (अहमदाबाद) के कार्यालय के सभी भविष्य निधि अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी	संपूर्ण गुजरात राज्य और दादर और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा गोवा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र का दमण और दीव क्षेत्र
5. प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा के कार्यालय के सभी भविष्य निधि अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी	संपूर्ण हरियाणा राज्य
6. प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक (बंगलौर) के कार्यालय के सभी भविष्य निधि अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी	संपूर्ण कर्नाटक राज्य
7. प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त केरल (त्रिवेन्द्रम) के कार्यालय के सभी भविष्य निधि अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी	संपूर्ण केरल राज्य और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का माहे क्षेत्र

1	2
8. प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश (इंदौर) के कार्यालय के सभी भविष्य निधि अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी	संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य
9. प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र (मुंबई) के कार्यालय के सभी भविष्य निधि अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी।	सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य और गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र का गोवा क्षेत्र।
10. भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर पूर्वी प्रदेश, गोहाटी, असम के कार्यालय के सभी भविष्य निधि अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी	सम्पूर्ण असम मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड राज्य और मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र
11. प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उड़ीसा (भुवनेश्वर) के कार्यालय के सभी भविष्य निधि अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी	सम्पूर्ण उड़ीसा राज्य
12. प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब (चंडीगढ़) के कार्यालय के सभी भविष्य निधि अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी	सम्पूर्ण पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
13. प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान (जयपुर) के कार्यालय के सभी भविष्य निधि अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी	सम्पूर्ण राजस्थान राज्य
14. प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु (मद्रास) के कार्यालय के सभी भविष्य निधि अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी	सम्पूर्ण तमिलनाडु, राज्य और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के पांडिचेरी और करैकल क्षेत्र
15. प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश (कानपुर) के कार्यालय के सभी भविष्य निधि अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य
16. प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिमी बंगाल (कलकत्ता) के कार्यालय के सभी भविष्य निधि अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी	सम्पूर्ण पश्चिमी बंगाल राज्य तथा अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र।

पाद टिप्पण : पूर्वतर अधिसूचना, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 2-4-1977 में का. आ. सं. 1045 के अधीन प्रकाशित की गई थी।

श्रीमती चित्रा चोपड़ा, निदेशक

[सं. ए.-11019/1/84-एस. एस.-III]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 17th September, 1985

S.O 4651.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) and in supersession of all the existing notifications in this regard, the Central-Government hereby appoints the Officers specified in column (1) of the Table below to be Inspectors for the areas specified in the corresponding entry in column (2) thereof for the purposes of the said Act and the Scheme, the Family Pension Scheme and the Insurance Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of, the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

THE TABLE

Officers	Area
(1)	(2)
1. All the Provident Fund Officers and the Enforcement Officers of the Office of the Regional Provident Fund-Commissioner, Andhra-Pradesh. (Hyderabad)	Whole of the State of Andhra Pradesh and Yanm area of Union Territory of Pondicherry.
2. All the Provident Fund-Officers and the Enforcement Officers of the Office of the Regional Provident Fund-Commissioner, Bihar (Patna)	Whole of the State of Bihar
3. All the Provident Fund-Officers and the Enforcement Officers of the office of the Regional Provident Fund-Commissioner, Delhi.	Whole of the Union territory of Delhi.
4. All the Provident Fund-Officers and the Enforcement Officers of the Office of the Regional Provident Fund-Commissioner. Gujarat (Ahmedabad).	Whole of the State of Gujarat and the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and the Daman and Diu areas of the Union territory of Goa, Daman and Diu.

(1)	(2)
5. All the Provident Fund Officers and the Enforcement Officers of the Office of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana.	Whole of the State of Haryana.
6. All the Provident Fund Officers and the Enforcement Officers of the Office of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka (Bangalore).	Whole of the State of Karnataka.
7. All the Provident Fund Officers and the Enforcement Officers of the Office of the Regional Provident Fund Commissioner, Kerala (Trivandrum)	Whole of the State of Kerala and the Union territory of Lakshdweep and the Mahe area of the Union territory Pondicherry.
8. All the Provident Fund Officers and the Enforcement Officers of the Office of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh (Indore).	Whole of the State of Madhya Pradesh
9. All the Provident Fund Officers and the Enforcement Officers of the Office of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay)	Whole of the State of Maharashtra and the Goa, area of the Union territory of Goa, Daman and Diu.
10. All the Provident Fund Officers and the Enforcement Officers of the Office of the Provident Fund Commissioner, North Eastern Region, Gauhati, Assam	Whole of the State of Assam, Manipur, Tripura, Meghalaya, Nagaland and the Union Territory of Mizoram and Arunachal Pradesh.
11. All the Provident Fund Officers and the Enforcement Officers of the Office of the Regional Provident Fund Commissioner, Orissa (Bhubaneswar).	Whole of the State of Orissa.
12. All the Provident Fund Officers and the Enforcement Officers of the Office of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab (Chandigarh).	Whole of the State of Punjab and Himachal Pradesh and the Union Territory of Chandigarh.
13. All the Provident Funds Officers and the Enforcement Officers of the Office of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan (Jaipur).	Whole of the State of Rajasthan.
14. All the Provident Fund Officers and the Enforcement Officers of the Office of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu (Madras)	Whole of the State of Tamil Nadu and the Pondicherry and Karaikal areas of the Union territory of Pondicherry.
15. All the Provident Fund Officers and the Enforcement Officers of the Office of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh (Kanpur).	Whole of the State of Uttar Pradesh.
16. All the Provident Fund Officers and the Enforcement Officers of the Office of the Regional provident Fund Commissioner, West Bengal, (Calcutta).	Whole of the State of West Bengal and the Union territory of the Andaman and Nicobar-Islands.

Foot Note:—

Earlier Notification was published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 2-4-1977 under S.O. No. 1045.

SMT. CHITRA CHOPRA, Director

[No. A-11019/84/SS/III]

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1985

का. आ. 4652.—पहले की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए और उत्प्रवास अधिनियम 1983 (1983 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, श्रम मंत्रालय में सहायक श्री बी. एस. मानिक को 20 सितंबर 1985 से पहली अक्तूबर 1985 तक उत्प्रवासी संरक्षी, चण्डीगढ़ के सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[संख्या जैड-11025/29/85-एमिग्रेशन-2]

New Delhi, the 17th September, 1985

S.O. 4652.—In supersession of earlier notification and in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorise Shri B. S. Manik, Assistant in the Ministry of Labour to perform all functions of Protector of Emigrants, Chandigarh with effect from 20th September, 1985 to 1st October, 1985.

[No. Z-11025/29/85-Emig-II]

का. आ. 4653.—पहले की अधिसूचना के अधिक्रमण में और उत्प्रवास अधिनियम 1983 (1983 का 31) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उत्प्रवासी संरक्षी त्रिवेन्द्रम के कार्यालय में सहायक श्री आर. श्रीनिवासन को 19 सितंबर से 30 सितंबर 1985 के बजाय 23 सितंबर से 30 सितंबर 1985 तक उत्प्रवासी संरक्षी, त्रिवेन्द्रम के सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं. जैड-11025/29/85-एमिग्रेशन-2]

S.O. 4653.—In supersession of the earlier notification, and in exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises Shri R. Srinivasan, Assistant, in the Protector of Emigrants' office, Trivandrum to perform all function of Protector of Emigration, Trivandrum with effect from 23rd September to 30th September, 1985 instead of 19th September, to 30th September, 1985.

[No. Z-11025/29/85-Emig.II]

का. आ. 4654.— पहले की अधिसूचना के अधिक्रमण में और उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, उत्प्रवासी संरक्षी कोचीन के कार्यालय में सहायक श्री के. एन. एस. नायर को 20 सितंबर से 26 सितंबर 1985 के बजाए 23 सितंबर से 1 अक्तूबर 1985 तक उत्प्रवासी संरक्षी कोचीन के सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं. जैड-11025/29/85-एमीग्रेशन-2]

S.O. 4654.—In supersession of the earlier notification, and in exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises Shri K. N. S. Nair, Assistant in the office of Protector of Emigrants, Cochin to perform all functions of Protector of Emigrants, Cochin with effect from 23rd September to 1st October, 1985 instead of 20th September, to 26th September, 1985.

[No. Z-11025|29|85-Emig.II]

का. आ. 4655.—पहले की अधिसूचना के अधिक्रमण में और उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उत्प्रवासी संरक्षी, मद्रास के कार्यालय में सहायक, श्री सुन्दर लाल को 20 सितम्बर से 26 सितम्बर, 1985 के बजाय 23 सितम्बर, से 27 सितम्बर, 1985 तक उत्प्रवासी संरक्षी मद्रास के सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[संख्या जैड-11025/29/85-एमीग्रेशन-II]

S.O. 4655.—In supersession of the earlier notification, and in exercise of the powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises Shri Sunderlal, Assistant, in the office of Protector of Emigrant, Madras to perform the functions of Protector of Emigrants, Madras with effect from 23rd September to 27th September, 1983 instead of 20th September to 26th September, 1985

[No. Z-11025|29|85-Emig.II]

का. आ. 4656.—पहले की अधिसूचना के अधिक्रमण में और उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 के साथ तपठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उत्प्रवासी संरक्षी दिल्ली कार्यालय में सहायक श्री बृज मोहन को 23 सितम्बर 1985 के बजाय 25 सितम्बर, 1985 को उत्प्रवासी संरक्षी, दिल्ली के सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[संख्या जैड-11025/29/85-एमीग्रेशन-II]

S.O. 4656.—In supersession of the earlier notification, and in exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises Shri Brij Mohan, Assistant in the office of Protector of Emigrants, Delhi to perform all functions of Protector of Emigrants, Delhi on 25th September, 1985 instead of 23rd September, 1985.

[No. Z-11025|29|85-Emig. II]

का. आ. 4657.—पहले की अधिसूचना के अधिक्रमण में और उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एच. राय, जन सम्पर्क अधिकारी, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कलकत्ता को 23 सितम्बर से 25 सितम्बर, 1985 के बजाय 23 सितम्बर, से 27 सितम्बर, 1985 तक आवेदकों की उत्प्रवासी हैसियत, अर्थात् "उत्प्रवासी नहीं" के रूप में हैसियत का निर्धारण करने के लिए, उत्प्रवासी संरक्षी के सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करती है।

[संख्या जैड-11025/29/85-एमीग्रेशन-II]

अमित दास गुप्ता, अवर सचिव

S.O. 4657.—In supersession of the earlier notification, and in exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises Shri H. Roy Public Relations Officer, Regional Passport Office, Calcutta to exercise all powers of Protectors of Emigrants to decide the emigrant's status viz., status as 'Not an emigrant' of the applicant with effect from 23rd September, to 27th September, 1985 instead of 23rd September to 25th September, 1985.

[No. Z-11025/29/85-Emig-II]

AMIT DAS GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 सितंबर, 1985

का. आ. 4658.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल कोलफील्ड्स हजारीबाग क्षेत्र के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2 धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 10-9-85 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 18th September, 1985

S.O. 4658.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Central Coalfields Limited, Hazaribagh Area, and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th September, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 94 of 1982

In the matter of Industrial Disputes under Section 10 (1)(d) of the I. D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Central Coalfields Limited, Hazaribagh Area and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers.—Shri R. S. Murthy, Advocate.

On behalf of the workmen.—Shri J. P. Singh, Advocate.

State : Bihar.

Industry : Coal.

Dhanbad, the 30th August, 1985

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-24012(11)|82-D.IV(B), dated, the 3rd August, 1982.

THE SCHEDULE

"Whether the action of the management of Hazaribagh Area of C.C. Ltd., at & P. O. Chari Distt. Hazaribagh in terminating the services of S/Shri Guni Mahto (2) Bishun Karmali (3) Chedi Mahto (4) Phagu Mahto (5) Baijnath Chowdhry (6) Somaru Ram (7) Madhawa Ganjhu (8) Ram Baran Ram (9) Dhaneshwar Mistry (10) Doman Das (11) Dhanukdhari Mahto (12) Haria Manjhi (13) Chanda Munda (14) Ishmail Mian (15) Prakash Bartia (16) Deoraj Baratia (17) Budhan Chowdhry (18) Bigan Saw is jusified? If not, to what relief the workmen are entitled?"

The case of the management is that the reference is invalid, illegal and not maintainable and without jurisdiction. The concerned workman in respect of whom the industrial dispute has been raised by the sponsoring union were never the workmen of the management and they do not fall within the scope of Section 2(k) of the I.D. Act and consequently it does not satisfy the test laid down in Section 2 (k) of the I. D. Act in as much as the concerned workmen are impersonator|imposter and there was no valid relationship of employer and employee between them and the management. The reference is bad inasmuch as the Hazaribagh area of the Central Coalfields Ltd. is not a single establishment as it consists of a number of collieries and a single reference covering the various establishments is not maintainable.

The group of mines known as Kedla Jharkhand Groups were in the Zamindari of the Raja of Ramgarh. In about 1946 Raja of Ramgarh purported to grant a lease of the entire property along with other similar properties to a company formed as Bokaro Ramgarh Ltd. which was floated by Raja of Ramgarh himself. Under the Bihr Land Reforms Act, the State Government of Bihar was given the power to annul any lease or transfer created by the ex-Zamindars from the year 1946 onwards. As the transfer in favour of M/s. Bokaro Ramgarh Ltd came under the mischief of the Bihar Land Reforms Act, the Government of Bihar filed a suit in the Court of Subordinate Judge, Hazaribagh for a declaration that the lease in favour of M|s. Boaro Ramgarh Ltd was a nullity and that the actual underground rights not passed to the said Company. A Receiver was appointed in the said suit by the Subordinate Judge and the State of Bihar was made a Receiver. The State Givernment deputed a senior Officer to administer those properties on behalf of the Court. Since the time of M|s. Bokaro Ramgarh Ltd. the mining property was divided into small blocks and given to different persons called as Raising-cum-Selling contractors who were practically the owners of the mines in the blocks in their possession. They were only liable to pay the amount of the royalty to the Receiver for coal transported by trucks. The receiver opend an office and a check post in Kedla Jharkhand Mining Area for realisation of the royalty. The Raising-cum-Selling contractors who were given the blocks of the mines were mostly not maintaining any record and even if they had maintained any record it was not genuine. The mines were all seasonal and were open cast mines/quarries which used to be closed down with the start of the rainy season due to its flooding. After the rains those mines used to be reopened in the month of October and November. Most of the labourers who were engaged by the contractors-cum-Selling Agents were not made members of the C.M.P.F. The Central Govt. by an ordinance took over the management of the Coking Coal Mines with effect from 17-10-71. Kedla Jharkhand Group of Mines was being considered till then as non coking coal mines. The Coal Board by an appropriate notification declared Kedla Jharkhand Group of Collieries as Coking Coal Mines with effect from 19-12-72 although the Coking Coal Mines Act 1972 had come into force with effect from 1-5-72. As soon as these mines were declared to be coking coal mines the management passed on to the Central Government and the National Coal Development Corporation (NCDC) which was a public sector Co. was directed to take over these mines on behalf of the Central Govt. The said NCDC Ltd. has since been renamed as Central Coalfields Ltd. with effect from 1-11-75. The Raising Contractors moved the Court of Subordinate Judge Hazaribagh for an injunction and their prayer was allowed. The said order of injunction was upheld by the Hon'ble Patna High Court. The NCDC Ltd. and the Central Govt. moved against the said order in the Supreme Court. The Hon'ble Supreme Court ordered the mines to be closed pending hearing of the application and the mines stopped working from June, 1973. Thereafter the NCDC Ltd. was ordered by the Spureme Court by the order dated 20-8-73 to run the mine as there was a strong resentment amongst the workers who were working earlier in these mines neither the Receiver nor the contractors handed over their documents to enable NCDC to start mines. Subsequently the Supreme Court by the order dated 22-8-73 directed the receiver to make over all its documents and the documents of the contractors and NCDC was directed to keep a seperate account for these mines in view of the fact that the question as to whether the mines had vested or not under the Nationalisation Act was pending. Thereafter the Receiver made over some documents after collecting it from the contractors which were found to have been fabricated. The contractors and unscrupulous officers had entered the names of thousands of persons who were not employed in such mines in the documents and a serious law and order problems arose in view of the fact that about 30 thousand persons claimed that they had been working in Kedla Jharkhand Mines. It was an uphill task for the law and order authorities to maintain peace in the area and as such armed police were posted under the command of the Magistrate.

Two unions of workmen were operating in Kedla Jharkhand Mines Area. One was colliery Mazdoor Sangh which was subsequently renamed as RCMS and the other colliery was the coal workers union which was later on renamed as the United Coal Workers Union. The management after discussing with the representatives of the above two unions evolved a procedure to select the genuine workers. About 6 thousand persons were found to be genuine and after an agreement all the workmen were given employment. Later on another 23,00 were selected for seasonal employment on the basis of scrutiny by screening committee in respect of those who had filed appeals. Out of these 23 00 about 2100 persons actually joined in April, May, 1974 and employment was to be provided to them only during the dry season. RCMS subsequently demanded that these 2100 persons should be provided employment on permanent basis. By an agreement the demand was referred to joint arbitration of S/Shri J. G. Kumarmangalam the then Chairman, C.M.A. Ltd. and Shri Bindeswari Dubey the then Health Minister of Bihar and respected labour leader. They gave an award by which 2050 persons were found fit for permanent employment and thus the dispute was finally resolved regarding the employment of worker in the Kedla Jharkhand Group of Collieries. Subsequently it transpired that a large number of spurious persons entered in the service of Kedla Jharkhand Group of Collieres instead of the genuinne persons who were selected for employment for the seasonal employment. The management therefore appointed a committee of officers including Finger Print expert to make enquiries. As a result of such enquiry it was found that all the 18 concerned workmen covered by the present reference were impersonators|imposters. They started working in the place of genuine workers either because the genuine persons had died or left their job or were terrorised or driven away or they sold their jobs to the impersonators| imposters. In the initial state there was no system of identity card and subsequently even the impersonators who were working received identity cards. During the course of enquiry held by the committee of officers it was found that the real persons were not working in Kedla Jharhand Group of Mines and the concerned wormen were imperosonators. The persons actually working were not found to be those who were actually appointed and for whom the appointment letters were issued. The management verified the thumb mars of the concerned workmen on the

records available with the management and verified it with the L.T.I. of the concerned workmen who were working in the mines. The concerned workmen had never at any time in the past prior to the take over of the mines had worked in the mines. Some persons had submitted photographs at the time of filling of their appeals which were found to be different from those who were actually working. The concerned workmen sarted working as a result of mal practices among the lower level staff in the coal mines. The concerned workmen indulged in fraud and dishonesty and managed to work in the different collieries of the management for sometime in a collisive and fradulent manner. They cannot therefore become genuine workers of the management and there can be no valid relationship of employer and employee between them and the management. Such persons cannot be covered under the definition of workmen under Section 2s of the I.D. Act or the provisions of Model Standing Orders. The concerned workmen being impersonators cannot be allowed to take advantage of the Standing Orders which are applicable to the real and genuine workmen. As such there was no need or legal requirement for giving such persons any notice of termination of their employment or discontinuance of their employment when the act of their impersonation came to the notice of the management. When the fact of impersonation of the concerned workmen came to the notice of the management, their employment was discontinued by due intimation to them from the date as indicated in Annexure A of the WS of the management. There was no requirement of show cause notice being given to or any domestic enquiry being held in respect of impersonators who had managed to enter the services of the management. On the above facts it has been submitte don behalf of the management that the management was justified in terminating the services of the concerned workmen.

The case of the workmen is that all the concerned workmen had become permanent employees by virtue of their length and continuity of service. They had been enjoying all the benefits of such employment. The concerned workmen were governed by the Model Standing Orders and all the statutory provisions applicable to such workmen. The management terminated the services of the concerned workmen with effect from different dates declaring them as impersonators on the basis of a report of so called committee unilaterally constituted by the management. It was neither properly constituted nor it constitution was based on any specific statutory provision of law empowering the management for constituting such a committee. The said committee acted maliciously violating the principles of natural justice of the proceedings of enquiry. The enquiry by the said committee was closed door enquiry in which some of the concerned workmen were not even asked to attend. In case of those workmen who attended the proceeding of enquiry, they were provided neither sufficient opportunity to defend themselves nor their statement were recorded properly. On the contrary the workmen were threatened and forced to sign a previously prepared statement by the management. The management had got the case of impersonation examined by its own private agency and as such the decision taken by the management based on the record of the aforesaid committee has no validity in the eye of law.

Sl. No. 1 of the order of reference Shri Guni Mahato is a genuine workman. In the appointment letter the word "Giri Mahto" was wrongly typed and on the mistake pointed out by Guni Mahato it was duly corrected by the issuing atuhority in the appointment letter at the time when the appointment letter was handed over to Guni Mahato. He was never asked to appear before the so called enquiry committee. Shri Bishun Karmali who is Sl. No. 2 of the order of reference is the son of Shri Deputy Karamali. He had submitted his application for employment without any photograph. Some other person of the same name had applied with photograph and as such there was bound to be difference with the application and photograph of the concerned workman. There was another claimant Shri Bishun Karmali son of Deo Charan Karmali and he had made an affidavit to the effect that he was claiming against the genuine workman Shri Bishun Karmali son of Deputy Karmali on being instigated and persuated by some vested persons. Thus there is no other claimant against the genuine workmen whose services have been terminated with effect from 16-9-80 Sl. No. 3 of the schedule of reference is Chhedi Mahto and there was a typhographical mistake in his name which has been corrected by the Ministry. He is a genuine workman and his termination with effect from 4-2-81 is unjustified. He was previously appointed at Kedla North and later on transferred to Kedla underground project. There is no other person of his name at Ichakdih who stands as claimant to his post. Sl. No. 4 is Shri Fagu Mahto who is a genuine workman. The filing of appeal was not a necessary criteria for securing employment and he had not filed any appeal but he was found to be the person who had worked during the erstwhile management. There was no other claimant in his name and the termination of his services is unjustified. Sl. No. 5 is Shri Baijnath Choudhury is genuine workman who had not filed any appeal. He was an old employee. His appointment letter was taken by one of his relative on his behalf, in his absence and the same was handed over to him when he returned from his village home and thereafter he had joined his services with the permission and knowledge of the authorities. Sl. No. 6 Sri Somaru Ram is a genuine workman and there is a typographical mistake in his name in the schedule of reference as Somaru Oraon. Somaru Ram is a genuine workman and he had not tampered with letter of appointment. The correction of the appointment letter was made by the management. There is a typographical mistake in the name of Madhaw Ganju in the schedule of reference and the mistake had been corrected by a corrigendum. After the close of the colliery he was residing at his village home. When he came to know that old employees are being employed he reported to the management and got his appointment letter. Sl. No. 8 of the order of reference is Shri Ram Baran Ram who is a genuine workman. The said Rambaran Ram is son of Ramlal Ram and had been working in the colliery since the time of the contractor. The management made an error by tagging the appeal of one Shri Ram Sharan Ram and wrongly terminated his services on the ground that he is a fake person. Sl. No. 9 is Dhaneswar Mistry who is a genuine workman. He had not filed any appeal. The particulars entered in his apointment letter were correct and there was no other claimant of the same name and address. Sl. No. 10 is Shri Doman Das who is a genuine workman. The management has made an error by taking appeal of another person with the genuine Doman Das. He had not filed any appeal as filling of appeal was not a necessary criteria for securing employment. Sl. No. 11 is Dhanukdhari Mahto who is a genuine workman and he was working since the time of erstwhile employer. The erstwhile employer used to take services by frequently changing the names of the same person in order to deprive them of various benefits. There is another person claiming to be Dhaneswar Mahato who is not genuine person and his brother one Dhanukdhari Thakur who is dead and used to work in Tapin Block No. 44. The present claimant is Dhaneswar Thakur. Sl. No. 12 of the order of reference is Haria Manjhi. His name in the schedule has been corrected by corrigendum. He was a genuine workman. There is no other claimant of his name and address. He had not filed any appeal for securing employment. Sl. No. 13 in the order of reference is Shri Chanda Munda and is a genuine workman. The enquiry conducted by so called committee was unfair as he was not an impersonator and had not tempered with the appointment letter. Sl. No. 14 in the order of reference is Ismail Mian who is a genuine workman. The particulars in his appointment letter are correct. The other Ismail Mian is a different man with different particulars and different photograph. The appointment letter was issued in the name of the concerned workman. Sl. No. 15 of the order of reference is Prakash Bartia. There was a typographical mistake in the schedule which has how been corrected by the corrigendum. He is a genuine workman. He is an Oriya Labourer who previously used to work under a Sirdar. The said Sirdar had filed an application as Prakash Baratia with a different photograph. As soon as the matter came to the knowledge of the concerned workman he appeared in person before the authority concerned and secured letter of appointment himself. He did not impersonate any person. Sl. No. 16 of the order of reference is Deoraj Baratia who is a genuine workman. He is also an oriya labourer and used to work under a Sirdar. The said Sirdar had filed an application as Debraj Baratia with a different photograph. As soon as Debraj Baratia came to know the fact he appeared before the concerned authority and obtained his appointment letter. He being an oriya does not

understand Hindi. The committee had given a prepared statement on which he was asked to sign. Sl. No. 17 is Shri Budhan Choudhary who is a genuine workman. He did not tamper with appointment letter and had not indulged in any fraud. Sl. No. 18 is Shri Bigan Saw who is a genuine workman. He had not filed any appeal as the same was not a necessary criteria. The particulars entered in the appointment letter of Shri Bigan Saw are correct and was meant for the concerned workman. On the above facts it is submitted that the action of the management in terminating the services of the concerned workmen is not justified and that all the concerned workmen are entitled for reinstatement with full back wages and other benefits from the date of the stoppage of their service.

The points for determination are whether: (1) the concerned workmen are workmen of the management as defined under Section 2(s) of the I.D. Act, (2) whether the termination of the services of the concerned workman was justified.

The management have examined by witness and the workmen have examined 10 witnesses in support of their respective cases. Besides that the management have exhibited a large number of documents which have been marked Ext. M-1 to M-131 and the workmen have exhibited documents which are marked Ext. W-1 to W-17.

Admittedly, all the concerned workmen referred to in the schedule of order of reference were in the employment of the management. The management has produced the appointment letters of all the concerned workmen and are marked Exts. M-4/2 to M-4/17. The management has also produced the office copies of the letters relating to the discontinuance of the employment of the concerned workmen which are marked Ext. M-1 to M-1/17. The management has also given in annexure A of their W.S. the date of discontinuance of employment of all the concerned workmen. It is the admitted case of the parties that all the concerned workmen had worked for about 5 to 6 years when the management stopped their work. The case of the concerned workmen is that they were in employment even prior to the takeover of the mine and that as the mines had stopped working, their work had been stopped and that when the Mining Operations started they were given employment after screening about their genuinness and appointment letters were given to them on the basis of which they joined in Kedla Jharkhand Group of Collieries. Thus it will appear clear that all the concerned workmen were working for the management continuously for about 5 years since they got appointment letters and they had become permanent as they had completed more than 240 days of attendance in all the previous years. The case of the management is that the concerned workmen were not their "workmen" in the true sense of the definition of Section 2 (s) of the I.D. Act. It is stated that the concerned workmen were impersonators/imposters/working in false names and as such there was no relationship of employer and employee between them and the management and that such impersonators could not be brought within the definition of workman. Section 2(s) defines "workmen" which means any person employed in any industry to do any skilled or unskilled manual work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied, and for the purpose of any proceeding under this Act in relation to an industrial dispute, includes any such person who has been dismissed ,dis-charged or retrenched in connection with, or as a consequence of, that dispute or whose dismissal, discharge or retrenchment has led to that dispute and the section further provides some exceptions which do not include the persons covered by those exceptions with which we are not concerned. The essential condition of a person being a workman within the terms of definition is that he should be employed to do the work in that industry and that there should, an employment of his by the employer and that there should be relationship between the employers and him as between employer and employees or master and servant. The appointment letters will show that there was a contract of service between the concerned workmen and the management in which the concerned workmen rendered service for which they had bee engaged by the management and the later agreed to pay them their wages as agreed between them. It is clear, therefore, that the concerned workmen were employed to do the work in the coal industry and there was relationship of employer and employee between the concerned workmen and the management. As there was relationship of employer and employee between the concerned workmen and the management, the concerned workmen were "Workmen" under Section 2(s) of the I. D. Act.

It is submitted on behalf of the management that the concerned workmen were impersonators working in fake names of others and as such they cannot be workmen of the management. A person may be fake or genuine while working for the industry. The test to judge whether a person is a workman is not whether he is a genuine or a fake person but whether the said person was employed in the industry and he had relationship as that of employer and employee or master and servant. On the admitted facts it is clear that the concerned workmen were admittedly working in Coal Industry of the management and there was relationship of employer and employee between the concerned workmen and the management and as such the management cannot say that the concerned workmen are not their workmen.

In the above view of the matter I hold that the concerned workmen are workmen as defined under Section 2(s) of the I. D. Act.

Now we take up the point whether the termination of the services of the concerned workmen was justified. The specific case of the management is set out in para 14 to 19 of the WS. It will appear from the facts stated in the W.S. that when it transpired to the management that the concerned workmen were impersonators/imposters who had started working in place of genuine workers either because the later had died or left their job or were terrorised or driven away or they sold their jobs to the impersonators. The management set up a committee of officers to enquire whether the concerned workmen and some other persons were genuine persons working in Kedla Jharkhand Group of Mines and the said committee found that the persons actually working were not the persons actiually appointed and for whom the appointment letters were issued. Thereafter the management finding the concerned workmen indulging in fraud and dishonesty and managing to work in the different collieries of the management in a collusive and fradulent manners were stopped work. It is further stated that such impersonators cannot be permitted to take advantage of the Standing Orders which are applicable to the real and genuine workers and as such there was no legal requirement or need for giving such persons the notice of termination of their employment or discontinuance of their employment when the act of impersonation came to the notice of the management. MW-1 has stated that only two complaints have been filed stating that fake persons were working in their name and that no other complaint had been made. MW-2 Shri P. N. Lal who had assisted the committee of officers making an enquiry whether the concerned workmen were imperosonators have stated that the impersonators came in employment in place of dead persons and also by threatening the workmen to leave their employment. He has further stated that the committee did not issue chargesheet to the concerned workmen and the system was to discontinue employment of persons who were identified to be impersonators. In cross-examination he has stated that no case was lodged before the Police regarding the impersonation and he did not remember if the cases of impersonation were referred for verification by the police. In the end he has stated that he did not remember the names of dead persons and the persons who were threatened to leave the jobs in whose place the impersonators started working. On perusal of the entire oral evidence adduced on behalf of the management, it will appear that no evidence has been adduced to show as to who were the persons dead in whose places any of the concerned workmen were working or that who were the persons who were threatended by the concerned workmen and that they started working in the name of the threatened persons. Thus this case of the management in the W.S. that the concerned workmen were either working in place of dead persons or were working in the place of persons who were threatened to leave the job had not at all been established. MW-3 is a Personnel Manager who was a member of the committee set up in 1977 to verify the case of impersonation in Hazaribagh Area. He has stated that the committee recorded the statement of the impersonators and in some cases their witness were also examined. Now let us see what type of enquiry had been

made on whose findings the work of the concerned workmen was stopped declaring them as impersonators. MW-3 has stated that the committee which was appointed by the management had no representative of the union in the said committee. Area Officers used to give list of the alleged impersonators before the committee and that the said committee had examined the case of about 7 to 8 hundred alleged impersonators. The sitting of the committee used to be held at different places in Jharkhand Group of Collieries. The committee had not sent any notice to any of the the alleged impersonators or their witness. The enquiry had continued for more than a year. 350 cases were found to be of impersonators by the committee. The area management used to send the concerned persons for their statement before the committee and they were called one by one and their statement were recorded. There was no co-worker to assist the alleged impersonator in the committee. MW-3 has stated that he was not aware if there was any rule or circular for dealing with the case of impersonators: It will appear from the evidence of MW-3 that the enquiry by the Officers was not a domestic enquiry as comtemplated under the Model Standing Order which is applicable in that industry in respect of misconduct of a workman. The alleged act of impersonation is an act of misconduct which is covered under Section 17(o) of the Model Standing Orders for industrial establishment in coal mines for which disciplinary action for misconduct has to be taken. As admitted in the W.S. of the management it will appear that the management did not think it necessary to hold any domestic enquiry against the charge of misconduct against the concerned workmen on the plea that when the Act of impersonation of the concerned workmen came to the notice of the management the services of the concerned workmen were stopped. When the concerned workmen were permanent workmen their services could not have been terminated for misconduct without holding proper enquiry and adhering to principles of natural justice. The management had, no doubt, set up a committee to verify about the impresonation which cannot at all be said to be a domestic enquiry giving the concerned workmen opportunity to defend themselves. The management was also aware of the fact that the committee which had declared the concerned workmen as impersonators was not the finding of a domestic enquiry as comtemplated under the Model Standing Orders because it will appear from the stand of the management that there was no necessity of any domestic enquiry or submitting any charge against the concerned workmen when the management came to know that the concerned workmen were impersonators. This is just putting the Cart before the horse. The said conclusion that the concerned workmen were impersonator could have been arrived at only after framing proper charge against the concerned workmen and holding proper enquiry into it. But instead of doing that the management almost behind the back of the concerned workmen got the findings from the committee that the concerned workmen were impersonators and stopped them from work. The discussion made above will show that no notice was given to the concerned workmen to explain whether they were impersonators or not and that the management had not framed any charge of misconduct against the concerned workmen for impersonation and even without holding any proper enquiry the services of the concerned workmen were stopped/terminated.

It has been contended before me on behalf of the concerned workmen that the termination of services of the concerned workmen was nothing but "Retrenchment" within the meaning of Section 2(oo) of the I. D. Act as admittedly no retrenchment compensation as envisaged by Section 25-F of the Act was paid to them by the management and as such the order of stoppage/termination should be set aside and the concerned workmen should be reinstated in services with full back wages and other benefits. Thus the main question which is involved in this reference is whether the termination of the services of the concerned workmen is tantamount to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the I. D. Act. "Retrenchment" means the termination by the employer of the services of a workman for any reason whatsoever otherwise than a punishment inflicted by *way of disciplinary action but does not include:* (a) Voluntary retirement of the workman, or (b) retirement of the workman on reaching the age of superannuation.....or (c) termination of the services of a workman on the ground of continued ill health. The word "Otherwise than as punishment inflicted by way of disciplinary action" under Section 2(oo) of the Act is significant. Section 2(oo) will come into place if the termination of the services of the concerned workmen is not as a punishment by way of disciplinary action which means that disciplinary action has been taken against a workman and have been found guilty and as a result thereof he has been dismissed by way of punishment. There is a procedure for taking disciplinary action in which the punishment can be inflicted. There is no doubt that if the order of termination of a workman was made as punishment by/or a disciplinary action, it will not be retrenchment within the meaning of Section 2(oo) but the question in this case is whether the termination of the services of the concerned workmen was really dismissal from service as a punishment by way of a disciplinary action. Admittedly no enquiry was held by the management against the concerned workmen for the alleged misconduct. They were not served with any notice to show cause, why their services should not be terminated on the ground of misconduct. There is no order of any domestic enquiry to show that the termination of the services of the concerned workmen was to be made by way of punishment. What the management did was that it had made some preliminary exparte enquiry by the officers of the management to see if the concerned workmen were impersonators. This type of enquiry made on behalf of the management was just a fact finding enquiry and the management on its basis could have framed charge and started disciplinary proceeding. The concerned workmen were not present in the said committee set up by the management and they were not given any chance to test the truth or correctness of what was being said in the enquiry as they were not given opportunity to cross-examine any of the persons giving statement before the committee nor they were given any opportunity to adduce their own evidence in support of the fact that they were genuine persons. The said alleged enquiry proceeding was not at all a disciplinary proceeding or a domestic enquiry against the concerned workmen and as such the action taken on its basis cannot be said to be a disciplinary action and the punishment inflicted on its basis cannot be a punishment inflicted by way of disciplinary action. Accordingly the management cannot bring the case of the concerned workmen within the exception of Section 2(oo) of the Act in which the termination of the services may not be retrenchment. The language of Section 2(oo) is very wide and very clear. Except in 4 cases mentioned in Section 2(oo) including the case of termination of services of a workman as punishment inflicted by way of disciplinary action. the termination of the services of a workman for any reason whatsoever tantamounts to retrenchment. The point has been very clearly elucidated in decision of their Lordships of the Supreme Court in 1976-LIC-769 The State Bank of India Vrs. Sundramani and 1976 LIC Page 1766 (Hindusthan Steel Ltd. Vrs. Labour Court Orissa).

It has been submitted on behalf of the management that in fact no disciplinary proceeding was gone into the allegation of misconduct of impersonation by the concerned workmen but the management have adduced evidence to establish the said charge against the concerned workmen and the Industrial Tribunal is competent to decide the said act of misconduct committed by the concerned workmen. We are aware of the principles of law that if it is held by the Tribunal that any domestic enquiry was not fair and proper or that no enquiry had been made in connection with the misconduct leading to the termination of the services of a workman, the Tribunal can go into the evidence afresh before it for the purpose of deciding whether the termination of the services of a workman on the allegation of misconduct was just and proper. In such cases the management has to make a prayer before the Tribunal that the management should be given a chance to establish the allegation by adducing evidence before the Tribunal but that is not the case in the present reference. The management has come with a definite case in their W.S. that such impersonators cannot be permitted to take advantage of the Standing Orders which are applicable to the real and genuine workmen and that in this view of the matter there was no legal requirement and need for giving such persons the notice of termination of their employment or discontinuance of their employment, when the act of impersonation came to the notice of the management. In para 24 of the W.S. it is stated by the management that there is no requirement of show cause notice being given for any domestic enquiry being held in respect of impersonators who have managed to enter into the services of the employer and that the employers are entitled to discontinue their employment when they discovered the fact. Thus the management stands on a definite footing that

in case of impersonator the management has not to go into the disciplinary proceeding and neither any prayer was made in the W.S. nor any petition has been filed that he management should be allowed to adduce evidence before the Tribunal to establish the misconduct alleged against the concerned workmen. In view of the definite stand taken by the management there is no scope for giving any chance to the management to adduce further evidence before this Tribunal to establish the charge that the concerned workmen were impersonators, although in fact the management has adduced evidence to establish that the concerned workmen were impersonators. The management cannot now be allowed to make out a new case that the order of termination of the concerned workmen was passed by way of punishment in as much as no domestic enquiry had been held against the concerned workmen making allegations in any charge and in which the punishment for termination of their services was passed. The evidence which has been produced on behalf of the management to establish the allegations of impersonation before this Tribunal cannot therefore be considered.

As however the management has adduced evidence to establish that the concerned workmen had impersonated I would like to just discuss the said evidence in brief :—MW-1 Shri Sahadeo Ram is working as a Senior Clerk of the management and he along with PW-2 Shri P. N. Lal had assisted the committee set up by the management to verify whether the concerned workmen and other were impersonators. In his cross-examination he has stated that the provision of Model Standing Orders are in force in case of termination of services of the workmen. But it appears that the provisions of the Model Standing Orders have not been complied with in respect of the termination of the concerned workmen. MW-1 and MW-2 are not the competent witnesses to show whether any of the concerned workmen were impersonators. MW-1 has further tried to show that he knew some of the concerned workmen but it appears that there was no occasion for him to identify any of the concerned workmen as he had always worked in the Area Office after the take over of the mine by CCL. MW-3 is Shri V. P. Kapoor, Personnel Manager one of the members appointed by the management to verify the case of the impersonation in Hazaribagh area. I have already discussed his evidence regarding the method adopted by them for coming with the conclusion about the impersonation. He himself did not know any of the concerned workmen personally and had not personal knowledge that any of the concerned workmen were impersonators. MW-4 Shri Abraham Ideculla is a Senior P.A. who is a formal witness and he does not say anything about the fact that the concerned workmen were impersonators. MW-5 is a Finger Print Expert and his opinion on finger print is stated in his report. He does not know any of the concerned workmen personally. He had received the file for comparison of LTI's o n23-3-83 when this Tribunal had already started taking evidence in this case and there was no order from the Tribunal that the LTIs be compared by a Private Finger Print Expert. MW-8 Shri M. Lal Security Inspector, MW-10 Shri C. Ram Senior, Personnel Officer, MW-11 Shri R. B. Singh, Dy. P. M., MW-12 Dr. C. A. Satpathy, MW-13 Shri K. P. Singh, Administrative Officer and MW-14 Shri V. S. Prasad Labour Welfare Officer are all persons who were sent by the management to make enquiries about some of the concerned workmen. They did not know the concerned workmen personally and they themselves have not stated that the concerned workmen are impersonators. What they did is that they had visited places to enquire about the different concerned workmen and had taken the statement of some persons indicating that the concerned workmen were not genuine. They had recorded the statement of the persons in the villages but the persons whose statements they had recorded have not been examined before me and have not come forward to support what is stated in the statement taken by these officers. The statements of persons taken by these officers cannot therefore be a substantive piece of evidence to be used against the concerned workmen. It is the cardinal principle of natural justice that the person against whom such a statement have been taken behind his back must get a chance to test the veracity of such a statement which has been taken behind his back. As those persons who had given the statement before those officers have not come forward in support of the facts recorded in the statement. I hold that the said statements cannot be used against the concerned workmen.

MW-6 Shadeo Singh is a Mukhiya of Charhi Gram Panchayat. He has stated that the photographs on Ext. M-3/6 is of Maluka Mistry father of Dhaneswar Mistry and has stated that the said Maluka Mistry used to work in Kedla Colliery. In his cross-examination he has stated that Dhaneswar Mistry did not work in Kedla Colliery and that Maluka Mistry used to work in place of Dhaneswar Mistry. He has further stated that the employment was in the name of Dhaneswar Mistry and that Dhaneswar Mistry should have worked in the colliery. Dhaneswar Mistry has examined himself as WW-10 and has stated that he was working in Kedla South previously under the contractor in 20 No. Quarry. He has stated that he was not given employment in the first lot and was given employment in 1974 and got his appointment letter and since then he is regularly working for about 7 years in Kedla underground project. He has also filed certificate issued to him by the same Mukhiya, MW-6 Sahadeo Singh and it is also signed by the BDO and the said certificate is Ext. W-17 in this case. He has stated that his name is Dhaneswar Mistry allias Malu and that Ext. M-3/6 contains his photograph. On perusal of Ext. W-17 it will appear that both Sahadeo Singh Mukhiya, Charhi Gram Panchayat and the BDO had granted the certificate and have attested his photograph identifying him as Dhaneswar Mistry son of Ledu Mistry. The appointment letter Ext. M-4/13 is in the name of Dhaneswar Mistry son of Ledu Mistry. The evidence of MW-6 that Dhaneswar is the son of Maluka Mistry does not appear to be correct and the concerned workman Dhaneswar Mistry is the son of Ledu Mistry. The above facts in evidence do not establish that the concerned workman Dhaneswar Mistry is a fake person.

MW-6 who is the Mukhiya, Charhi Gram Panchayat has identified the photos marked with letter "K" and letter "L" on Ext. M-3/2 and has stated that the photo marked with letter "K" is of Budhan Thakur and the photograph marked with letter "L" is of Dhanukdhari Thakur. According to him Budhan Thakur and Dhanukdhari Thakur are cousins and reside in village Jarba. He has further stated that Budhan Thakur has impersonated Dhanukdhari Thakur and working by representing himself as Dhanukdhari Mahto in Kedla Colliery. The appointment letter Ext. M-4/17 is in the name of Dhanukdhari Mahto son of Nakul Mahato village Jarba. Ext. M-8/1 is the appeal filed by Dhanukdhari Mahto son of Nakul Mahto of village Jarba. The claimant Dhanukdhari Thakur has examined himself as MW-7 and has stated that the appointment letter was taken by his cousin Budhan Thakur and that Budhan Thakur started working in his name. Admittedly, he had not worked in the colliery after its take over. He has stated that there is dispute between him and Budhan Thakur regarding their appointment in the colliery. The appointment letter and the appeal will show that one Dhanukdhari Mahto son of Nakul Mahto had filed an appeal and was given the appointment letter. Admittedly the concerned workman Dhanukdhari Mahto was working in the colliery. The claimant Dhanukdhari Thakur has described himself as son of Nakul Thakur whereas the concerned workman Dhanukdhari Mahato has described himself as Dhanukdhari Thakur Mahato son of Nakul Mahato. WW-8 Smt. Ramanika Gupta who had sponsored the industrial dispute has stated that the concerned workman Dhanukdhari Mahato son of Nakul Mahato, village Jarba is working since the time of the contractor in the said name and that his real name is Budhan Thakur. She has further stated that there is no man named Dhanukdhari Mahato son of Nakul Mahato in village Jarba. She has further stated that one Dhaneswar Thakur claiming appointment that he is Dhanukdhari Thakur is named Dhaneswar Thakur and that his elder brother was named Dhanukdhari Thakur. She has stated that such claimaint Dhanukdhari Thakur was not the concerned workman who was actually working in the colliery. There is dispute for employment between the concerned workman and Dhanukdhari Thakur and there is no evidence on behalf of the management that the said claimant Dhanukdhari Thakur had ever worked in the mine. It appears that the management has not been able to establish that the concerned workman Dhanukdhari Mahato is an impersonator for there is postive evidence that he was a person who was working since the erstwhile management.

The management very much stressed on the identification on the basis of the L.T.I. on the appeals. It is stated on behalf of the workmen that all the persons who had got employment had not necessarily filed the appeals. WW-8 has stated that some of the workmen had filed claim petition while other did not file any claim petition and that the appointment were first made on the basis of the records received from some of the contractors, mines department, C.M.P.F. and union. She has further stated that the screening committee consisted of those persons who are staff of the old contractors—the Receiver and they had committed mistake and irregularity by typing the name and address wrongly. She has stated that the genuineness of the workmen were verified at the time of handing over the appointment letters to them and that identity card had been issued by the management to all of them. WW-8 has stated that here was an agreement between her and the then Director (P) but the said agreement was not accepted by the management and thereafter she went to the then Chairman, CIL and thereafter the management agreed that the workmen should file appeals for consideration of their appointment to which the CPI and other union did not agree. She has further stated that she got some appeal forms printed and appeals filed by the workmen. Thereafter the management arranged for screening the workmen who had filed the appeals or otherwise and also the persons whose names were included in the list submitted by her. It will thus appear that the appointment letters were issued not only on the basis of appeals filed but also on consideration of other lists. As such there were some of the concerned workmen who had not filed appeals and there can be no comparison of their thumb mark with the thumb mark on the appeals. It is stated by the workmen that the appeals of other persons have been taken into consideration for comparing their LTI. The workmen have examined the concerned workmen WW-1 Baijnath Chowdhry, WW-2 Guni Mahto, WW-3 Deorai Baratia, WW-4 Prakash Bhartia, WW-5 Rambaran Ram, WW-6 Ismail Mia, WW-7 Somaru Ram and WW-10 Dhaneswar Mistry to show that they are the real persons who were working with the management and they had also worked prior to the takeover. The management has not produced evidence to completely dislodge their assertion. Accordingly it has to be held that the management has not been able to establish that the concerned workmen are impersonators or imposters.

It has been submitted on behalf of the management that the concerned workmen are not the members of the union which has sponsored the dispute. On this point WW-8 Smt. Ramanika Gupta who had sponsored their industrial dispute has stated that all the 18 concerned workmen were members of her union when she had raised the dispute on their behalf. She has further stated that some of them were formerly members of CPIM and as such they had not filed the appeal forms but subsequently they became members of her union. It is evident from the management's record that Smt. Ramanika Gupta was representing the workmen before the management and her union was working in Kedla Jharkhand Collieries. She has also clearly stated that the concerned workmen were members of her union. There is no reason to disbelieve her evidence because she was representing the case of the concerned workmen since the industrial dispute was raised before the ALC(C), Hazaribagh. If the concerned workmen were not the members of her union she would not have raised a dispute on their behalf and there was nothing to prevent her from enrolling the concerned workmen as members of her union. Taking all the above facts into consideration, I hold that the concerned workmen were the members of Coalfield Labour Union and that the said union was working in Kedla Jharkhand Group of Collieries.

It has been submitted on behalf of the workmen that they do not persue the case of Sl. No 2 Bishun Karmali Sl. No. 3 Chhedi Mahto, and Sl. No. 17 Budhan Chowdhry in the schedule of the order of reference. It has been submitted on behalf of the management that Bishun Karmali, Chhedi Mahto have got employment in the colliery of the management on the ground that they are dependents/owners of the land acquired by the management. So far Sl. No. 17 is concerned it has been submitted in course of argument on behalf of the workmen that Budhan Chowdhry is not the right person and as such his case was not being persued. WW-8 has also stated in her evidence that she does not persue the case of Bishun Karmali and Chhedi Mahto as they have already got employment from the management. She has not given any specific reason as to why she was not persuing the case of Budhan Chowdhry but the same has been submitted at the time of argument. Accordingly, this reference will not cover the case of Sl. No. 2, 3 and 17 of the schedule of the order of reference and this reference will govern the remaining 15 concerned workmen.

In the result, I hold that the action of the management of Hazaribagh Area of CCL in terminating the services of the concerned 15 workmen is not justified and as such the said concerned workmen will be deemed to be continuing in the services and are entitled to all the back wages and other consequential benefits since the date of stoppage of their work.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-24012(11)/82-D.IV (B)]

का. आ. 4659.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार व तलचर कोलियरी मैसर्ज सैण्ट्रल कोलफील्ड्स लि., डाक डेरा कोलियरी जिला धनकनाल (उड़ीसा) के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण भुवनेश्वर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-9-85 को प्राप्त हुआ था।

S.O.4659.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Govenment Industrial Tribunal, (Orissa), Bhubaneswar, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Talcher Colliery of M/s. Central Coalfields Limited, P.O. Dera Colliery Distt. Dhenkanal (Orissa), and their workman, which was received by the Central Government on the 12th September, 1985.

ANNEXURE

INDUSTRIAL TRIBUNAL, ORISSA, BHUBANESWAR.

nal Bhubaneswar.

Industrial Dispute Case No. 1 of 1981 (Central)

Dated Bhubaneswar, the 28th August, 1985

BETWEEN

The employers in relation to the management of Talcher Colliery of Central Coalfields Ltd., Post Office Dera Colliery, District Dhenkanal (Orissa).—First-party;

AND

Their workmen.

APPEARANCES:

None for the-first-party.

None for the—second-party.

AWARD

Dispute referred to by the Central Government for adjudication under Clause (d) of Sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, vide Notification No. L-24012(1)/80. D. IV (B) dated 26-8-1980 of the Ministry of Labour, reads thus:

"Whether the action of the management of Talcher Colliery of Central Coalfields Limited, Post Office Dera Colliery, District Dhenkanal (Orissa) in dismissing Shri Gokul Chandra Das, Senior Cashier at Talcher Colliery with effect from the 15th December, 1979 was legal and justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. Both the parties remained absent on the date of hearing and did not take any steps on that date despite service of notices on them by registered post. I am, therefore, inclined to think that there exists no dispute between the parties now to be adjudicated by this Tribunal. Hence I pass this no-dispute Award.

K.C. RATH, Presiding Officer

[No. L-24012 (1)/80-D. IV (B)]

R. K. GUPTA, Desk Officer

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1985

का॰आ॰ 4660.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰, नार्थ बदजना कोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं॰ 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-9-1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 18th September, 1985

S.O. 4660.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of North Badjna Colliery in Nirsa Area of M/s. Eastern Coalfields Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th September, 1985.

(ANNEXURE)

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 56 of 1985

In the matter of Industrial Disputes under Section 10 (1) (d) of the I.D. Act, 1947.

PARTIES:

Employer in relation to the management of North Badjna Colliery in Nirsa Area of Messrs. Eastern Coalfields Limited and their workmen.

APPEARANCES:

On behalf of the employers—None.

On behalf of the workmen—None.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad the 30th August, 1985

AWARD

The Government of India, in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(81)/84-D. III (A), dated the 7th May, 1985.

SCHEDULE

"Whether the demand of Pichhra Painther Mazdoor Sangh that the dependant son of Shri Ram Swarup Nunia, Miner of North Badjna Colliery in Nirsa Area of Messrs Eastern Coalfields Limited should be provided employment by the management of said colliery in terms of the provisions contained in Clause 10.4.3 of the National Coal Wage Agreement-II, is justified? If so, to what relief is the said workman entitled?"

Inspite of notice issued to the Vice President Pichhra Painther Mazdoor Sangh representing the workmen there was no apperance on behalf of the workmen. A few adjournments were granted to the workmen to file their W.S. documents etc. but neither any step were taken on behalf of the workmen nor any W.S. etc. were filed. It appears therefore that the union representing the concerned workman is not at all interested in contesting the case. It will appear from the schedule to the order of reference that it was for the union to establish the demand made on their behalf and as no W.S. has been filed and no evidence has been adduced. I hold that the demand has not been established.

In result, I hold that the demand of Pichhra Painther Mazdoor Sangh that the dependant son of Shri Ram Swarup Nonia, Miner of North Badjna Colliery in Nirsa Area of Messrs Eastern Coalfields Limited should be provided employment by the management of the said colliery in terms of the provisions contained in Clause 10.4.3 of the National Coal Wage Agreement-II is not justified and consequently the concerned workman is entitled to no relief.

This is my Award.

Dated : 30-8-1985.

I.N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012 (81)/84-D. III (A)]

का॰आ॰ 4661.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारत कोकिंग कोल लि॰ की मुराईडीह कोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं॰ 2 धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 10-9-1985 प्राप्त हुआ था।

S.O. 4661.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Muraidih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th September, 1985.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 47 of 1985

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)-(d) of the I.D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Muraidih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—None.

On behalf of the workmen—Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal

Dated, Dhanbad, the 30th August, 1985

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(373)|84-D.III(A), dated, the 26th April, 1985.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Muraidih Colliery of Barora Unit of Messrs Bharat Coking Coal Limited, P.O. Nawagarh, Distt. Dhanbad, in not regularising S|Shri Hulash Mahato and Jagdish Mahra as Timber Mistries in Cat. IV is justified? If not, to what relief the concerned workmen are entitled and from what date ?"

Shri D. Mukherjee, Secretary, BCKU appeared on behalf of the workmen and prayed for time to file W.S. and time was granted to him for filling the W.S. Thereafter the case was adjourned for several times and ultimately Shri Mukherjee filed a petition dated 8-7-85 praying to pass a "No dispute" Award in this case as the dispute has been settled outside the court.

In view of the fact that the dispute has been settled outside the Court and Shri D. Mukherjee appearing on behalf of the workmen has prayed to pass "No dispute" Award in the case let a "No dispute" Award be passed in this case. Dated 30-8-1985.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012/373/84-D. III(A)]

A. V. S. SARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1985

का०आ० 4662—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री बिरेन्द्र नाथ मिश्रा को मुख्य खान निरीक्षक के अधीन खान निरीक्षक के रूप में नियुक्त करता है।

[सं. ए-12025/1/83-एम 1]

एल. के. नारायणन, अवर सचिव

New Delhi, the 19th September, 1985

S.O. 4662.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri Birendra Nath Mishra as Inspector of Mines subordinate to the Chief Inspector of Mines.

L. K. NARAYANAN, Under Secy.

[F. No. A-12025|1|83-M.I]

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1985

का०आ० 4663—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के के अनुसरण में और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 48 तारीख 8 दिसम्बर, 1982 को अधिक्रांत करते हुए बिहार राज्य के लिए एक क्षेत्रीय समिति का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

अध्यक्ष

1. सचिव बिहार सरकार श्रम और रोजगार विभाग, पटना ।	केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त

सदस्य

2. विशेष सचिव, बिहार सरकार, श्रम रोजगार और प्रशिक्षण विभाग, पटना । 3. श्रम आयुक्त बिहार सरकार, पटना ।	राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दो व्यक्ति ।
4. श्री जी०पी०धुर्का महा-प्रबन्धक, भारत शुगर मिल्स लिमिटेड सिधोलिया, गोपालगंज 5. श्री ए०एस० वर्मा प्रबन्ध निदेशक, कल्याणपुर लाईम एंड सीमेण्ट वर्क्स लिमिटेड, मौर्य सेक्टर फ्रासर रोड, पटना । 6. श्री राधे श्याम हरलालका, प्रधान, उषा मार्टिन ब्लेक लिमिटेड, तातीसिलवाय, रांची ।	राज्य में नियोजकों के संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नियोजकों के तीन प्रतिनिधि ।
7. श्री ललितेश्वर झा, संगठन सचिव, इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बिहार शाखा 6, विद्यापति मार्ग, पटना । 8. श्री राम राय, उपप्रधान, बिहार स्टेट कमेटी, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नारायण मार्केट लंगर, टोली, पटना । 9. श्री रामदेव प्रसाद, महा-सचिव, भारतीय मजदूर संघ, बिहार शाखा, बिहार स्टेट क्षेत्रीय कार्यालय, 6/22 आर ब्लाक, पटना—800001	राज्य में कर्मचारियों के संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के तीन प्रतिनिधि ।

[संख्या वी०20012/4/84-पी० फ० II]

ए०के०भट्टराई, अवर सचिव

New Delhi, the 19th September, 1985

S.O. 4663.—In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 48, dated the 8th December, 1982, the Central Government hereby sets up a Regional Committee for the State of Bihar consisting of the following persons, namely:—

CHAIRMAN

1. The Secretary to the Government of Bihar, Department of Labour, Employment and Training, Patna.	Appointed by the Central Government

MEMBERS

2. The Special Secretary to the Government of Bihar, Department of Labour, Employment and Training, Patna. 3. Labour Commissioner, Government of Bihar, Patna.	Two persons appointed by the Central Government on the recommendation of the State Government.
4. Shri G.P. Dhurka, General Manager, Bharat Sugar Mills Limited, Sidhaulia, Gopalganj.	
5. Shri A.S. Verma, Managing Director, Kalyanpur Lime and Cement Works Limited, Maurya Centre, Frasor Road, Patna. 6. Shri Radhey Shyam Harlalka, President, Usha Martin Black, Limited Tati Silway, Ranchi.	Three representatives of employers appointed by the Central Government in consultation with the Organisation of employers in the State.
7. Shri Lralitoshwar Jha, Organising Secretary, Indian National Trade Union Congress, Bihar Branch, 6, Vidyapati Marg, Patna. 8. Sri Ratan Rai, Vice-President, Bihar State Committee, All india Trade Union Congress, Nalain Market, Langortoli, Patna. 9. Shri Ramdev Prasad, General Secretary, Bhartiya Mazdoor Sangh, Bihar Branch, Bihar State Regional Office, 6/22, R. Block, Patna-800001.	Three representatives of employees appointed by the Central Government in consultation with the Organisation of employees in the State.

[No. V. 20012/4/84-PF. II]

A. K. BHATTARAI Under Secy.

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1985

का० आ० 4664 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार देहली टेलीफोन्स के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29 अगस्त, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 23rd September, 1985

S.O. 4664.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal New Delhi, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Delhi Telephones and their workmen, which was received by the Central Government on the 29th August, 1985.

ANNEXURE

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 163|81

In the matter of dispute between :

Shri Om Parkash, S|o. Shri Puran Singh, R|o 10427, Gali No. 2, Bagichi Allaudin, Paharganj, New Delhi-110055.

Versus

The General Manager, Delhi Telephones, Eastern Court, New Delhi.

APPEARANCES :

Shri Narinder Chaudhary Adv.—for Management.

Shri Netra Parkash—for the workman.

AWARD

Central Government, Ministry of Labour on 13-1-81 vide Order No. L-40012(2)|81-D.II.B. made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the General Manager, Delhi Telephones, Eastern Court, New Delhi, in terminating the services of Shri Om Parkash, Typewriter Technician w.e.f. 18-3-80 without following the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act and the principles of last come first go is legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. It was pleaded by the workman that he joined Delhi Telephones as Typewriter Technician on 1-5-76 and worked continuously for more than 10 years.

3. His claim is that the job of Typewriter Technician was of permanent nature and was skilled category of work which he had been doing for more than 10 years satisfactorily and when the classification list was prepared by the Department for purpose of absorption of casual labourers in the Establishment he was assigned as a class Typewriter Mistry to be categorised as workman when absorbed in the department but his services were terminated on 19-3-80 without any notice or formal letter of termination or compensation. He claimed that his services were terminated in contravention of Section 25-F of the I.D. Act and that he was quasi-permanent employee. He claimed that he should be reinstated with full back wages and continuity of service, and that retrenchment compensation with interest and costs should also be paid to him and he should be reinstated in the post of Typewriter Mechanic in regular capacity and be granted continuity of service in Delhi Telephones.

4. The Management of Delhi Telephones contested the claim and asserted that the dispute did not qualify as 'Industrial Dispute' and that Section 25-F of the I.D. Act, 47 was not applicable.

5. On merits it was pleaded that Om Parkash did not join as Typewriter Mechanic and there was no such cadre in the department. He was employed as skilled casual labour and that Typewriters were repariod under contingencies fund through Authorised Dealers and the Mechanic and that being skilled labour Om Parkash was paid Rs. 11 per day. He was considered for appointment as regular mazdoor in group 'D' and the offer was sent to him in 1977 and 1980 but he was reluctant to accept the same and never accepted. Consequently the posts were filled by open recruitment from amongst casual labourers.

6. It was denied that his name was placed at Sl. No. 2 for selection as Typewriter Mechanic. The list was prepared only for the post of regular mazdoor from amongst skilled and unskilled casual labour to provide them better service conditions, he was selected for a Group 'D' post but be did not join as mentioned earlier.

7. The petitioner worked as skilled casual labour from 1-5-70 to 18-3-80 and was still working as skilled mazdoor. He was never retrenched at any time nor reverted. Any retrenchment of the petitioner was denied. The status of the claimant was said to be a skilled casual mazdoor and question of his quasi permanent did not arise.

8. The matter referred to the Tribunal has been tried as per terms of reference. The workman filed his own affidavit and has been cross-examined by the Management. The Management filed affidavit of M. Jagannathan, Administartive Officer, Office of the General Manager and he has been cross-examined at length by the workman. I have heard the arguments of the parties representatives.

9. Mr. Narinder Chaudhary Advocate for the Management argued that Om Parkash was never a Typewriter Technician engaged as such and he was paid from contingencies. He was not a Government Servant in the regular service and there was no question of continuing him always and that Government Servants were not "workmen" entitled to protection under section 25-F of the I.D. Act, 1947 and the department did not retrench his services and he was himself responsible for not working after 18-3-80 and when he agreed to serve he was taken in from September, 1980 and that he absented himself from duty from 19-3-1980 to 31-8-1980. It was his failure to work that meant his not being paid for the period of absence from 19-3-1980 to 31-8-1980 and he insisted on being made Quasi Permanent or Permanent as Typewriter Mechanic.

10. Mr. Jagannathan has been working as Administartive Officer only since 1-11-83 and was not the Administrative Officer in the year 1980. Workman had certainly worked with the department for a number of years and the documents filed leave no doubt that he did work as Typewriter Mechanic and set the typewriters right when they did not function properly. In fact the department sought sanction for regular posts of typewriter mechanics as early as the year 1971 as the letter No. E-6|113 dated 25-10-71 of the Assistant Electrical Engineer(T) Central Telegraph Office, New Delhi to the General Manager, Delhi Telephones indicates but the sanction for regular post of typewriter mechanic was not available even when the A.G.M.(E) strongly recommended for creation of posts and regularisation of existing staff and sanctions of additional staff.

11. The question referred to this Tribunal is not the confirmation or regularisation of Om Parkash as Typewriter Technician. The question is about termi-

nation of his services on 18-3-80 without following the provisions of Section 25-F of the I.D. Act, 47 and there is no doubt that this workman had worked for more than 240 days before 18-3-80 in a year and so was entitled to protection of section 25-F of the I.D. Act, 47.

12. Government Servants governed by Article 309 of the Constitution may be excluded from the category of 'Workman' under I.D. Act, 1947 when there is a proper provision made by rules under Article 309 of the Constitution making the provisions of Section 25-F of the I.D. Act, 1947 inapplicable to them either expressly or by necessary implication but in the present case Om Parkash was continued as a worker on contingencies and there are no rules under Article 309 of the Constitution applicable to him and he cannot be denied the status of 'workman' under I.D. Act, 47 when Delhi Telephones are an 'Industry' under I.D. Act, 47.

13. I am of the clear opinion that Sh. Om Parkash should not have his services terminated without complying with section 25-F of the I.D. Act, 1947 and termination of his service w.e.f. 18-3-80 was illegal and ineffective. He was getting Rs. 11 per day as a skilled labour and he has to be paid at the same rate for the period he was not engaged from 19-3-80 to end of August, 1980. It is incorrect to assert that Om Parkash workman did not come voluntarily to work as before. It was the Management that refused work to him from 19-3-80 but gave him work again from 1-9-80.

14. In the light of the foregoing, the Management of Delhi Telephones is directed to pay Om Parkash, workman from 19-3-80 till 31-8-80 at Rs. 11 per day and the period should count as duty for him. He should also be paid Rs. 500 as costs, of this reference by the Management of Delhi Telephones. Award is made accordingly.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

Dated : August 21, 1985.

O. P. SINGLA, Presiding Officer

[No. L-40012(2)|81-D.II(B)]

HARI SINGH, Desk Officer.

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1985

का. आ. 4665.—केन्द्रीय सरकार खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 27 के अनुसरण में, बिहार राज्य के जिला धनबाद में स्थित हुरीलाडीह कोयला खान में 14 सितम्बर, 1983 को हुई दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिये नियुक्त जांच न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 24 की उप धारा (4) के अधीन प्रस्तुत की गई निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित करती है।

[एन 11015/3/84एम 1-]

एल. के. नारायणन, अवर सचिव

जांच न्यायालय

हुरिलाडीह कोयला खान दुर्घटना

अध्यक्ष जस्टिस सी. टी. दिघे

जज, बंबई उच्च न्यायालय (सेवा निवृत्त)

असेसर श्री जी. एस. मारवाहा,
निदेशक,
इंडियन स्कूल आफ माइन्ज
धनबाद।
श्री के. एन. त्रिवेदी,
संगठन मंत्री,
इंडियन नेशनल माइन वर्कर्ज फेडरेशन,
धनबाद।

पेशियां

क्रम संख्या	पक्ष	प्रतिनिधि
	2	3
1.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	श्री आर. वाई श्रीपुरकर, एडवोकेट। श्री एस. बी. सिन्हा, एडवोकेट।
2.	इंडियन माइन्ज मैनेजरर्ज एसोसिएशन	श्री यू. डब्ल्यू. दात्ते
3.	आल इंडिया माइन पर्सोनल एसोसिएशन	श्री आर. के. प्रसाद
4.	यूनाइटेड कोल वर्कर्ज यूनियन इंडियन माइन वर्कर्ज फेडरेशन/ आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस।	श्री चिन्मय मुखर्जी
5.	इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंडियन नेशनल माइन वर्कर्ज फेडरेशन राष्ट्रीय कोलरी मजदूर संघ।	श्री एस. दासगुप्ता श्री एस. एन भट्टाचार्य
6.	इंडियन नेशनल माइन ओवरमेन/ सिरदार्ज एंड शाटफायरर्ज एसोसिएशन	श्री जानकी महतो
7.	आल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन/ कोलरी मजदूर सभा आफ इंडिया बिहार कोलरी कामगार यूनियन	श्री एस. के. बक्शी
8.	जनता मजदूर संघ/ हिन्द मजदूर सभा	श्री के. बी. सिंह

अध्याय- 1

प्रस्तावना

1.1 धनबाद को भारत के कोयला क्षेत्र में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त है। झरिया कोयला क्षेत्र में उत्तम कोटि का कोयला अब भी उपलब्ध है, हालांकि वर्षों से यहां कोयले की खुदाई हो रही है। इस नगर की जनता धुएं से प्रदूषित वातावरण, कामगारों में फैली खतरनाक बीमारियों तथा खानों में आए दिन होती रहने वाली छोटी-मोटी दुर्घटनाओं की आदी हो चुकी है। ऐसी भारी दुर्घटना, जिससे समूची आबादी प्रभावित हो जाए, कभी-कभार ही घटित होती है। ऐसी ही एक घटना 14 सितम्बर, 1983 को हुरिलाडीह कोयला खान में हुई जब खदानों में पानी की अचानक बाढ़ आ जाने से 19 व्यक्ति डूब गए।

1.2 खान अधिनियम की धारा 24 के अधीन सरकार को ऐसी दुर्घटनाओं के मामले में जांच न्यायालय नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। धारा 23 के अधीन, साधारण प्रवृत्ति की कुछ दूसरी दुर्घटनाओं की जांच का अधिकार मुख्य खान सुरक्षा निरीक्षक अथवा महानिदेशक को दिया गया है। इस मामले में, दुर्घटना के तुरंत बाद 22 सितम्बर, 1983 को भारत सरकार ने एक अधिसूचना, जो इस रिपोर्ट के अनुबंध 'क' के रूप में संलग्न है, जारी करके उन कारणों तथा परिस्थितियों की औपचारिक जांच की घोषणा की जिनके परिणामस्वरूप यह दुर्घटना हुई। मुझे इस जांच न्यायालय का प्रधान अधिष्ठाता तथा मेरी सहायता के लिए श्री के. एन. त्रिवेदी, संगठन सचिव, भारत राष्ट्रीय खान कामगार संघ, धनबाद, एवं श्री जी. एस. मरवाह, निदेशक भारतीय खान स्कूल को असेसर नियुक्त किया गया।

1.3 पहली अक्तूबर, 1983 को मैंने असेसरों तथा विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों के साथ प्रबंधकों एवं खान सुरक्षा महानिदेशक के प्रतिनिधियों की स्थिति में दुर्घटना स्थल की जांच की और इस जांच से संबंधित एक विस्तृत टिप्पणी तैयार की गई, जो अनुबंध 'ख' के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। हुरिलाडीह कोयला खान 1.6 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली 2343.5 तथा 2344.2 पूर्व अक्षांश उत्तर तथा 86,23.7 और 24.4 उत्तर देशांश के मध्य स्थित है। इस खान के उत्तर में भालगोरा कोयला खान, पूर्व में स्टैण्डर्ड कोयला खान, पश्चिम में बरारी कोयला खान तथा दक्षिण में जामदोबा एवं भूतगोरिया कोयला खानें हैं। धनबाद रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 12 किलो मीटर है।

1.4 निर्विवाद तथ्यों से यह पता चलता है कि समूचा झरिया कोयला क्षेत्र, यह कोयला खान जिसका कि एक भाग है, अवासी निक्षेप है जिसमें लगभग 26 कोयला सीमें हैं। हुरिलाडीह कोयला खान इस कोयला क्षेत्र के दक्षिण केंद्रीय भाग में आती है तथा इस में अनुप्रस्थ रूप में कई आग्नेय अंतर्भेदन पाए जाते हैं। यह क्षेत्र कुछ ऊंची-नीची भूमि में है। कोयला खान की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ पूर्व-पश्चिम की दिशा में एक नाला बहता है।

1.5 झरिया कोयला क्षेत्र की 25 कोयला-सीमों में से नीचे से ग्यारहवीं से अठारहवीं सीमों का विशेष महत्व है क्योंकि इनमें इस्पात संयंत्रों में युक्त होने वाले हार्ड कोक को बनाने वाले उच्च कोटि के धात्विक कोयले के देशभर के भंडार का 95 प्रतिशत पाया जाता है। हुरिलाडीह कोयला खान अब भारत कोकिंग कोल लि. (बी. सी. सी. एल.) के प्रबंधाधीन है। कोकिंग कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1972 के अधीन से बंद स्थिति में, सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। राष्ट्रीयकरण से पूर्व यह खान मै. इक्विटेबल कोल कं. लि. के पास थी तथा इसका प्रबंध मै. मैकनील एंड बारी लि. के हाथों में था। यह 16-1-1967 को बंद की गई थी।

1.6 भारत कोकिंग कोल लि. की स्थापना 1 मई, 1972 को एक सरकारी क्षेत्र कंपनी के रूप में की गई थी और इसे उन कोकिंग कोयला खानों के प्रबंधन, नियंत्रण एवं संचालन का काम सौंपा गया था जिनको कि 17-10-1971 को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। बाद में, जनवरी, 1978 में सरकार ने देश की ज्यादातर कोयला खानों को अपने हाथ में ले लिया था। सरकार ने पहली जून, 1978 को, हुरिलाडीह कोयला खान समेत, सारा झरिया कोयला क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लि. को सौंप दिया।

1.7 जिस दुर्घटना में 19 व्यक्तियों की जानें गईं वह 14 सितम्बर, 1983 को प्रातः 6 बजे के लगभग घटित हुई। यह दुर्घटना पानी की अचानक बाढ़ के कारण चौदहवीं सीमा में भूमि के नीचे हुई। विकास क्षेत्र में तीसरी पारी काम कर रही थी। कामगार वहां फंस गए तथा 29वें लेवल के नीचे के क्षेत्र में डूब गए। पानी का रेला मुख्य डिप के 29वें पूर्वी लेवल से परे डिप की छत तथा पूर्वी क्रास-कट मुख्य डिप के 27वें पश्चिमी लेवल से परे तीसरे डिप गैलरी के फर्श के बीच विभाजक दीवार के अचानक फट जाने के कारण वहां बह आया। विभाजक दीवार संभवतः इतनी पतली थी कि पानी के दबाव के कारण यह फट गई और उससे ऊपर पानी भर गया जो विभिन्न गैलरियों में फैल गया। इस पानी की मात्रा का अनुमान 7 लाख से 9 लाख गैलन के बीच लगाया जाता है।

1.8 कोयला खान के लगभग सभी सम्बद्ध अधिकारी तथा सह-संस्थाओं के कर्मचारी बचाव कार्य में भाग लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर भागे गए। भारी पम्प कार्य द्वारा इस क्षेत्र से पानी को निकाला गया। पहले दो पम्प तो 14 तारीख को ही दस घंटे के अंदर-अंदर चालू कर दिए गए तथा 15 सितम्बर, 1983 को प्रातः तक सभी नौ पम्प चालू हो चुके थे।

1.9 मुख्य डिप का 29वां पूर्वी लेवल 17 सितम्बर, 1983 की दोपहर तक पानी से खाली कर लिया गया था। डिप गैलरियों में से पानी निकालने का काम चलता रहा तथा 17 सितम्बर, 1983 को प्रातः छह बजे तक मुख्य डिप से चार शव निकाले जा चुके थे। 17 सितम्बर, 1983 की दोपहर तक चार शव और निकाल लिए गए थे तथा उसी दिन शाम तक दो और शव निकाले जा चुके थे। इस प्रकार मुख्य डिप से ही 10 शव मिले थे। पूर्वी टगर डिप में से पानी की निकासी का काम चलता रहा तथा 17 सितम्बर, 1983 की रात में वहां पड़े दो और शवों का पता चला जिन्हें 18 सितम्बर, 1983 की प्रातः निकाला गया। शेष सात शव इसी स्थान से 18 सितम्बर, 1983 की शाम को निकाले गए।

1.10 मरने वालों के नाम तथा जिस स्थान पर उनके शव मिले इसकी जानकारी खान सुरक्षा महानिदेशक के कार्यालय के सर्वेक्षण द्वारा बनाए गए नक्शे (प्रदर्श. 19) में दी गई है जो निम्नलिखित है :--

क्रम सं.	मृत व्यक्ति का नाम	पदनाम
1	2	3
	मुख्य डिप : दिनांक 17-9-1983	
1.	विभूति बौरी	लोडर
2.	अनंत महतो	लोडर
3.	मधु बौरी	लोडर (बेलिया मजदूर के रूप में कार्यरत)
4.	महावीर तुरी	पम्प आप्रेटर
5.	अखलू बौरी	लोडर
6.	सुखदेव बौरी	लोडर
7.	पंचू महतो	लोडर
8.	अनंत मोदी	लोडर
9.	सुभाष राय	लोडर
10.	अनिल बौरी	लोडर

टगर डिप : दिनांक 18-9-1983

11. बचन चमार	लोडर
12. सोनशहाय धोबी	पम्प आपरेटर
13. धर्मू चौहान	खदान सरदार
14. रामजी चमार	लोडर
15 मंगी चमार	लोडर
16. गुरुफेकर साओं	लोडर
17 सानु राम	लोडर
18. मुसफिर हरिजन	लोडर
19. काली साओं	लोडर

अध्याय- 2

निरीक्षण टिप्पणी, सार्वजनिक सूचना तथा कार्यवाही के पक्ष

2.1 दुर्घटना चौदहवीं सीम में हुई जो लगभग 30 फुट मोटी है। इसमें दक्षिण 49 पश्चिम में लगभग 8 में 1 का एक डिप है। मेरे नेतृत्व में निरीक्षण दल नीचे पिट सं. 2 में पूर्व दिशा में मुख्य डिप तक गया तथा 29वें लेवल से परे उस स्थल पर भी गया जहां दस मृत मिले बताए जाते हैं। उस समय 29वें लेवल पर कोई पानी नहीं था। 29वें लेवल पर वापस आकर तथा सहस्थित डिप के साथ-साथ 40 फुट आगे चलकर दल ने पाया कि गैलरी खाली टबों से अवरुद्ध थी। दल इससे आगे न जा सका, परंतु कैप लैम्पों की सहायता से डिप के कोने के पास मोटे स्तम्भ का ऊपरी सिरा दल को दिखाई दे रहा था।

2.2 29वें लेवल को वापस आते हुए दल पंक्चर स्थल को गया। यह पंक्चर, 29वें लेवल तथा तीसरे पूर्वी डिप के योजक स्थल परे थोड़ा सा डिप की दिशा में, एक छत में दिखाई पड़ा। दरार की चौड़ाई केवल एक फुट के लगभग थी। तीसरे पूर्वी डिप फेस में दो शाट होल ड्रिल किए हुए दिखाई दिए और 29वें पूर्वी लेवल के सामने वाले हिस्से में शाट होल की 6-7 साकटें दिखाई पड़ीं। बताया गया कि यह अग्रिम बोर होल नहीं थे। मुख्य ढुलाई डिप तथा टगर डिप और दूसरे पूर्वी सहस्थित डिप में थोड़ा कोयला दिखाई दे रहा था।

2.3 टगर डिप को वापस आते हुए तथा सड़क पथ से 26वें लेवल को जाते हुए, दल ऊपरी हिस्से में गया। सीढ़ियों के पास में एक जाली-दार दरवाजा हाल ही में बनाया गया था। डिप के सिरे की तरफ आते समय पंक्चर स्थल दिखाई पड़ता था। तत्पश्चात् दल पूर्व की ओर चलते हुए 25वें लेवल पर लौट आया तथा पूर्वी क्रास-कट ढुलाई डिप में उतरा और वह स्थान देखा जहां दुर्घटना से पूर्व 90 हार्स पावर का पम्प लगाया गया बताया गया था। यह पम्प संप में भरे पानी को 17वें लेवल पर पहुंचाने के लिए लगाया था, जहां से इस पानी को गड्ढे के तल पर मुख्य संप में पम्प द्वारा पहुंचाया जाता था।

सार्वजनिक सूचना

2.4 निरीक्षण पूरा होने के तुरंत बाद उसी दिन एक सार्वजनिक सूचना, इस रिपोर्ट का अनुबंध 'घ' जारी करने के लिए कार्रवाई की गई। इस सूचना में इस दुर्घटना में मरने वालों के कानूनी प्रतिनिधियों तथा हुरिलाडीह कोयला खान के कर्मचारियों के प्रतिनिधि मजदूर संघों को लिखित बयान एवं गवाहों के नाम यदि कोई हों, देकर इस जांच में भाग लेने को कहा गया। लिखित बयान धनबाद स्थित जांच न्यायालय कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने थे।

पक्ष

2.5 जांच से वस्तुतः सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई की गई जोकि दुर्घटना के कारण तथा दुर्घटनाजनक परिस्थितियों से संबंधित वाद में योगदान कर सकते थे। कुल आठ पक्ष जांच न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए। पहला पक्ष भारत कोकिंग कोल लि. के प्रबंधक हैं। दूसरा पक्ष है भारतीय खान प्रबंधक, संघ, जिसे संक्षेप में 'इम्मा' कहा जाता है। तीसरा पक्ष अखिल भारतीय खदान कार्मिक संघ, जिसे संक्षेप में 'ऐम्पा' कहा जाता है। ये तीनों पक्ष प्रबंधक वर्ग के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां तक कामगारों का संबंध है, अखिल भारतीय संघों से सम्बद्ध संघों को एक पक्ष के नाम से कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान की गई। अतः अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस (ऐटक) चौथा पक्ष है जो संगठित कोयला कामगार संघ तथा भारतीय खान कामगार परिसंघ का भी प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस (इंटक), भारतीय राष्ट्रीय खान कामगार परिसंघ तथा राष्ट्रीय कोयला खान मजदूर संघ, मिलकर, पांचवां पक्ष हैं। भारतीय राष्ट्रीय कोयला खान ओवरमैन, सिरदार तथा शाट फायरर संघ (इनमोसा) छठा पक्ष है। अपने सम्बद्ध संघ भारतीय कोयला कामगार परिसंघ समेत भारतीय मजदूर संघ केंद्र (सीटू), भारतीय कोयला खान मजदूर सभा तथा बिहार कोयला खान कामगार संघ, मिलकर, सातवां पक्ष हैं। हिंद मजदूर सभा से सम्बद्ध जनता मजदूर संघ आठवां पक्ष है।

2.6 जांच न्यायालय की वर्तमान कार्रवाई से ज्ञात होगा कि खान सुरक्षा महानिदेशालय इस मामले में पक्ष नहीं बना है। मुझे बताया गया है कि यह कोई पहला अवसर नहीं है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय किसी जांच से एक पक्ष के रूप में अलग-थलग रहा हो। कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संघ इस बात से विचलित थे कि खान सुरक्षा महानिदेशालय जांच न्यायालय की कार्रवाई में क्यों भाग नहीं ले रहा। फिर भी, ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आए जिनसे यह पता चले कि इसके पीछे कोई कदाशय या प्रबंधकों के साथ मिली-भगत की भावना है। यह स्पष्ट था कि खान सुरक्षा महानिदेशालय ने तटस्थ रहना बेहतर समझा। वैसे उसने, लिए गए साक्ष्य, हस्तगत किए गए नक्शों तथा दस्तावेजों तथा खान अधिनियम की धारा 23 के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों के सांविधिक कार्यों के अनुपालन में दुर्घटना के उपरांत दुर्घटना पर प्रकाश डालने वाले, इसके विभागीय सर्वेक्षकों द्वारा बनाए गए, नक्शों आदि को पेश करके न्यायालय को हर तरह से सहायता प्रदान की।

2.7 खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा खान अधिनियम की धारा 23 के अधीन विनियमों अथवा विधि-उपबन्धों के किसी उल्लंघन की घोषणा करने संबंधी किसी औपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व ही यह जांच शुरू कर दी गई थी। इसलिए खान अधिनियम की धारा 24 के अधीन जब जांच न्यायालय ने अपना कार्य शुरू कर दिया, तो ऐसी रिपोर्ट निष्प्रयोज्य हो ही गई है। यह कहा जाता है कि जब कभी भी जांच न्यायालय की नियुक्ति से पूर्व इस प्रकार की रिपोर्ट की गई, वह प्रबंधक वर्ग अथवा कामगार संघ दोनों में से किसी न किसी के विरोध का लक्ष्य बनी है क्योंकि इसके निष्कर्ष किसी न किसी पक्ष, प्रबंधक वर्ग अथवा कामगार संघ, के पक्ष में जाते ही होते हैं। यदि खान सुरक्षा महानिदेशालय ने प्रबंधक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया तो प्रबंधक वर्ग अपनी खाल बचाने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय के कार्य करने के ढंग में खामियां निकालने लगता है। इसी प्रकार जब भी इसके निष्कर्षों ने प्रबंधक वर्ग को जिम्मेदारी से बरी कर दिया, तो कामगार संघ इस पर खान प्रबंधकों के साथ मिलीभगत होने का आरोप लगा देते हैं। इससे सम्बद्ध पक्षों का ध्यान दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों के निर्धारण पर केंद्रित नहीं हो पाता और इसलिए कई बार दुर्घटना के मुख्य कारण का उद्घाटन नहीं हो पाता। इस तर्क को मानते हुए तथा वर्तमान मामले में इस संगठन द्वारा दिए गए सहयोग को स्वीकारते हुए भी, न्यायालय का विचार है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय को चाहिए कि वह, खान अधिनियम की धारा 24 के अधीन स्थापित जांच न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश करने से पूर्व प्रत्येक मामले में, ऐसे अन्य दस्तावेजों तथा सामग्री की जांच करें जोकि खान सुरक्षा महानिदेशालय के कार्यालय के पुराने रिकार्डों में उपलब्ध हों अथवा उसके अधिकारियों की जानकारी में हों, जिससे कि दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों के, उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में, मूल्यांकन पर और अधिक प्रकाश पड़ने की संभावना हो। इसके लिए जांच कार्रवाई में सतर्क रुचि की आवश्यकता है तथा इससे खान सुरक्षा महानिदेशालय के कार्यकलापों के संबंध में गलत धारणा नहीं बनेगी।

अध्याय 3

मुख्य नक्शा तथा अन्य नक्शे

3.1 जांच कार्रवाई में भाग लेने वाले पक्षों की ओर से प्रस्तुत कथन-प्रतिकथन पर विचार करने से पूर्व, यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस मामले में पेश किए गए विभिन्न प्रकार के नक्शों का जायजा ले लिया जाए। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि दुर्घटना के होते ही, दुर्घटना स्थल पर पहुंचें तथा दुर्घटना के कारणों के निश्चयन में सहायक नक्शों समेत सभी दस्तावेज अपनी रिपोर्ट के साथ लगाएं। हस्तगत किए गए ऐसे दस्तावेजों की सूची इस कार्रवाई के प्रदर्श 12 तथा 18 पर दी गई है। खान सुरक्षा महानिदेशालय के कार्यालय ने सूचीगत कुछेक नक्शों के आधार पर अथवा वास्तविक सर्वेक्षण द्वारा कुछ और महत्वपूर्ण नक्शे भी तैयार किए हैं। कार्रवाई में प्रदर्श 14 खनन-योजना के उस नक्शे की प्रतिलिपि है जो कागज पर मढ़ा हुआ है तथा प्रदर्श 62 है। प्रदर्श 15 बचाव योजना का नक्शा है। प्रदर्श 16 अनुभाजीयन नक्शा है। प्रदर्श 18 ट्रेसिंग पेपर पर बनाया गया कार्य-योजना नक्शा है। प्रदर्श 19 तथा 19ए वे नक्शे हैं जो खान सुरक्षा महानिदेशालय के कार्यालय ने दुर्घटना के बाद बनाए हैं। अनुभाग प्रदर्श 19ए में प्रदर्शित हैं जबकि प्रदर्श 19ए-ए मुख्य नक्शा है, जिसके एक हिस्से, जोकि दुर्घटना स्थल के निकट है, का दुर्घटना के उपरांत पुनः सर्वेक्षण करके खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों ने आलेखन किया है। प्रदर्श 19 तैयार करने के लिए दुर्घटनाग्रस्त हिस्से का पूर्ण-रूपेण सर्वेक्षण एवं निरीक्षण किया गया था। प्रदर्श 19 उस हिस्से का विवरणात्मक नक्शा है जिसमें पानी के आने वाले रेले को दिखाया गया है। इसकी एक लघुकृत प्रति तुरंत संदर्भ के लिए इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध 'घ' के रूप में संलग्न है। इसी प्रकार, होने वाली चर्चा को समझने के लिए, प्रदर्श 19ए-ए वाले आधार नक्शे की प्रतिलिपि आवश्यक है। यह चौदहवीं सीम खदान का आधार नक्शा है। इसकी लघुकृत प्रति इस रिपोर्ट के अनुबंध 'च' के रूप में संलग्न है।

3.2 प्रदर्श 42 वह नक्शा है जो पहले के नक्शों में रह गई अशुद्धियों को दर्शाने के लिए प्रबंधकों ने दुर्घटना के बाद तैयार किया था। यह रेखा चित्र मात्र है और प्रदर्श 62 की नक्शा ट्रेसिंग के बिना इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रदर्श 43 एक अन्य खदान-योजना नक्शा है जो 1983 का है। प्रदर्श 63 तथा 64 अगली नक्शे हैं। प्रदर्श 67 त्यक्त खान का नक्शा है जो कि खान सुरक्षा महानिदेशक के कार्यालय से प्राप्त किया गया है। प्रदर्श 70 वह नक्शा है जो चौदहवीं सीम के पेनल 'ई' के विस्तम्भन हेतु अनुमति मांगते समय प्रबंधकों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रदर्श 80 वायु संचारण का नक्शा है। प्रदर्श 89 प्रबंधकों द्वारा जिला बोर्ड सड़क स्थल के नीचे से क्रास की अनुमति हेतु दिए गए आवेदन-पत्र के साथ संलग्न नक्शा है। प्रदर्श 90 जल से होने वाले खतरे का नक्शा है। प्रदर्श 101 ठोस विस्फोटन के लिए अनुमति लेते समय तैयार किया गया नक्शा है।

3.3 चर्चा के दौरान विभिन्न अवसरों पर यद्यपि भिन्न-भिन्न लेवलों अथवा डिपों का उल्लेख होगा, तथापि इस समय यदि आधार नक्शे के आधार पर यदि कुछ चर्चा कर ली जाए तो यह लाभप्रद रहेगा। पूरी को पूरी चौदहवीं सीम ए. बी. सी. डी. और ई. पैनलों में विभाजित अलग-अलग खनन-स्थल प्रदर्शित करती है। इस जांच में हमारा संबंध मुख्यतः पेनल 'ई.' प्रदर्श 19 ए ए में हाशिए में जहां लाल स्याही से रेखा लगाई गई है, तथा पश्चिमी के थोड़े से भाग, जोकि मुख्य डिप के पूर्व में है से है। पेनल 'च' के दो उप क्षेत्र हैं—पूर्व की ओर विस्तंभन क्षेत्र और पश्चिम की ओर विकास क्षेत्र। पूर्वी साइड पर एक तिरछी काट है तथा पेनल 'ई' इस तिरछी काट के मुख्य डिप के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों ओर स्थित हैं। विस्तम्भन क्षेत्र इस तिरछी काट मुख्य डिप के पूर्व में हैं जबकि दुर्घटना स्थल इस पूर्वी तिरछी काट मुख्य डिप के पश्चिम की ओर है, हालांकि यह मुख्य डिप के पूर्व में है। दुर्घटना विकास खण्ड में हुई है जोकि मुख्य डिप के पूर्व में तथा पूर्वी तिरछी काट के पश्चिम में स्थित है। साक्ष्यों के दौरान मुख्य डिप के पूर्व में पुराने खनन-स्थलों का उल्लेख भी किया गया है, परंतु इस स्थान से हमारा कोई संबंध नहीं। एक ही स्तर को अलग-अलग नाम देने का कोई औचित्य हो या न हो, इस बात में कोई विवाद नहीं कि मुख्य डिप के पूर्व में स्थित 26 वें लेवल पूर्वी तिरछी काट के पूर्व में स्थित 25 वें लेवल से जुड़ा हुआ है। वस्तुतः यह एक ही लेवल है किंतु जब हम इसे तिरछी काट के सहसंबंध में देखते हैं तो उसे 25वां लेवल पश्चिमी कहते हैं, और जब हम इसे मुख्य डिप के संदर्भ में देखते हैं, तो इसे 26वां लेवल पूर्वी कह देते हैं। दुर्घटनास्थल को प्रदर्श 19 ए ए नक्शे पर लाल बिंदु के रूप में दिखाया गया है। यह मुख्य डिप के 29वें लेवल पूर्वी के तीसरे डिप के ऊपर 27वें लेवल पश्चिमी क्रास-कट के तीसरे डिप में स्थित है। पूर्वोक्त 26वें लेवल से डिप की ओर जाते समय, हमें 27वां लेवल पूर्वी दिखाई पड़ता है जोकि मुख्य डिप से साथ वाले टगर डिप को जाता है और वहां से दूसरे डिप को जाता हुआ थोड़ा आगे बढ़ता है, परंतु नीचे वाले लेवल से जुड़ता नहीं। 27वां लेवल पूर्वी पूर्व की ओर ही आगे बढ़ता है, परंतु यह पूर्वी तिरछी काट के 26वें लेवल पश्चिमी से जुड़ता नहीं। जहां तक मुख्य डिप के पूर्व में, स्थित 28वें लेवल का संबंध है। यह साथ वाले अर्थात् टगर डिप तक आकर, रुक जाता है, यद्यपि यह कुछ पूर्व में बढ़ा हुआ है जिसे कि साक्ष्य में 28वें लेवल का विस्तार भी कहा गया है। पूर्वी क्रास कट का समरूप 27वां लेवल पश्चिमी पश्चिम की ओर बढ़ता है जिससे लेवल के पश्चिम में थोड़े से विस्तार के साथ-साथ चौथा डिप बनता है। फिर आगे डिप की ही दिशा में 29वां लेवल है जो मुख्य डिप, साथ वाले डिप तथा दूसरे डिप की ओर चलती है। सहस्थित डिप की ड्राइवेज मुख्य डिप से लंबी है। पहले सहस्थित डिप की ड्राइवेज कुछ पूर्व की ओर है जिससे 30वां लेवल बनता है, परन्तु यह छोटा सा विस्तार मात्र है। 29वें लेवल पूर्वी का दूसरा डिप काफी बढ़ा हुआ है। 29 वें लेवल पूर्वी का तीसरा डिप ही वह गैलरी है जिसमें पूर्वी क्रास कट के 27वें लेवल पश्चिमी के ऊपर के तीसरे डिप से छत के गिरने से पानी भर गया था।

3.4 क्रास-कट डिप की ओर से देखने पर ऐसा दिखाई पड़ता है कि 25वां पश्चिमी लेवल मुख्य डिप के 26वें पूर्वी लेवल के साथ और 26वां पश्चिमी लेवल 25वें पश्चिमी लेवल के तीसरे डिप के साथ जुड़ गया है। जहां तक पूर्वी क्रास कट के 27वें पश्चिमी लेवल का संबंध है, यह 26वें पश्चिमी लेवल के तीसरे डिप से जा मिला है और डिप की तरफ आगे बढ़ गया है जहां तीसरा डिप बनता है यहीं वह ऊपर की नासक गैलरी है जहां जल मौजूद था, इसलिए कि यह आस-पास की गैलरियों से बने संप का एक हिस्सा थी। संप का प्रयोग जल-स्टोवन में जल की प्राप्ति एवं जल को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता था। 27वां पश्चिमी लेवल और आगे तक चला गया है और वहां इस का चौथा डिप बन गया है। इसका विस्तार पश्चिम की तरफ भी हो गया है। प्लान प्रदर्श 19 से यह प्रदर्शित होता है कि 27वें पूर्वी लेवल में चढ़ाव (उत्तर) की तरफ मोड़ है। साक्ष्य से यह पता चलता है कि इस 29वें लेवल के पूर्वी लेवल प्रतांग्र (फेस) पर खदान रोक दिया गया था। किंतु डिप-अग्रांग का आगे बढ़ना जारी रहा और डिप की तरफ आगे बढ़ने की इसी प्रक्रिया के दौरान पूर्वी क्रास कट के 27वें पश्चिमी लेवल के तीसरे डिप में ठीक ऊपर स्थित पानी विभाजक दीवार के बह जाने के कारण बढ़ती तेजी से अन्दर बह निकला और डिप की तरफ की खदानों में फैल गया और वहां काम कर रहे व्यक्तियों को डुबो गया।

अध्याय 4

पक्ष समर्थन और प्रयुक्त क्रिया विधि

4.1 प्रबंधक वर्ग की ओर से एक बयान प्रदर्श 5 दिया गया है। खान की भौमिकी (भू-विज्ञान) की चर्चा करते हुए, लिखित बयान के पैरा 3.4 में और इससे आगे यह उल्लेख किया गया है कि यह पूरा

4.6 यह कहा जाता है कि दुर्घटना के बाद संभावित ज कितों संभावित जल-साधनों, जल-लेवलों की स्थिति आदि का पता लगाने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पूर्ण जांच की गई थी। जब 29वां पूर्वी लेवल जल से खाली कर दिया गया तो मुख्य डिप के 29 वें पूर्वी लेवल से परे के तीसरे डिप की तरफ की खदानों में घुसा था। प्रबंधक वर्ग ने दुर्घटना की जांच के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की थी, किंतु सरकार द्वारा जांच न्यायालय नियुक्त कर दिए जाने से वह जांच आगे नहीं बढ़ाई गई। प्रारम्भिक छानबीन के अनुसार, यह पाया गया कि स्टोइंग जल वाले स्थान पर जल संचित हो जाने के कारण, छत के उस छेद से जल का रेला तीव्रगति से आया। कोयला खान के स्थानीय प्रबंधक वर्ग ने उन्हें उपलब्ध सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर, जल के ज्ञात पैंच के सामने ठोस कोयले की काफी मोटी अवरोधिका छोड़ दी थी। कुछ नक्शों में, त्रासक पुराने डिप गैलरी गहरी लाइनों से दिखाई गई है जिससे ऐसा लगता है कि खदानों का सर्वेक्षण किया गया था और ये उस 29वें लेवल से दूर थी जो वास्तव में, दुर्घटना, और खदानों को जल से खाली कर दिए जाने के बाद गलत पाया गया।

4.7 पक्ष सं. 2, भारतीय कोयला खान प्रबंधक संघ ने अपना लिखित बयान प्रदर्श 7 पर फाइल किया। यह कहा गया है कि यह संघ व्यावसायिक खान प्रबंधकों का संघ है जो 61 से भी अधिक वर्षों से प्रतिष्ठित है। बयान में कहा गया है कि 14 सितम्बर, 1983 की दुर्घटना एक विशेष प्रकार की दुर्घटना थी जो भूमिगत खदानों में पानी के अकस्मात् प्रवहित होने के कारण हुई। फिर, इसमें मानसून के दौरान और अन्यथा भी, खान में जाने वाले जल का उल्लेख किया गया है और 10,000 गैलन से लेकर एक लाख गैलन की क्षमता वाले जल-हौज की आवश्यकता की बात कही गई है। यह कहा गया है कि ऐसे जल स्रोतों में से कुछेक तो ऐसे सुविचारित तरीके से बनाए जाते हैं कि वे पंपिंग संस्थापनों के लिए संप का कार्य करें। अन्य जल भंडार खनन कार्यों के परिणामस्वरूप बन जाते हैं। जब ये जल हौज सुविचारित तरीके से बनाए गए होते हैं तो अकस्मात जल प्लावन की बहुत कम अर्थात् नहीं के बराबर गुंजाइश होती है। झरिया कोयला क्षेत्र की संरचना एक तश्तरीनुमा बेसिन की तरह की बनाई जाती है। इस संरचना के कारण धरातल सभी ओर से मध्य की ओर नमित रहता है कोयला-पट्ट बनाने वाला अवसाद-स्तर अत्यधिक संरंध्री है और इसमें जल आसानी से आ जा सकता है। तश्तरीनुमा आकार के कारण जल स्वाभाविक रूप से मध्य की ओर प्रभावित होता है। इसका परिणाम यह होता है कि बेसिन के मध्य क्षेत्र की खानों में बहुत अधिक जल रिसाव होता रहता है। हुरिलाडीह कोयला खान इस बेसिन के मध्य क्षेत्र में स्थित बताई जाती है। पूरे वर्ष भारी मात्रा में पानी पंप करना आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि जल सीपेज की समस्या वहां और भी उग्र हो जाती है जहां अपेक्षाकृत उथली गहराइयों की सीमों में से केविंग प्रणाली द्वारा कोयला निकाला जाता हो। इससे रिक्तियां पैदा हो जाती हैं, ये रिक्तियां भरी नहीं जाती जिसके परिणामस्वरूप सतह का अवतलन हो जाता है। अवतलन के कारण चट्टानें टूटती हैं, तल पर दरारें आ जाती हैं और सामान्य लेवल नीचे हो जाता है तथा जल का रिसाव अधिक हो जाता है। हुरिलाडीह में ऊपर की सीम का बहुत पहले केविंग हो चुका था।

4.8 भारतीय खान प्रबंधक संघ के अनुसार दुर्घटना के बाद किए गए दुर्घटना स्थल के निरीक्षण से यह पता चलता है कि जल 29वें लेवल के ऊपर डिप के दूसरे पूर्वी डिप तथा 27वें लेवल से पूरे तीसरे डिप के विस्तार, जो संभवतया ज्ञात नहीं था, के बीच के योजक-स्थल में से डिप खदानों में घुसा था। लिखित बयान में यह बताया गया कि संप के क्षेत्र में सड़क मार्गों के विस्तार के परिकलन से यह प्रदर्शित होता है कि संप में 70,0000 गैलन जल जो स्टोइंग-आपरेशनों के कारण दिन में संप में पहुंचता था, से कहीं अधिक जल मात्रा की क्षमता थी। संप में इतनी जल मात्रा को आधे से भी कम प्रचालन शिफ्ट में पंपिंग करने की पर्याप्त क्षमता थी। आश्चर्य की बात यह है कि पांच लाख गैलन जल जो डिप-पार्श्व की खदानों में भर गया बताया गया है वह क्षेत्र से कैसे आ गया। 27वें लेवल से नीचे का संप केवल स्टोइंग जल को संचित करने के लिए प्रयुक्त होता था। अतएव, निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि जो साक्ष्य उपलब्ध है उनसे इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारणों और परिस्थितियों पर स्पष्ट प्रकाश नहीं पड़ता।

4.9 पक्ष सं. 3 अखिल भारतीय खान कार्मिक संघ जो प्रबंधक-वर्ग के एक हिस्से से संबद्ध संगठन है ने अपना लिखित बयान प्रदर्श 23 पर फाइल किया है। आश्चर्य तो यह है कि इसमें सड़क-दुर्घटनाओं में मरे लोगों के आंकड़े दिए गए हैं। खनन एक जोखिम भरा व्यवसाय है। यह कहा गया है कि कि इस दुर्घटना को उन अन्य दुर्घटनाओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिनमें मृतकों की संख्या कहीं अधिक होती है। 14-9-1983 के बाद, पानी के रेलें के कारण हुई चार दुर्घटनाओं-- 2-10-1983, 10-10-1983, 25-10-1983 और पूर्वी भुगतडीह कोयला खान की दुर्घटना जिसकी तारीख ज्ञात नहीं है की सूची दी गई है और यह सुझाव दिया गया है कि हुरिलाडीह कोयला खान की दुर्घटना की उपरोक्त दुर्घटनाओं के समकक्ष जांच की जानी चाहिए, एकाकी तौर पर नहीं। आगे यह भी सुझाव दिया गया है कि कोयला खान विनियम, 1957 और खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए ज्ञापन, खान अधिनियम, 1952 पर आधारित है। जिसका प्रारूप ब्रिटिश खान विनियमों के आधार को लेकर तैयार किया गया था किन्तु झरिया कोयला क्षेत्र की भू-विज्ञानीय और खनन-पर्यावरणात्मक स्थितियां ब्रिटेन के कोयला क्षेत्रों की स्थितियों से बहुत भिन्न हैं और इसलिए उन नियमों और ज्ञापनों की सुसंगतता चर्चा का विषय बन जाती है। आगे यह भी कहा गया है कि कोयले का उत्पादन निश्चित जोखिम उठाकर और यहां तक कि कभी-कभी जानबूझकर कोयला खान नियमों का उल्लंघन करके भी किया जाता है। जब तक सब ठीक चलता है और कोई दुर्घटना नहीं होती तब तक इस ओर जनता का ध्यान नहीं जाता किन्तु एक बार जब कोई जान लेवा दुर्घटना हो जाती है तो खान-प्रबंधक और पर्यवेक्षण-अमले के अधिकारी राष्ट्र के लिए कोयला पैदा करने हेतु किए गए अपने खनन कार्यों के कारण लोक-भर्त्सना का शिकार बन जाते हैं। दुर्घटना के कारणों को सूचीबद्ध करते हुए यह कहा गया है कि कोयला खानों द्वारा रखे गए पुराने नक्शे भले ही वे सही प्रमाणित कर दिए गए हों, सही स्वीकार नहीं किए जा सकते क्योंकि राष्ट्रीयकरण से पूर्व कोयला खानों के पास न तो सर्वेक्षण के मानक उपकरण थे और न ही पूर्णकालिक सर्वेक्षक। जैसा कि खान सुरक्षा महानिदेशालय के ज्ञापनों में निर्दिष्ट है, भूलों की कोई परिसीमा निश्चित नहीं की गई थी। भूमिगत अपरदन, छत का गिरना, फर्श का कास कट विस्थापन, अंश-तल के साथ-साथ स्तर का स्खलन इन सब को तथा पास पड़ोस के प्राकृतिक परिवर्तनों को जानने के लिए कोई साधन नहीं थे। समस्त पुरानी गैलरियों का मौजूदा सर्वेक्षण-उपकरणों से नए सिर से सर्वेक्षण कर पाना संभव नहीं है। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबंधक वर्ग ने किसी एक विशेष कारण का उल्लेख न करते हुए एक सामान्य मामला तैयार कर दिया है जिसमें प्रबंधक वर्ग की भूलों को क्षमा करने की ओर अधिक ध्यान दिया गया है।

4.10 प्रदर्शन 9 पर, पक्ष संख्या 4 यूनाईटेड कोल वर्कर्ज यूनियन, इंडियन माइन्स वर्कर्ज फैडरेशन तथा आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा दिया लिखित बयान है। दुर्घटना के दौरान क्या हुआ इस विषय में शुरू-शुरू में थोड़ी सी चर्चा के बाद यह कहा गया है कि कोयला खान का प्रबंधक वर्ग जल संचयन के लिये जान-बूझकर एक विशेष डिप गैलरी का प्रयोग कर रहा था। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रबंधक

वर्ग को इस डिप गैलरी के ड्राइवेज की सीमा की तथा इस तथ्य की पूरी जानकारी थी कि यह डिप गैलरी जलाक्रांत थी । यह भी बताया गया है कि जो विभाजक दीवार बनाई गई थी वह बिल्कुल पर्याप्त नहीं थी । और प्रबंधक वर्ग ने यह समझने में भूल की कि उनका मुख्य कर्तव्य खान और खान श्रमिकों को पानी में डूबने के किसी भी खतरों-विशेषतया उन स्थानों पर जहां भारी मात्रा में जल इकट्ठा हो जाता है से सुरक्षा सुनिश्चित करना है । यह कहा गया है कि प्रबंधक वर्ग ने कानूनी सुरक्षा-उपाय किये बिना ही, जानबूझकर 29वें लेवल के ठीक ऊपर जहां विस्फोटन, और कोयला निकालने का कार्य चालू था—जल संचित करके खान के कामगारों को खतरनाक स्थान पर काम पर लगा दिया था । यह उल्लेख किया गया है कि दुर्घटना से कुछ समय पहले 29वें लेवल की गैलरी की छत से ठीक ठंडे जल के भारी सीपेज हो रही थी । प्रबंधक वर्ग ने सीपेज के खतरों की ओर ध्यान नहीं दिया और पहले से ही वेध छिद्र करके, विभाजक दीवार की मोटाई का जायजा नहीं लिया । भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने आवश्यक सुरक्षा उपाय किये बिना ही खनन प्रचालनों को पुनः शुरू करने का जोखिम उठाया । चूंकि खान लंबे अर्से से बंद थी, इसलिये प्रबंधक वर्ग और खान सुरक्षा महानिदेशक के कार्यालय का यह कर्तव्य था कि वे खनन-कार्यों को पुनः शुरू करने से पहले पुरानी खदानों का स्वतन्त्र एवं सम्पूर्ण सर्वेक्षण करें । परिणामतः यह कहा गया है कि प्रबंधक वर्ग इस घातक दुर्घटना के लिये जो अधिनियम एवं विनियमों के सुरक्षा उपबन्धों की पूर्ण उपेक्षा के कारण हुई—पूरी तरह से जिम्मेदार है । यह भी कहा गया है कि खान सुरक्षा महानिदेशक का विभाग भी इसके लिये उत्तरदायी है क्योंकि स्पष्टतया इस ने **प्रबंधक वर्ग को अनुमति देने से पहले और 29वें लेवल के ड्राइवेज के दौरान भी** स्वतन्त्र सर्वेक्षण करके पूरी सावधानी नहीं बरती ।

4.11 पक्ष सं. 5 इन्टक और इसकी संबद्ध संस्थाओं ने लिखित बयान—प्रदर्श 10 फाइल किया है । यह कहा गया है कि दुर्घटना, आठ फुट व्यास वाले एक छिद्र के स्थान से अचानक बड़ी तेजी से लगभग 15 लाख गैलन पानी का रेला कार्य-स्थलों पर आ जाने के कारण हुई । इसमें कहा गया है कि दुर्घटना के बाद यह पता चला कि दोषपूर्ण खदानों/प्लानिंग के कारण, 27वें पूर्वी लेवल के मुख्य डिप के दूसरे सहवर्ती डिप का परिचालन लगभग 190 फुट पाया गया जो 29वें पूर्वी लेवल के अंताग्र से परे है जहां छिद्र हो गया था । छिद्र के संभव कारण इस प्रकार बताये गये हैं :—(1) संप में ज्यादा जल जमा हो जाना (2) डिप अंताग्रों में किये गये विस्फोटनों के कारण होने वाले कंप, (3) 29वें पूर्वी लेवल अंताग्र पर किये गये विस्फोटन और (4) जल की विद्यमानता जानते हुए भी किसी ने भी स्थल का निरीक्षण करने और डिप गैलरी के नीचे अर्थात् 29वें पूर्वी लेवल के साथ-साथ किसी भी गैलरी को परिचालित करने से पूर्व उस डिप गैलरी की वास्तविक स्थिति जानने का प्रयत्न नहीं किया । अतः यह कहा गया है कि प्रबंधक वर्ग ने कोयला खान विनियम 127 और 64 का उल्लंघन किया है क्योंकि विनियमों के अनुसार प्लानें नहीं रखी गईं । उन्होंने कोयला खान विनियम 127(3) में संशोधन करने और प्रत्येक कोयला खान में सुरक्षा अधिकारी तथा कामगारों के निरीक्षक की नियुक्ति करने के लिये अपने सुझाव दिये हैं ।

4.12 पक्ष सं. 6 इंडियन नेशनल माइन ओवर मेन, सिरदार्ज एंड शॉटफायरर्ज एसोसिएशन ने अपना लिखित बयान प्रदर्श 11 पर फाइल किया । अधिकांशतया इसमें सिरदारों, ओवरमेनों को प्लानें दिये जाने की बात कही गई है जिनमें कुछ भी स्पष्टतया प्रदर्शित नहीं किया गया था । गैलरियों की स्थिति सही तरीके से नहीं दिखाई गई थी । यह कहा गया है कि यह केवल सोचने की बात है कि 27वां पूर्वी लेवल दो स्तम्भों के विकास के बाद बंद कर दिया गया था और 28वां पूर्वी लेवल पश्चिमी अनुभाग के मुख्य डिप से केवल एक स्तम्भ के लिये विकसित किया गया था किन्तु 29वें और 30वें पूर्वी लेवल नियमित रूप से विकसित किये जा रहे थे । अतएव यह सुझाव दिया गया है कि प्रबंधक वर्ग को आस पास कहीं जल जमा रहने की जानकारी, सम्भवतया थी फिर भी उन्होंने 29वें लेवल के ड्राइवेज को बढ़ाते समय पर्याप्त सावधानियां नहीं बरतीं । उन्हें दिखाई गई प्लान गलत प्लान थी क्योंकि उसमें गलत प्रोजैक्शनें दिखाई गई थीं और इसमें प्रबंधक वर्ग ने विनियम 64, 65, 104, 126 और 127 का उल्लंघन किया है । बयान में न्यायालय को यह आश्वासन दिया गया है कि ओवरमैनों, माइनिंग सिरदारों और शाटफायरों ने अपनी अपनी ड्यूटियां बड़ी ईमानदारी और उचित तरीके से निभाई थीं ।

4.13 सी० आई० टी०यू० से संबंध संस्था की ओर से लिखित बयान प्रदर्श 8 पर दिया गया है । इसमें परिचय के तौर पर कहा यह गया है कि विभिन्न दुर्घटनाओं, और जीतपुर, चसनाला, केशरगढ़, सुदामडीह और खास निरसा कोयला खानों की दुर्घटनाओं के बाद नियुक्त जांच न्यायालयों की रिपोर्टों के बावजूद उनकी सिफारिशों को कभी क्रियान्वित नहीं किया गया है । यह तो जब व्यक्तियों की कीमती जानें चली जाती हैं तभी इस ओर ध्यान केन्द्रित होता है । यदि मौजूदा सुरक्षा कानूनों और पहले के जांच न्यायालयों द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया जाता है तो यह दुर्घटना बड़ी आसानी से टाली जा सकती थी । दुर्घटना का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि दुर्घटना के समय खान के अन्दर काम कर रहे व्यक्तियों ने यह कहा था कि पानी भर जाने से कुछ दिन पहले कार्य स्थल की छत से पानी रिस रहा था और इसकी रिपोर्ट अवर अधिकारियों को की गई थी किन्तु किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया । कामगारों ने यह दावा किया कि पानी की सीपेज सदा से विशेषतया 29वें लेवल के परिचालन के समय बहुत अधिक रही थी । अतएव यह कहा गया है कि यह दुर्घटना व्यक्तियों द्वारा स्वयं लाई गई विपत्ति थी । वास्तव में, वर्षा कोई बहुत अधिक नहीं हुई थी और नदियों अथवा नालों में कोई ऐसी बाढ़ नहीं आई थी कि पानी 29वें लेवल के ऊपर खान की कोटरों में इकट्ठा हो जाता जो प्रबंधक वर्ग की पूरी और स्पष्ट जानकारी में था । यह कहा गया है कि इस बात की संभावना है कि पहले के लेवलों की गैलरी की सही गहराई प्लानों में नहीं दिखाई गई हो । पानी जिस तेजी से बहा उससे इस सिद्धांत की पुष्टि होती है कि पानी कहीं ऊंचे लेवलों पर एकत्रित हो गया था । अतएव, जलाप्लावन कोई भूवैज्ञानिक कारणों से नहीं हुआ । जलाक्रांत क्षेत्रों के आस पास के खननों में संबंद्ध नियमों का पालन नहीं किया गया था । कोयला खान विनियम 127 का यह दिखाने के लिये हवाला दिया गया है कि किस प्रकार प्रबंधक वर्ग इसका पालन नहीं करता रहा है । आगे यह भी कहा गया है कि दोषपूर्ण संवातन प्रणाली भी कामगारों द्वारा लगाये गये आरोपों में से एक है जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है । इससे यह प्रदर्शित होता है कि सुरक्षा की तरफ प्रबंधक वर्ग का रुख कितना उपेक्षापूर्ण था । जहां तक खान सुरक्षा महानिदेशक के कार्यालय का संबंध है, यह कहा गया है कि संगठन की स्थिति दयनीय है जिससे यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र में सुरक्षा की तरफ सरकार का रवैया कितना लापरवाही से भरा हुआ था । लगभग 500 कोयला-खानें और 8600 गैर-कोयला खानें हैं, इनके लिये खान सुरक्षा महानिदेशक के अधीन कुल स्टाफ संख्या उपलब्ध जानकारी के अनुसार केवल 844 है जिसमें निरीक्षण, मुख्यालय के कार्य के लिये प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी तथा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी शामिल हैं । खान की सुरक्षा की दृष्टि से, तीन महीने में कम से कम एक बार तो जांच की ही जानी चाहिये किन्तु विद्यमान स्टाफ एक वर्ष में एक बार भी निरीक्षण के लिये अपर्याप्त है । इस खान का खनन सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा पिछले छः महीने में निरीक्षण नहीं किया गया था जिसका कारण स्टाफ की अल्पता थी । घटना के जिम्मेदार कारणों को सूचीबद्ध करते हुए यह कहा गया है कि पहले के न्यायालयों द्वारा की गई सिफारिशों की घोर उपेक्षा करते हुए उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया था, कोयला खान विनियमों विशेषतः कोयला खान विनियम 127

का आपराधिक उल्लंघन किया गया था तथा खानों में लापरवाही से अंधाधुंध खनन किया जा रहा था और अधिकारियों द्वारा पर्याप्त पर्यवेक्षण नहीं किया गया था।

4.14 प्रदर्श 6 में दो बयान दिए गए हैं एक जनता मजदूर संघ द्वारा तथा दूसरा कोयला इस्पात मजदूर पंचायत और हिंद मजदूर संघ, बिहार द्वारा दिया गया है ये दोनों बयान लगभग एक जैसे ही हैं। इनके अनुसार रात की शिफ्ट में काम करने वालों को खान में किसी खतरे के संबंध में कोई नोटिस या पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। खानों का दैनिक निरीक्षण करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था और प्लान का सावधानी से अध्ययन नहीं किया गया था। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने प्रभावी सुरक्षात्मक विनियम बनाए बिना ही कोयला खान को फिर से चालू कर दिया। काम बड़ी जल्दी जल्दी शुरू किया गया था। इस घातक दुर्घटना में खान विभाग द्वारा की गई घोर उपेक्षा का बड़ा हाथ है। काफी समय तक तो छत की मोटाई अपर्याप्त थी। दुर्घटना के पहले पानी का भारी रिसाव था जिसके परिणामस्वरूप छत की मोटाई कटती गई किंतु इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह कहा गया है कि यह प्रबंधक वर्ग की जानकारी में था कि 1200 लाख गैलन से भी अधिक पानी ऊपरी सीमा में बालू के साथ-साथ जमा था, इस पर भी उन्होंने कोई सावधानी बरते बिना कार्य को जारी रखा। यह कहा गया है कि उनकी जानकारी के अनुसार, दुर्घटना से 2-3 दिन पहले से ही पम्प खराब था और जब कामगारों ने प्रबंधक वर्ग को यह रिपोर्ट की कि वे सीम को पानी से खाली करने के लिए कोई उपाय करें तब भी प्रबंधक वर्ग ने कुछ नहीं किया अथवा उनके सुझाव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस संगठन का यह भी कहना है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय के कार्यालय में स्टाफ की कमी है स्टाफ को अपर्याप्त वेतन तथा अल्प सुविधाएं दी जाती हैं। ऐसी स्थिति में खानों का अक्सर निरीक्षण नहीं किया जाता। दुर्घटना के कारणों को गिनाते हुए यह कहा गया है कि कोयला खान विनियमों के उपबंधों के अनुपालन में घोर उपेक्षा की गई। खान में ताबड़तोड़ खनन कार्य, खान सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त पर्यवेक्षण, पहले के जांच न्यायालयों की सिफारिशों को कार्यरूप न दिया जाना, कामगारों की शिकायतों और उनके सुझावों की नितांत अवहेलना, खान खनन अंतरालों का समुचित सर्वेक्षण न करवाया जाना और वेध छिद्र न बनाए जाना—इन सब के कारण दुर्घटना हुई।

4.15 प्रदर्श 24 पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रबंधक वर्ग द्वारा पेश प्रत्युत्तर है। इस आरोप के कि कामगारों को पहले से चेतावनी नहीं दी गई उत्तर में यह कहा गया है कि इस प्रकार के खतरे का कोई पूर्वाभास नहीं था। वे इस बात को अस्वीकार करते हैं कि खान का नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा था। वे यह खंडन करते हैं कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने कोयला खान को सुरक्षा विनियम का अनुपालन किए बिना पुनः चालू कर दिया अथवा यह कि खान को अंधाधुंध शुरू किया गया था या फिर दुर्घटना से पहले पानी का भारी रिसाव था या किसी प्रकार का कोई सीपेज था। यह कहा गया है कि मुख्य डिप के 27वें और 29वें पूर्वी लेवल खान की प्लान पर दिखाए प्रोजेक्शन के अनुसार ही परिचालित किए गए थे। पहले के जांच न्यायालयों की सिफारिशों को क्रियान्वित न किए जाने की बात का भी खंडन किया गया है। प्रबंधक वर्ग ने कोई तथ्य दबाया नहीं है। विशेषतया, यह अस्वीकार किया गया है कि पानी का ऐसा 15 लाख गैलन था। 29वीं पूर्वी गैलरी का ड्राइवेज दुर्घटना से बहुत पहले बंद कर दिया गया था किंतु तीसरी डिप अभी परिचालित थी जहां दुर्घटनावश संयोजन हो गए। उनका कहना है कि 29वें पूर्वी लेवल और स्टोइंग पम्प के बहाव पार्श्व के बीच पर्याप्त मोटाई वाली कोयले की अवरोधिका, खान में उपलब्ध कानूनी खान प्लान के आधार पर ही खड़ी की गई थी। उनके अनुसार, कोयला खान विनियम 127 लागू नहीं किया जा सकता और इसी कारण खान सुरक्षा महानिदेशक की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं थी।

4.16 अखिल भारतीय खान कामगार संघ ने भी एक प्रत्युत्तर प्रदर्श 25 के द्वारा पेश करना उचित समझा जिसमें यह कहा गया है कि कोयला खान नियम 127 लागू नहीं किया जा सकता और यह भी कि इन्क्लाइन कोयला खान के संदर्भ में, भूमिगत पानी को सीम अवस्था में पंपिंग करने में पर्याप्त सावधानी बरती गई थी। यह कहा गया है कि सभी पुरानी खानों में, सभी खदानों का नए सिरे से सर्वेक्षण छतों के गिर जाने, पानी संचयनों, कीचड़ और मक के निक्षेपों आदि के कारण संभव नहीं होता। यह अस्वीकार किया गया है कि खान दुर्घटनाओं में उत्तरदायित्व खनन इंजिनियर का होता है और संदेह का लाभ अभियोजक को दिया जाता है। किसी भी मौके पर दुर्घटनाग्रस्त डिप गैलरी के ड्राइवेज की लंबाई के बारे में कोई शंका व्यक्त नहीं की गई। पुरानी खानों में पुनः सर्वेक्षण के लिए मक और अवपातों को हटाने के लिए प्रत्येक डिप गैलरी को पानी से खाली करना संभव नहीं है। अतः पुरानी प्लानों पर निर्भर रहना ही होता है। यह भी कैफियत दी गई कि खान सुरक्षा महानिदेशालय अपने बचाव के लिए फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है।

4.17 पक्ष संख्या 4 द्वारा प्रदर्श 27 पर पेश प्रत्युत्तर से यह प्रदर्शित होता है कि प्रबंधक वर्ग ने प्लानों की शुद्धता से संबंधित विनियम 65 का अनुपालन नहीं किया। यह बताया गया है कि अगम्य अथवा जलाक्रांत खदानों सहित सभी खदानों का नए सिरे से व्यापक सर्वेक्षण आवश्यक है। सम्बद्ध प्लान पर स्पाट लेवल नहीं दिखाए गए हैं। प्लान 30-6-1983 तक अद्यतन दिखाई गई है किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं था। क्रास कट के 27वें लेवल का सर्वेक्षण किया जा चुका है। पश्चिम में, 26वें लेवल का मुख्य डिप पहले ही दिखाया जा चुका है। मुख्य डिप से परे का क्रास 29वीं पूर्वी लेवल बिल्कुल नहीं दिखाया गया है, हालांकि अब यह पता चला है कि छेद (पंक्चर) 29वें पूर्वी लेवल के खदान के समय हुआ था। 29वें लेवल को न दिखाए जाने से यह संकेत मिलता है कि सर्वेक्षण के समय यह डिप सम्भवतया जलाक्रांत था। दुःख की बात है कि प्रबंधक वर्ग के उच्चाधिकारियों और खान सुरक्षा महानिदेशालय के यह कभी ध्यान में नहीं आया कि बिन्दुकित डिप गैलरी कार्य प्लान में जहां तक परिचालित दिखाई गई है, संभवतया उससे कहीं आगे तक परिचालित की गई हो। यदि प्लान को अद्यतन रखा गया होता तो यह स्पष्ट होता कि 29वें पूर्वी लेवल का ड्राइवेज कोयला खान विनियम 127 में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार पहले से ही वेध छिद्र निकाले बिना, टगर डिप से परे तक नहीं किया जा सकता था। अतएव प्रबंधक वर्ग जलाप्लावन के खतरे का पूर्वानुमान नहीं लगा सका और उसने इस संबंध में विनियमों और ज्ञापनों का अनुपालन करने में उपेक्षा बरती। अतएव यह कहा गया है कि दुर्घटना इस भूल के कारण तथा अन्य कोयला खान विनियमों का अनुपालन न करने के कारण हुई तथा प्लानों को अद्यतन न रखे जाने के कारण उन की शुद्धता चर्चा का विषय बनी रही।

4.18 पक्ष सं. 7 ने प्रदर्श 28 पर अपने प्रत्युत्तर में इस तथ्य पर स्पष्ट प्रकाश डाला है कि दुर्घटना भूवैज्ञानिक विक्षोभों के कारण नहीं हुई। यह कहा गया है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा दर्ज बयान लगभग एक औपचारिकता ही है। सी. ई. टी. यू. द्वारा दर्ज बयान के बारे में यह कहा गया है कि यह अस्पष्ट है। उसके अनुसार पानी का रिसाव सामान्य और रोजमर्रा की तरह था। इस बात पर जोर दिया गया है कि कोई भी कामगार अपने जीवन को खतरे में नहीं डालेगा और यदि कहीं पानी का रिसाव हो तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वह अपने तथा अपने सहयोगियों के जीवन को खतरे में समझ कर भी इसकी रिपोर्ट न करें। संकेत किया गया है कि खान सिरदार धर्मू चौहान इस दुर्घटना में मृत्यु का शिकार बने। यह कहा गया है कि उन जैसे व्यक्ति यदि वास्तव में पानी का असाधारण रिसाव देखते तो इसकी रिपोर्ट अवश्य करते।

प्रयुक्त क्रियाविधि

4.19 लिखित बयान प्राप्त हो जाने के बाद साक्ष्य को रिकार्ड करने के लिए जो प्रणाली अपनाई गई उसके अनुसार पक्षों तथा उनके गवाहों को हलफनामा फाइल करने के लिए कहा गया। ये हलफनामें एक साथ फाइल किए जाने थे ताकि किसी भी गवाह या किसी भी पक्ष को किसी दूसरे गवाह या पक्ष द्वारा फाइल किए गए हलफनामों का अध्ययन करने तथा उसी के अनुसार अपना हलफनामा तैयार करने का मौका न मिले।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली का अनुसरण करने से पक्ष समर्थन में परिवर्तन की संभावना नहीं के बराबर हो गई और दूसरों के साक्ष्यों को देख सुन कर साक्ष्य देने की प्रवृत्ति पर रोक लग गई। फिर भी हलफनामें प्राप्त हो जाने पर पक्षों को एक और मौका दिया गया कि वे अन्यों द्वारा फाइल किए गए हलफनामों के प्रकाश में अपने बयानों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त हलफनामे पेश करें प्रबंधक वर्ग के दो गवाहों के हलफनामों को छोड़कर वस्तुतः कोई भी अतिरिक्त हलफनामा प्राप्त नहीं हुआ। ये दो हलफनामें भी दुर्घटना की तारीख के बाद प्रबंधक वर्ग द्वारा किए गए सर्वेक्षण को स्पष्ट करने के लिए पेश किए गए थे। वह सर्वेक्षण जांच न्यायालय की नियुक्ति के बाद, न्यायालय को इसकी सूचना दिये बगैर ही किया गया था। किंतु किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं उठाई। सर्वेक्षण में पुरानी प्लान में पाई गई गलतियों की ओर संकेत किया गया है।

4.20 प्राप्त हलफनामें सुनवाई के समय प्रमुख जांच के रूप में लिए गए। दूसरे शब्दों में, गवाह के 'बाक्स' में प्रवेश करने के तुरन्त बाद उससे यह पूछा गया कि हलफनामें में दी गई सूचनाएं सही हैं या नहीं और उसके द्वारा यह स्वीकार कर लिए जाने के तुरन्त बाद उसे जिरह के लिए पेश किया गया।

4.21 सारी कार्यवाहियों पर दो विरोधी पक्षों की कार्यवाहियों के रूप में पुनः विचार किया गया। एक तरफ प्रबंधक-वर्ग के विचारों का पक्ष था और दूसरी तरफ उनका विरोध पक्ष अतएव जिरह के समय, प्रबंधक-वर्ग के गवाह पहले जिरह के लिए उन यूनियनों को पेश किए गए जिन्होंने प्रबंधक वर्ग का पक्ष लिया था और इसके बाद इन के स्थान पर कर्मचारियों की प्रतिनिधि यूनियनें आईं। इसी प्रकार जब प्रबंधक वर्ग का पक्ष लेने वाले संघ ने गवाह पेश किया तो पहले उनके बीच जिरह पूरी की गई और उसके बाद गवाह को कर्मचारियों की प्रतिनिधि विरोधी यूनियनों को पेश किया गया। केवल एक यूनियन "इंडियन नेशनल माइन ओवरमेन एवं सिरदारस एसोसिएशन" ने एक गवाह की जांच की। उस मामले में जिरह पहले कर्मचारियों के प्रतिनिधि एक यूनियन दल तक सीमित कर दी गई थी और उसके बाद गवाह को दूसरे पक्ष को पेश कर दिया गया।

अध्याय 5

5.1 प्रबंधक वर्ग को सबसे पहले साक्ष्य देने के लिए कहा गया। कुल मिलाकर उन्होंने 9 गवाहों की परीक्षा की है। भारतीय खान कामिक संघ जो प्रबंधक वर्ग के पक्ष में है, की ओर से दो अन्य गवाहों की परीक्षा की गई और एक अन्य गवाह की परीक्षा कामिक संघ (एम्प्लाईज एसोसिएशन) जिसका प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्रीय खान ओवरमेन, सिरदार और शाट फायरर्ज संघ है, ने की। पूरे मामले में साक्ष्य के नाम पर यही कुछ था। हालांकि अन्य कई यूनियनें भी इसमें भाग ले रही थीं किन्तु उन्होंने इन गवाहों की जिरह तक ही स्वयं को सीमित रखा। अतएव न्यायालय ने पुराने समय के जब संबद्ध लेवल परिचालित किए गए थे। प्रबंधक और सर्वेक्षक तथा उस पम्प खलासी की भी परीक्षा करने का निर्णय किया जो दुर्घटना के समय पम्प पर काम कर रहा था। खान सुरक्षा महानिदेशालय के दो वरिष्ठ अधिकारी और एक सर्वेक्षक जो दुर्घटना के तुरन्त बाद दुर्घटना स्थल पर गए थे उनकी भी अदालती गवाहों के रूप में परीक्षा की गई। कुल मिलाकर इस तरह के गवाह 7 थे।

5.2 प्रबंधक वर्ग की ओर से गवाह 2, 3 और 4 लोडर, ड्रिलर और शाटफायरर हैं जिन्होंने अंताग्र पर दुर्घटना से तुरन्त पहले के समय काम किया था। गवाह सं. 1 सर्वेक्षण अधिकारी है जिन्होंने दुर्घटना के बाद प्लान प्रदर्श 42 तैयार की थी। उन्होंने पुरानी प्लेन के दोष निकाले जिसके बारे में कहा गया है कि उसे देखकर प्रबंधक-वर्ग गुमराह हो गया और उसने यह विश्वास कर लिया कि वे पानी से काफी दूर है। उन्होंने विद्युत इंजनियर, कार्यकारी इंजनियर, प्रबंधक, संबद्ध सर्वेक्षक तथा एजेंट की क्रमशः गवाह सं 5, 6, 7, और 8 के रूप में परीक्षा की। इन गवाहियों के निहितार्थों पर बहस करने अथवा इनसे जो चित्र उभर कर आता है उसे जानने से पहले यह उपयोगी होगा कि इन का संक्षिप्त सार तैयार कर लिया जाए।

प्रबंधक-वर्ग के गवाह

5.3 गवाह सं. 1 सर्वेक्षक सुनील भट्टाचार्य जो दुर्घटनाग्रस्त खदान का, इंडियन स्कूल आफ माइन्ज, धनबाद द्वारा उन्हें दिए गए चौदहवीं मास के निदेशकों के साथ किए गए संद-परिपथ-सर्वेक्षण की बात करते हैं। इस पुनः सर्वेक्षण के निष्कर्ष में मुख्य डिप क्षेत्र के संदर्भ में 29वें लेवल की स्थिति वही बताई गई थी जो उपलब्ध प्लान में दिखाई गई थी, किन्तु पूर्वी पार्श्व में 27वें लेवल के क्षेत्र में इसकी अपनी स्थिति के दक्षिण की ओर लगभग 45 फुट का डिपोन्मुख शिफ्ट दिखाई गई है। इस गवाह के अनुसार, प्लान पर दिखाई गई बिंदुकित रेखा का अर्थ यह है कि गैलरी का विस्तार तो ज्ञात है किन्तु इसके ब्यौरे ज्ञात नहीं हैं।

5.4 गवाह सं. 2 घनश्याम मंडल लोडर रात के नौ बजे से प्रातः नौ बजे तक चलने वाली तीसरी शिफ्ट में 13-9-1983 को कार्य कर रहे थे। उनके गैंग ने 4 बजे तक, 29वें पूर्वी लेवल में 7 टब भारित कर लिए थे। जब और ज्यादा काम करने के लिए कहा गया तो सिरदार स्वर्गीय धर्मू चौहान ने उसके गैंग को यह सूचना दी कि तीसरे डिप में छत की स्थिति अच्छी नहीं है और उन्होंने गैंग को सहवर्ती डिप में चले जाने के लिए कहा। उनके एक सहकर्मी कालिशा भी धर्मू चौहान के साथ दूसरे डिप की ओर गए। प्रातः लगभग पांच-साढ़े पांच बजे, 29वें लेवल के दूसरे और तीसरे डिपों के बीच बाड़ा लगा दिया गया, उसके कुछ समय बाद, गवाह को तीसरे डिप अंताग्र से अपनी टोकरी और गावल उठाने के लिए जाना था किन्तु जैसे ही वे डिप संयोजन स्थल से आगे बढ़े उन्हें कुछ चटकने की सामान्य आवाजें सुनाई दीं और पानी की रेखा, बाहर की ओर बह निकली। अतः उन्होंने "पानी, पानी" का शोर मचाया और स्वयं अन्यों के साथ सुरक्षा स्थान की ओर दौड़े। वे आश्वस्त हैं कि जब वे नीचे खान में गए तो उन्होंने पानी का कोई सीपेज नहीं देखा था और सिरदार ने छत की जांच की थी। उनके अनुसार, 29वें पूर्वी लेवल दुर्घटना से चार-पांच दिन पहले बंद कर

5.5 प्रबंधक वर्ग के गवाह सं. 3 ड्रिलर हरी पंडित 13-9-83 को तीसरी शिफ्ट में, शाट छिद्र ड्रिल करने के लिए 29वें पूर्वी लेवल के तीसरे डिप अंताग्र (फेस) पर गए थे, किन्तु वे ड्रिल किए बिना ही लौट आए क्योंकि कुछ कोयला हटाना अभी शेष था। वे दूसरे अंताग्रों पर गए। इसके कुछ समय बाद, उसने धर्मू चौहान के आदेशानुसार तीसरी डिप में, जब अंताग्र से कोयला हटा लिया गया, छः शाट छिद्र ड्रिल कर लिए थे। उस समय पानी की सीपेज नहीं थी। अंताग्र बिल्कुल ठीक था और 29वें पूर्वी लेवल सामान्य दिखाई दे रहा था। उन्होंने छत को गिरते नहीं देखा किन्तु उसने दूसरों की चिल्लाहटों को सुना। पानी की जांच के लिए कभी कोई छिद्र नहीं बनाए गए थे। खान सुरक्षा महानिदेशालय के समक्ष उन्होंने कहा कि उन्होंने पानी का थोड़ा सा रिसाव देखा और यह भी कि छत की स्थिति अच्छी नहीं थी।

5.6 गवाह सं. 4 काली प्रसाद मंडल खनन-सिरदार एवं विस्फोटकारी है। ये 13-9-1983 को तीसरी शिफ्ट में काम पर लगाए गए। कुछ काम करने के बाद उन्हें 29वें लेवल के अंतिम पूर्वी डिप में छः छिद्र चार्ज करने के लिए कहा गया। जब वे वहां गए तो उन्होंने छत में कुछ चटकने की आवाज सुनी और कोयले के 3/4 पौने इंच से एक इंच मोटे भारी टुकड़े छत से गिर रहे थे। ओवरमेन और खनन-सिरदार धर्मू

चौहान ने स्थल का निरीक्षण किया और लेवल अताग्र से 50 फुट पश्चिम में [illegible] बाद गवाह घनश्याम मंडल ने शोर मचाया और सभी वहां से दौड़ने लगे। उनके अनुसार, पानी तेजी से डेढ़ से दो मिनट के अन्दर ही 28वें लेवल के ऊपर आ गया था। गवाह इस बात की पुष्टि करता है कि 29वां पूर्वी लेवल दुर्घटना से 4-5 दिन पहले बंद कर दिया गया था।

5.7 गवाह के अनुसार, 90 हार्स पावर का पम्प तीन साढ़े तीन स्तम्भ परे स्थित था अर्थात् यह टगर डिप से 120 फुट दूर था। यह न तो फर्श के लेवल और न ही छत के लेवल पर बल्कि बीच में 7-8 फुट की ऊंचाई पर लगाया गया था। उनकी गवाही से यह प्रदर्शित होता है कि 12 सितम्बर, 1983 तक 20वां लेवल परिचालित था और उसके बाद विस्फोटन रोक दिया गया।

5.8 प्रबंधक-वर्ग के गवाह सं. 5 मुहम्मद मुस्ताक खां उस पम्प के, जो उनके पर्यवेक्षण में लगाया गया था प्रभारी सहायक इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिकी) थे। यह 26वें लेवल से नीचे, 27वें लेवल से 15-20 फुट दूर था और वहां काम कर रहा था। दुर्घटना के बाद उन्होंने 14-9-1983 के प्रातः 6-30 बजे पानी निकालने के लिए पम्प को वहां से हटा कर मुख्य डिप तक ले जाने का काम किया। यह बात उन्होंने जिरह के दौरान कही है। संप से पानी निकालने के बारे में उनका अनुमान स्टोइंग चालू न होने की स्थिति में एक घंटा और स्टोइंग चालू रहने की स्थिति में 4 घंटे था। उनके अनुसार पम्प और टगर डिप के बीच का अन्तर लगभग 100 फुट था।

5.9 प्रबंधक-वर्ग का गवाह संख्या 6 कादुट सत्य नारायण कार्यकारी इंजीनियर है। उनका कहना है कि पम्प की क्षमता 400 गैलन प्रति मिनट थी और यह 90 हार्स पावर की मोटर द्वारा चालू किया जा रहा था। यह क्रास-कट डिप के पश्चिमी पार्श्व में 26वें लेवल के नीचे लगाया गया था, चूषण नली लगभग 100 फुट थी और फुट-वाल्व 2-3 फुट नीचे था। इस पम्प में क्रास कट के पश्चिम की ओर लगभग 27वें लेवल तक पानी निकालने की क्षमता थी। गवाह का कहना है कि मुख्य डिप को पानी से खाली करने में 16 की पूरी रात लग गई। अतएव उनका अनुमान है कि बीच के 3 दिनों के रिसाव सहित लगभग 9 लाख गैलन पानी निकाला गया था। उनका आगे यह कहना है कि डिप के फुट-वाल्व से परे की खदानें सदा जलप्लावित रहती थीं।

5.10 गवाह सं० 7, प्रबंधक पीतैश कुमार भट्टाचार्य ने 12-9-1982 को कार्यभार संभाला। वे भूमि के नीचे गए और उन्होंने यह पाया कि तीसरी डिप गैलरी संचित जल के समीप तक जा लगी थी जिसके कारण दुर्घटना हुई। वे दुर्घटना के बाद के सर्वेक्षण का उल्लेख करते हैं जिससे यह पता चलता है कि तासक डिप गैलरी की लम्बाई 40 फुट दिखाई गई थी जबकि वास्तव में उसकी लम्बाई लगभग 100 फुट पाई गई। गवाह के अनुसार, सम्प को पानी से खाली रखने के लिए 90 हार्स पावर का पंप पर्याप्त था।

5.11 वे डिप की तरफ के ऐसे क्षेत्र, जिसमें से अभी तक कोयला नहीं निकाला गया, को विकसित करने के निर्णय का भी हवाला देते हैं। साथ ही 'ई' क्षेत्र में पानी के चढ़ाव की तरफ के स्तम्भ हटाने के साथ उन्होंने यह निर्णय भी लिया था कि 29वें लेवल के पहले डिप को, जो अन्य ड्राईवेजों के बीच उपयुक्त विभाजक दीवारें खड़ी करके संप से दूर माना जाता था, परिचालित किया जाए। इस ड्राईवेज को इस तरह से अलग किया गया ताकि यह सीम के तल को छूने लगे और भविष्य में ड्रेनिंग भी मुकर बना सके। इसे क्रास कट के पश्चिम में 27वें लेवल से मिलाने का कोई इरादा नहीं था। अतएव, 29 वें पूर्वी लेवल का ड्राईवेज 9 अथवा 10 सितम्बर को छोड़ दिया गया और 29वें लेवल के तीसरे डिप का विकास शुरू कर दिया गया लेकिन प्लोटिंग में त्रुटि के कारण केवल एक बारीक सी दरार छूट गई।

5.12 जिरह के दौरान गवाह ने बताया कि जिस कार्य प्लान का उसने प्रयोग किया वह आरेखण कागज पर बनी हुई थी क्योंकि उस समय माउंटेड कागज वाला नक्शा तैयार किया जा रहा था। अनुरेखण कागज वाला नक्शा अदालत के पास नहीं है। गवाह का कहना है कि कार्यभार संभालने के समय उसे यह कतई शक नहीं था कि नक्शा गलत है क्योंकि रोजमर्रा के कार्य में उसने गैलरियों को अपेक्षा के अनुरूप जुड़ा हुआ पाया था।

5.13 गवाह यह स्वीकार करता है कि उसे प्रत्येक त्रैमासिक सर्वेक्षण के पश्चात् प्लान पर हस्ताक्षर करने होते थे आगे वे यह भी कहते हैं कि उन्होंने यह हस्ताक्षर जरूर किए होंगे। संभवतः वे इस तरह के जवाब की कमजोरी को समझते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि सर्वेक्षक ने उन्हें यह बताया था कि वह वर्किंग प्लान और माउंटेड प्लान दोनों पर अंकन कर रहा है और कार्य समाप्त हो जाने के बाद माउंटेड प्लान पर उसे हस्ताक्षर करने होंगे। गवाह का कहना है कि सर्वेक्षक श्री एस. एस. मुकर्जी ने जुलाई के अंत में या अगस्त, 1983 में कभी उन्हें यह बताया था कि वे नए सिरे से सर्वेक्षण कर रहे हैं। उनका कहना है कि 15 जुलाई, 1982 को जब उन्होंने कार्य ग्रहण किया तो उस समय पुनः सर्वेक्षण का काम चालू था। वे यह भी उल्लेख करते हैं कि दो लेवल अर्थात् मुख्य डिप के पूर्व में 26वां लेवल और पूर्वी क्रास कट के पश्चिम का 25वां लेवल एक दूसरे से मिल गए थे और वस्तुतः एक ही लेवल बन गए थे।

5.14 90 हार्स पावर के पम्प के बारे में गवाह का कहना है कि यह पूर्वी क्रास कट के पश्चिम में स्थित 26वें लेवल के ठीक नीचे लगा था और पूर्वी चढ़ाई क्षेत्र पर पप के नीचे की खदानों से संप बना था। गवाह के अनुसार, नक्शे पर दिखाई गई तारांकित रेखा का तात्पर्य यह है कि खदानों का विस्तार तो निश्चित अथवा ज्ञात है किन्तु इसके अन्य ब्यौरे ज्ञात नहीं हैं। यहां अन्य ब्यौरों का अर्थ ऊंचाई और चौड़ाई है। गवाह का यह भी कहना है कि चौदहवीं सीम का खदान कार्य एक ही भाग में हो रहा था। इसमें समुचित अनुप्रस्थता नहीं बनाए रखी गई।

5.15 गवाह के अनुसार 29वें लेवल का विकास मुख्य डिप की पूर्वी दिशा में लगभग 360 से 380 फुट तक किया गया किंतु प्रदर्श 43 में यह 200 से 220 फुट प्रतीत होता है। गवाह ने यह उल्लेख किया कि 27वें पूर्वी लेवल के सामने के हिस्से और सम्प-खदान के बीच लगभग 60 फुट की एक कोयले की दीवार थी। 28वां लेवल टगर डिप से परे 15 फुट से अधिक परिचालित नहीं किया गया क्योंकि दूसरी ओर एक सम्प का होना आवश्यक था। उन्हें यह आशंका थी कि बिजली फेल हो जाने के कारण, जमा पानी को हटाने के लिए पानी के पंप का जितना प्रयोग आवश्यक होता है, उतना नहीं किया जा सकेगा। अतः इसके लिए भारी क्षमता वाले एक सम्प की आवश्यकता थी। उनका कहना है कि चूंकि इसमें पर्याप्त फासला रखा गया था इसलिए कोयला खान विनियम 127 (1) लागू नहीं किया जा सकता और चूंकि सम्प त्यक्त खान नहीं होता इसलिए कोयला खान विनियम 127 (3) लागू नहीं होता। उन्होंने कहा है कि मुख्य डिप से 28वां, 29वां और 30वां लेवल उनके कार्यकाल के दौरान परिचालित किए गए थे। 29वां लेवल थोड़ा सा चढ़ाई की ओर कर दिया गया जिससे कि वह तल को छूने लगे। 28 वें पूर्वी लेवल का फेस टगर डिप से थोड़ा पहले 16-7-83 को बंद कर दिया गया। गवाह आगे यह कहता है कि पूर्वी क्रास कट के 27 वें पश्चिमी लेवल के दूसरे डिप में कोयला उत्पादन नहीं किया जा रहा था। इसका प्रयोग सम्प के रूप में हो रहा था 27वें लेवल के पश्चिमी सिरे से कोयला नहीं निकाला जा रहा था। पूर्वी क्रास कट के 27वें पश्चिमी लेवल की चार डिप गैलरियों में थोड़ा

या पानी, कीचड़ और रेत आदि थे । 90 हार्स पावर का पंप इन्हें पानी से खाली नहीं कर सका था । मुख्य डिप और चौथे डिप के बीच की दूरी लगभग 240 फुट है। 27 वें पूर्वी लेवल और 29 वें पूर्वी लेवल को भी बंद करने का निर्णय किया गया जिससे कि ये संप के साथ न जुड़ें । 29 वें लेवल को परिचालित किए गए बिंदु तक ही परिचालित करने का उद्देश्य सम्प के डिप सिरे की ओर की खादानों तक के क्षेत्र का विकास करना था । उन्हें उपलब्ध नक्शे के अनुसार सम्प और 29 वें पूर्वी लेवल के बीच एक सुरक्षित बैरियर मौजूद था ।

5.16 27वें पश्चिमी लेवल के तीसरे डिप और 29 वें पूर्वी लेवल के तीसरे डिप के तल के बीच विभाजक दीवार कहीं 5 फुट तो कहीं 9 इंच हीं थी । यह बात दुर्घटना के बाद सामने आई । गवाह का कहना है कि दुर्घटना दोहरी गलती के कारण हुई । 100 फुट का ड्राइवेज 40 फुट का दिखाया गया था और शिफ्ट में हुई 60 फुट की गलती को मिलाकर कुल 100 फुट की गलती हो गई थी । फिर भी, वे कहते हैं कि यहाँ कोयला खान नियम 104 (2) लागू नहीं होता क्योंकि दो खंडों में विकास करने का कोई इरादा नहीं था ।

5.17 गवाह के अनुसार, सितम्बर, 1983 में पानी के इकट्ठा होने की दर, जिसमें भरा पानी शामिल नहीं है, प्रतिमिनट लगभग 200 से 300 गैलन थी । उनका कहना है कि दुर्घटना के तुरन्त बाद जब उन्होंने दुर्घटना-स्थल का निरीक्षण किया तो उस समय पूर्वी क्रास कट के 27 वें पश्चिमी लेवल पर कोई अधिक पानी नहीं था । यह कीचड़ से 1 से 1½ फुट ऊंचा था । फुट वाल्व सम्प के नजदीक पानी कीचड़ और बालू के अवरोध के कारण रुक जाता था किंतु अक्सर एक नाली निकाल कर उसे हटा दिया जाता था । 27वें लेवल के लिए ऐसी कोई नाली नहीं थी और यही कारण है कि 27वें लेवल सामान्य परिस्थितियों में भी सूखा नहीं रखा जा सकता था । उन्होंने इसे मानने से इंकार किया कि दुर्घटना के समय बह रहे पानी की मात्रा 9 लाख गैलन थी । वे अपने इस अनुमान को ही सही समझते हैं कि पानी की मात्रा 27वें लेवल तक 7 लाख गैलन थी । उनका कहना है कि [सम्प जलाक्रांत क्षेत्र नहीं है क्योंकि जलाक्रांत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें पानी खड़ा रहता है । वे यह स्वीकार नहीं करते कि 27वे लेवल का तीसरा डिप जो कि त्रासक गैलरी है, जलाक्रांत क्षेत्र था । वे यह मानते है कि सम्प दिनांक 13-9-1983 को जिस रूप में था उसमें 20 लाख गैलन पानी भरने की क्षमता थी। उन्हें यह स्मरण नहीं कि अपनी पदावधि में उन्होंने, कोयला खान विनियम 60 के अन्तर्गत अपेक्षित प्लानों की प्रतियाँ प्रस्तुत की थीं या नहीं। उन्होंने 27 वें पश्चिमी लेवल के पहले, दूसरे, तीसरे डिपों को सुखाने का कोई प्रयत्न नहीं किया था। उन्होंने 27वे लेवल को सूखा किंतु कीचड़ और कचरे से भरा पाया था और यह अनुमान लगा लिया था कि डिप भी इसी प्रकार के होंगे ।

5.18 गवाह सं० 8 सर्वेक्षक श्याम मुकर्जी हुरिलाडीह कोयला खान में जुलाई 1978 से काम कर रहे थे । वे भारतीय सर्वेक्षण की ज्योदातिक अनुसंधान शाखा द्वारा, पूरे कोयला क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किए गए सर्वेक्षण का जिक्र करते हैं । वे दुर्घटना के बाद के सर्वेक्षण का भी हवाला देते हैं जिससे यह पता चलता है कि 27वे पश्चिमी लेवल का तीसरा डिप 100 फुट था हालाँकि नक्शे में यह 40 फुट दिखाया गया है और शिफ्ट 45 फुट से 50 फुट की थी । वे यह मानते है कि नक्शा (प्रदर्श 43) प्रदर्श 58 में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। उनके अनुसार प्रदर्श 58 में क्रमांक 4 पर दिखाया नक्शा अप्राप्य है । वे यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने नक्शे पर हस्ताक्षर लेने पर जोर नहीं दिया और हस्ताक्षर करने से पहले पूरे प्रदर्श 58 की जाँच नहीं की । वे कहते हैं कि उन्होंने 26 वें लेवल और नीचे के मुख्य डिप सेक्शन का सर्वेक्षण किया था । 29वाँ पूर्वी लेवल दुर्घटना से एक डेढ़ महीना पहले शुरू किया गया था । सर्वेक्षण 9 या 10 सितम्बर के आस-पास किया गया था । उन्होंने पूर्वी क्रास कट के 27वें पश्चिमी लेवल का सर्वेक्षण नहीं किया था ।

5.19 उन्होंने स्पाट लेवल नहीं दिखाए क्योंकि एक तो इन खदानों पर उनके कार्यभार संभालने से पहले काम शुरू हो गया था और दूसरे वे बालू और कीचड़ से इतनी भरी हुई थी कि वे वहाँ जा नहीं पाए। वे दुर्घटना से तो दो तीन दिन पहले 27 वें पश्चिमी लेवल के तीसरे डिप में गए थे । वहाँ 27 वें पश्चिमी लेवल के पश्चिमी कोने में एक प्रपात था । यह तीसरा डिप कीचड़ से भरा हुआ था जो स्तर तक भी फैल गया था । उन्होंने प्लान प्रदर्श 63 पर प्रक्षेप-रेखाएं खींची। किन्तु प्लान, प्रदर्श 65 पर उन्होंने कोई प्रक्षेप-रेखाएं नहीं खींची। वे मानते हैं कि प्रदर्श 63 और प्रदर्श 64 की प्रक्षेप रेखाओं में अंतर है भले ही वे एक समान नक्शे हैं । वे इस बात का कोई कारण नहीं बताते कि उन्होंने कोयला खान सुरक्षा महानिदेशक के सामने 27वें पूर्वी क्रास कट डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिप गैलरियों के बारे में गलत बयान क्यों दिया कि ये गैलरियाँ बिंदुकित रेखाओं में इसलिए दिखाई गई थीं कि उन्होंने सर्वेक्षण के समय उन्हें जलाक्रांत पाया था ।

5.20 वे 90 हार्स पावर के पंप की स्थिति में 26वें पश्चिमी लेवल से 30 फुट नीचे बताते हैं परन्तु वे कोयला खान सुरक्षा महानिदेशक के सामने दिए अपने इस बयान को स्पष्ट नहीं कर सके कि 26 वें और 27वें पश्चिमी लेवलों के बीच पानी का स्तर बदलता रहता था । 27वाँ और 28वाँ पूर्वी लेवल जहाँ तक आज दिखाई देते हैं उससे आगे परिचालित नहीं किए गए क्योंकि वे इन लेवलों को सम्प के साथ जोड़ना नहीं चाहते थे । कोयला खान सुरक्षा महानिदेशक के सामने दिए गए अपने इस बयान को वे नकारते हैं कि उन्होंने मुख्य नक्शे में बंद सिरे वाली जलाक्रांत डिप गैलरियों को बिंदुकित रेखाओं जिनमें दिखाया है जबकि अन्य कुछ नक्शों में वे गैलरियाँ खुली दिखाई गई हैं । वे यह मानते हैं कि उन्होंने कोयला खान, विनियम 58 (3) द्वारा अपेक्षित त्रैमासिक सर्वेक्षण नहीं किया क्योंकि उनका समय अन्यत्र भी काम करने में बीत जाता था ।

5.21 प्रबंधक वर्ग का गवाह संख्या 9—श्री कुमार दुर्घटना के समय एजेंट थे । उन्होंने जनवरी 1980 में कार्यभार संभाला और जुलाई 1982 में वे स्थानान्तरित कर दिए गए । बीच के समय वे हुरिलाडीह कोयला खान के प्रबंधक के रूप में कार्य करते रहे । पहला अक्तूबर 1982 से उन्होंने कोयला खान के एजेंट का कार्यभार संभाला। जुलाई-सितम्बर के दौरान वे कस्तूर क्षेत्र-कार्यालय में खान-अधीक्षक के पद पर कार्य कर रहे थे । वे कोयला खान सुरक्षा महानिदेशक से पत्र सं० 33/एच [यू/पी-100/78 दिनांक 10-8-1978 द्वारा स्तम्भ हटाने के लिए ली गई अनुमति का हवाला देते हैं जिसके आधार पर, दुर्घटना के समय स्टोइंग के साथ स्तम्भ हटाने का कार्य किया जा रहा था । वे 27वे पश्चिमी लेवल के तीसरे डिप को लेकर हुई गलती का भी हवाला देते हैं, यह डिप वास्तव में 100 फुट का था किंतु इसे दिखाया सिर्फ 40 फुट का गया था । उनका कहना है कि 29वे लेवल के तीसरे डिप के प्रदर्श 14 अर्थात् प्रदर्श 63 पर दिखाए प्रोजेक्शन उन्होंने स्वयं प्रबंधक की हैसियत से बनाए थे और इससे आगे के प्रोजेक्शन उस समय के प्रबंधक ने इनकी सूचना देते हुए बनाए थे । 5 सितम्बर, 1983 को 29वाँ लेवल ठोस विस्फोटनों द्वारा परिचालित किया जा रहा था और यह दूसरे डिप के 25 फुट पूर्व तक पहुंच चुका था । त्रासक गैलरी अर्थात 27वें लेवल के पश्चिम में तीसरा डिप उनकी कार्यावधि के दौरान परिचालित नहीं किया गया ।

5.22 वे यह नहीं मानते कि सम्प-खदान जलाक्रांत था। वे यह मानते हैं कि प्रदर्श 62 पर जहाँ सिरे बंद किए गए है वहाँ स्पाट लेवल नहीं दिखाए गए । पंप 26वें लेवल के नीचे लगा था । उन्हें यह याद नहीं कि मुख्य डिप के 26वें, 28वें और 29 वे पूर्वी लेवल कब चालू किए गए । 27वें पश्चिमी लेवल का चौथा डिप उनके कार्यभार संभालने से पहले ही सम्प के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा था 28 वे पूर्वी लेवल का परिचालन बंद कर दिया गया अन्यथा यह सम्प के साथ जा लगता और इसकी अपनी क्षमता समाप्त हो जाती। उनके कथनानुसार, 1977 से 1978

के बीच दोषपूर्ण प्लान तैयार की गयी थी। उन्हें पक्का पता था कि पश्चिमी डिप की तरफ, सम्प में पर्याप्त अवरोध था। उनका कहना है कि स्पाट लेवल इसलिए नहीं दिखाए जा सके क्योंकि हैडिंग पानी के अन्दर थे और उनका सर्वेक्षण नहीं किया जा सका। पानी के कारण इन खदानों तक पहुंचा नहीं जा सकता था इसलिए, जैसाकि वे कहते हैं, कोयलाखान विनियम 137 (3) यहां पर लागू नहीं होता और न ही 29 वें पूर्वी लेवल के मामले में ही यह लागू होता है क्योंकि तीसरे डिप में पानी भरा था। उनका कहना है कि उन्होंने पुन: सर्वेक्षण से संबंधित प्लान पर हस्ताक्षर कर दिए हालांकि यह सर्वेक्षण उस समय तक पूरा नहीं हुआ था। वे यह स्वीकार करते हैं कि 29 वां पूर्वी लेवल सम्प के 60 मीटर के अन्दर परिचालित किया जा रहा था। गवाह यह साबित करने के लिए कि त्रैमासिक सर्वेक्षण किया गया, कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका।

यूनियन गवाह—कोयला खान के अधिकारी

5.23 इण्डियन माइन्स पर्सनेल एसोसिएशन (भारतीय कोयला खान कार्मिक संघ) के गवाह सं० 1 श्री सहदे सोरेन सहायक प्रबंधक उन दोषपूर्ण प्लानों के बारे में बताते हैं जिसके कारण दुर्घटना हुई। 14-9-83 को वे दूसरी पारी में लगभग चार बजे सायं भूमि के नीचे गए। उस समय पानी मुख्य डिप के 28 व पूर्वी लेवल तक था। पानी का अन्त: श्रवण सामान्य था। उनके अनुसार 29 वें पूर्वी लेवल का परिचालन उनके समय में हुआ था। वे नियमित रूप से फेस का प्रेक्षण करते थे। 29 वें लेवल का और आगे परिचालन पहली पारी में समाप्त कर दिया गया था और इसके तुरन्त बाद तीसरा डिप चालू कर दिया गया। उन्हें यह मालूम नहीं था कि परिचालन क्यों बंद किया गया था।

5.24 भारतीय कोयला खान कार्मिक संघ के गवाह सं 2, मदन मोहन श्रीवास्तव, सुरक्षा अधिकारी ने यह आश्चर्यजनक बात कही कि कोयले की छत का पंक्चर 27 वें लेवल की एक पुरानी डिप गैलरी से जा लगता था। इसी पुरानी डिप गैलरी की विद्यमानता के बारे में किसी भी प्राप्य अभिलेख से पता नहीं चला था। वह यह दावा करते हैं कि संगत प्लानों के अध्ययन से उन्हें यह कोई डर नहीं था कि सतह के पानी का भीतर सीपेज हो जाएगा। दुर्घटना के समय जो पानी देखा गया वह सम्प से कहीं अधिक था। वे यह नहीं बता सकते कि पानी कहां से आया। स्टोइंग के समय, डिप में पानी वर्षा ऋतु को छोड़ कर कभी बहता नहीं था। दुर्घटना से कुछ दिन पहले वे 26 वें पूर्वी लेवल और इसके तीसरे डिप से होते हुए 27 वें पश्चिमी लेवल पर गए। उनके अनुसार 28 वें पूर्वी लेवल के परिचालन को बंद करना प्रबंधक का निर्णय था अन्यथा बिजली फैल हो जाने की स्थिति में सम्प का पानी डिप खदानों में प्रवेश कर जाता।

5.25 14-9-83 को सायं सात बजे पानी 28 वें लेवल के नजदीक ही था। गवाह का कहना है कि यह कथन सही है कि 27 वें लेवल की डिप गैलरियां निरीक्षण के समय पानी से भरी पाई गई। वे आगे कहते हैं कि इनमें मक और बालू भी था। कोयला खान सुरक्षा महानिदेशक के सामने इन्होंने कहा था कि नक्शे में डिप गैलरियां बिन्दुकित लाइन द्वारा दिखाई गई थीं। वे यह नहीं बता सके कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया जबकि शपथपत्र में उन्होंने यह कहा था कि पुरानी गैलरी की विद्यमानता के बारे में उन्हें मालूम नहीं था। तभी वे कहते हैं कि पुरानी गैलरी की मौजूदगी तो ज्ञात थी किन्तु इसका विस्तार पता नहीं था। गवाह के अनुसार, 28 वें पूर्वी लेवल के साथ-साथ वेधन नहीं किया जा सका क्योंकि वेधन-छड़ें ठीक से काम नहीं कर सकती थीं। अत: एव, वास्तव में वे दो कारण बताते हैं: 28 वें लेवल को बंद करने का एक अन्य कारण यह है।

यूनियन—गवाह—कर्मचारी

5.26 भारतीय राष्ट्रीय खान ओवरमैन, सिरदार तथा शाटफायरर संघ (इनमोसा) का गवाह संख्या 1 निर्मल कुमार सिंह, ओवर मेन है जो दुर्घटना के समय तीसरी पारी में काम कर रहा था। निर्मल कुमार सिंह के अनुसार, पारी शुरू होने के समय छत की जांच की गई और इसे सही पाया गया, इसमें से सही धात्विक ध्वनि निकलती थी। जब शाटफायरर (विस्फोटकारी) छिद्रों के स्टैमन के लिए गया तो उस समय छत से कोयला टूट-टूट कर गिरने लगा, इसलिए स्वर्गीय सिरदार धर्म चौहान ने काम रुकवा दिया और बाड़ा लगवाने की बात कही। इसके बाद जब व दूसरी तरफ गए तो खतरे की घंटी सुनाई दी। उन्होंने चटकने की अवाज सुनी। उनके अनुसार, 90 हार्स पावर का पम्प 26 वें पश्चिमी लेवल के योजक स्थल से तीस फुट नीचे लगाया गया था और फुट वाल्व 27 वें पश्चिमी लेवल से 3-4 फुट नीचे था। 27 वां पूर्वी लेवल मक, बालू और ईंटों से भरा हुआ था। 29 वें पूर्वी लेवल 11-9-83 के आस-पास बंद किया गया और तीसरा डिप उसी दिन शुरू कर दिया गया।

अदालती गवाह—कोयला खान से सम्बद्ध

5.27 अदालती-गवाह सं 1 गोकुल दोसाध दुर्घटना के समय पम्प प्रचालक (आप्रेटर) का काम कर रहा था। उनका कहना है कि पम्प टगर की मेन लाइन में 26 वें लेवल के ठीक ऊपर लगाया गया था। शुरू में यह एक लेवल से दूसरे लेवल पर लगाया जाता रहा। दुर्घटना के दिन सबसे पहले बिजली फेल हो गई थी, किन्तु स्टाइंग-आप्रेशन सुबह लगभग पांच बजे शुरू हुआ था। इसके एक घंटा बाद पाठ्यांक जीरो था और पम्प का पहिया फ्री हो गया था। उसने पम्प को बंद कर दिया और कारण जानने के लिए आगे गया तब उसे दुर्घटना के बारे में पता चला। पम्प के द्वारा बाहर निकाला गया पानी 17 वें लेवल पर जा रहा था। उसके कथनानुसार, 27 वें और 28 वें लेवल बालू, मक और पानी से भरे रहते थे।

5.28 13 सितम्बर को जब उसने ड्यूटी शुरू की तो उसने संप के पानी का स्तर दिखाने के लिए सैक्शन नली पर निशान लगा दिया था और चाक से नली पर तारीख सहित हस्ताक्षर कर दिए थे। पम्प और उस जगह जहां उसने हस्ताक्षर किए थे, के बीच का फासला लगभग 40 फुट अथवा दो पाइपों के बराबर था। जिस जगह उसने हस्ताक्षर किए वहां पश्चिमी लेवल में पानी नहीं देखा गया, पानी एक पाइप-लम्बाई नीचे था जो कि फुट वाल्व से लगभग 10 फुट ऊंचा था।

5.29 अदालती गवाह संख्या—2—अखिलेश्वर प्रसाद वर्मा कुरि-लाडीह कोयला खान में सर्वेक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। चौदहवीं सीम में स्तम्भ हटाने का काम अभी शुरू ही हुआ था और उस समय उन्होंने चौदहवीं सीम का बंद परिपथ सर्वेक्षण किया था। किन्तु परिकलन तैयार होने अथवा आलेखन किए जाने से पहले ही उनका स्थानांतरण हो गया। उस समय 27 वें पश्चिमी लेवल पानी से भरा रहता था किन्तु वे यह नहीं स्वीकार करते कि यह त्यक्त खदान था, इसलिए उन्होंने स्पाट लेवल नहीं दिखाए। उनके कथानुसार उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनसे पहले के सर्वेक्षक ने स्पाट लेवल दिखाए थे अथवा नहीं। उन्होंने 26 वें पूर्वी या 25 वें पश्चिमी लेवल का सर्वेक्षण नहीं किया, और न ही वे एक दूसरे से मिले हुए पाए थे। गवाह यह जानता था कि चौदहवीं सीम और ग्यारहवीं सीम का नक्शा तैयार किया जाना है। उन्होंने 20वें लेवल का बंद-परिपथ सर्वेक्षण पूरा कर लिया, उन्होंने अपनी मापकन-पुस्तिका में प्रविष्टियां दर्ज की किन्तु उन्हें यह

याद नहीं था कि कोयला खान विनियम 60 के द्वारा अपेक्षित रूप में नक्शे भिजवाए गए थे या नहीं। उनके अनुसार, 27वें पश्चिमी लेवल तक पहुंचा नहीं जा सकता था। वे आरेखण कपड़े वाले अप्राप्त नक्शा-प्लान का जो उन्होंने कार्यालय में दिया था हवाला देते हैं।

5.30 गवाह यह उल्लेख करता है कि खाने सितम्बर, 1978 के अन्तिम सप्ताह से निमज्जित हो गई थी जिससे कार्य बिल्कुल ठप्प हो गया था। वे प्रदर्श 69वें में, मृत सर्वेक्षक दास की लिखावट को पहचानते हैं और दास द्वारा नोट किए गए तीसरे और चौथे डिप के परिचालनों को इस प्रकार पढ़ते हैं यथा तीसरा डिप 4 मीटर अर्थात 13 फुट 12 1092 घन फुट चौथा डिप 5 मीटर अर्थात 16 फुट 12 फुट 8 फुट : 1532 घन फुट। इससे यह पता चलता है कि दोनों डिप क्रमशः 13 फुट और 16 फुट तक परिचालित किए गए थे। प्रदर्श 62 पर वे यह बताते हैं कि तीसरा डिप 40 फुट दिखाया गया है। प्रदर्श 80-संचालन—प्लान के बारे में उनका यह मत है कि इस पर उनके हस्ताक्षर तो हैं किंतु यह उसके हस्ताक्षर वाले नक्शे का जो केवल हस्त—नक्शा था प्रिंट है। यही कारण है कि इस के त्रैमासिक निरीक्षण के पृष्ठांकन नहीं हैं। उन्होंने बड़े आराम से यह कहा कि उन्होंने नक्शे पर स्पाट लेवल दिखाए हैं, जो इस समय अदालत के सामने नहीं हैं किंतु वे यह स्वीकार करते हैं कि खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा भेजे गए दर्जन से भी अधिक नक्शे में से किसी पर भी स्पाट लेवल नहीं दिखाए गए थे वे दास द्वारा तैयार किया गया एक भी ऐसा नक्शा नहीं दिखा पाए जिसे 30-6-1978 के बाद अद्यतन किया गया हो।

5.31 जहां तक गवाह द्वारा रखे गए रजिस्टर, प्रदर्श 81 का संबंध है, उसने शपथ पूर्वक यह कहने में टालमटोल की कि रजिस्टर की टिप्पणियां पानी के स्तर के बारे में थी, हालांकि उसके शीर्षक से यह स्पष्ट पता चलता है कि यह सारा रिकार्ड क्रमिक ड्रावेज के संबंध में है। गवाह—गुप्ता, प्रबंधक ने यह स्थिति स्वीकार की है। प्रत्यक्षतः श्री वर्मा प्रदर्श 81 में दिखाए ड्रावेज को आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते थे। 27 वें पश्चिमी लेवल के तीसरे डिप के सामने की पैमाइश 70 फुट दिखायी गयी है, 27 वें पश्चिमी लेवल के पहले डिप के सामने प्रविष्टि 112 फुट की है जबकि 27 वें पश्चिमी लेवल के दूसरे डिप में यह 97 फुट की है।

5.32 अदालती गवाह संख्या 3, श्री जे० एन० गुप्ता हैं, जो 3-5-77 से 1-10-78 तक हुरिलाडीह कोयला खान के प्रबंधक थे। उनके स्थानांतरण के समय, खदानें क्रास कट के 26 वें और 28 वें पूर्वी लेवलों के बीच, चौदहवीं सीम में क्रास कट सेक्शन में थीं। अपने पत्र सं० एच० आर० सी/ई०ए०/78/एफ-11/1563/67, दिनांक 10-11-78 के द्वारा उन्होंने चार्ज रिपोर्ट प्रदर्श 84 तैयार किया है जिसमें यह उल्लेख किया है कि पहले का सर्वेक्षण गलत प्रतीत होता है इसलिए नक्शों को सही प्रमाणित नहीं किया जा सकता उनका कहना है कि सम्प की योजना 27 वें और 28 वें लेवलों के बीच पूर्वी क्रास कट क्षेत्र के पूर्वी पार्श्व में निम्नतम स्तरों में की गई थी। पश्चिमी पार्श्व 30 वें लेवल तक विकसित किया जाना था। उन्होंने पूर्वी क्रास कट के पश्चिमी पार्श्व की खानों और मुख्य डिप की खानों के बीच लगभग सौ फुट के अवरोधक की भी योजना बनाई थी। यह 23 वें लेवल के नीचे से शुरू किया जाना था। प्रदर्श 84 के बारे में गवाह का कहना है कि चौदहवीं सीम के 27 वें स्तर से ऊपर तक के लेवल का भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा तत्कालीन प्रबंधकों द्वारा किया गया सर्वेक्षण गलत था। वे यह स्पष्ट करते हैं कि वे ग्यारहवीं सीम के सर्वेक्षण में अशुद्धियां पाई गईं इसलिए उन्होंने चौदहवीं सीम के नक्शों के संबंध में भी टिप्पणियां की थीं।

5.33 गवाह के अनुसार, की नियोजित क्षमता 10 से 15 लाख गैलन और इसकी स्टोइंग धारिता 250 से 300 घन मीटर बालू प्रति दिन थी और इसे बढ़ाकर 500 घन मीटर प्रतिदिन किया जाना था। वे आरेखण कागज वाले नक्शे का भी उल्लेख करते हैं जो प्राप्य नहीं था। उनके कथनानुसार कमजोर स्मरण शक्ति के कारण उन्हें यह याद नहीं था कि उन्होंने कोयला खान सुरक्षा विनियम 60 का अनुपालन करते हुए कोयला खान सुरक्षा महानिदेशक को नक्शे भेजे थे या नहीं। उनके कथनानुसार, विकास कार्य सीम के लगभग मध्य सेक्शन में किया जा रहा था।

5.34 अदालती गवाह सं. 5, देवेंद्र सिंह हुरिलाडीह कोयला खान में 19-4-1976 से 30-4-1980 तक एजेंट था। उनके अनुसार जल को स्ट्रोइंग क्षेत्र, में पूर्वी पार्श्व के डिप की ओर के हिस्से के लेवलों तक ले जाने की योजना बनाई गई थी। इस कारण पूर्वी क्रास कट के 27 वें और 28 वें डिपोन्मुख लेवलों में सम्प की योजना बनाई गई। स्टोइंग-प्रचालन के समय 500 गैलन प्रतिमिनट के प्रकार पानी छोड़ा जा रहा था। वे आगे यह कहते हैं कि जब पूर्वी क्रास कट के चौदहवीं सीम पार्श्व के विकास खदानें पानी में डूब गई तो उनके स्थान पर स्तम्भ हटा लिया गया क्षेत्र (डिपिल्लरिंग) लाया गया। वे इस बात से इनकार करते हैं कि प्रतिबिंदु तल बनाए रखना आवश्यक था क्योंकि उनके कथनानुसार, चौदहवीं सीम के ऊपर वाली सोलहवीं सीम को गत वर्षों में स्तम्भविहीन कर दिया गया था और अब उस तक नहीं पहुंचा जा सकता था।

5.35 चौदहवीं सीम के पुनः सर्वेक्षण के बारे में उनका कथन है कि यह उनकी पदावधि में किया गया किंतु उन समय आलेखन आदि नहीं किए गए थे। उल्लंघन-रिपोर्ट, प्रदर्श 87, में बताई गई गलतियों के संबंध में गवाह का कथन है कि उन्होंने प्रबंधक और सर्वेक्षक को भूलें सुधारने के लिए कहा था, किन्तु उन्हें (गवाह) यह याद नहीं था कि खान सुरक्षा महानिदेशक को कोई उत्तर भेजा गया था अथवा नहीं। वे यह मानते हैं कि प्रबंधक को इस प्रक्षेपण लाइनों, प्रदर्श 94 में परिवर्तन करने का अधिकार दिनांक 1-6-1983 तक प्राप्त था। बाद में यह अधिकार एकमात्र महाप्रबंधक को दे दिया गया था। गवाह, प्रदर्श 87 में उल्लिखित नक्शे पी.-31 एच.यू.आर.आर.एस. के बारे में कुछ नहीं बता सका। उसके अनुसार सीम के बीच में निचले क्षितिज में विकास की योजना बनाई गई थी।

अदालती गवाह-खान सुरक्षा महानिदेशालय का कार्यालय

5.36 अदालती गवाह सं. 4-धनबाद में खान सुरक्षा निदेशक के पद पर काम कर रहे श्री पी. सी. श्याम दिनांक 14-9-83 को सवेरे लगभग 8.30 बजे दुर्घटना स्थल पर गए। उन्होंने सर्वेक्षण कार्यालय और उपस्थिति कक्ष के सारे अभिलेख अपने कब्जे में कर लिए। 16-9-1983 को उन्होंने भूमि के नीचे जाकर विस्तृत निरीक्षण किया। अन्यों के अलावा उनके साथ उपसहायक सर्वेक्षक भी थे। गवाह ने पूर्वी क्रास कट सेक्शन के 'ई' पैनल का निरीक्षण किया। उन्नीसवें लेवल पर उन्हें चार धारित टब मिले। उन्हें 26 वें लेवल और पूर्वी क्रास कट के 28 वें स्तर के बीच पम्प का एक फुट-वाल्व भी मिला। जल का स्तर पूर्वी क्रास कट के 28 वें लेवल के योजक-स्थल के आस पास था। 27 वां लेवल तो दोषमुक्त था किन्तु पानी के बहाव के कारण उस पर चलना कठिन था। आगे चलकर उन्होंने 6 इंच व्यास वाला एक पंपर देखा। पूर्वी क्रास-कट सेक्शन जल का स्तर लगभग 26 वें लेवल के बराबर था। उन्होंने 27 वें पश्चिमी योजक स्थल पर निचले डिप में 35 का कोण बनाते हुए अंग्रेजी के 'वी' अक्षर के आकार का एक बांध बनाया। बांध में जल की ऊंचाई 8 इंच थी इसके अनुसार जल का बहाव प्रतिमिनट 80 गैलन था। गवाह के अनुसार दुर्घटना और उसके दौरे के बीच के पांच घंटों के दौरान पानी की मात्रा 300 घन मीटर से अधिक नहीं होगी।

5.37 गवाह 28-12-79 को मजूमदार (गवाह) द्वारा किए गए सामान्य निरीक्षण और उस पर आधारित रिपोर्ट प्रदेश-87 दिनांक

20-1-80 को हवाला देते हैं। दोष मुख्य डिप के 26 वें लेवल के नीचे पाए गए। गवाह का कहना है कि इस अशुद्ध (गलत) प्लान के कारण तुरंत खतरे की कोई बात नहीं थी। आगे वे यह कहते हैं कि उन्होंने मामले पर आगे कारवाई नहीं की क्योंकि उनके कार्यालय को पता लग चुका था कि प्रबंध वर्ग संशोधित प्लान तैयार कर रहा है और इसलिए भी कि जब कभी किसी विनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अनुमति की प्रार्थना की जाती थी तो वे सदैव शुद्ध प्लान प्रस्तुत किए जाने पर बल देते। उनका कहना है कि कोयला खान विनियम 60 के अंतर्गत भी पिछले 2-3 वर्षों के दौरान कोई भी प्लान प्राप्त नहीं हुई है। इससे पहले के वर्षों का जहां तक संबंध है वे अभिलेखों के संदर्भ के बिना कोई उत्तर नहीं दे सके। मोटे तौर पर, खान-सुरक्षा महानिदेशालय में 350 कोयला खानों और 4400 धातुमय खानों के नक्शे प्राप्त होते हैं और इनकी जांच के लिए कोई एजेंसी विद्यमान नहीं है। उन्होंने आगे यह कहा कि उन नक्शों को इकट्ठा कर के रख दिया जाता था। गवाह ने यह भी कहा कि उन्होंने विनियम 60 को हटाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा हुआ है।

5.38 गवाह के अनुसार, मार्च, 83 तक के सभी निरीक्षण मुख्य डिप सेक्शन के 26 वें लेवल से ऊपर के थे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि 27वां स्तर कब खुलवाया गया, किंतु 1979 से यह सम्प के रूप प्रयुक्त हो रहा था। उनके अनुसार, सामान्य तौर पर सम्प के नीचे काम नहीं किया जाता। यदि काम जल से ऊर्ध्वाधर नीचे किया जाना होता है तो 30 मीटर की विभाजक दीवार आवश्यक होती है। यदि ऊपरला जल स्तंभ लगभग 40-45 मीटर हो तो विभाजक दीवार 10 मीटर पर्याप्त होगी। उन्हें ऐसा लगा कि प्रदर्श 62 कार्य-प्लान था। रोड क्रासिंग के लिए, कोयला खान विनियम 105 के अधीन मार्च, 1982 में प्रदत्त अनुमतियों का हवाला देते हुए वे कहते है कि ये खदानें जल-रेखा से ऊपर थीं और जलाप्लावन का कोई खतरा नहीं था। उनके अनुसार, विनियम विशेषयता उस योजक स्थल के मामले में लागू होता है जहां दो व्यासक गैलरियां काटती हैं। प्लान प्रदेश 90 जहां व्यासक पुरानी गैलरी बिन्दुकित रेखा द्वारा दिखाई गई है और उसके सिरे खुले है—को देखकर उनका कहना है कि बिंदुकित रेखा का अर्थ यह है कि विस्तार—और मुड़ना संदेहास्पद है, भले ही सिरे बंद हो अथवा खुले। गवाह यह नहीं मानता कि लगातार पंपिंग के कारण सम्पों को जलाक्रांत खदानें नहीं माना जाना चाहिए। वे सम्प की परिभाषा यह देते हैं कि सम्प पानी से भरा गड्ढा है जिसमें से पम्प के द्वारा पानी निकाला जाता है। यह पानी भरा गड्ढा स्थायी होता है अस्थायी नहीं। उनके शब्दों में सम्प जलाक्रांत खदान होती है जिसके जलस्तर में उतार-चढ़ाव होता रहता है, यह त्यक्त खदान होती है क्योंकि कोई भी इसके अंतिम कोने तक नहीं जा सकता और न ही कुछ देख सकता है। यह परित्यक्त खदान इस अर्थ में है कि इसमें से कोई उत्पादन नहीं किया जा सकता।

5.39 उनका कहना है कि यदि पहली पारी में गैलरी जल से खाली है और दूसरी पारी में उसमें जल भर दिया जाता है तो उसे त्यक्त ही कहा जाएगा क्योंकि कोई भी वहां जाकर उसका प्रयोग और उसका निरीक्षण नहीं कर सकता। अतएव, गवाह का कहना है कि यहां विनियम 127 (3) लागू किया जा सकता है। तर्क की दृष्टि से, वे यह मानते हैं कि प्रत्येक पारी के लिए अनुमति लेना आवश्यक होता है जब तक कि गैलरी में से पहले पानी निकाल न दिया गया हो। किंतु उन्होंने किसी भी अवसर पर ऐसी अनुमति नहीं दी। उनके अनुसार, सम्प के लिए प्रयुक्त गैलरियां प्रयोग में आने वाली गैलरियां नहीं होंगी क्योंकि प्रयोग का अर्थ 'उत्पादन अथवा अभिगम्यता' है। गवाह यह स्वीकार नहीं करता कि यदि गैलरी किसी भी प्रकार के लिए प्रयोग में है तो यह त्यक्त अथवा परित्यक्त गैलरी नहीं हो सकती। त्यक्त अथवा परित्यक्त का एक ही अर्थ है अर्थात् प्रयोग न किया जाना। उनका कहना है कि जब क्षेत्र जल में डूबा हो तो प्रतिकुतल मापांकित नहीं किए जा सकते किंतु वे सीम के ग्रेडिएंट से नापे जा सकते हैं। यथार्थ ग्रेडिएंट सतत है और खदान कार्य तल या छत या फिर भ्रात क्षितिज से शुरू हुआ है।

5.40 गवाह यह स्पष्ट करते है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा दुर्घटना के बाद लिया गया प्रत्येक बयान अंग्रेजी जानने वाले खान के कैशियर या स्टोरकीपर के स्तर के किसी व्यक्ति द्वारा सम्बद्ध व्यक्ति को हिंदी में स्पष्ट कर दिया जाता है और इस बात के सबूत के लिए बयान पर उसके हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं। गवाह को खान-टैक्नोलाजी स्पष्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आई। उनका कहना है कि विनियम 58(4) का प्लान पी (3) एच यू आर आर के मामले में अनुपालन नहीं किया गया जिसके बारे में निरीक्षण रिपोर्ट प्रदेश 87 में उल्लेख किया गया है—किंतु जो रजिस्टर प्रदर्श 58 में दर्ज नहीं की गई।

5.41 अदालती गवाह सं० 6 खान सुरक्षा महानिदेशक के कार्यालय के मुख्य सर्वेक्षक गणपति सिन्हा है। उन्होंने प्लान प्रदेश 19 तैयार की थी जिसमें दुर्घटना से पहले 90 हार्स पावर के पंप की स्थिति बताई गई थी। 14-9-83 को दोपहर के लगभग 1.45 बजे वे उस स्थल पर गए और वहां उन्होंने यह देखा कि स्लिपर पम्प की अस्थायी नींवों के रूप में व्यवस्थित किए गए थे। उन्होंने फुट-वाल्व प्रदेश 19 में दिखाए बिंदु पर ही पाया। चूषण नली का कुछ हिस्सा इसके साथ जोड़ा गया था। वे अपनी मापांकन-पुस्तिका साथ ले गए थे और उन्होंने सभी प्रेक्षण इसमें नोट कर लिए थे। उनके अनुसार प्रदर्श 19 में दिखाया गया जल-स्तर दिनांक 13-9-83 के जलस्तर के बराबर था। उन्होंने यह खंडन किया कि जल का स्तर कभी भी 36000 घन मीटर नहीं हो सकता। उन्होंने 4,409 घन मीटर के अपने परिकलन में 27 वें लेवल के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे डिप की गैलरी की छत के जल स्तर में शामिल नहीं किया है। उनका यह अनुमान था कि दुर्घटना से पहले जल का स्तर—चूषण नली पर चाक से लगाए गए निशान पर था। उनके अनुसार, फुट वाल्व से संलग्न चूषण नली पानी में प्रयोग होने के कारण फैल गयी थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप में जो प्रेक्षण किए, वे सब दिखा दिए हैं सिवाय शब्दों के जो उन्होंने अपने प्रेक्षण अधिकारी के कहने पर प्रदर्श 19 में उल्लिखित कर दिए हैं। पर्यवेक्षण अधिकारी को जब उन्होंने तैयार प्लान दिखाई थी तो उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था।

5.42 अदालती गवाह सं०-7 खान सुरक्षा के उप निदेशक श्री मजूमदार हैं। वे हुरिलाडीह कोयला खान में दल अधिकारी थे और अपनी इसी हैसियत में इन्होंने सामान्य निरीक्षण, अनुवर्ती निरीक्षण तथा घातक दुर्घटना की जांच पड़ताल आदि की थी। प्रदेश 88 इन निरीक्षणों का सारांश है। उनका कहना है कि प्रत्येक निरीक्षण किसी विशिष्ट प्रयोजन को लेकर किया गया है और ऐसा करने के लिए विशेष रास्ते से विशिष्ट कार्य स्थल का निरीक्षण किया जाता है। उन्होंने जुलाई 1974 में कार्यभार संभाला था। उनके अधीन 11 कोयला खानें थीं निरीक्षण कार्यवृत्त, दुर्घटना के विशेष लक्षणों, खान के इतिहास आदि के आधार पर तैयार किया जाता है। उन्होंने किसी भी अवसर पर क्रास कट के 27 वें पश्चिमी लेवल का निरीक्षण नहीं किया। उन्होंने 'ई' पैनल का निरीक्षण किया था किंतु उस समय उन्होंने सम्प को नहीं देखा था। वे पूर्वी क्रास कट के 27 वें लेवल के आगे की पश्चिमी डिप-खदानों पर नहीं गए थे। उन्होंने मध्य डिप का 22 वें लेवल तक निरीक्षण किया था। वे अपनी उल्लंघन रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि नक्शों में प्लान की पुरानी संख्या को दिखाने वाले विहित प्रमाण-पत्र नहीं थे।

5.43 गवाह का कथन है कि उन्हें कोयला खान विनियम 60 के अन्तर्गत, हुरिलाडीह कोयला खान से कोई नक्शा प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने पुनः सर्वेक्षण का सुझाव दिया। वे कहते हैं कि जोड़दार प्लान की पुन: जांच के लिए यदि दल में पूरे समय के लिए एक सर्वेक्षक, एक

सहायक सर्वेक्षक और तीन श्रृंखला—कार्मिक होंगे तो इसमें 2 मास का समय लग जाएगा। उनके अनुसार प्रदर्श 87 में देखे गए उल्लंघनों के बारे में अनुपालन-रिपोर्ट भिजवाने के लिए स्मरण-पत्र दिए गए और अगले निरीक्षण तक प्रदर्श 87 इसी रूप में बना रहा। पहले उन्होंने यह जानकारी दी थी कि अन्य अभिकरणों को लेकर भी सर्वेक्षण चालू था। उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि और आगे कुछ नहीं हुआ था। नए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए वे इस बात पर जोर दे रहे थे कि सम्बद्ध क्षेत्र का अद्यतन प्लान प्रस्तुत किया जाए। प्रबंधक गुप्ता द्वारा की गई चार्ज रिपोर्ट प्रदर्श 84 का हवाला देते हुए वे कहते हैं कि उसमें व्यक्त शंकाओं के मामले में उन्होंने 10-1-79 को खान का दौरा किया था। चूंकि उस समय तुरंत खतरे की कोई बात नहीं थी इसलिए धारा 22 के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

5.44 गवाह का कहना है कि उसे यह जानकारी नहीं थी कि पूर्वी क्रासकट को 27वां पश्चिमी लेवल सम्प के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। खान के किसी भी अधिकारी ने उन्हें यह नहीं बताया था कि मुख्य डिप के पूर्व वाले क्षेत्र में खदान कार्य चल रहा था। उन्होंने गवाह को मुख्य डिप के 26 वें लेवल से 11 स्तम्भ नीचे के रोड को क्रास करने का अपना विचार बताया था। उनका कहना है कि विनियम 60 के अन्तर्गत प्रस्तुत नक्शों की जांच मुख्यालय में सर्वेक्षण द्वारा की जाती है। प्रदर्श 87 में बताई गई त्रुटि के बावजूद कोई जल-खतरा प्लान नहीं रखा गया कोयला खान विनियम 105 के अन्तर्गत अनुमति देने से पूर्व भूमिगत खदानों का विशिष्ट निरीक्षण नहीं किया गया। छत की गड़बड़ी की संभावना को लेकर यह शर्त रख दी गई थी कि छत के साथ साथ थोड़ा कोयला छोड़ दिया जाए। विनियम 65 (3) के अन्तर्गत कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि इस विनियम को विशिष्ट परिस्थितियों में लागू किया जाता है, यहां प्रबंधक वर्ग स्वयं कार्य कर रहा था।

अध्याय -6

छत का गिरना और सीपेज

6.1 साक्ष्यों के आधार पर जो मामला सामने आया है उससे यह प्रदर्शित होता है कि 14-9-1983 को सुबह सुबह जब तीसरी पारी खान में भूमि के नीचे काम कर रही थी उस समय मुख्य डिप के पूर्व में, 29वें लेवल के तीसरे डिप के सामने से कुछ चटकने की आवाजें आईं और अचानक भारी मात्रा में जल ऊपर से नीचे की ओर तेजी से बहने लगा जिससे साथ के टगर डिप और मुख्य डिप में कार्य कर रहे 19 व्यक्ति डूब गए। पूर्वी क्रासकट के 27वें पश्चिमी लेवल का तीसरा डिप जिससे जल बहा था, 29 वें पूर्वी लेवल के तीसरे डिप के ऊपर था, चूंकि इन दोनों के बीच विभाजक दीवार बहुत पतली थी इसलिए जल-प्रवाह के दबाव से निचला तल फट गया। प्रबंधक वर्ग द्वारा दिये गये बयान प्रदर्श-5 में और कुछ यूनियनों के लिखित बयानों में यह उल्लेख किया गया है कि हरिलाडीह कोयला खान में पूरे वर्ष मानसून में और भी अधिक जल का भारी सीपेज होता रहता था। प्रायः ही यह संकेत दिया गया कि दुर्घटना से तुरन्त पहले इस प्रकार का सीपेज हुआ था किन्तु प्रबंधक वर्ग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और यही कारण है कि यह दु:खद घटना समय रहते टाली नहीं जा सकी। किन्तु दुर्घटना से तुरन्त पहले भारी मात्रा में पानी के रिसाव होने का प्रमाण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। दुर्घटना का हवाला देने वाला पहला गवाह प्रबंधक-वर्ग का गवाह सं०-2 घनश्याम मंडल है। वह लोडर का काम करता है। वह रात 1 बजे से शुरू होने वाली तीसरी पारी में काम कर रहा था। सुबह लगभग चार बजे, थोड़े से लोडिंग काम के बाद उसने सिरदार स्वर्गीय धर्मू चौहान से और अधिक कोयला देने के लिए कहा। उस समय सिरदार ने उसके गैंग को तीसरे डिप के अग्राग्र (फेस) पर न जाने की सलाह दी क्योंकि छत की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके स्थान पर उन्हें सहवर्ती डिप पर जाने के लिए कहा गया। श्री चौहान स्वयं गैंग के एक व्यक्ति को साथ लेकर टगर डिप की तरफ

गए। इसके तुरन्त बाद खतरे की घन्टी बज उठी, उस समय गवाह डिप के योजक स्थल से 15-20 फुट दूर था और उसे यह पता चला कि भारी मात्रा में जल बहा चला आ रहा है। अतः भारी मात्रा में जल का प्रवाह ही आस पास काम कर रहे व्यक्तियों की मृत्यु का कारण बना।

6.2 जिरह के दौरान गवाह ने यह स्पष्ट तौर पर कहा कि उसे यह ज्ञात नहीं था कि छत की स्थिति अच्छी नहीं है। उस रात जब सिरदार और ओवरमैन को लोडिंग करने के लिए कहा गया तो उन्होंने इससे पहले छत की जांच की थी। छत सही पाई गई थी। गवाह इस सुझाव को स्वीकार नहीं करता कि अग्राग्र में पानी के रिसाव होने के कारण व्यक्तियों ने काम करने से इंकार कर दिया था।

6.3 वह यह जरूर बताता है कि सिरदार श्री चौहान ने व्यक्तियों को यह निर्देश दिए थे कि दूसरे और तीसरे डिप के बीच 29 वें पूर्वी लेवल में बाड़ लगा दें ताकि कोई भी तीसरे डिप तक न जा सके। उस स्थल पर कार्य बंद कर दिया गया था। किन्तु गवाह को यह पूरी तरह स्पष्ट था कि कार्य को किसी भारी रिसाव के कारण बंद नहीं किया गया था।

6.4 गवाह सं० - 3- हरिबंदिस ड्रिलर था। 13-9-83 को तीसरी पारी में उसने कुछ थोड़ा काम किया था। उसके बाद स्वर्गीय श्री चौहान ने उसे तीसरे डिप में होल बनाने के लिए कहा। तदनुसार उसने अग्राग्र से कोयला हटा लिए जाने के बाद 6 होल ड्रिल किए। प्रति-परीक्षा में वे स्पष्ट बताते हैं कि छत के निकट कोई भी होल नहीं बनाया गया था। उनका कथन है कि छत की जांच उसके द्वारा तो नहीं किन्तु की अवश्य गई थी। उन्होंने कोई छत गिरती नहीं देखी। जो होल उन्होंने ड्रिल किए थे उनमें से कहीं पानी नहीं निकला। उन्होंने खतरे की घंटी सुनी थी। गवाह की गवाही से यह स्पष्ट है कि यद्यपि वह उसी अग्राग्र में जहां कुछ ही मिनट बाद त्रासदी हुई कार्य कर रहा था किन्तु उसे पहले से इस प्रकार की दुर्घटना का कोई आभास नहीं मिला था। दुर्घटना के तुरन्त बाद खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा लिए गए अपने बयान में वह कहता है कि पानी का कुछ रिसाव हो रहा था। छत की स्थिति भी बुरी थी इसलिए उसने होल नहीं बनाए। गवाह ने ऐसा बयान कैसे दिया इसका वह कोई कारण नहीं दे पाया। हो सकता है वर्तमान बयान गलत हो या फिर पहले वाला बयान। पहले का बयान भी गड़बड़ी में दिया गया हो सकता है। किन्तु यह स्पष्ट है कि अदालत में शपथ ग्रहण के बाद गवाह ने जो ठोस बयान दिया वह खान सुरक्षा महानिदेशक के सामने दिए गए पहले के बयान से भिन्न है। यह पहले का बयान जब तक कि तथ्यों के प्रमाण न दिए जाएं स्वीकार नहीं किया जा सकता। उस बयान में तथ्यों के प्रमाणन का अभाव है।

6.5 गवाह सं-4-काली प्रसाद भुइयां का कहना है कि गवाह सं० 3 ने जब होल ड्रिल कर लिए तो उसे उन होलों को चार्ज करने के लिए कहा गया। वे होल चार्ज करने के लिए गए तो उन्होंने छत में चटकने की आवाज सुनी और कोयले का 3/4 इंच से 1 इंच मोटी कुछ परतें छत से गिरता भी देखा। आसन्न दुर्घटना की यही निकटतम चेतावनी थी। प्रति-परीक्षा में वे बहुत स्पष्ट थे कि छत से कोयले की परतें तो गिरी थीं किन्तु वहां से पानी निकलने का कोई संकेत नहीं मिला था। गवाह का कथन है कि उसने छत से कोयला परतें गिरने की घटना सिरदार धर्मू चौहान को रिपोर्ट की जिन्होंने उस स्थान का निरीक्षण किया और वहां बाड़ा लगाने के लिए कहा ताकि वहां कोई न जा सके। चूंकि सिरदार ने - जो स्वयं इस दुर्घटना में मारे गए—इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की, इससे यह स्पष्ट है कि उन्हें ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि यह स्थिति गंभीर खतरे की स्थिति हो सकती है। उन्होंने उस क्षेत्र में बाड़ लगवा कर खदान कार्य बंद करवा दिया यदि उन्होंने यह महसूस किया होता कि मामला कहीं अधिक गंभीर है तो वे आगे के तुरन्त उपायों के लिए इसकी रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अवश्य करते। इसके विपरीत वे स्वयं भी वहीं पास में काम करते रहे। स्पष्ट है कि उन्हें

यह नहीं लगा कि उनका अपना जीवन अथवा अन्य किसी का जीवन खतरे में है। यही कारण है कि वे बाड़ लगाने का आदेश देकर ही संतुष्ट हो गए।

6.8 खान कार्मिक संघ की ओर से गवाह सं०-1-सहायक प्रबंधक सोरेन—का भी यही कथन है कि घटना-स्थल पर पानी का सामान्य रिसाव था। वे दूसरी पारी में भूमि के नीचे गए थे। इसी प्रकार खान कार्मिक संघ के गवाह सं-2 सुरक्षा अधिकारी मदन मोहन श्रीवास्तव भी केवल छत गिरने और बाड़ लगा दिए जाने की बात कहते हैं। वे पानी का कोई भारी रिसाव होने की बात नहीं करते। अतएव इस बिंदु के समूचे साक्ष्य विशेषतया धर्म चौहान, जो स्वयं इस दुर्घटना में मृत्यु का शिकार बने के द्वारा की गई तुरन्त कार्रवाई से यह पता चलता है कि पानी के इस तरह भारी रिसाव के कारण या छत गिरने के कारण विभाजक दीवार ढह जाने की कोई पहले से चेतावनी नहीं थी। हालांकि दुर्घटना से कुछ ही मिनट पहले 29 वें पूर्वी लेवल के तीसरे डिप के संतास में कुछ खराबी अवश्य पैदा हो गई थी। अतएव, यही मानकर चलना पड़ेगा कि स्फोटन अकस्मात हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि अवसादी कोयला शैल समूह जो 27 वें पश्चिमी लेवल के तीसरे डिप के अधस्तल का कार्य करता था और जो ऊपर जल के भारी कालम को थामे हुए था, वह न मालूम प्रभावों के कारण विघटित हो गया और जब वह ऊपर के जल के कालम दबाव को सह नहीं पाया तो बोझ के कारण बह गया। ज्यादा रिसाव की कोई पहले से चेतावनी नहीं थी। सम्भवतया इसलिए कि अधस्तल के छिद्र पुरानी झासक गैलरी के फर्श के साथ साथ जमा हुई सिल्ट के कारण बंद हो गए थे।

अध्याय 7

पंप की स्थिति

7.1 बहस के दौरान, स्टोइंग के समय बहते जल की मात्रा तथा पंप की क्षमता के संबंध में प्रश्न उठाए गए। इस संबंध में प्रबंधक-वर्ग की ओर से दुर्घटना से पहले 90 हार्स पावर के पंप के स्थान को बड़े विश्वास के साथ बताया गया था। उनके तर्कानुसार, पंप 27 वें पूर्वी क्रास कट क्षेत्र के ठीक ऊपर था। पंप लगाए जाने के स्थान से पंप द्वारा निकाले जा सकने वाले पानी का स्तर पता चल जाता है, और यही कारण है कि 90 हार्स पावर के पंप की स्थिति को निश्चित करना आवश्यक हो गया है।

7.2 प्रबंधक वर्ग के गवाह सं. 5 सहायक प्रबंधक श्री खान का कथन है कि 90 हार्स पावर का पंप उनके पर्यवेक्षण में लगाया गया था। दुर्घटना की तारीख को यह 26 वें लेवल के नीचे स्थित था। ओवरमैन, सिरदार और शाट फायरर संघ के गवाह सं. 1 निर्मल कुमार सिंह का कहना है कि 90 हार्स पावर का पंप 26 वें पश्चिमी लेवल से 30 फुट नीचे लगा हुआ था और फुट वाल्व 27 वें पश्चिमी लेवल से 3-4 फुट नीचे था। प्रबंधक भट्टाचार्यी प्रबंधक वर्ग के गवाह सं. 7 के कथनानुसार पंप 26 वें पश्चिमी लेवल से नीचे था। प्रबंधक वर्ग के गवाह सं. 8 सर्वेक्षक मुखर्जी के बयान के अनुसार 90 हार्स पावर का पंप 26 वें पश्चिमी लेवल से 20 फुट नीचे लगाया गया था और 26 वें तथा 27 वें पश्चिमी लेवलों में नीचे जल का स्तर भिन्न भिन्न रहता था। प्रबंधक वर्ग के गवाह सं. 9 एजेंट कुमार का कहना है कि दुर्घटना के तुरन्त बाद उन्होंने पंप को 26 वें लेवल से नीचे लगा पाया। गवाह खान ने इस बात का खंडन किया।

7.3 पंप की जो स्थिति बताई गई है वह प्लान, प्रदर्श 19 पर दिखाई गई पंप की स्थिति, तथा अदालती गवाहों सर्वश्री दुसाध, पी. सी. श्याम और सर्वेक्षक गणपति सिन्हा द्वारा बताई गई स्थिति के साथ मेल नहीं खाती। अदालती गवाह सं. 1 श्री दुसाध पंप खलासी हैं। दुर्घटना के समय वह तीसरी पारी में काम कर रहा था। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों ने दुसाध के बयान रिकार्ड कर लिए हैं किन्तु इन्हें अदालती गवाह इसलिए बनाया गया है क्योंकि अदालती कार्रवाई के किसी भी पक्ष ने गवाह के रूप में इनका नाम नहीं लिया। अपने बयान में वह कहता है कि तीसरी पारी के लगभग 12.45 बजे (रविवार) अर्थात दुर्घटना की तारीख के बिल्कुल सुबह सुबह उसने पंप चालू किया। निकालने के लिए जल थोड़ा सा था, किन्तु इसके 15 मिनट बाद बिजली चली गई। बिजली एक घंटे बाद अर्थात लगभग 2.00 बजे (रविवार) आई, स्टोइंग कार्य सुबह पांच बजे शुरू किया गया, इसलिए उस समय पंप चालू किया गया था। इसके एक घंटा बाद पंप अचानक बंद हो गया। मीटर पर पठनांक शून्य था, और उनके अपने ही शब्दों में, पंप का पहिया फ्री हो गया था। उन्हें जल नहीं दिखा। यह जानने के लिए कि क्या हुआ है जैसे ही वे आगे बढ़े उन्हें दूसरे व्यक्ति मिले जिन्होंने उन्हें दुर्घटना के बारे में बताया। उनके बयान से, आगे यह भी पता चलता है कि 90 हार्स पावर का पंप पहली बार सात वर्ष पहले इस्तेमाल किया गया था। शुरू शुरू में जल लगभग 23वें लेवल पर था। उस क्षेत्र से जल निकालने के लिए पंप को 28वें लेवल पर डिप खदानों के नजदीक लगाया गया था, इसके बाद डिप खदानों में बालू और मल जमा होते गए और पंप को क्रमशः इसके वर्तमान स्थान 26 वें लेवल के ऊपर लगा दिया गया। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि पिछली बार पंप को हटाने के समय से ही 27वां लेवल जल से भरा हुआ था।

7.4 गवाह के अनुसार, 13 और 14 सितम्बर की रात को जब वह ड्यूटी पर आया तो उस समय पानी तीन पाइप लम्बाइयों से कुछ कम पाया गया था। जब उसने ड्यूटी शुरू की तो उसने चूषण नली पर एक निशान लगा दिया और चाक से उस पर तारीख सहित हस्ताक्षर कर दिए। जिस स्थान पर 90 हार्स पावर का पंप लगाया गया था, वहां से उस बिंदु तक जहां उसने हस्ताक्षर किए थे का फासला लगभग 2 पाइपों के बराबर अर्थात 40 फुट था। जल-स्तर फुट-वाल्व से लगभग 10 फुट ऊपर था।

7.5 अदालती गवाह सं. 6 श्री एस. गणपति सिन्हा हैं जो खान सुरक्षा महानिदेशालय में सर्वेक्षक के पद पर काम कर रहे हैं। वे इस बिंदु पर काफी प्रकाश डालते

हैं। वे 14-9-83 को लगभग 1.45 बजे, दुर्घटना से कोई आठ घंटे बाद, भूमि के नीचे गए थे और उप महानिदेशक (सेंट्रल जोन) के निर्देशानुसार उन्होंने, सर्वेक्षण स्टेशनों को निश्चित करने और जो कुछ देखा उसे नोट करने के बाद अपनी मापांकन पुस्तिका में प्लान तैयार कर दी थी। प्रदर्श 19 में उन्होंने ऐसा कहीं कुछ भी नहीं प्रदर्शित किया जिसे उन्होंने स्वयं नहीं देखा था, सिवाय शवों की स्थिति के जो उन्होंने उप महानिदेशक के अनुदेशानुसार प्लान में दिखाई थी। प्लान के अनुसार, पंप 26वें स्तर के ऊपर था। गवाह ने उस स्थान पर लकड़ी के स्लिपरों की अस्थायी नींव देखी थी उन्होंने चाक से लगाया गया निशान और चूषण नली पर धुंधले से हस्ताक्षर भी देखे। उन्होंने उस स्थान के पास एक तांबा फुट-वाल्व जिसके साथ उतनी ही लम्बी चूषण नली जुड़ी हुई थी, भी देखा। वे इस विचार का खंडन करते हैं कि उन्होंने अपने दिमाग में कुछ पूर्व-निश्चित जल-स्तर को रख कर प्लान तैयार की थी, अतएव उन्होंने पंप की स्थिति वही दिखाई जो इस समय प्रदर्श 19 पर है। वे चाक से बने निशान और उस पर लिखे अक्षर डब्ल्यू एल का आधार लेकर चलते हैं।

7.6 खान सुरक्षा निदेशक—अदालती गवाह सं. 4—श्री पी. सी. श्याम फुट वाल्व पाए जाने की बात करते हैं। वह फुट वाल्व संक्षारित नहीं था, अतः दुर्घटना से तत्काल पहले प्रयोग में था। वे यह नहीं बता सकते कि प्रबंधक वर्ग ने दुर्घटना के बाद पंप को स्थानांतरित करते समय फुट वाल्व बदला था या नहीं।

7.7 प्रबंधक-वर्ग की ओर से यह जोरदार तर्क दिया गया कि जब प्रत्येक गवाह ने यह संगत विवरण किया है कि 90 हार्स पावर का पंप 26वें लेवल के नीचे था तो फिर दुसाध और सिन्हा के बयान स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए। किन्तु साक्ष्य की जांच गवाहों की संख्या के आधार पर नहीं की जाती। साक्ष्य गुणवत्ता के आधार पर स्वीकार किया जाता है। गवाह सिन्हा ने जो गवाही दी है उसमें सच्चाई की झलक है और इसके समर्थन में अस्थायी नींव, फुट वाल्व का मिलना और चाक के निशान पर हस्ताक्षर परिस्थिति जन्यसाक्ष्य है। दुसाध के इस बयान को कि उसने चाक से निशान लगाया और हस्ताक्षर किए बिल्कुल चुनौती नहीं दी जा सकती। व्यक्ति असत्य कह सकते हैं किन्तु परिस्थितियां नहीं। इसके अतिरिक्त, खान सुरक्षा महानिदेशालय के गवाह—सर्वेक्षक सिन्हा और निदेशक पी. सी. श्याम स्वतंत्र गवाह हैं और इनके अपने कोई स्वार्थ निहित नहीं हैं जब कि प्रबंधक-वर्ग ने जो गवाह पेश किए हैं वे अधिक सम्भावना यही है कि प्रबंधक वर्ग के हित में ही मामले की गवाही देंगे। अतएव, 90 हार्स पावर के पंप के बारे में यह बयान कि यह 27वें लेबल के ठीक ऊपर था 26वें लेबल के नीचे नहीं था सत्य प्रतीत होता है।

7.8 इसके अतिरिक्त, निरीक्षण, टिप्पणी-प्रदर्श-3 में जो प्रेक्षण दर्ज किए गए हैं। वे खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों के पक्ष को पुष्ट करते हैं। निरीक्षण-टिप्पणी के पैरा 5 के अनुसार, निरीक्षण-दल 25वें लेबल पर वापिस आया, लगभग तीन स्तम्भ लम्बाई तक पूर्व की ओर गया और लगभग एक स्तम्भ नीचे तक गया जहां रिपोर्ट के अनुसार, दुर्घटना से पहले 90 हार्स पावर का पंप लगाया गया था। उपचार कार्यों के दौरान पंप को अपने स्थान से हटा दिया गया। पंप के स्थान तक और इससे आगे तक भी डिप रोड का फर्शसंचित जल के साथ की बालू से भरा हुआ था।

7.9: उपरोक्त बहस को ध्यान में रखते हुए मेरा यह निष्कर्ष है कि 90 हार्स पावर का पंप 26वें लेवल पर लगाया गया था। इसमें 27वें लेवल को शामिल करने की संप की क्षमता का संकेत मिलता है।

7.10 इस निष्कर्ष की पुष्टि में, दुर्घटना के समय की जल की मात्रा, स्टोइंग कार्मों के दौरान बहुत पानी की मात्रा आदि के रिकार्ड किए गए साक्ष्य और संप की क्षमता के साक्ष्य मौजूद हैं।

7.11 प्रबंधक-वर्ग के गवाह सं० 7—श्री भट्टाचार्य जी का कहना है कि उन्होंने दुर्घटना के तुरन्त बाद दुर्घटना क्षेत्र में घुस आने वाले जल की कुल मात्रा का अनुमान लगाया था। उनके अनुमान के अनुसार जल की मात्रा 4.5 लाख गैलन थी। उनका यह अनुमान 29वें लेवल तक का था, किन्तु वे यह स्वीकार करते हैं कि जल 28वें लेवल से परे और उससे और भी आगे बढ़ता चला जा रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जल की पुनः अनुमानित मात्र पहले के 4.5 लाख गैलन की मिलाकर 7 लाख गैलन बताई उनके अनुसार, संप जिस रूप में 13-9-83 को था, उसके अनुसार उसमें 20 लाख गैलन जल भंडारन की क्षमता थी।

7.12 इस बिंदु पर, अखिल भारतीय खान कामिक संघ के गवाह सं० 1— श्री महदेव सोरेन का कहना है कि 14-9-1983 को वे दूसरी पारी में भूमि के नीचे गए थे। उस समय दिन के चार बजे थे। उन्होंने जल-स्तर मुख्य डिपो के 28 वे पूर्वी लेवल तक देखा। मुख्य डिपो के पश्चिम पार्श्व में जल का स्तर 28 वें लेवल के बराबर था। सम्भवतया उनका मतलब क्रास कट के 27वें पश्चिमी लेवल से है। प्लान-प्रदर्श 19 से हमें यह पता चलता है कि जो स्तर मुख्य डिप के 28वें लेवल के समकक्ष है वह पूर्वी क्रास कट का 27वां पश्चिमी लेवल है। अतएव, जल का स्तर पूर्वी क्रास-कट के 27वें पश्चिमी लेवल तक था। प्रबंधक-वर्ग के गवाह सं० —8 सर्वेक्षक मुखर्जी कहते हैं कि वे पंप के स्थल पर नियमित रूप से नहीं जाते थे उनके अनुसार दुर्घटना से 1 महीना पहले पंप-स्थल शुष्क था। किंतु, उन्होंने खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों के समक्ष यह बयान

बयान दिया था कि पूर्वी क्रास कट के 26वें और 27वें पश्चिमी लेवलों के बीच जल का स्तर ऊंचा नीचा होता रहता था। वे यह नहीं स्पष्ट कर पाए कि उनके उस बयान को गलत बयान क्यों न माना जाए।

7.13 यह पहले से ही प्रकट कि अदालती गवाह सं०-1 पंप खलासी दुसाध से जल स्तर पूर्वी क्रास कट के 27वें पश्चिमी लेवल के कहीं ऊपर फुट वाल्व से लगभग 10 फुट ऊपर पाया था। अदालती गवाह सं० 2-- प्रबंधक गुप्ता का कथन है कि स्टोइंग क्षमता 250-300 घन मीटर प्रतिदिन थी। नियोजित उत्पादन 100-150 टन प्रतिदिन था जो आगे चल कर 200-250 टन प्रतिदिन हो जाना था। इस संदर्भ में, उनका कहना है कि पंप की नियोजित क्षमता 10-15 लाख गैलन थी।

7.14 इसके बाद हम एजेंट देवेन्द्र सिंह--अदालती गवाह सं० -5 जो उस समय खान में काम करते थे--के बयान पर आते हैं। इनका कहना है कि स्टोइंग कार्य में लगभग 500 गैलन प्रतिमिनट जल छोड़ा जा रहा था। हालांकि स्टोइंग कार्य के दौरान आने वाले इस जल को 24 घंटों में निकाल दिया जाता था। उन्होंने उच्चतर स्तर पर जल प्रतिधारण के तथा डिप-खदानों से जल के अधिप्रवाह को पंप से निकालने के लिय प्रबंध किए हुए थे।

7.15 उपरोक्त विवाद से यह स्पष्ट है कि पंप विशाल पैमाने पर तैयार किया गया था और इसकी धारण क्षमता 10-15 लाख गैलन थी। अतएव, आश्चर्य ही नहीं दुर्घटना के समय 9 लाख गैलन जल अन्दर आ गया था जैसा कि कुछ गवाहों ने अपने बयानों में बताया है। इस पृष्ठ भूमि में हमें प्लान प्रदर्श-16 और खान सुरक्षा महानिदेशाल के सर्वेक्षक गणपति सिन्हा के परिकलनों को समझना और उसका मूल्याकन करना होगा। सर्वेक्षक सिन्हा ने प्लान, प्रदर्श 19 पर जल की विभिन्न स्थितियां नोट की हुई है। दुर्घटना से पूर्व, पूर्वी क्रास-कट डिप में 25वें लेवल से डिप की ओर (स्तम्भ कोने के पश्चिमी पार्श्व से) जल की स्थिति 33 मीटर है। दुर्घटना के बाद टगर डिप में 28वें लेवल का चढ़ाव (स्तम्भ कोने के पश्चिमी पार्श्व से) की तरफ जल की स्थिति 2.5 मीटर है और दुर्घटना के बाद पश्चिमी सहवर्ती डिप में 28वें डिप लेवल से चढ़ाव (स्तम्भ कोने के पश्चिमी पार्श्व से) की तरफ पानी की स्थिति पांच मीटर थी। इन प्रेक्षणो के आधार पर जो परिकलन किए गए उनसे यह प्रदर्शित होता है कि मुख्य डिप के क्षेत्र में जल की मात्रा लगभग 4180 घन मीटर अर्थात् 9,18,000 गैलन थी और पूर्वी क्रास--कट क्षेत्र में जल की मात्रा 4409.709 घन मीटर अर्थात् लगभग 9,70,000 गैलन थी।

7.16 इस साक्ष्य को देखते हुए, प्रबंधक वर्ग का यह प्रतिवाद कि संप निम्न धारिता वाला था या पंप की स्थिति से संप की निम्न धारिता का पता चलता है अमान्य प्रतीत होता है।

बहस के दौरान, संप की धारण-क्षमता से अधिक जल-मात्रा होने के मान्यता सू चार कारण सुझाए गए। पहला, वे यह बताते हैं कि जल की वृद्धि सम्भवतया 14-9-83 को सुबह 6 बजे घबराहट की स्थिति में स्टोइंग पम्प को बन्द कर दिए जाने के कारण हुई हो। किंतु इससे सिर्फ यह पता चलता है कि कुछ देर के लिये जल की मात्रा को कम करने के लिए कोई पंपिंग नही की गई थी। इससे इस प्रश्न पर कोई प्रकाश नही पड़ता कि संप की वास्तविक धारण क्षमता कितनी थी अर्थात् अधिकाधिक इसमें कितना जल आ सकता था।

7.17 दूसरा कारण लगभग 12 घंटे के समय में हुई जल मात्रा की सामान्य वृद्धि माना गया है। इस अवधि में जल निकालने का काम शुरू करने के लिये कोई पंप नहीं लगाया गया था। सामान्य जल मात्रा को इस घटक को ध्यान में रखने के बाद ही पंप का डिजायन तैयार किया गया था। इसके फलस्वरूप जल पंप की धारण क्षमता से अधिक नही हो सकता था, और किसी भी हालत में, इसमें वृद्धि केवल मामूली वृद्धि होगी।

7.18 तीसरे यह संभावना भी बताई गई है कि अधि-प्रवाह के कारण 17वें लेवल पर मध्य पंप से जल वापस आ गया हो। यह एक तथ्यात्मक पक्ष है। हमें 17वें लेवल पर संप की धारण-क्षमता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पक्षसमर्थन अथवा साक्ष्यों में इस प्रकार का कोई केस तैयार नही किया गया था। यदि दुर्घटना का यही वास्तविक कारण होता तो प्रबंधक-वर्ग इसकी संभावना की ओर से आंखें मूंद नहीं सकते थे। हम अनुमानों को लेकर नहीं चल सकते। अतएव यह तर्क भी स्वीकार नही किया जा सकता।

7.19 चौथा कारण यह व्यक्त किया गया है कि छत और स्टोवित क्षेत्र की रिक्तियों के बीच, स्तम्भ हटा लिए गए स्टोवित क्षेत्र में जल इकट्ठा हो गया था यह संचित जल उठान की तरफ था जो गुरुत्वाकर्षण के कारण आप्लावन-स्थल जो डिप की तरफ के हिस्से में था की ओर तेजी से बह निकला। श्री दात ने भी बहस के दौरान इसी कारण की ओर संकेत किया था। मैंने उन्हें तब भी यह बता दिया था कि यह सब अटकलबाजी अधिक प्रतीत होती है, वास्तविक घटना कम। फिर, यह सब प्रमाणित करने के लिय कोई सबूत पेश नही किए गए कि उपर लिखित रिक्त स्थान मौजूद थे, या फिर जल जमा हो गया था अथवा जल दुर्घटना के समय ही क्यों और कैसे वह निकला जब कि गत समय में कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हो रहा था--इसके लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया यदि इस तरह का जल लगभग प्रायः ही बहता रहता था तो फिर इसे जल की सामान्य मात्रा ही कहा जाएगा अतएव, यह कारण भी अनुमानों पर आधारित है। यदि यह पानी, स्तम्भ हटा लिए गए क्षेत्र से बह कर आता तो अपने पीछे यह पंक, सिल्क आदि की एक लीक छोड़ देता, किंतु न तो लेवलों से जल निकाल लिये जाने के तुरन्त बाद या फिर 1-10-1983 की अदालती जांच के समय भी ऐसे कोई संकेत नहीं पाए गए।

7.20 निष्कर्ष रूप में, जितने भी कारणों की ओर संकेत किया गया है उन्हें पंप में अत्यधिक जल होने के कारणों के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि कोई 9 लाख गैलन जल दुर्घटना के समय प्रवाहित हुआ था। मेरे विचार में इस धारण की भी कोई गुंजायश नहीं है कि पंप की धारण-क्षमता कम थी। अतएव, यह बहस 90 हार्स पावर के पप के स्थिति के बारे में इसी निष्कर्ष को पुष्ट करती है कि यह दुर्घटना से पहले 26वें लेवल के ऊपर था।

अध्याय—8

27वां लेवल और संप

8.1 यह दर्दनाक दुर्घटना 27वें पश्चिमी लेवल के तीसरे डिप के तल के फट जाने और 29वें पूर्वी लेवल के तीसरे डिप में—जो उस समय 27वें पश्चिमी लेवल के तीसरे डिप के नीचे था—तेजी से पानी घुस आने के कारण हुई। अतः यह पता लगाना लाभकारी होगा कि 27वां पश्चिमी लेवल कब और किस तरीके से परिचालित किया गया और 29वें पूर्वी लेवल का तीसरा डिप नीचे कैसे हो गया था।

8.2 अदालती गवाह सं०-3-प्रबंधक श्री गुप्ता है जो हुरिलाडीह कोयला खान में 3-5-1977 से 1-10-1978 तक काम करते थे। अदालती गवाह सं० 5—देवेन्द्र सिंह दिनांक 19-4-76 से 25-4-1980 तक कोयला खान में एजेंट थे और अदालती गवाह सं० 2—सर्वेक्षक श्री वर्मा इस कोयला खान में सर्वेक्षक के रूप में जुलाई 1978 से आए और 21 नवम्बर 1981 तक रहे। गवाह श्री गुप्ता का कथन है कि अपनी कार्यावधि के अन्तिम चरण में वे 26वें और 28वें लेवलों के बीच, पूर्वी क्रास-कट सेक्शन में चौदहवीं सीम में काम कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले उन्होंने पूर्वी क्रास-कट क्षेत्र के पूर्वी पार्श्व तथा मुख्य डिप के पश्चिमी पार्श्व का विकास करने की योजना बनाई थी। किंतु जुलाई, 1978 से ही पूर्वी क्रास कट के डिप की तरफ वाले क्षेत्र पानी में डूब गए थे और वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे नहीं बढ़ सके। तब प्रबंधक वर्ग ने 'ई' पैनल से स्तम्भ हटाने का काम शुरू करने और साथ-साथ पूर्वी क्रास-कट के पश्चिमी पार्श्व वाले क्षेत्र में विकास कार्य को हाथ में लेने का निर्णय किया। इन्हीं परिस्थितियों में, अगस्त, 1978 में, स्तम्भ हटाने की अनुमति प्राप्त की गई थी। स्तम्भ हटाए गए क्षेत्र में स्टोइंग कार्य के लिये संप आवश्यक था। स्वभाविक रूप से ही अंतःस्रवण के कारण जल पूर्वी पार्श्व की सबसे नीचे की गैलरियों में रिसना शुरू हो गया था। गवाह का कथन है कि स्तम्भ हटाए गए क्षेत्र के लिये संप की पूर्वी क्रास-कट क्षेत्र के पूर्वी पार्श्व में सबसे निचले स्तर पर बनाने की योजना बनाई गई थी। उनके अनुसार, यह 27वें और 28वें लेवलों के बीच बनाने का विचार किया गया था। उन्होंने पूर्वी क्रास-कट के पश्चिमी पार्श्व के खदानों और मुख्य डिप की खदानों अर्थात् मुख्य डिप की खदानों और वर्तमान संप के बीच कोई 100 फुट का अवरोधक बनाने की योजना बनाई थी। वे यह स्पष्ट कहते कि पूर्वी क्रास-कट का 27वां लेवल उनकी कार्यावधि में परिचालित किया गया था। हालांकि उन्हें यह याद नहीं था कि उनके सेवाकाल में इस स्तर के पहले, दूसरे और तीसरे डिप परिचालित किए गए थे अथवा नहीं। वे यह जरूर कहते हैं कि उनके सेवाकाल में विकास कार्य सीमा के लगभग मध्य सेक्शन में किया जा रहा था और उत्पादन उसी क्षेत्र में हो रहा था।

8.3 अदालती गवाह सं० 5—श्री देवेन्द्र सिंह का कहना है कि उन्होंने पूर्वी पार्श्व के डिप की ओर के हिस्से के स्तरों तक पानी ले जाने की योजना बनाई थी। प्रदर्श 80 को देख कर वे कहते है कि संप को पूर्वी क्रास-कट डिप के 27वें और 28वें डिप की तरफ के पूर्वी लवलों में बनाने की योजना बनाई गई थी। यह बताते हुए कि स्तम्भ हटाने का यह कार्य क्यों शुरू किया गया, उनका यह कथन है चौदहवां सीमा पूर्वी क्रास-कट के पार्श्व वाले विकास क्षेत्र में जल में डूब गए थे और उनकी जगह स्तम्भ-विहीन क्षेत्र बना दिया गया था। मुख्य डिप के 22वें पूर्वी लेवल और पूर्वी क्रास-कट के पश्चिमी लेवल के नीचे वाला छोटा सा हिस्सा अविकसित था और अब उसके विकास का कार्य हाथ में लिया गया था। उनके कथनानुसार, 27वां पश्चिमी लेवल हालांकि संप के रूप में विकसित नहीं किया गया था किन्तु उनके सेवा काल में इसका संप के रूप में प्रयोग किया जाने लगा था।

8.4 इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 26वें लेवल के डिप की तरफ के नीचे के स्तरों को संप के रूप में प्रयोग करने की योजना बनाई गई थी। और 27वें पश्चिमी लेवल का भी संप के रूप में प्रयोग किया जाने लगा था। गवाह श्री गुप्ता की तरह ही देवेन्द्र सिंह का कथन है कि चौदहवी सीमा का विकास कार्य सीमा के मध्य के निचले क्षितीज में हाथ में लिया गया था और जहां तक मुख्य डिप विकास का संबंध है, यह सीमा से मिलने के बाद पहले उपलब्ध ग्रेडिएण्ट के साथ-साथ किया जा रहा था। इन गवाहों की गवाही से यह स्पष्ट है कि पूर्वी क्रास-कट के परिचालन जो मध्य क्षितीज में थे वे मुख्य डिप में ग्रेडिएण्ट के साथ-साथ के परिचालनों के तुलना में भिन्न-भिन्न सेक्शनों में थे। अतः यह सोचना स्वाभाविक था कि कोई न कोई सेक्शन किसी न किसी स्थान पर किसी दूसरे सेक्शन के ऊपर होगा।

8.5 गवाह श्री वर्मा के अनुसार, वह क्षेत्र जुलाई 1978 के पहले से ही जल में डूबा हुआ था। इसके बाद चौदहवीं सीम में स्तम्भ हटाने का कार्य शुरू किया गया। उन्होंने सीम का बंद परिपथ-सर्वेक्षण किया था। किन्तु आरेखण अथवा परिचालन तैयार करने से पहले ही उसका स्थानांतरण हो गया था। वे आगे यह कहते है कि सर्वेक्षक के रूप में उनके पूरे कार्यकाल में 26वां लेवल जल से भरा हुआ था। 26वां पूर्वी और 25वां पश्चिमी लेवल उनके सेवा काल में एक दूसरे से संयोजित नहीं किए गए थे। जब उन्होंने कार्यभार संभाला था, 27वां पश्चिमी लेवल चालू किया गया था, किन्तु उनका कहना है कि यह अभिगम्य नहीं था।

8.6 जिरह के दौरान, उनसे, स्वर्गीय श्री दास जो उनसे पहले के सर्वेक्षक थे की लिखावट वाली प्रदर्श 69 पर आधारित प्रश्न पूछे गए। प्रदर्श 69 में दिखाए गए माप के अनुसार 27वें पश्चिमी लेवल के तीसरे डिप का ड्राईवेज 4 मीटर (अर्थात् 13 फुट) और चौथे डिप का ड्राईवेज 5 मीटर (अर्थात् 16 फुट) तक था। किन्तु वे यह स्वीकार करते है कि दिनांक 30-6-1982 तक की संशोधित प्लान प्रदर्श-62 में तीसरा डिप 40 फुट लम्बा दिखाया गया है और प्लान, प्रदर्श 19 जो दुर्घटना के बाद तैयार किया गया—उसमें 27वें पश्चिमी लेवल से परे के तीसरे और चौथे डिप की वास्तविक लंबाई क्रमश: 100 फुट और 68 फुट पाई गई।

8.7 गवाह से उसे अभिलेख पुस्तकों प्रदर्श 81— जो उन्होंने स्वयं रखी थी—के संदर्भ में प्रश्न पूछे गए। उन्होंने टाल मटोल की और यह कह कर अदालत को गुमराह करने का प्रयत्न किया कि वहां की माप-टिप्पणियां जल स्तर की थीं हलांकि उनके ऊपर के उपशीर्ष 'कुल माप' 'पहले के' और 'प्रगति' के बारे में बताते है। प्रदर्श 81 में दिनांक 2-8-1978 के नीचे, 27वें लेवल के तीसरे डिप के सामने दिखाया गया माप 70 फुट है। गवाह वर्मा का कथन है कि यह माप जल स्तर का परिचायक है और वे इस कथन का परिणाम भुगतने को भी तैयार है कि डिप में पानी उस स्तर तक ऊंचा चला गया था जो विश्सनीय प्रतीत होता है। इसी प्रकार, उन्होंने ये भी कहा कि 27वें लेवल के पहले और दूसरे डिप के माप जो क्रमश: 112 फुट और 97 फुट दिखाए गए हैं वे इन डिपों के जल स्तरों के परिचायक हैं। यह साक्ष्य ऐसा है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। किंतु, प्रबंधक श्री गुप्ता ने इस बारे में उन्हें झूठा साबित कर दिया है। श्री गुप्ता को प्रदर्श 81 की उन प्रविष्टियों का अर्थ-विवेचन करने के लिये कहा गया जो सर्वेक्षक श्री वर्मा ने की थी तो उन्होंने यह कहा था कि ये माप ड्राईवेजों के परिचायक हैं। अत: प्रदर्श 81 से यह स्पष्ट है कि श्री वर्मा के कार्यकल के दौरान 27वें लेवल के पहले, दूसरे और तीसरे डिपो का कार्य पूरी तरह चालू था और यह भी कि पहला डिप 112 फुट, दूसरा डिप 97 फुट और तीसरा डिप 70 फुट की लंबाई तक चालू किया गया था। अत: हमारे सामने यह स्पष्ट चित्र है कि इस क्षेत्र में 1977 से 1978 के बीच विकास कार्य कैसे चालू किया गया और यह भी कि अगस्त 1978 तक पहले, दूसरे और तीसरे डिप काफी लम्बाई तक परिचालित किए जा चुके थे। अतएव इन साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि पूर्वी क्रास कट के दोनों तरफ, 26वें लेवल के नीचे का क्षेत्र संप के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा था ताकि वहां पर ऊर्ध्वमुखी खदानों से जल एकत्रित किया जा सके।

8.8 प्रबंधक वर्ग के गवाह सं० 7 श्री एस० के० भट्टाचार्जी प्रबंधक का कथन है कि 28वें, 29वें और 30वें पूर्वी लेवल उसके सेवा काल में परिचालित किए गए थे। उनके कथनानुसार 29वां पश्चिमी लेवल सामान्य परिस्थितियों में भी शुष्क नहीं किया जा सकता था। उन्होंने 12-7-82 को कार्यभार संभाला था, अतएव वे उस समय की परिस्थितियों के संबंध में ही बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्वी उठान डिस्ट्रिक्ट में पंप के नीचे की खदानें संप थीं। हालांकि यह विवाद का प्रश्न था कि क्या 90 हार्स पावर का पंप जैसा कि प्रबंधक-वर्ग के कुछ गवाहों ने अपने शपथ पत्रों या फिर जिरह के दौरान कहा है, 26वें पश्चिमी लेवल से थोड़ा सा नीचे लगाया गया था, या जैसा कि प्लान प्रदर्श 19 में दिखाया गया है। यह 27वें पश्चिमी लेवल से कुछ थोड़ा सा ऊंचा लगाया गया था। इस विवाद का निपटान मैंने अपने इस निष्कर्ष में कर दिया है कि पंप वहीं पर लगा हुआ था जहां यह प्लान, प्रदर्श 19 में दिखाया गया था, किंतु यह निर्विवाद है कि डिप की तरफ के 27वें लेवल से संप का क्षेत्र था, गवाह यह पुष्टि करता है कि चौदहवीं सीमा में खदान के दौरान समुचित हाराईजन नहीं बनाए रखा गया उनके कथनानुसार, मुख्य डिप के 27वें पूर्वी लेवल के अंताग्र और संप-खदान के बीच लगभग 60 फुट का कोयले का अवरोधक था। वे यह भी कहते हैं कि मुख्य डिप से 28वें, 29वें और 30वें लेवल न्यूनाधिक रूप से फर्श के साथ-साथ परिचालित किए गए थे। अत: इसमें ताज्जुब नहीं कि एक खदान उसी सेक्शन की दूसरी खदान के उपर हो।

8.9 ये ड्राईवेज पानी से भरे क्षेत्र जिसे संप कहते हैं- के आस पास ही थे। यह इस बयान से भी स्पष्ट हो गया है कि गवाह ने सहवर्ती डिप से परे, 28वें पूर्वी लेवल के ड्राईवेज को रोक दिया था। वास्तव में गवाह ने 27वें और 29वें लेवल के पूर्व की तरफ वाले ड्राइवेजो को तथा 27वें लेवल को पार करने के बाद 26 वें पूर्वी लेवल के पूर्वी और डिप की तरफ वाले ड्राईवेज को बंद कर दिया था। प्रबंधक वर्ग के गवाह सं० 4 काली पद मंडल 28वें लेवल के पूर्वी अंताग्र को बंद किए जाने का उल्लेख करते हैं, हालांकि वें इसका कारण नहीं जानते। प्रबंधक वर्ग का गवाह सं० 8वें सर्वेक्षक मुखर्जी 27वें लेवल और साथ ही मुख्य डिप के 28वें पूर्वी लेवल के पूर्व दिशा के ड्राईवेजों को बंद कर दिए जाने की बात कहते हैं। इसी तरह कामिक संघ गवाह संख्या 1—सहायक प्रबंध मारेन भी, दुर्घटना से कुछ ही दिन पहले 29वीं पूर्वी लेवल को बन्द करने और उसके तुरन्त बाद 29वें लेवल के तीसरे डिप को चालू करने का हवाला देते हैं। प्रबंधक भट्टाचार्जी और सर्वेक्षक मुखर्जी इन ड्राईवेजों को बन्द करने के कारणों के विषय में स्पष्टतया कहते हैं-कि वे नहीं चाहते थे कि संप समाप्त हो जाए अर्थात् वे चाहते थे कि संप अपेक्षाकृत अधिक धारिता वाला जैसा कि यह उस समय था-हो। प्रबंधक का यह कथन था कि 27वां पश्चिमी लेवल सामान्य परिस्थितियों में भी शुष्क नहीं किया जा सकता था जब तक कि निकासी के लिए एक नाली न बना दी जाए। इस बयान को इसी पृष्ठ भूमि में रख कर समझना होगा। सर्वेक्षक मुखर्जी का कथन है कि 27वें लेवल के चारों डिपो को शुष्क (जल-विहीन) करने के लिये किसी भी समय कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। प्रबंधक-वर्ग के गवाह सं० 9 एजेंट का कहना है कि

27वें पश्चिमी लेवल का चौथा डिप संप का ही एक हिस्सा था। इसी प्रकार, तीसरा डिप भी संप का ही एक हिस्सा था और सदैव जल में डूबा रहता था। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि 29वां पूर्वी लेवल संप से 60 मीटर के अन्दर परिचालित किया गया था हालांकि उनके कथनानुसार संप को जलाक्रांत क्षेत्र नहीं माना जा सकता।

8.10 उपरोक्त बहस से यह स्पष्ट हो जाता है कि 27वें पश्चिमी लेवल का परिचालन कब और कैसे हाथ में लिया गया और कैसे उन खदानों का संप के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। वास्तव में, 27वें लेवल के डिप अनिवार्य तथा जल से भरे रहते थे और प्रबिन्दु-तल अंकित करने के लिए कहीं कोई प्रयास नहीं किया गया था।

अध्याय 9

प्रबिंदु-तल (स्पाट लेवल)

9.1 फर्श पर प्रबिंदु तल दिखाने से उन भिन्न स्तरों के जिन पर कार्य चालू था, विषय में उपयोगी भूमिगत संकेत मिल जाते हैं और ये प्रबिंदु तल संभवतया कुछ सीमा तक वर्तमान दुर्घटना के संबंध में चेतावनी का कार्य कर सकते थे।

9.2 प्रबिंदु-तल, विनियम 59 के उप-नियम (3)(बी) के अधीन दिखाए जाने आवश्यक होते हैं। विनियम 59 के अंतर्गत जो प्लानें रखनी आवश्यक होती हैं उनमें से एक प्लान खान की भूमिगत प्लान है। उप विनियम 3(बी) का संबंध भूमिगत प्लान से है और उसमें यह उपबंध है कि प्लान में खदान कार्य के फर्श पर निम्नलिखित प्रबिंदु-तल दिखाने भी आवश्यक हैं ;

(1) उन सड़क मार्गों को छोड़कर जहां ट्रामिंग हस्तचालित साधनों से की गई हो और जहां प्रबिंदु-तल उन बिंदुओं पर जो एक दूसरे से 150 मीटर से अधिक दूरी पर न हों, दिखाए गए हों—सभी सड़क मार्ग जंक्शनों पर ढुलाई सड़क-मार्गों के साथ साथ, और

(2) उन मुख्य दिशाओं में भी जो अस्थायी अथवा स्थायी तौर पर त्यक्त कर दी गई हों—ऐसे प्रबिंदु-तल इनके अंतिम सिरों पर दिखाए जाएं।

9.3 निसंदेह यह सत्य है कि प्रबिंदु-तल तब अंकित किए जाते हैं जब खदानें बंद कर दी गई हों किंतु उपर्युक्त विनियम में खदान कार्य के परित्याग की फिर चाहे वे स्थायी हों अथवा अस्थायी बात कही गई है। कामिक संघ गवाह सं.-1 श्री सोरेन की गवाही में यह कहा गया है कि दुर्घटना के समय केवल पांच अंतागों पर कार्य किया जा रहा था। वे मुख्य डिप अंताग्र टगर डिप अंताग्र, 29वें पूर्वी लेवल का तीसरा डिप टगर डिप से परे का 30वें लेवल का अंताग्र और पश्चिमी सहवर्ती डिप। जहां तक अन्य क्षेत्रों का संबंध है, उन्हें चालू अंताग्र नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रबिंदु तलों को प्रदर्शित करने के विषय में विनियम का हवाला दिया जा रहा है।

9.4 किन्तु यह स्वीकृत स्थिति है कि प्लान प्रदर्श 62 तैयार हो जाने और उस पर सर्वेक्षक द्वारा दिनांक 30.6-82 को हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद किसी भी प्लान पर कोई प्रबिंदु-तल नहीं दिखाए गए थे। प्रबंधक वर्ग के गवाह सं. 8 सर्वेक्षक मुखर्जी ने अपने बयान में यह कहते हैं कि प्रबिंदु-तल इसलिए नहीं दिखाए गए क्योंकि 27वें पश्चिमी तल से परे का तीसरा डिप मलबा से भरा हुआ था जो लेवल तक भी फैल गया था। केवल इसी एक लेवल के संबंध में उन्होंने खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों के सामने बयान दिया है कि 27वें लेवल की डिप गलियां सर्वेक्षण के समय जल निमग्न पाई गई और इसी कारण उन्होंने इनको बिंदुकित लाइनों द्वारा प्रदर्शित किया है। बिना कुछ कारण दिए वे कहते हैं कि खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों के सामने दिया गया बयान गलत है। अब उनका कहना है कि से संप में डिप की तरफ की खदानों के तल पर प्रबिंदु-तल नहीं दिखाए पाए क्योंकि एक तो ये खदानें उनके कार्यभार संभालने से पहले की बनी हुई थी और दूसरे वह क्षेत्र बालू से और जल भरा हुआ था जिसके परिणामस्वरूप वे वहां जा नहीं सके। इस प्रकार वे यह स्वीकार करते हैं कि सर्वेक्षण नहीं किया गया किंतु वे इस बात पर अटल नहीं है कि 27वां लेवल जलाक्रांत था।

9.5 प्रबंधक वर्ग के गवाह संख्या 4—एजेंट कुमार यह स्वीकार करते हैं कि प्रबिंदु-तल, ढुलाई सड़क पर प्रदर्श 62 में 23वें लेवल तक और क्रास कट डिप में 27वें लेवल तक जो अंतिम योजना स्थल है, दिखाए गए हैं। वे यह स्वीकार करते हैं कि जहां भी मुख दिशाएं बंद हैं वहां प्रबिंदु-तल नहीं दिखाए गए हैं यद्यपि विनियम 59 के अंतर्गत ये दिखाए जाने आवश्यक थे। वे इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए कि प्रबिंदु-तल क्यों नहीं दिखाए गए। अदालती गवाह सं. 2 सर्वेक्षक वर्मा जो जुलाई 1978 से नवंबर 1981 तक वहीं थे उनका कथन है कि अप्राप्य कार्य-प्लान पर प्रबिंदु-तल दिखाए गए थे किंतु वे उन सारी प्लानों के जो इस समय अदालत के सामने थी अतिरिक्त अन्य ऐसी कोई भी प्लानों के बारे में नहीं बता पाए जिनसे इस बयान की पुष्टि हो होती हो कि प्रबिंदु-तल दिखाए गए थे। अदालती गवाह सं. -3 प्रबंधक श्री गुप्ता यह कह कर ही संतुष्ट हो जाते हैं कि इस संबंध में उन्होंने सामान्य अनुदेश दे दिए थे उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि उनके अनुदेशों का अनुपालन किया गया अथवा नहीं।

9.6 अदालती गवाह सं. 5 श्री देवेंद्र सिंह का ध्यान खान सुरक्षा महानिदेशक के अगस्त 1978 के पत्र की शर्त सं. 7 की ओर दिलाया गया जिसमें उन्होंने स्तम्भ हटाने की अनुमति दी थी, गवाह से यह पूछा गया कि प्रबिंदु-तल दिखाए गये थे अथवा नहीं उन्होंने ताज्जुब भरा जवाब दिया कि उस शर्त के बावजूद प्रबिंदु-तल दिखाये जाने आवश्यक नहीं थे क्योंकि सोलहवीं सीम जो चौदहवीं सीम के ऊपर है—गत समय में स्तम्भ विहीन कर दी गयी थी और उस तक पहुंचा नहीं जा सकता था। किंतु यह स्पष्ट है कि उन्होंने खान सुरक्षा महानिदेशक को इस शर्त को हटाने के लिए कभी प्रार्थना नहीं की थी। प्रोफेसर श्री मरवाहा द्वारा पूछे

गए एक प्रश्न के उत्तर में उनका कथन है कि उस स्थिति में विनियम 59(3)(बी)(ii) का हवाला नहीं दिया गया जब पूर्वी क्रास कट का 27वां पश्चिमी लेवल और उनके नीचे के लेवल जल में डूब गए थे। दूसरे शब्दों में यद्यपि ये डिप जल से भरे हुए थे फिर भी प्रबंधक वर्ग ने यह महसूस नहीं किया कि इनसे मोटर पंप आदि के प्रयोग द्वारा जल निकाला दिया जाए और प्रबिंदु-तल अंकित कर दिए जाएं इस संबंध में अदालती गवाह नं. 4 श्री पी. सी. श्याम ने यह बयान दिया है कि जब क्षेत्र जल डूबा हो, हम प्रबिंदु-तल नहीं नाप सकते किन्तु उन्हें हम स्कीम के ग्रेडिएंट से माप सकते हैं। इस तरह के प्रबिंदु-तलों का परिकलन ग्रेडिएंट के आधार पर उस स्थिति में नहीं किया जा सकता यदि ग्रेडिएंट सतत हो और यदि खदान कार्य तल अथवा छत अथवा ज्ञात क्षितिज में किया गया हो।

9.7 उपरोक्त बहस से यह प्रतीत होता है कि जहां तक 27वें पश्चमी लेवल के डिपों का संबंध है कोई प्रबिंदु-तल कभी भी मापे नहीं गए। संभवतया यह संकेत दिया गया है कि डिपों का प्रयोग सम्प के रूप में किया जा रहा था और इसलिए प्रबिन्दु-तल अंकित करना ठीक नहीं समझा गया। किन्तु सामान्य स्थिति यह है कि हाल के वर्षों में प्रबिंदु-तल अंकित करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

अध्याय-10

नक्शों में गलतियां और चूकें

10.1 तीसरे डिप, 27 वें पश्चिमी लेवल को तीसरे डिप, 29 वें पूर्वी लेवल से जोड़ना इस दुर्घटना का प्रत्यक्ष कारण है, जिसमें 19 निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई। ऊपर के तीसरे डिप, 27 वें लेवल को संप का पानी तेजी से नीचे की ओर आया, जिसमें सम्पूर्ण क्षेत्र जलमग्न हो गया। प्रबन्धकों ने अपने लिखित बयान, प्रदर्श-5, में कहा है कि अचानक ही एक छेद हो गया था। उन्होंने यह नहीं बताया कि ये दोनों गैलरियां किस प्रकार जुड़ सकीं। पैरा 11,6 में कहा गया है कि कुछ पुराने नक्शों से यह आभास मिलता है कि दुर्घटना वाली पुरानी गैलरी 29 वें लेवल से दूर थी परन्तु दुर्घटना के बाद इसे पानी से खाली करने पर यह बात गलत पाई गई। गवाही के समय वे इस परिणाम पर पहुंचे कि दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि वह नक्शा गलत था जिसके अनुसार वे कार्य कर रहे थे। प्रबन्धक-वर्ग के प्रत्येक गवाह ने गलत नक्शे होने की बात कही है। उन्होंने यह बात भी सामने रखी कि वे जिस नक्शे के अनुसार कार्य कर रहे थे वह अनुरेखण कपड़े वाला था, जो गुम है और न्यायालय के सामने नहीं है। प्रबन्ध गवाह नं.-1, श्री सुधीर कुमार भट्टाचार्य, सर्वेक्षण अधिकारी ने अपने अतिरिक्त शपथ-पत्र में बताया है कि उन्होंने 14 वीं सीम का सर्वेक्षण शाफ्ट लेवल से शुरू किया था, जहां भारतीय खान स्कूल द्वारा सतह से भूमितल में स्थानान्तरित दो स्टेशन मौजूद थे। उन्होंने खान के दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था। इस पुनःसर्वेक्षण से पता चला कि मुख्य डिप क्षेत्र से सम्बन्धित 29 वें लेवल की सही स्थिति उपलब्ध नक्शे के अनुसार थी; परन्तु पूर्व की ओर के 27वें लेवल के क्षेत्र से पता चलता है कि पहले के नक्शों में इसकी वास्तविक स्थिति उत्तर में लगभग 45 फुट डिप वार बदल दी गई थी। इस स्थानान्तरण की बात दूसरे गवाहों ने भी कही है, जैसाकि प्रबन्धक भट्टाचार्य, प्रबंध गवाह 7 सर्वेक्षक मुखर्जी, प्रबंध गवाह-8 और एजेंट कुमार, प्रबंध गवाह-9। इसके अलावा इन गवाहों ने बताया है कि तीसरे डिप 27 वें पश्चिमी लेवल अर्थात दुर्घटना ग्रस्त पुराने डिप की लम्बाई 100 फुट है, जबकि कार्यकारी नक्शे और अन्य नक्शों से तैयार किए गए नक्शे, प्रदर्श 62 में यह लम्बाई केवल 40 फुट दिखाई गई है। इसका मतलब यह हुआ कि 60 फुट की एक और गलती है। परिणामतः कुल गलती 45 फुट+60 फुट अर्थात 105 फुट की बनती है। इससे उस चौकी का पता ठीक-ठीक नहीं चलता जहां वे काम कर रहे थे और जहां दो गैलरियां अप्रत्याशित और अचानक ही जुड़ गई।

10.2 गवाह भट्टाचार्य, प्रबन्धक, एजेंट कुमार और अदालती गवाह-2 गुप्ता, भूतपूर्व प्रबन्धक के अनुसार वे अनुरेखण कपड़े पर बनाए गए उस नक्शे को, जो गुम है, प्रतिदिन इस्तेमाल करते थे और उस नक्शे में प्रोजेक्शन दिखाए गए थे। प्रत्येक व्यक्ति का कहना है कि नक्शा कार्यालय में पड़ा था। लेकिन यह नक्शा वह नहीं है जो खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा मंगाया गया था। नक्शे को कब्जे में लेते समय खान सुरक्षा महानिदेशक के पास वह नक्शा उपलब्ध नहीं था, यद्यपि सर्वेक्षक मुखर्जी ने यह कहा है कि सूची-पुस्तक, प्रदर्श 58 में उसका उल्लेख है यह बात सिद्ध नहीं होती कि खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों ने उस नक्शे को दबा लिया है। वस्तुतः नक्शों और दस्तावेजों को कब्जे में लेते समय पावती दी जाती है। अतः इस संभावना को सहज ही अस्वीकार किया जा सकता है, परन्तु फिर यह नक्शा कहां गया? स्पष्ट है कि किसी ने चोरी से संभवतः गुप्त उद्देश्य से उसे निकाल लिया होगा, क्योंकि उस नक्शे में कई तरह के दोष थे और प्रबंधक वर्ग का उससे पर्दाफाश होता था कि उसने ऐसे दोषपूर्ण नक्शे के अनुसार काम किया। इसलिए नक्शा चुराने वाला व्यक्ति यह चाहता था कि यह सब कुछ न्यायालय की जानकारी में न आए। जो भी हो, हमारा प्रयास होगा कि अब तक जो साक्ष्य रिकार्ड किया गया है, उससे पता लगाया जाए कि क्या प्रबंधक वर्ग परिश्रम करके दुर्घटना के बाद ज्ञात गलतियों का पता लगा सकता था और क्या वह समय पर गलतियों को सुधारने की कार्रवाई कर सकता था हालांकि जो गवाही ली गई है, उससे संभवतः हम ठीक ठीक यह न बता सकें कि ये गलतियां किसने कीं।

10.3 लिखित बयान के अनुसार, राष्ट्रीकरण के बाद विकास का प्रारम्भिक कार्य 1978 तक चलता रहा। सितम्बर, 1978 में खान पानी में डूब गई और चौदहवीं सीम का काम अस्थायी रूप से रोक दिया गया। इसके स्थान पर खंभा हटाने का क्षेत्र तैयार कर दिया गया जिसे खान के उभरे भाग पर पैनल "ई" कहा जाता है। मुख्य डिप क्षेत्र में डिप की तरफ का कार्य छत में मजबूत टेक लगाए बिना पुनः चालू नहीं किया जा सका। पश्चिमी तरफ छत में टांका लगाने के काम को करने के बाद अनछुए क्षेत्र के कार्य को 1981 में पूरा किया गया और डिप की तरफ मध्य पूर्वी खान का काम 1982 में शुरू किया गया। यह कार्य खम्भ हटाने के काम के साथ ही साथ किया गया, जिसकी अनुमति

अगस्त 1978 में ली गई थी। किन्तु दिसम्बर 1978 में ही यह बात मालूम थी कि इग्लिाडीह खान के नक्शों के संबंध में सारी बातें संतोषजनक नहीं हैं।

10.4 अदालती —गवाह 7 तपन मजूमदार, उपनिदेशक ने 28.12.1978 को अन्य सीमों के साथ-साथ चौदहवा सीम का भी निरीक्षण किया था। उनकी 'उल्लघंन' रिपोर्ट प्रदर्श 87 से पता चलता है कि उनको जो पी-2/हुरि/एस और पी-3/हुरि/एस नक्शे दिए गए थे, उनमें इस बात का प्रमाण-पत्र नहीं था कि नक्शों की नकल किन्ही खास नम्बर के पुराने नक्शों से की गई है और वे सही है। पी-2/हुरि/एस नक्शे में बैंच मार्क के ब्यौरे नहीं दिखाए गए थे और सर्वेक्षक को इनकी जानकारी नही थी। पी-3/हुरि/एस नक्शे में बिन्दु लेवल अपेक्षित स्थानों में नहीं दिखाए गए थे। वह नक्शा अद्यतन नहीं था और पिछली बार उस पर 1-10-1977 को हस्ताक्षर किए गए थे। गवाह का निर्देश था कि नया संयोजन और सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और नया नक्शा भी तैयार किया जाना चाहिए।

10.5 यदि इस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता और इस पर सावधानीपूर्वक अनुवर्ती कार्यवाही की जाती तो इससे प्रबंधकों को नक्शे में संशोधन करने का अच्छा मौका मिलता क्योंकि जिस गलती का अब पता लग गया है उसे दूर किया जा सकता था। दूसरी बार सावधानी बरतने का मौका तब आया जब प्रबन्धक गुप्ता, अदालती गवाह 3 ने 6-11-1978 को कार्यभार रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट, प्रदर्श 84 में उन्होंने नक्शे की अशुद्धि के बारे में उल्लेख किया है। सभी सीमों के बारे में सामान्य सूचना देने के बाद उन्होंने संचालन के बारे में लिखा, और उसके बाद पानी के खतरे के बारे में अपनी बात कहते हुए उन्होंने दो पैरा लिखे, जो इस प्रकार है :—

"4 पिछला सर्वेक्षण गलत प्रतीत होता है, और इसलिए नक्शों को सही होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता। नवीन सर्वेक्षण करना होगा और नए नक्शे तैयार करने होंगे।" सीमों का सर्वेक्षण लगभग पूरा हो गया है और आरोपण कागज आदि मिलते ही उन्हें आलेखित किया जा सकता है।

"5 नए सर्वेक्षण के अनुसार एक और विकास प्रक्षेप नक्शा तैयार किया गया है और क्षेत्र प्रबन्धक (तकनीकी) द्वारा अनुमोदित किया गया है; आगे का विकास कार्य इस प्रक्षेप के अनुसार किया जाना है।" इन टिप्पणियों को पढ़ने मात्र से पता चलता है कि तत्कालीन प्रबन्धक नक्शों के सही होने के बारे में संतुष्ट नहीं थे। वे नवीन सर्वेक्षण चाहते थे, परन्तु ग्यारह सीमों का सर्वेक्षण लगभग पूरा हो चुका था और उस सर्वेक्षण के आधार पर आगे के कदम सुझाए गए थे।

10.6 उनके मौखिक साक्ष्य से पता चलता है कि कार्यभार रिपोर्ट के पैरा 4 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "पिछला सर्वेक्षण" से उनका अभिप्राय बी.सी.जी.एल. तथा भूतपूर्व प्रबन्धकों द्वारा तैयार की गई चौदहवीं सीम के ऊपर की ओर से 27वें लेवल से लेकर किए गए सर्वेक्षण से है। ग्यारहवीं सीम का पुनः सर्वेक्षण करने के बाद उन्हें संदेह हुआ। वहाँ अशुद्धियां मिलने के कारण, उसी प्रकार की अशुद्धियां चौदहवीं सीम में होने का उन्हें संदेह हुआ। यह खेद का विषय है कि प्रदर्श 84 के विवरणों या प्रदर्श 87 में सुझाई गई बातों को उतनी गम्भीरता से नहीं लिया गया, जितनी गम्भीरता से उन्हें लिया जाना चाहिए था, हालांकि ये अशुद्धियां ऐसी नहीं थी, जिनसे प्रबन्धक-वर्ग उत्साहित होकर कार्य शुरू करता।

10.7 तत्कालीन एजेन्ट देवेन्द्र सिंह, अदालती गवाह 5 का इस सम्बन्ध में कहना है कि उन्होंने खान बंद करने की बात नहीं सोची थी क्योंकि उस समय विकास कार्य चल रहा था। जब उनसे खास तौर पर प्रश्न किया कि प्रदर्श 87 में दिखाई गई गलतियों को ठीक करने के लिए उन्होंने क्या किया तो कहा कि उन्होंने प्रबंधक और सर्वेक्षक से 3 गलतियों को ठीक करने के लिए कहा था। यह भी कहा जाता है कि पुनः सर्वेक्षण का काम हाथ में लिया गया।

10.8 दलीलों में पुनः सर्वेक्षण के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और यह दिखाने की कोशिश की गई है कि काम को हर तरह से सही करते हुए भी दुर्भाग्य से दुर्घटना हो गई। इस प्रकार यह कहा गया है कि प्रबन्धक-वर्ग ने परिश्रम किया परन्तु ईमानदारी से अपने पूरे प्रयास करने के बावजूद दुर्घटना हो गई। मैं इस दलील को नहीं मानता हूं। चौदहवीं सीम का तथाकथित पुनः सर्वेक्षण सितम्बर 1983 तक पूरा नहीं हुआ था, हालांकि जैसा कहा जाता है, इसका काम वर्ष 1979 के समाप्त होने से पहले हाथ में ले लिया गया था। यह सोचना भी मुश्किल है कि सीम के पुनः सर्वेक्षण का काम लगभग 4 वर्ष चलता रहा। पुनः सर्वेक्षण चलता रहा इस मामले के समर्थन में प्रबंधकों की ओर से दलील दी गई है कि खान सुरक्षा महानिदेशक इस बात को जानते थे और इसलिए दंड देने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह सच है कि खान सुरक्षा महानिदेशक को और आगे निरीक्षण करने का अवसर मिला, जैसा कि रूपरेखा - प्रदर्श 88 से पता चलता है। 28-12-78 के निरीक्षण के बाद और बहुत से निरीक्षण हुए, जिनमें से कुछ आंशिक निरीक्षण थे और वर्ष 1981 में कम से कम एक सामान्य निरीक्षण किया गया था। यह भी सच है कि गवाह पी.सी. श्याम (अदालती गवाह 4) और गवाह मुखर्जी (अदालती गवाह 7) ने प्रश्नोत्तर में बताया कि उन्होंने मामले में अनुवर्ती कार्यवाही इसलिए नहीं की क्योंकि वे जानते थे कि प्रबन्धक-वर्ग काम कर रहा है। किन्तु इन उत्तरों को पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता। यदि पुनः सर्वेक्षण का काम दोष मालूम हो जाने के तुरन्त बाद, जिस समय

शुरू हो गया होता तो इसमें इतना लम्बा समय नहीं लगना चाहिए था।

10.9 इस बारे में ध्यान देने योग्य बात यह है कि एजेन्ट (अदालती गवाह 5) का कहना है कि प्रबन्धक को पुनः सर्वेक्षण के बारे में दी गई हिदायतें लिखित रूप में नहीं थी। अदालती गवाह 7 ने भी कहा है कि चौदहवीं सीम की चौतरफा जांच करने में छाई महीने लगेंगे बशर्ते कि एक दल को पूरे समय के लिए इस काम पर लगा दिया जाय। एक दल से मतलब है - एक सर्वेक्षक, एक सहायक सर्वेक्षक और तीन चेनमैन। कुछ यूनियनों ने इस बात पर जोर दिया है और जिस प्रकार से अदालती गवाह 7 ने साक्ष्य दिया है, उससे भी साफ है कि खान सुरक्षा महानिदेशक पर आवश्यकता से अधिक काम का बोझा है। कहा गया है कि प्रबन्धक वर्ग काम कर रहा था परन्तु इस बारे में न्यायालय को विश्वास हो सके, ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं की जा सकी। किसी भी बात से पता नहीं चलता कि प्रबन्धकों और खान सुरक्षा महानिदेशक के बीच पुनः सर्वेक्षण विषय पर नियमित पत्राचार हुआ हो। मेरे सामने इस प्रकार का कोई पत्र पेश नहीं किया गया। यह बात प्रबन्धकों की जानकारी में थी कि किसी विशेष समय पर और समय-समय पर पुनः सर्वेक्षण के कार्य में जितनी प्रगति हुई। इस बारे में क्षेत्र पुस्तिका, कच्चे नक्शे आदि जैसी सामग्री होनी चाहिए जिससे पुनः सर्वेक्षण के बारे में कदम-कदम पर हो रही क्रमिक प्रगति का पता चल सके। इस तरह की कोई सामग्री पेश नहीं की गई। न्यायालय को केवल मौखिक बयान ही मिले हैं कि पुनः सर्वेक्षण चालू था। यह भी नहीं बताया गया कि काम कब समाप्त होता नजर आता था। सारांश यह है कि "पुनः सर्वेक्षण चालू होने" की बात केवल रक्षात्मक उपाय के रूप में इस्तेमाल की गई है, यह मानते हुए कि खान सुरक्षा महानिदेशक का कार्यालय, जो खामोश था, असहमति प्रगट नहीं कर सकता। प्रतीत होता है कि खान सुरक्षा महानिदेशक का कार्यालय इसलिए खामोश रहा क्योंकि निरीक्षण की जाने वाली खानों की इतनी अधिक संख्या है कि उनका निरीक्षण करना उनके बूते से बाहर था। यदि इस अवसर पर हुरिलाडीह कोयला खान के सर्वेक्षण के काम में अत्यधिक सतर्कता रखने का समय उनके पास नहीं मिल सका तो वे ऐसा ही उत्तर दे सकते थे, जैसा कि उन्होंने दिया है। परन्तु यह दलील नहीं दी जा सकती कि खान सुरक्षा महानिदेशक के नियंत्रण के अभाव में खान में काम करने वाले व्यक्तियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह साफ जाहिर है कि उन लोगों की यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे खानों में सुरक्षा के लिए कानूनी अपेक्षाओं का पूर्णरूप से पालन करें। यह उनकी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी कि वे सही मार्ग पर रहते और इस बात में सतर्क रहते कि खानों के सर्वेक्षण नक्शे सही किए जाएं और गलत नक्शों के कारण किसी दुर्घटना होने की गुंजाइश न रहे।

10.10 इस प्रसंग में यह मालूम करना उपयोगी होगा कि प्रबंधकों ने जिस ढंग से सर्वेक्षण और संबद्ध मामलों को लिया और कार्रवाई की गई है, इस बारे में रिकार्ड पर जो साक्ष्य उपलब्ध है, उससे क्या परिणाम निकलता है। लिखित बयान और मौखिक रूप से भी सह-संबंध सर्वेक्षण का उल्लेख हुआ है, परन्तु वह तो समुचित अभिविन्यास के लिए भारत कोकिंग कोल लि. की सभी खानों को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने और एक सामान्य संदर्भ ग्रिड बनाने के उद्देश्य से था। यह काम जियोडलाइट तथा भारत के सर्वेक्षण कार्यालय की अनुसंधान शाखा को सौंपा गया था और जैसा कि अदालती गवाह 5 ने कहा है, यह काम 1980 में समाप्त हो गया था, जब सतह पर दो स्टेशन स्थापित कर दिए गए थे। स्पष्ट है कि यह काम संपूर्ण झरिया कोयला खान को सह-संबद्ध करने के लिए हाथ में लिया गया था। हुरिलाडीह के भूमिगत सर्वेक्षण का काम अखिल भारतीय संगठन द्वारा नहीं किया जाना था; वह काम खानों में काम कर रहे लोगों का था। अदालती गवाह, 2, सर्वेक्षक श्री वर्मा, 1978 से 1981 के दौरान कोयला खान से संबद्ध थे, उनका कहना है कि उन्होंने चौदहवीं सीम का बंद परिपथ सर्वेक्षण किया, परन्तु उनके द्वारा आकलन और आलेखन करने से पूर्व ही उनका तबादला हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने 20वें लेवल तक का बंद परिपथ सर्वेक्षण समाप्त कर लिया था। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि वे नक्शे को अद्यतन बना रहे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्र-पुस्तिका प्रदर्शन 69 में प्रविष्टियां की और यह पुस्तक उन्होंने प्रबंधकों को सौंप दी थी, परन्तु जहां तक कोयला खान विनियम 60 के अनुपालन का संबंध है, उनका कहना है कि उन्हें यह याद ही कि उन्होंने नक्शे खान सुरक्षा महानिदेशक को नियमित रूप से भेजे थे या नहीं। उनके अनुसार 29 जुलाई 1978 से खानें जलमग्न थी और जैसे ही उनका पानी निकाल दिया गया, विकास कार्य शुरू हो गया। फिर, उनके साक्ष्य से पता चलता है कि किस प्रकार से ड्राइवेज के काम में प्रगति हुई है जो कि हम 27वें पश्चिमी लेवल के ड्राइवेज के बारे में चर्चा करते हुए देख चुके हैं।

10.11 अदालती गवाह 5 एजेंट देवेंद्र सिंह ने भी कहा है कि चौदहवीं सीम का पुनः जांच सर्वेक्षण उनके कार्य-काल में हुआ था, परन्तु आलेखन करने का काम उस समय नहीं किया गया था। उन्होंने विशिष्ट रूप से बताया कि सभी प्रवण्य भागों का सर्वेक्षण किया गया था। प्रबंध-गवाह प्रबंधक भट्टाचार्य ने अपनी गवाही में बताया कि पश्चिमी तरफ का बंद परिपथ सर्वेक्षण किया गया था। यह मुख्य डिप से पश्चिमी की तरफ 20वें या 23वें लेवल के पास था। प्रबंध गवाह 8 सर्वेक्षक मुखर्जी का कहना है कि जुलाई 1978 से नवम्बर 1981 तक वे चौदहवीं भूमिगत सीमा के सर्वेक्षण कार्य से संबद्ध थे। उनके कार्यकाल में मुख्य परिपथ पूरे कर लिए गए थे, आकलन हो गया था और कपड़ा-चढ़े कागज पर; जो अब न्यायालय के सामने प्रदर्श 62 के रूप में है, आलेखन कर लिया गया था। सर्वेक्षण कार्य वर्मा और अधिकारी सर्वेक्षकों ने किया था। नवंबर 1981 में सांविधिक सर्वेक्षक के रूप

में कार्यभार संभालने पर उन्होंने विकास कार्य प्रणाली का सर्वेक्षण हाथ में लिया। यह 23वें पश्चिमी लेवल के मुख्य डिप सेक्शन और उसमें नीचे का सर्वेक्षण था। उन्होंने आगे प्रत्युत्तर में बताया कि विनियम 58(3) के उपबंध के अनुसार वे हर तिमाही में सर्वेक्षण नहीं करते थे क्योंकि उनका समय बहुत से ऐसे कार्यों में लग जाता था जो सांविधिक कार्यों के अंतर्गत नहीं आते। वह प्रवणता लाइन का निर्देशन नहीं कर रहे थे क्योंकि प्रवणता लाइन के काम में झामा लगा हुआ था और वह लाइन स्वतः इधर-उधर हो सकती थी।

10.12 अतः यह स्पष्ट है कि बंद परिपथ सर्वेक्षण का कार्य नक्शे में दो बार गलतियों की अधिसूचना के बाद किसी समय हाथ में लिया गया था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 29वें पूर्वी लेवल तथा 27वें पश्चिमी लेवल, जिनमें हमारा संबंध है, दोनों में ही बंद परिपथ सर्वेक्षण नहीं हुआ। पूर्वी क्रास कट के 27वें पश्चिमी लेवल के संबंध में ब्यौरों, अर्थात् ड्राइवेज अंक शुरू हुआ तथा कहां तक डिप खोदा गया, के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। खंभे हटाने की अनुमति अगस्त 1978 में दे दी गई थी। उस समय 'ई' पैनल दर्शाते हुए एक नक्शा पेश किया गया था और मान लिया जाता है कि उस हिस्से का सर्वेक्षण अवश्य हुआ होगा। परन्तु उस समय गैलरी या लेवल थी ही नहीं। 29वें पूर्वी लेवल और अन्य दो लेवलों अर्थात् 27वें पूर्वी लेवल तथा 28वें पूर्वी लेवल को प्रबंधक भट्टाचार्य के कार्यकाल में शुरू किया गया था। 27वें पूर्वी लेवल को कब शुरू किया गया, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रबंध गवाह 7 प्रबंधक भट्टाचार्य से पता चला कि छुट्टी के दौरान उनकी अनुपस्थिति में 28वें पूर्वी लेवल का काम पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा था। परन्तु उन्होंने लौटने पर अपना कार्यभार संभालते ही ड्राइवेज रुकवा दिया क्योंकि व चाहते थे कि संप ज्यों को त्यों बनी रहे। प्रबंध गवाह 8 मुखर्जी ने भी हमें जानकारी दी कि 29वें लेवल का काम दुर्घटना से लगभग एक या दो महीने पहले शुरू हुआ था और इसके एकदम आखिरी पूर्वी मुंह पर किए जा रहे काम को रोक दिया गया था ताकि संप न बिखरे।

10.13 इस ड्राइवेज को रोकने के तुरन्त बाद, 29वें पूर्वी लेवल की तीसरे डिप के काम को हाथ में लिया गया। इस प्रकार तीनों लेवलों और उनकी डिपों के ड्राइवेज के बारे में उस भाग की कार्य प्रणाली की धुंधली सी तस्वीर ही है। अब हम जानते हैं कि प्रबंधक भट्टाचार्य के शब्दों में 26वें पूर्वी लेवल और 25वें पश्चिमी लेवल को जोड़ दिया गया था। वस्तुतः यह एक और उसी लेवल पर है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि संप की ओर किए जा रहे कार्य का बंद परिपथ सर्वेक्षण करने का शानदार अवसर उसे आरंभ न करके गंवा दिया गया।

10.14 यह मालूम करना उपयोगी होगा कि प्रबंधकों ने सर्वेक्षण कार्य करते समय कितनी परवाह और सावधानी बरती। गवाह भट्टाचार्य का कहना है कि कोयला खान विनियम 59(3) के उपबंध के अनुसार उन्हें आशा थी कि वे प्रत्येक तिमाही में नक्शा बनाए रखे रहेंगे, परन्तु सर्वेक्षक ने न तो कार्यकारी नक्शे पर और न ही कपड़ा चढ़े कागज के नक्शे पर आलेखन किया। उन्होंने वायदा किया था कि वे कपड़ा चढ़े कागज के नक्शे को उसके पूरा होने के बाद लाएंगे। परन्तु प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं हुआ और गवाह ने पूरी सतर्कता या काम को शीघ्र समाप्त करने का कष्ट नहीं उठाया। स्पष्ट है कि वे कोयला खान विनियम 60 के अनुबंध के अनुसार नक्शा प्रस्तुत नहीं कर सके। जाहिर है कि जहां तक 6-4-1983 वाले प्रदर्श 43 का संबंध है उनका कहना है कि यह अनुरेखबंद कपड़े पर बने कार्यकारी नक्शे की प्रति है। गवाह ने बताया कि प्रदर्श 62 विनियम 59 (10) (ख) के उपबंध के अनुसार भूमिगत भाग का नक्शा है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि गुमशुदा अनुरेखण कपड़े के नक्शे को पुस्तिका, प्रदर्श 58, में दर्ज किया गया था, जैसा कि विनियम 63(4) में अपेक्षित है। प्रदर्श 59 जिल्द चढ़ी और पृष्ठ संख्या अंकित पुस्तक है जिसे विनियम 49 (2) के अधीन बनाया गया था परन्तु उसमें पानी के बारे में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं है, जिससे पता चल सके कि कौन से पानी दुर्घटना हुई। उन्होंने स्वीकार किया कि विनियम 59(ख) के अनुसार वे बिंदु रेखाएं जिनमें तिमाही प्रगति और तारीख दी जाती है, किसी भी नक्शे में नहीं है।

10.15 यही स्थिति सर्वेक्षक मुखर्जी की है। वे दास, मेहता और वर्मा के साथ एक सर्वेक्षक थे तथा नवम्बर 1981 से कानूनी रूप से सर्वेक्षक बन गए थे। इनका कहना है कि पूर्वी क्रास-कट के 27वें पश्चिमी लेवल का सर्वेक्षण उनके कार्यभार संभालने के बाद नहीं हुआ, हालांकि काम चल रहा था। उन्होंने अनुरेखण कपड़े वाले नक्शे के गुम होने की बात कही और उस नक्शे के बारे में प्रदर्श 58 के पृष्ठ, 8 क्रम सं. 4 की प्रविष्टि का उल्लेख किया। परन्तु उन्होंने भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श 43, जिसे कार्यकारी नक्शा कहा जाता है, की प्रविष्टि प्रदर्श 58 में नहीं है। उनके अनुसार प्रदर्श 43 रोजमर्रा के काम के लिए तैयार किया गया था और इसलिए रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई। प्रदर्श 62 कपड़ा चढ़े कागज वाले नक्शे में 'प्रतिबंध' 'अनुमति' आदि शब्द हैं, परन्तु जिसने यह नक्शा बनाया, उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। गवाह के अनुसार यह इसलिए हुआ क्योंकि वे उस समय सहायक के रूप में काम कर रहे थे। कार्यभार संभालने के बाद वे उसकी शुद्धता के बारे में संतुष्ट थे और इसलिए उन्होंने प्रदर्श 62 पर हस्ताक्षर कर दिए, परन्तु साथ ही तुरन्त यह भी जोड़ दिया कि उन्होंने संपूर्ण नक्शे की जांच नहीं की थी। उन्होंने केवल 28वें लेवल के नीचे मुख्य डिप के पूर्वी तरफ के हिस्से में आलेखन अंकित किया था, लेकिन उन्होंने इसकी जांच नहीं की। उन्होंने मुख्य डिप 4 के 26वें पूर्वी लेवल का सर्वेक्षण और आलेखन किया था। वह भी बंद परिपथ नहीं था, बल्कि खुला परिपथ था। उसका संबंध मुख्य डिप के 28वें पूर्वी लेवल से था जिसका काम दुर्घटना होने से 1 1/4 महीने पहले शुरू हुआ था। सर्वेक्षण कार्य लगभग 9 या 10 सितम्बर 1982 को किया गया था प्रदर्श 62वें

सर्वेक्षक के 3-6-1982 के हस्ताक्षर हैं, परन्तु प्रबंधक ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उनका कहना है कि वे जुलाई 1982 में स्थानांतरित हो गए थे।

10.16 जहां तक गुमशुदा अनुरेखण कागज पर नक्शे का प्रश्न है, इसके बारे में उनका ध्यान विनियम 59 (1) (घ) की ओर दिलाया गया, जिसमें इस प्रकार के नक्शों को सीधे सपाट स्थिति में रखने की व्यवस्था है। परन्तु उन्होंने बताया कि अनुरेखण कागज वाले नक्शे को सीधा सपाट स्थिति में रखते थे। 29वें पूर्वी लेवल का काम उनके कार्यकाल में शुरू हुआ। परन्तु उन्होंने कोयला खान विनियम 49(2) (क) के अनुसार जिल्दबंद संख्या अंकित पुस्तक में रिकार्ड नहीं रखा। गुमशुदा नक्शे के संदर्भ में उनका कहना है कि पूर्वी क्रास कट के 27 वें पश्चिमी लेवल के डिप उस नक्शे में स्पष्ट रेखा के रूप में दिखाए गए थे। विनियम 49(2) के बारे में उनका कहना है कि उन्हें कोई संदेह नही था और इसलिए जिल्दबंद पृष्ठ संख्या अंकित पुस्तक में यह प्रविष्टि नहीं की। उनका ध्यान दो नक्शों, प्रदर्श 63 व 64 में प्रक्षेप रेखाओं की ओर दिलाया गया। उनके अनुसार प्रदर्श 63 पर उन्होंने प्रक्षेप रेखाएं नही बनाई। वे नहीं जानते कि ये रेखाएं किसने बनाई। लेकिन प्रदर्श 64 की प्रक्षेप रेखाएं उन्होंने बनाई थीं। परन्तु उन्होंने यह बात नहीं मनी कि यदि प्रदर्श 63 में दिखाई गई प्रक्षेप रेखाओं के अनुसार विकास कार्य किया जाता तो कोई दुर्घटना न होती।

10.17 गवाह ने दुर्घटना के बाद खान सुरक्षा महानिदेशलय के अधिकारियों को नक्शा बनाने संबंधी उनके द्वारा किए गए कुछ कार्य के बारे में बयान दिया था। खान सुरक्षा महानिदेशक के सामने उन्होंने कहा कि उन्होंने पूर्वी क्रास-कट हिस्से के 27वें लेवल की डिप गैलरियों को बिंदु रेखा द्वारा अंकित किया था, क्योंकि जब उन्होंने 27वें लेबल का सर्वेक्षण किया तो उस समय वह पानी में डुबी थी। अब उनका कहना है कि वे कीचड़ और पानी से भरी थीं और इस बात से इंकार करते हैं कि उन्होंने इनका सर्वेक्षण किया था। उनका कहना है कि बयान में गलती घबराहट के कारण हुई है।

10.18 उनका कहना है कि वे एक अलग विभागीकृत नक्शा तैयार कर रहे थे और इसलिए उन्होंने प्रदर्श 16 पर हस्ताक्षर नही किए। परन्तु न्यायालय के सामने कोई अलग नक्शा नहीं है। उन्होंने बचाव नक्शा प्रदर्श 15 पर 30-6-1982 को हस्ताक्षर किए, परन्तु प्रदर्श 16 पर हस्ताक्षर न करने के लिए दिए गए कारण को देखते हुए यह मतलब निकालना होगा कि संभवतः उन्हें यह नक्शा महत्वपूर्ण नहीं लगा। 30-6-1982 के बाद यहां तक कि प्रदर्श 15 पर भी हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं और इसके लिए उनका कहना है कि वे सर्वेक्षण की तैयारी में पूरी तरह व्यस्त रहे। प्रदर्श 15 में उन्होंने 29वें पूर्वी लेवल और इसके सभी डिप को दिखाया है। परन्तु उनका कहना है कि इन खदानों को दिखाने के बाद उस नक्शे पर हस्ताक्षर करना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा।

10.19 उनके कथनानुसार पेंसिल से चिह्न दुर्घटना से लगभग 6-7 दिन पहले लगाए गए थे और इनमें से कुछ दुर्घटना से 1/2 महीने पहले भी लगाए गए थे। ये निशान पेंसिल से इसलिए लगाए गए क्योंकि उस समय परिपथ बंद नही था। उनकी अच्छी खासी दलील यह है कि किसी ऐसी गलती को पकड़ने का कोई विशेष तरीका नहीं है कि जब नक्शे में ड्राइवेज 40 फुट दिखाया गया हो और ड्राइवेज वस्तुतः 100 फुट हो।

10.20 उन्होंने खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों को दिए गए अपने किसी ऐसे बयान से इंकार कर दिया जिसमें उन्होंने मुख्य नक्शों में बिंदु रेखाओं के रूप में जलमग्न डिप गैलरियां दिखाई हों परन्तु कुछ अन्य नक्शों में उन्होंने उन गैलरियों को खुला भी दिखाया है। यह गलत बयान क्यों दिया गया, इसका वे कोई कारण नहीं बता सके हैं। उनके कार्यकाल में ही मुख्य डिप के 26वें पूर्वी लेवल और क्रास कट के 25वें पश्चिमी लेवल को जोड़ा गया था। उसके अनुसार इन्हें संवातन और पूर्वी हिस्से के निरीक्षण की सुविधा के प्रयोजन से जोड़ा गया। खान सुरक्षा महानिदेशक के सामने उनका बयान था कि ऐसा पानी के स्तर की जांच करने के लिए किया गया। जब उनका ध्यान खान सुरक्षा महानिदेशक के सामने उनके इस बयान की ओर दिलाया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें जोड़ने का यह भी एक कारण था। हालांकि पानी के स्तरों की जांच की जानी थी, परन्तु उन्होंने यह आवश्यक नही समझा कि पूर्वी क्रास-कट के 27वें पश्चिमी लेवल के उन सिरों के अंत में स्टाट लेवल दिखा दिए जाएं जो रोक दिए गए थे। 25वें और 26वें लेवलों को जोड़ने के लिए उनके द्वारा दिए गए तीसरे कारण को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसा मैंने पहले कहा कि यह बंद परिपथ सर्वेक्षण करने का अच्छा अवसर हो सकता था। तब प्रबंधकों को मुख्य डिप के पूर्व और पश्चिम दोनों भागों में तथा 29 वें और 27वें पश्चिमी लेवल, जहां दुर्घटना हुई, के बारे में नवीनतम विकास कार्य की निश्चित और विश्वसनीय स्थिति का पता लग जाता। यदि इसे तुरन्त कार्यान्वित कर दिया जाता तो विभिन्न लेवलों और डिपों के कार्यों की वास्तविक स्थिति मालूम की जा सकती थी और संभवतः दुर्घटना की स्थिति से बचा जा सकता था। संभवतः प्रबंधकों के पास इस प्रकार के उपाय करने का न समय था और न ही उन्होंने सोचा था।

10.21 उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने विनियम 59(3) के अनुबंधानुसार तिमाही सर्वेक्षण नहीं किया और उनका कहना है कि ऐसा सांविधिक कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में लगे रहने के कारण हुआ। निश्चय ही, ऐसी स्थिति में वे या तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर सकते थे या राहत की मांग कर सकते थे। परन्तु उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन न करते हुए पूरी तरह से शिथिलता बरतने का रवैया अपनाया और अपने कर्त्तव्यों की अनदेखी की।

10.22 आइए, अब हम देखें कि एजेंट कुमार सर्वेक्षण और खदानों के बारे में क्या कहते हैं। उनका ध्यान मुख्य डिप के

पूर्व में तीसरे डिप के 29वें लेबल, प्रदर्श 62 (जिसकी एक प्रति प्रदर्श 14 है) में प्रक्षेपों की ओर दिलाया गया। एजेण्ट बनने से पहले वे हुरिलाडीह कोयला खान के प्रबंधक थे। उनका कहना है कि प्रबंधक के रूप में उन्होंने प्रक्षेपों का कार्य टगर डिप तक किया था। आगे के प्रक्षेपों का काम संबंधित प्रबंधक द्वारा किया गया था जो उन्हें उनके बारे में सूचित करते रहते थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने चौदहवीं सीम के पुनः सर्वेक्षण वाले नक्शे पर हस्ताक्षर कर दिए थे, हालांकि सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ था। 5 सितम्बर 83 को वे भूमितल में गये थे। और उस समय 29वें पूर्वी लेबल का ड्राइवेज शक्तिशाली विस्फोट द्वारा किया जा रहा था। यह कार्य दूसरे डिप से और आगे लगभग 25 फुट तक बढ़ गया था। जैसा कि अब हम जानते हैं कि इसके आगे पूर्व की ओर यह कार्य रोक दिया गया था। प्रबंधक के रूप में उन्होंने ड्राइवेज का कोई रिकार्ड नहीं रखा। वे नक्शे पर निर्भर रहे। उन्होंने स्वीकार किया है कि 29वें पूर्वी लेवल का आम संप खदान, अर्थात् क्रासकट से 27वें पश्चिमी लेवल सहित खदान के 60 मीटर अन्दर किया जा रहा था। दूसरे शब्दों में यह बात स्पष्ट रूप से मान ली गई लेवल पानी के भंडार की ओर बढ़ रहा था और उसकी दूरी 60 मीटर से कम थी। स्पष्ट है कि किसी भी छेद आदि करके कोई भी पूर्वोपाय करने का कष्ट नहीं उठाया। विनियम 127 लागू होता है या नहीं, इस बारे में अलग से चर्चा की गई है। परन्तु इस स्थिति में एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या पूर्वोपाय किए बिना आगे काम बढ़ाना बुद्धिमता थी, जबकि आगे 9 लाख गैलन की क्षमता वाला सप दिखाई दे। ऐसा लगता है कि अधिक सावधानी की जरूरत थी जो नहीं बरती गई।

10.23 गवाह ने जवाब में कहा कि विनियमों के अनुसार तिमाही सर्वेक्षण किए जाते थे, परन्तु अपने बयान को सिद्ध करने के लिए वे ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके जिससे पता चलता कि 30-6-1982 के बाद तिमाही सर्वेक्षण किए गए। उनका कहना है कि एजेंट बनने के बाद यह काम प्रबंधक को सौंपा गया था। असेसर के सवाल के जवाब में उन्होंने आगे यह स्वीकार किया कि यह उनका कर्त्तव्य था कि वे यह देखे कि तिमाही सर्वेक्षण किएं जाते हैं, परन्तु स्पष्ट है कि वे अपने कर्त्तव्य निर्वाह में असफल रहे। उन्होंने एक गोलमोल जवाब दिया कि उन्हें याद नहीं कि मुख्य डिप के 27वें, 28वें और 29वें पूर्वी लेवलों का ड्राइवेज कब शुरू हुआ था परन्तु जब उनसे 28वें पूर्वी लेवल के रोक देने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया है कि काम रोकने से पहले प्रबंधक ने उनसे परामर्श किया था अतः स्पष्ट है कि प्रबंधक ड्राइवेज के बारे में अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करते रहे हैं। इस मामले में, 29वें पूर्वी लेवल और 27वें पश्चिमी लेवल के ड्राइवेज अधिक संगत हैं, परन्तु यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि प्रबंधक द्वारा उच्चाधिकारियों को घटनाओं की जानकारी दी जाती रही। गवाह का ध्यान प्रदर्श 18 में प्रक्षेप की ओर दिलाया गया। उन्होंने माना कि गलत नक्शों के कारण दुर्घटना हुई। गवाह का ध्यान कोयला खान विनियम 64(4) की ओर दिलाया गया, जिसमें निहित है कि यदि सर्वेक्षण खदान के किसी भाग को नहीं दिखाता है या उनसे कोई भाग दिखाना छूट जाता है या नक्शों अथवा सेक्शनों में गलतियाँ होने देता है तो एजेंट या प्रबंधक जिम्मेदार होते हैं। गवाह ने मुंहफट उत्तर दिया है कि यह एक थोपी गई जिम्मेदारी है। गवाह ने यह भी कहा कि क्रासकट के 27वें पूर्वी लेवल के तीसरे डिप का काम कभी भी उसके कार्यकाल में नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने स्वीकार किया कि सिरे का कार्य बंद कर दिया गया और उन्होंने सहमति प्रकट की थी कि विनियम 59 (3) (ख) को लागू होता है परन्तु स्पाट लेवलों को न दिखाए जाने के बारे में उन्होंने यह दलील दी कि संप के रूप में प्रयुक्त होते थे।

10.24 मैं पहले ही इस बारे में चर्चा कर चुका हूं कि हुरिलाडीह कोयला खान के प्रबंधकों ने स्पाट लेवलों को चिह्नित करने के काम एक लंबे समय तक कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। जैसा कि पूर्वोक्त पैराओं से पता चलता है, उन्होंने अन्य विनियमों के अनुपालन पर भी ध्यान नहीं दिया। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि नक्शा तैयार करने और सर्वेक्षण का काम कभी भी संतोषजनक ढंग से नहीं किया गया।

10.25 गवाह का ध्यान विशेष रूप से खान सुरक्षा महानिदेशक के परिपत्र, प्रदर्श 100, की ओर दिलाया गया, जिसके अनुसार पानी के खतरे का एक अलग नक्शा बनाना अपेक्षित था। उसमें अनेक पूर्वोपाय करने की व्यवस्था है ताकि पानी भरने की कोई गुंजाइश न हो। यदि परिपत्र के अनुबंधों का पालन दृढ़ता से किया जाए तो ऐसा लगता है कि किसी खान में पानी भरने का कोई मामला न हो। यह याद रखने योग्य है कि दिसम्बर, 1978 में या जनवरी, 1979 में निरीक्षण अधिकारी ने अपनी उल्लंघन रिपोर्ट, प्रदर्श 87, में चेतावनी दी थी और सावधान किया था परन्तु सामान्य नक्शा गलत होने तथा पुनः सर्वेक्षण किए जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट सुझाव पर स्थिति से निपटने के लिए कोई विशेष कार्रवाई नही की गई। पुनः सर्वेक्षण कितने लम्बे समय तक चलता रहा, इस बारे में कुछ पता नहीं चला और न ही चल सकेगा क्योंकि इसका कोई निश्चित समय नहीं रखा गया था। और किसी भी स्तर पर इसकी प्रगति को न तो योजना बनाई गई थी और न ही पूर्वानुमान लगाया गया था। यह विधाता का लेखा ही है कि पुनः सर्वेक्षण की धीमी प्रगति इस घातक दुर्घटना से रुक गई और प्रबन्धकों को स्थानीय सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लेना पड़ा, जिससे दोहरी गलती सामने उभर कर आई। जहां तक पानी के खतरे के बारे में नक्शा तैयार करने का सम्बन्ध है, खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों ने इस मामले पर आगे कार्रवाई नहीं की। किन्तु गवाह मजूमदार का कहना है कि पानी के खतरे संबंधी नक्शे को बीच में तैयार करने से सही ढंग से नहीं था।

क्योंकि इसका मह सर्वेक्षण न सर्वेक्षण नक्शे में करना पड़ता था, जो तैयार नहीं था। परन्तु परिणाम यह हुआ कि दोहरे दुर्भाग्य की बात हुई अर्थात् न तो पानी के खतरे सम्बन्धी नक्शों को तैयार किया जा सका और न ही अद्यतन सर्वेक्षण हो सका। निश्चित ही यह अच्छी स्थिति नहीं है ; जरूरत थी कि अद्यतन सर्वेक्षण नक्शा और साथ ही पानी के खतरे से संबंधित अद्यतन नक्शा तैयार होता।

10.26 किस प्रकार से सर्वेक्षण कार्य किया गया और किस तरह से बिना सोचे-समझे इस पर काम हुआ, इसकी एक साफ झलक देखने के लिए न्यायालय के सामने जो कुछ नक्शे हैं, उनका अध्ययन करना उपयोगी होगा।

इससे गलतियों की चली आ रही श्रृंखला स्पष्ट होगी जैसाकि पहले बतलाया गया है कि एक बंद पश्चिम सर्वेक्षण चल रहा था, जिसमें मुख्य डिप के पश्चिम भाग की खदान शामिल थी। क्रासकट के एक भाग का सर्वेक्षण भी हो रहा था, जबकि खंभे हटाने की अनुमति मांगी गई, जो अगस्त, 1978 में कुछ समय पहले दी गई, परन्तु संबंधित लेवलों अर्थात् मुख्य डिप के 26 वें और 29 वें पूर्वी लेवलों तथा क्रासकट के 25 वें और 27 वें पश्चिमी लेवलों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। जब 26वें पूर्वी लेवल और 25वें पश्चिमी लेवल को जोड़ा गया तब सर्वेक्षण के शानदार मौके को गंवा दिया गया।

10.27 परित्यक्त नक्शों के अलावा जो सबसे पुराना नक्शा उपलब्ध है, वह न्यायालय के सामने प्रदर्श 80 है। इस पर सर्वेक्षक वर्मा ने 21-4-1979 को हस्ताक्षर किए। इसे संधातन नक्शा कहते हैं। वर्मा ने इस बारे में कुछ अलग ही कहानी बताई। उनका कहना है कि प्रदर्श 80 पर मुद्रण के रूप में जो हस्ताक्षर हैं, वे उनके हैं, परन्तु उन्होंने संधातन नक्शे पर हस्ताक्षर नहीं किए। जब उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, तब केवल हाथ से बना नक्शा था और उस पर 'संधातन' शीर्षक नहीं दिया गया था, जैसा कि अब इस नक्शे में है। जिस नक्शे पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, उसमें तिमाही सर्वेक्षण चिह्नों के दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और इसलिए प्रदर्श 80 पर तिमाही सर्वेक्षण चिह्न नहीं हैं। किन्तु प्रदर्श 80 के आरेख के बारे में जो ध्यान देने वाली बात है, (चाहे यह श्री वर्मा द्वारा तैयार किया गया मूल नक्शा हो और संधातन नक्शा न हो) वह यह है कि मुख्य डिप के पूर्व में, वह भाग जिससे हमारा सरोकार है, एक रुकावट या अविकसित अछूता भाग है, जबकि क्रास-कट 27वें लेवल के पश्चिमी हिस्से में 1, 2, 3 और 4 नम्बर के डिप हैं। इन डिपों को पक्की रेखाओं से जिनके सिरे खुले हैं, दिखाया गया है, और इस प्रकार संकेत मिलता है कि काम चल रहा था। इसलिए निश्चय ही 21-4-79 को, अर्थात जिस तारीख को सर्वेक्षक वर्मा ने नक्शे पर हस्ताक्षर किए, इन डिपों में काम चल रहा था। एक और बात जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, यह है कि इस नक्शे में तीसरा डिप 40 फुट लम्बा है। सर्वेक्षक श्री वर्मा की गवाही के अनुसार हमें पता चलता है कि 3-6-1978 को इसकी पैमाइश 4 मीटर (अर्थात् 12 फुट) थी, जैसा कि सर्वेक्षक दास द्वारा रखे गए प्रदर्श 69 में है और 19-6-1978 को इसकी पैमाइश 29.5 मीटर (अर्थात् 96 फुट) था, जैसा कि प्रदर्श 10, जो अब प्रदर्श 108 है, में दिखाया गया है। प्रदर्श 81 में वर्मा ने स्वयं 2-8-1978 को ड्राइवेज की पैमाइश 70 फुट लिखी है। 21-4-1979 को ड्राइवेज का 40 फुट दिखाया जाना बड़ा खतरनाक है और यह 21-4-1979 को उनके द्वारा तैयार किए मूल नक्शे को तैयार और हस्ताक्षर करने में वर्मा की अकर्मण्यता का द्योतक है।

10.28 इसके बाद हम 6-12-1979 के प्रदर्श 16 पर विचार करते हैं। यह एक विभागीय नक्शा है, जिस पर सर्वेक्षक अंसारी के हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने वर्मा के साथ काम किया था। आरेख और आकार-प्रकार में यह प्रदर्श 80 जैसा है, अर्थात् जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है इसमें पूर्वी भाग में रुकावट और पश्चिमी 27वें लेवल का ड्राइवेज दिखाया गया है। प्रदर्श 80 के सम्बन्ध में जो टीका टिप्पणी और आलोचना की गई है, वही प्रदर्श 16 पर भी लागू होती है।

10.29 इसके बाद, जहां तक समय का प्रश्न है हम प्रदर्श 15 पर विचार करते हैं जो कि एक बचाव नक्शा है। इसे 14-6-1980 से 31-3-1982 तक अद्यतन किया गया है। इसके सभी पृष्ठांकनों पर सर्वेक्षक अधिकारी के हस्ताक्षर हैं; केवल आखिरी दो पर सर्वेक्षक अधिकारी के न होकर सर्वेक्षक मुखर्जी के हस्ताक्षर हैं। कपड़ा चढ़े नक्शे 62 पर भी सर्वेक्षक द्वारा 31-3-1982 और 30-6-1982 को हस्ताक्षर किए गए हैं, परन्तु प्रदर्श 15, 26 वें पूर्वी लेवल को क्रासकट के 25 वें पश्चिमी लेवल को जोड़ने के मामले में भिन्न दिखाई पड़ता है। प्रदर्श 62 में 26 वें लेवल को सीधे 25 वें लेवल से मिलते हुए नहीं दिखाया गया है, बल्कि अंतिम रूप में उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर बढ़ता हुआ दिखाया गया है। फिर प्रदर्श 15 में 28 वें पूर्वी लेवल का ड्राइवेज है ही नहीं, हालांकि 29 वें लेवल ड्राइवेज का काम जो बाद में हाथ में लिया गया था, नक्शे में दिखाया गया है।

10.30 समय के बारे में एक और नक्शा 24-11-1979 का प्रदर्श 89 है, जो उस समय तैयार किया गया जब विनियम 105 के अनुसार मार्ग पार करने के लिए

जिला परिषद की अनुमति मांगी गई थी। सर्वेक्षक मुखर्जी ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और मुख्य डिप का पूर्वी भाग जिसमें हमारा सरोकार है, एक रुकावट या अछूता क्षेत्र जैसा है अर्थात नक्शे में 26, 27वें, 28वें और 29वें पूर्वी लेवलों को नहीं दिखाया गया है। विशेष बात जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए यह है कि 27 वें पश्चिमी लेवल का दूसरा डिप और तीसरा डिप बिन्दु-रेखाओं द्वारा दिखाया गया है जो इस बात का द्योतक है कि इनका सर्वेक्षण नहीं किया गया। डिपों का आरेखन इस तरह किया है कि उनकी पुरानी लम्बाई की नकल कर दी गई है और इस तरह तीसरे डिप की लम्बाई 40 फुट दिखाई गई है। यह ऐसी हालत में किया गया है जबकि इस पर सामान्य रूप में यह प्रमाणपत्र दिया गया है कि नक्शा सही है। स्पष्ट है कि वास्तविकता पर ध्यान दिए बिना यह प्रमाण-पत्र लगा दिया गया है। इसके अलावा यह बात समझने की है कि 27 वें लेवल के डिपों को, जो अभी तक पक्की रेखाओं द्वारा दिखाए जाते रहे हैं, अचानक ही बिन्दु रेखाओं द्वारा क्यों दिखाया गया। डिपों और विशेष रूप से तीसरे डिप को लम्बाई दिखाने के बारे में प्रारम्भिक गलती वर्मा ने की और वही गलती दूसरे लोग भी आगे करते रहे संयोगवश, प्रदर्श 79 के बारे में यह ध्यान देने योग्य बात है कि यद्यपि मार्ग पार करने की अनुमति 4 स्थलों पर मांगी गई थी, लेकिन वस्तुतः इससे अधिक स्थलों पर मार्ग पार किया गया, जैसा कि गवाह पी. सी. श्याम की गवाही से पता चलता है।

10.31 अब हम प्रदर्श 90 पर विचार करते हैं, जिस पर मुखर्जी ने 29-3-1982 को हस्ताक्षर किए हैं और जो 30-6-1982 तक सही किया गया है। यह पानी के खतरे का नक्शा है। यहां भी तीसरे डिप को बिन्दु रेखाओं द्वारा दिखाया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि उस समय तक कभी भी पानी निकालने, मापने और यहां तक कि आगे के ड्राइवेज वाले पुराने रिकार्ड को संभालने के बारे में कोई प्रयास नहीं किया गया बल्कि पुराने नक्शे की मात्र नकल की जाती रही।

10.32 समय के बारे में अगला प्रदर्श 43 है, जो एक कार्यकारी, नक्शा है, जिस पर सर्वेक्षक मुखर्जी के 6-4-1983 के हस्ताक्षर हैं। पूर्वी पेनल की खदानों के बारे में दो डिपों को बिन्दु और छोटी रेखाओं द्वारा दर्शाया गया है। इसमें भी वास्तविकता की झलक नहीं है। ऊपर की गई चर्चा के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत यह मामला कि दुर्घटना के बाद अचानक उन्होंने महसूस किया कि नक्शों में छोटे ड्राइवेज दिखाए गए है और इसलिए वे दुर्घटना को रोकने में असमर्थ, मान्य नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपना काम ठीक ढंग से करने और अपने सर्वेक्षकों पर सख्त नियंत्रण रखने में अत्यधिक लापरवाह रहे। जहां तक अपराध से संबंधित पुराने डिप का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है कि ठीक 1979-80 वर्ष से ही सर्वेक्षक वर्मा को इसकी लम्बाई 40 फुट नहीं दिखानी चाहिए थी और मुखर्जी के कार्यकाल में डिपों को बिन्दु रेखाओं द्वारा दर्शाने का कोई संतोषजनक कारण दिखाई नहीं पड़ता। यद्यपि प्रबन्धकों को वर्ष 1978 में ही सावधान किया गया था कि नक्शा ठीक नहीं है, उन्होंने इसके प्रति ध्यान नहीं दिया गुमशुदा नक्शे का मामला भी कुचक्रपूर्ण है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि यह बात वस्तुतः सही है। जब कम से कम 45 फुट के अंतर की प्रमुख गलती और 100 फुट के स्थान पर 40 फुट लम्बाई रिकार्ड करने की गलती के संबंध में सभी अन्य नक्शे गलत प्रतीत होते हैं तब ट्रेसिंग कपड़े पर तैयार किया गया तथाकथित नक्शा भी गलत हो सकता है। क्या यह नक्शा नियमित कार्य के लिए प्रयुक्त होता था, यह बात भी संदेहास्पद है क्योंकि यह सांविधिक अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती जिनके अनुसार उसे सीधे सपाट हालत में रखा जाना चाहिए था।

10.33 विभिन्न नक्शों के इस रोचक सारांश से यह बात ज्ञात होती है कि काफी गलतियां की गई थी और यह भी पता चलता है कि बाद में आने वाले लोग भी इन गलतियों को उतनी ही लापरवाही से करते रहे। अतः यह अनुमान लगाना सम्भव है कि उन्होंने कभी भी सर्वेक्षण का ठीक रिकार्ड रखने की परवाह नहीं की, जो कि अन्यथा थोड़े से अध्यवसाय और प्रभावकारी नियंत्रण द्वारा रखा जा सकता था। इस प्रकार सर्वेक्षण रिकार्डों के रख-रखाव में पूरी असावधानी बरती गई है जिसे आपराधिक लापरवाही भी कहा जा सकता है।

10.34 यह हो सकता है कि यह इसलिए हुआ हो कि प्रबन्धक वर्ग अधिक उत्पादन के पक्ष में था। प्रदर्श 95 और 96 में प्रदत्त पत्राचार से यह अवश्य दिखाई पड़ता है कि अधिक से अधिक उत्पादन के लक्ष्य रखने पर बहुत जोर दिया जाता रहा है। प्रदर्शन 96, 26-2-1983 की बैठक का कार्यवृत है। 6-8-1983 का प्रदर्श 95 संयोग से दुर्घटना से कुछ दिन पहले श्री एस. एन. झा, महा-प्रबन्धक द्वारा जेण्ट कुमार को लिखा गया पत्र है, जिसमें हर कीमत पर उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने की बात कही गई है। संलग्न सारणी से पता चलता है कि चौदहवीं सीम 'बिना खंभों वाले क्षेत्र' से उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में काफी पिछड़ गई थी और इसको पूरा करने के लिए विकास-शील क्षेत्र से उत्पादन को औसत से अधिक बढ़ाने का निश्चय किया गया था जिससे स्पष्ट ही उस क्षेत्र पर दबाव पड़ा। निश्चय ही यह दलील पेश करना ठीक नहीं होगा कि उच्च प्रबंधाधिकारियों ने कर्मचारियों की सुरक्षा की उपेक्षा करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने पर जोर दिया था। परन्तु हमें व्यावहारिक दृष्टि से देखना होगा। हमें पूरे वातावरण तथा पर्यावरण पर, जिसमें मौके पर लोग अपने

को पाते हैं विचार करना होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने भविष्य की आशंका से अपने वरिष्ठों को सन्तुष्ट करने में असफल रहता है तो मौके पर कार्यरत व्यक्ति अति-विश्वास से आगे बढ़ने, जोखिम को नजरअन्दाज करने, कर्मचारियों की सुरक्षा से खेलने के लिए विवश हो जाएगा। यह कहना व्यर्थ है कि इससे सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ी। जिस ढंग से इस कोयला खान का प्रबन्ध किया गया, उससे जो तस्वीर उभरती है, उसके आधार पर निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि सुरक्षा की अनदेखी नहीं की गई।

10.35 प्रबन्धक-वर्ग की ओर से एडवोकेट सिन्हा ने भारतीय खान अधिनियम 1952 की धारा 87 का सहारा लिया है, जिसमें यह निहित है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी ऐसे कार्य के लिए मुकदमा या कानूनी कार्य-वाही नहीं की जा सकती जो उसने सद्भाव से या इस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया हो। पहली बात तो यह है कि यह संरक्षण उन लोगों को दिया गया प्रतीत होता है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई आरम्भ करते हैं। किन्तु मान लें कि खान में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति या उच्च अधिकारी इसके अधीन संरक्षण प्राप्त कर सकता है तो यह नितान्त आवश्यक है कि वह कार्य सद्भाव से किया गया हो। केवल यह कह देने से कार्य सद्भावपूर्ण नहीं हो जाता कि वह कार्य सद्भाव से किया गया था। सद्भाव का मतलब उस समय की विद्यमान परिस्थितियों से जुड़ा है। इस विशेष मामले की विद्यमान परिस्थितियां विपरीत हैं। इसके अलावा कानूनी भाषा में सद्भाव का एक विशेष अर्थ है। कोई भी काम, जो सतर्कता और साव-धानी से न किया गया हो उसे सद्भाव से किया गया कार्य नहीं कहा जा सकता। यदि कोई व्यक्ति मामूली अध्यवसाय का उपयोग नहीं करता तो वह यह नहीं कह सकता कि उसने सद्भाव से कार्य किया था। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 52 में भी 'सद्भाव' की जो परिभाषा दी गई है, उसमें कहा गया है कि जो कार्य सतर्कता और सावधानी से नहीं किया गया हो, उसे 'सद्भाव से किया कार्य नहीं कहा जाएगा। एक या अनेक व्यक्ति, जो बिना समझे-बूझे काम करते हैं, उपेक्षाकृत कार्य करते हैं, सुरक्षा उपबंधों की ओर ध्यान नहीं देते, उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने/उन्होंने सद्भाव से कार्य किया है। यहां ऐसा ही हुआ है और फलस्वरूप 'सद्भाव' का तर्क ठीक नहीं है।

अध्याय 11

कोयला खान विनियम--विनियम 127 यदि लागू हो

11.1 अब यह स्पष्ट है कि 29 वें पूर्वी लेवल के अपराध संबंधी तीसरे डिप तथा स्वयं 29वें पूर्वी लेवल का ड्राइवेज संप के निकट और उसकी तरफ हुआ है। इन गैलरियों के ड्राइवेज के समय कोयला खान विनियम 127 के अधीन कोई अनुमति नहीं ली गई। कर्मचारी संघ की ओर से यह कहा गया है कि प्रबन्धकों का इस चूक के कारण कर्मचारियों के जीवन खतरे में पड़े। कहा जाता है कि प्रबन्धक-वर्ग बहुत अच्छी तरह जानता था कि उन खदानों पर काम करने के लिए विनियम 127 के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशक की अनुमति ली जानी चाहिए थी और निर्धारित पूर्वोपाय किए जाने चाहिएं थे। यह उल्लंघन जानबूझकर किया गया। इसके विपरीत, प्रबन्धक-वर्ग की ओर से एडवोकेट श्री श्रीपुरकर ने पूरे जोशो-खरोश से यह दलील दी कि अनुमति लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी क्योंकि विनियम 127 का प्रयोजन अलग है और संप जलमग्न खदान या त्यक्त खदान नहीं मानी जा सकती। इसलिए प्रबन्धकों द्वारा अनुमति न लेना, उनकी अपनी सीमा में था। इस सम्बन्ध में उन्होंने 1965 की आपराधिक अपील सं. 222 (एस. डी. प्रसाद बनाम श्री सेठ हाजी मुल्ला अकबर अली तथा अन्य) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का भी सहारा लिया, जिसकी एक प्रति बहस के दौरान पेश की गई। प्रबन्धकों का यह कहना है कि इस निर्णय के अनुसार यदि कोई खदान मात्र जलमग्न है तो विनियम 127 (3) लागू नहीं होता है। उनका यह भी कहना है कि विनियम 127 (1) और 127 (2) भी लागू नहीं होते। इस मामले में विनियम 127 की संगत प्रयोज्यता इस प्रकार है :—

"भूमितल में पानी भरने से खतरा—(1) हरेक खान में उसी खान या निकट की खान या खदान से पानी या अन्य कोई तरल पदार्थ के प्रवेश को रोकने के लिये समुचित व्यवस्था की जायेगी। (2) जहां कार्य (i) किसी अन्य सीम या सेक्शन के नीचे किसी सीम या सेक्शन में किया जा रहा हो अथवा (ii) किसी ऐसी सीम के किसी स्थान में किया जा रहा हो जो उस दोषपूर्ण ऊपरी सीम या सेक्शन तक पहुंच रही हो जिसमें पानी या अन्य तरल पदार्थ भरा हो या भरा रह सकता हो तो उस खदान में पानी या अन्य किसी तरल पदार्थ के प्रवेश को रोकने के लिये पर्याप्त पूर्वोपाय किये जायेंगे।

(3) उस किसी भी खदान का विस्तार जो किन्हीं त्यक्त या परित्यक्त खदानों (वह खदान नहीं, जिसकी जांच कर ली गई और उसे पानी या अन्य तरल पदार्थ से मुक्त पाया गया है) के 60 मीटर की दूरी पर हो, चाहे वह उसी खान या निकट की खान के हों, मुख्य निरीक्षक की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा और उस पर मुख्य निरीक्षक द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तें लागू होंगी।

स्पष्टीकरण : इस उपविनियम के प्रयोजन के लिये उक्त खदानों के बीच की दूरी से तात्पर्य यथा स्थिति उसी सीम के खदानों के बीच अथवा किन्हीं दो सीमों या सेक्शनों के बीच की न्यूनतम दूरी से होगा जिसे खड़ी, आड़ी या आनत किसी भी स्थिति में माप लिया जाये।

11. विनियम 127 का उल्लेख 'आग, धूल, गैस और पानी से खतरों से बचने के लिये पूर्वोपाय' नामक अध्याय में किया गया है, जिसमें विनियम 116 से 129 शामिल हैं। जहां तक पानी से बचने के लिये पूर्वोपायों का संबंध है, इसके बारे में कुल 4 विनियम हैं, उदाहरणार्थ विनियम 126 से 129। विनियम 126 का उप-शीर्षक है 'सतरी पानी से खतरा' विनियम 127 का उपशीर्षक है 'भूमितल में पानी भरने से खतरा', विनियम 128 का उपशीर्षक है 'जानबूझ कर पानी भर देना' और विनियम 129 का उपशीर्षक है 'पानी के बांध का निर्माण' आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल विनियम 127 है, जिसमें भूमितल में पानी भरने से सबंधित विषय पर विचार किया गया है। विभिन्न उपधाराओं का अर्थ--विवेचन करते समय इस तत्व को ध्यान में रखना होगा।

11.3 उप विनियम (1) में पानी या अन्य तरल पदार्थ के प्रवेश को रोकने के लिये पूर्वोपायों के बारे में सामान्य व्यवस्था की गई है। यह प्रबन्धकों और खान में काम कर रहे व्यक्तियों के विवेक और कुशलता पर छोड़ दिया गया है कि वे इस बारे में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में निर्णय लें। उप-विनियम (2) में किसी अन्य खदान के नीचे वाली खदान के बारे में 3 स्थितियों की परिकल्पना की गई है, जो खतरे का स्रोत हो सकती है। ये तीन स्थितियां हैं, जब कोई सीमा या सैक्शन किसी अन्य सीम या सेक्शन के नीचे हो या जब किसी सीम या सेक्शन का स्थल किसी सीम या सैक्शन में अन्य किसी स्थल से कम लेवल पर हो या जब सीम में कोई ऐसा स्थल हो जिसमें खराबी आ रही हो आदि। उप-विनियम के अनुसार ऊपरी सीम, सैक्शन या लेवलों से आने वाले पानी या किसी अन्य तरल पदार्थ के प्रवेश को रोकने के लिये पर्याप्त पूर्वोपाय करना आवश्यक है। यहां भी पूर्वोपायों की सूची नहीं दी गई है बल्कि इन्हें खान में काम करने वाले व्यक्तियों के विवेक और कुशलता पर छोड़ दिया है।

11.4 किन्तु तीसरा उपविनियम अलग किस्म का है। इसमें किसी ऐसी खदान के विस्तार के लिये मुख्य निरीक्षक से लिखित पूर्व-अनुमति लेने की बात कही गई है, जो किसी ऐसी अन्य खदान से 60 मीटर की दूरी के अन्दर हो, जो परित्यक्त कर दी गई हो या जिसका उपयोग न किया जा रहा हो। इसका सारांश यह है कि ज्यों ही किसी त्यक्त या परित्यक्त खदान से 60 मीटर की दूरी में खदान का काम किया जाये तो मुख्य निरीक्षक से अनुमति लेना आवश्यक है और काम उपविनियम (6) में दी गई शर्त के अनुसार किया जाये। इसका एक अपवाद भी है और वह यह है कि जिस खदान की ओर खदान का विस्तार किया जाना हो यदि उसकी जांच कर ली गई हो तथा उसमें पानी या अन्य तरल पदार्थ भरा हुआ नहीं पाया गया हो तो मुख्य निरीक्षक की पूर्व-अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब परित्यक्त और त्यक्त खदान, जिसकी ओर खदान का विस्तार किया जाना है, उसकी जांच कर ली जाये और उसे पानी या अन्य तरल पदार्थ से मुक्त पाया जाये तो अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है और उप-विनियम (6) लागू नहीं होगा। स्पष्ट है कि यदि उसकी जांच नहीं की गई है तो अनुमति लेने की आवश्यकता है अर्थात् खान में काम करने वाले व्यक्तियों पर यह जिम्मेदारी डाल दी गई है कि वे यह वस्तुतः जांच करके सुनिश्चित कर लें कि पानी या अन्य तरल पदार्थ के संचय होने की सभावना नहीं है--ऐसी स्थिति में ही उन्हें अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

11.5 बहस के दौरान विनियम 127 के इतिहास की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। 1926 में दो विनियम थे--विनियम 74 और 76, जिनमें इन स्थितियों पर विचार किया गया था। वर्ष 1957 में विनियम 127 लगभग वर्तमान रूप में विद्यमान था, परन्तु 19 मार्च 1980 के संशोधन द्वारा इसमें कुछ और उप-धाराएं जोड़ दी गई। 1926 के विनियम 74 में वर्जित दूरी 100 फुट थी और जिधर पानी या अन्य तरल पदार्थ संचित होने या संचित होने की संभावना हो वहां के लिये पहुंचने का रास्ता होना चाहिये उस विनियम में भी त्यक्त अथवा परित्यक्त खदानों का उल्लेख था और वर्तमान काष्ठअंक अंश उस समय भी विद्यमान थे। विनियम 75 में प्रयुक्त 'जिसमें पानी होने या पानी होने की सभावना' शब्दों के बिना वह विनियम अब विनियम 127 का उप-विनियम (2) है। क्या पूर्वोपाय करने चाहियें, इस बारे में विनियम 74 और 75 दोनों में ही निर्णय खान में काम कर रहे व्यक्तियों पर छोड़ दिया गया था।

11.6 त्यक्त खदान से संबंधित भाग को 'परित्यक्त' शब्द जोड़कर विनियम 74 की अपेक्षा वर्तमान उपनियम (3) में और अधिक विशिष्ट बना दिया है। जहां तक मार्च, 1980 के संशोधन का प्रश्न है, पानी रिसने से संबंधित उप विनियम (3) के उपबन्ध को हटा दिया गया है और एक अलग उपविनियम (5) के रूप में रख दिया गया है। पहले उप विनियम (4), (5) और (6) को व्यापक रूप से उद्धृत किया गया है और साथ ही उप विनियम (4), (6), (7) और (8) को कुछ अन्य अतिरिक्त अपेक्षाएं भी दी गई हैं। 1980 के संशोधन के परिप्रेक्ष्य में उप-विनियम (3) जिससे हमारा संबंध है, के अर्थ विवेचन करने का कोई लाभ नहीं और वर्तमान मामले में इस प्रश्न का निर्णय इस संदर्भ में करना होगा कि खदान उस त्यक्त या परित्यक्त खदान की निषेधात्मक दूरी पर था या नहीं जिस की जांच कर ली गई है और उसे पानी तथा अन्य तरल पदार्थ से मुक्त पाया गया है।

11.7 बहस इस प्रश्न पर केन्द्रित है कि क्या संप जलमग्न खदान होती है । प्रबन्ध गवाह 7 भट्टाचार्य ने विनियम 127 से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि 'उसकी राय में 29वें पूर्वी लेबल के ड्राइवेज के लिये विनियम 127 के अधीन अनुमति देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास जो नक्शा था, उसके अनुसार उसने काफी गुंजाइश रख ली थी । इसलिये विनियम 127 (1) लागू नहीं होता । विनियम 127 (3) भी लागू नहीं होता क्योंकि संप त्यक्त खदान नहीं होती । "एक अन्य स्थान पर संप की परिभाषा देते हुए उनका कहना है कि 'संप एक जलाशय है, जहां से पानी निकाला जाता है, उसमें पानी पुनः जमा हो जाता है और उसे फिर निकाला जाता है । जबकि जलमग्न क्षेत्र का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां पानी इकट्ठा रहता है ।" प्रबन्ध गवाह 9 कुमार, खान के एजेंट भी कहते हैं कि मुख्य डिप के 29वें पूर्वी लेवल में खदानों पर विनियम 127(3) लागू नहीं होता, हालांकि वे स्पष्ट रूप से मानते हैं कि 29वें पूर्वी लेवल का ड्राईवेज संप के खदानों से 60 मीटर के दायरे में हो रहा था, जिसमें 27वें पश्चिमी लेवल शामिल है ।" वे स्वीकार नहीं करते कि संप की खदान पानी में डूबी है । अदालती गवाह 2 सर्वेक्षक वर्मा ने भी अपनी गवाही में कहा है कि क्रास-कट के पूर्व में 27वें पश्चिमी लेवल पानी से भरा था । परन्तु वे यह नहीं मानते कि बंद इसे खदान कहना चाहिये।

11.8 इसके विपरीत अदालती गवाह 4 श्री पी सी श्याम, खान सुरक्षा निदेशक का कहना इससे अलग है । विभिन्न स्थितियों और हालतों का विवरण देते हुए उनसे सवाल-जवाब किये गये । प्रबन्ध-वर्ग के एडवोकेट श्री सरपुरकर द्वारा किये गये प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि संप को जलमग्न खदान नहीं माना जाता है । संप की परिभाषा देते हुए उनका कहना है कि संप में पानी भरा रहता है जिसमें से वह पंप की सहायता से बाहर निकाला जाता है। वे नहीं मानते कि यह पानी का अस्थायी जमाव है । उन्होंने उसे पानी का स्थायी जमाव बताया । उनके अनुसार यह पानी से भरा क्षेत्र होता है । उन्होंने इसे जलमग्न खदान कहा, जिसमें पानी का लेवल फुट वाल्व से कभी कम नहीं होता । उनके मतानुसार यह त्यक्त जलमग्न क्षेत्र होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति खदानों के परले सिरों तक नहीं जा सकता और नहीं कुछ देख सकता है । उनके विचार में यह परित्यक्त खदान होती है, क्योंकि इसमें कोई उत्पादन कार्य नहीं होता । वे नहीं मानते कि मात्र पानी इकट्ठा हो जाने से त्यक्त अथवा परित्यक्त तात्पर्य नहीं लिया जा सकता। उन्हें इस प्रश्न में भी फंसाया गया कि यदि पहली शिफ्ट में गैलरी में पानी न हो और दूसरी में वही गैलरी पानी से भर जाये तो क्या वह त्यक्त गैलरी कहलायेगी । गवाह ने जवाब दिया कि इसे त्यक्त गैलरी कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय वहां न तो कोई जा सकता है और न ही उसका उपयोग कर सकता है और न ही निरीक्षण कर सकता है । किन्तु वे इस बात का उत्तर नहीं दे सके कि क्या इसलिये प्रत्येक शिफ्ट के लिये जब तक कि उसका पानी निकाल न दिया जाये, अनुमति लेनी पड़ेगी । उन्हें स्वयं कभी इस प्रकार की अनुमति देने का अवसर नहीं मिला । गवाह ने स्पष्ट किया कि प्रयोग करने का मतलब उत्पादन और वहां तक पहुंचने से है । उस गैलरी को सम्प के उपयोग के लिये "अप्रयुक्त" 'त्यक्त' और 'प्रयोग में नहीं' के रूप में कह सकते हैं । वे यह स्वीकार नहीं करते कि यदि किसी भी प्रकार का उपयोक्ता गैलरी का प्रयोग करता है तो वह त्यक्त या परित्यक्त गैलरी नहीं है । त्यक्त अथवा अप्रयुक्त का अर्थ एक ही है अर्थात् जिसका प्रयोग नहीं किया जा रहा हो ।

11.9 असेसर श्री त्रिवेदी के प्रश्न के उत्तर में उनका कहना है कि 27वें लेवल के तीसरे डिप में क्रास-कट में 90 हार्स पावर के पंप के होते हुए भी हमेशा पानी भरा रहता था और इसलिये सही अर्थों में वह त्यक्त या परित्यक्त खदान थी क्योंकि खादानों की जांच नहीं की जा सकती थी और यह मालूम नहीं किया जा सकता था कि वहां पानी या अन्य कोई तरल पदार्थ इकट्ठा है या नहीं । इस प्रकार गवाह ने दो कसौटियां रखी अर्थात् खदानों में पहुंच और उत्पादन होने या न होने की स्थिति । उनके अनुसार जब उपयोक्ता कोयले का उत्पादन कर रहा है तब खदान की अनुप्रयुक्तता का निश्चयन इस बात से किया जाता है कि क्या वहां तक पहुंचा जा सकता है या उसका निरीक्षण किया जा सकता है—भले ही उसमें पानी भरा हो।

11.10 प्रबन्धक-वर्ग की ओर से प्रयास किया गया है कि विनियम 127(3) के अर्थ-विवेचन में जलमग्नता की धारणा को अधिक प्रकाश में लाया जाये और इसलिये श्री सरपुरकर ने संप की परिभाषा का सहारा लिया । संप की परिभाषा कोयला खान विनियमावली में नहीं दी गई है और इसलिये हमें खनन पद्धति पर निर्भर करना होगा । श्री सरपुरकर ने ए० नेलसन के 'माइनिंग कोश' का हवाला दिया और निम्नलिखित परिभाषा उद्धृत की—

> संप: एक ऐसा जल-स्थल या कैच-बेसिन है जहां खान का पानी इकट्ठा होता है और पंपों को सप्लाई होता है । यह संप एक बेसिन का काम करती है जिसमें कीचड़ और मिट्टी नीचे बैठ जाती है तथा जिसे पानी को पंप द्वारा फैंके जाने से पहले निकाला जा सकता है । जल निकासी खाइयों के संपों के बीच स्क्रीन लगाये जा सकते हैं ताकि पानी से लकड़ी और कूड़ेकरकट को निकाला जा सके । संप में पर्याप्त स्थिरण क्षमता होनी चाहिये और उसमें पानी को ठहरा रखने के लिये रोधिकाएं होनी चाहिये ।

उन्होंने वेंकटरमैया द्वारा लिखित पुस्तक 'ला लेक्सिकन एंड लीगल मैक्सिम्स' में दी गई संप की परिभाषा को भी आधार बनाया; इसमें संप की परिभाषा इस प्रकार दी गई है :

> संप : संपिंग—'संप' शब्द का अर्थ कोयले की खान के निचले भाग में खोदे गये एक 'पिट' से है जिसमें खान का पानी इकट्ठा होता है—कोल रन कोल कं० बनाम जोंस 19 III परि० 365 : शाफ्ट के केज के नीचे एक पिट—डल्लासकोल कं० बनाम स्टेनबरी 107 एस डब्ल्यू 997 : 85 आर्क 237; एक रूल कुंआं या हौज, जिसमें खान का पानी इकट्ठा होता है और जहां से उस भाप-इंजन द्वारा पानी पंप से बाहर निकाला जाता है, जो शाफ्ट में कारों को आगे बढ़ाता है—वुडवर्ड लायन कं० बनाम जोउस एन 80 अल : 123

11.12 "डिक्शनरी आफ माइनिंग एंड मिनरल एंड रिलेटेड टर्मस' में पृष्ठ 1102 पर कई परिभाषाएं दी गई हैं। 18 उद्धरणों में से एक उद्धरण नेलसन द्वारा दी गई परिभाषा से सम्बद्ध है और जिसका उल्लेख श्री सरपुरकर ने किया है । एक अन्य संगत परिभाषा इस प्रकार है :

> "पानी इकट्ठा करने के लिये एक भूमिगत उत्खनन, जिससे पंप द्वारा पानी को सतह पर या सतह के निकट एक दूसरे संप में डाला जाता है । संप लेवल पर या अन्य किसी अंदरूनी स्थल पर शाफ्ट के निकट शाफ्ट की तली में बनाई जाती हैं । लेविस पृ० 21

11.13 यहां हमारा सम्बन्ध किसी उस प्रकार की संप से नहीं है जिसे हम हौज या टैंक या पिट कह सकें । इस मामले में संप स्वयं गैलरियों से बनी थी जहां सभी गैलरियों का पानी एक गैलरी से दूसरी गैलरी में बहता हुआ फर्श से छत तक भर गया था और इस स्थल को संप के रूप में लिया गया है । इस पानी को 17 वें लेवल पर लगे बीच के पंप द्वारा पिट की तली में मुख्य संप में पिट के ऊपरी भाग तक ले जाया गया और अंततः संचयन के लिये उपयोग में लाया गया ।

11.14 उपर्युक्त परिभाषाओं पर विचार करते हुए और जिन स्थितियों से हमारा संबंध है, उनके परिप्रेक्ष्य में हमें ध्यान रखना होगा कि प्रस्तुत मामले में संप खान के अन्दर भूमितल में बना एक उत्खनन है, जिसमें प्रवणता है और जिससे खदानों के डिप ढके हुए हैं । नेलसन की परिभाषा के सन्दर्भ में यह एक जल-स्थल भी है ।

11.15 प्रबन्धक-वर्ग के एडवोकेट श्री सरपुरकर ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय का सहारा लिया है और इस निर्णय में से बहुत से उद्धरण पेश किये हैं । यह एक आपराधिक मुकदमा था, जो विनियम 127 के उप-विनियम (1)(3) और (5) तथा साथ ही विनियम 190 के उल्लंघन करने पर चलाया गया था और खान अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत दण्डनीय था । अचानक ही पानी के प्रवेश के कारण भूमिगत गैलरी में कार्य कर रहे अनेक व्यक्ति डूब गये थे । उस समय परन्तुक सहित जिस प्रकार से उप-विनियम (3) लागू था, उसी रूप में उसका उद्धरण देते हुए जिसका इस विचाराधीन मामले से संबंध नहीं है, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने यह माना है कि खदानों के विस्तार के लिये अनुमति लेने के वास्ते दो शर्तों का एक साथ होना जरूरी है—उदाहरणार्थ (1) जिन खदानों का और विस्तार किया जाये वे त्यक्त अथवा परित्यक्त खदान हों और (2) खदानें जलमग्न हों । विद्वान न्यायाधीशों ने आगे यह भी कहा कि यदि खदानों में पानी न भरा हो तो यदि वे खदानें त्यक्त और परित्यक्त खदानें भी हों तो भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । विद्वान न्यायाधीशों के अनुसार जलमग्नता एक अतिरिक्त शर्त है और खान में काम बन्द या छोड़ देने से नहीं जुड़ी है, इसलिये 'त्यक्त' अथवा 'परित्यक्त' शब्दों का अर्थ विवेचन जलमग्नता के तथ्य के संदर्भ में नहीं किया जा सकता । विद्वान न्यायाधीशों ने अन्तिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि यदि विस्तार ऐसी खदान की ओर किया जा रहा है, जो केवल जलमग्न है तो अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है ।

11.16 इस अर्थ विवेचन के आधार पर श्री सरपुरकर का विचार है कि जिस संप से हमारा संबंध है, यदि वह जलमग्न हो भी तो भी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि इसे त्यक्त या परित्यक्त खदान नहीं माना जा सकता और यह इसलिए कि संप के पानी का इस्तमाल लगातार संचयन के लिए किया जाता रहा । पहली बात तो यह है कि यह कहना सही नहीं है कि सतह पर लाया गया सारा पानी संचयन के लिए पुनः खान में ले जाया गया । तथ्य तो यह है कि केवल इसका कुछ भाग ही संचयन के लिए इस्तेमाल में लाया गया है और फालतू पानी को सतह पर बहा दिया गया है । इसलिए संप में उतना पानी था जिसका इस्तेमाल नहीं होता था ।

11.17 इसके अलावा इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि मेरी राय में 'जल से मुक्त नहीं' शब्दों की अपेक्षा 'जलमग्न' शब्द का एक अलग अर्थ है, जो विनियम में प्रयुक्त नहीं किया गया है । अतः उपविनियम (3) को लागू करने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं (क) खदान त्यक्त अथवा परित्यक्त हो (ख) उसमें पानी न हो । त्यक्त खदान दो कारणों से त्यक्त मानी जा सकती है, या तो उसमें पानी इकट्ठा हो गया हो जिससे खदान के रूप में उसका उपयोग न हो सके या छत गिर जाने अथवा अन्य किसी रुकावट के कारण उसमें प्रवेश करना सम्भव न हो। ऐसा लगता है कि एक 'परित्यक्त' खदान वह खदान है जिसे मर्जी से 'परित्यक्त' कर दिया गया हो, जब कि खदान का 'त्यक्त' होना मर्जी या बिना मर्जी के हो सकता है ताकि 'त्यक्त' होने के कारण के समाप्त होते ही खदान का उपयोग पुनः आरम्भ किया जा सके ।

11.18 भू-वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर हम देखेंगे कि यदि खदान उस क्षेत्र के प्राकृतिक जल स्तर से नीचे हों तो खान में पानी अवश्य घुस जाएगा । यदि ये खदानें डिप की तरफ हों तो पानी वहीं रहेगा, बशर्ते कि उसे निकाल कर बाहर न किया जाए । किन्तु उभार वाले क्षेत्र में पानी डिप की तरफ बहेगा । परन्तु फिर भी उभार की तरफ खदानों को सम्भवतः व्यक्त माना जाएगा बशर्ते कि उनका अन्यथा उपयोग न किया जा रहा हो । इसलिए यह कहा जा सकता है कि पानी के स्तर के नीचे डिप की तरफ वाली सभी खदानें जलमग्न और व्यक्त दोनों ही होती हैं; जबकि उभार की तरफ की खदानें जलमग्न तो नहीं होती, किन्तु उनका प्रयोग नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, जो स्थिति पर निर्भर करेगा ।

11.19 उपर्युक्त चर्चा के प्रकाश में और शब्दों के सामान्य पठन से यह साफ लगता है कि विनियम की रचना करने वालों के मस्तिष्क में परित्यक्त खदान या त्यक्त खदान में पानी के सामान्य रूप से प्रवेश करने की बात थी जो आकस्मिक खतरे का स्रोत हो सकता है और इसीलिए इसके लिए पूर्वोपाय करने के लिए उपबन्ध रखा गया । उपविनियम के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, पहले तो कोष्ठक में दिए गए अंश को बिना देखे और फिर कोष्ठक अंश पर विचार कर सकते हैं । उक्त उप-विनियम (3) से पता चलेगा कि मुख्य निरीक्षक की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, यदि किसी खान का विस्तार किसी त्यक्त अथवा परित्यक्त खदान के 60 मीटर की दूरी में पहुंच जाए। दूसरे शब्दों में यदि कार्य किसी परित्यक्त खदान की ओर या त्यक्त खदान की ओर पहुंचाता है तो अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है । यह मान लिया जाता है कि सामान्य परिस्थितियों में परित्यक्त या त्यक्त खदान में पानी होगा, इसलिए अनुमति प्राप्त करने के लिए शर्तों का अनुपालन करने का कार्य उन व्यक्तियों पर छोड़ दिया जाता है जो इन त्यक्त और परित्यक्त खदानों की तरफ काम कर रहे होते हैं ।

11.20 किन्तु व्यावहारिक रूप में ऐसा हो सकता है कि परित्यक्त खदान या त्यक्त खदान के बारे में खान में काम करने वाले व्यक्तियों को अच्छी जानकारी हो और इनमें विस्तार सम्बन्धी कार्य करने की ओर बढ़ने से पहले वे इसकी जांच कर लें और उनमें पानी या अन्य किसी तरल पदार्थ को इकट्ठा होने के बारे में मालूम कर लें या उनमें पानी इकट्ठा न होने दें । ऐसी स्थिति में जिस प्रयोजन के लिए विनियम बनाया गया है, वह सिद्ध हो जाता है अर्थात् पानी या अन्य किसी तरल पदार्थ के इकट्ठा होने का कोई प्रच्छन्न खतरा नहीं रहता और इसलिए यह स्वतन्त्रता प्रदान की गई कि बिना अनुमति के भी खदान में काम जारी रखा जा सकता है ।

11.21 मेरे विचार में उपविनियम में प्रयुक्त शब्दों का स्पष्ट अर्थ यही है । यह कानून में निहित उद्देश्य से भी मेल खाता है । इस संबंध में हम एस जी जी एजर की पुस्तक 'क्रेज आन एटेच्युट ला' के संदर्भ दे सकते हैं । 'निहित उद्देश्य के अनुसार अर्थ विवेचन' शीर्षक के अन्तर्गत अध्याय 5 के पैरा 2 में अंश इस प्रकार है--"संसद के अधिनियमों के अर्थ-विवेचन का प्रमुख नियम यह है कि स्वयं अधिनियम में जो उद्देश्य निहित किया गया है, उसी के संदर्भ में अर्थ लगाया जाना चाहिए । यदि कानून के शब्द ही स्पष्ट और असंदिग्ध अर्थ देने वाले हों तो उन शब्दों का सामान्य और स्वाभाविक भाव ग्रहण करने के अलावा और अधिक कुछ करने की जरुरत नहीं है । ऐसी स्थिति में स्वयं शब्दों से ही विधिकर्ता का उद्देश्य सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट हो जाता है । जब ट्रिब्यूनल को विधायिका के किसी अधिनियम या किसी भी अन्य दस्तावेज में दिए गए शब्दों का अर्थ लगाना होता है तो उसमें प्रयुक्त शब्दों में अभिव्यक्त उद्देश्य को निश्चित करना होता है और इन शब्दों को समझने के लिए यह जानना आवश्यक होगा कि ये शब्द किस विषय के सम्बन्ध में प्रयुक्त किए गए है और उनका उद्देश्य क्या है ।" 1955 में मुख्य न्यायाधीश लार्ड गेलार्ड ने कहा था 'कानूनी का अर्थ लगाते समय काफी कुछ सामान्य बुद्धि लगाना अत्यावश्यक है । अधिनियम के उद्देश्य पर भी विचार करना होगा ।'

11.22 1983 में दिए गए निर्णय पी एल जे आर पृ. 716 (अजीमुद्दीन अंसारी बनाम बिहार राज्य) जिसकी एक प्रति मुझे दी गई है, को भी देखना उपयोगी होगा । कानून के अर्थ-विवेचन के प्रश्न पर यह कहा गया है कि किसी धारा का अर्थ-विवेचन उसके कोष्ठक को हटा कर किया जा सकता है । निर्णय के पैरा 9 में निम्नलिखित टिप्पणी संगत है---

> "जैसा कि लार्ड एम आर ईशर ने ड्यूक आफ डेवन शायर बनाम ओ कोनोर (1890) 24 क्यू बी डी 468, पृ. 478 में माना है कि कोष्ठक को विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता । ऐसा प्रतीत होता है कि यह बात सिद्ध हो गई है कि विराम चिह्न आदि को किसी कानून विशेष का अंग नहीं माना जा सकता और इसलिए अर्थविवेचन के समय इन पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है ।' (हैल्सबरी, खण्ड 44, चौथा संस्करण, पैरा 820) किन्तु इंगलैण्ड में कुछ न्यायाधीश और कानून के विशेषज्ञ "विराम चिह्न आदि के प्रयोग पर ध्यान न देने से वास्तविकता की उपेक्षा होती है"-- इस स्थिति का अनुपालन करते हुए उक्त स्थिति से कुछ अलग हटकर रहे हैं । "(हैनान बनाम ला सोसाइटी, 1980 (2) ए ई आर 199 पृष्ठ 221 लार्ड लारी (एच एल)"

11.24 इसलिए, कोष्ठक को छोड़ा जा सकता है और समूचे उप-विनियम को पढ़ा जा सकता है । अतः 'वे खदान नहीं जिनकी जांच कर ली गई है और जिन्हें पानी अथवा किसी अन्य तरल पदार्थ से मुक्त पाया गया' ये शब्द उन खदानों के द्योतक होंगे जिनकी अभिव्यक्ति

'त्यक्त' अथवा 'परित्यक्त' विशेषण लगाकर की गई है। इसलिए संक्षेप में जिस खदान के लिए रास्ता बनाया जाना है वह मुख्यतः 'त्यक्त' या 'परित्यक्त' होनी चाहिए और वह पानी या अन्य किसी अन्य तरल पदार्थ से खाली नहीं होती।

11.25 इसलिए विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या कोई 'संप' त्यक्त या परित्यक्त खदान होती है? उचित बात यही है कि प्रबंध गवाह नं. 7 भट्टाचार्जी द्वारा 'संप' की दी गई इस परिभाषा को मानने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि संप एक ऐसा जलाश्य है जहां से पानी लिया जाता है, उसे फिर से भरा जाता है और फिर पानी लिया जाता है। इसी प्रकार अदालती गवाह नं. 4 श्री श्याम का यह कहना भी उचित प्रतीत होता है कि संप पानी इकट्ठा करने का एक ऐसा स्थान है, जहां से पम्प के द्वारा पानी निकाला जाता है। गवाह श्याम यह नहीं मानते कि यह पानी इकट्ठा करने का अस्थायी स्थान है। उनके अनुसार यह पानी इकट्ठा करने का स्थायी स्थान है। यह कुछ भी हो जिस प्रकार का संप की चर्चा हम कर रहे हैं उसके पानी का लेबल घटता-बढ़ता रहता होगा, जो इस पर निर्भर करता होगा कि पम्प द्वारा उस संप से कितना पानी निकाला जा सकता है। यदि हम यह भी मान लें कि पम्प अपनी अधिकतम क्षमता से पानी फेंकता है तो भी क्या यह माना जा सकता है कि संप पूर्णतया खाली और सूखी होगी? ऐसा नहीं होगा। यह भी हो सकता है कि इस प्रकार की स्थिति केवल अल्पावधि के लिए ही जारी रहे क्योंकि संप में पानी पुनः आना शुरू हो जाएगा तथा वह भर जाएगी तथा उसे फिर से पम्प द्वारा बाहर निकाला जाएगा।

11.26 गवाह श्याम के दो मापदण्ड थे: निरीक्षण के लिए सुगमता और उत्पादन के लिए इस्तेमाल उनके अनुसार, यदि कोयले का कोई उत्पादन नहीं हो रहा हो तो खदान को त्यक्त खदान माना जाता है। संभवतः यह चरम स्थिति है और यह सही नहीं होगी। फिर भी, उन्होंने खदान को देखने या खदान का निरीक्षण करने के मापदण्ड के बारे में बताया। स्पष्ट है कि उनके ध्यान में विनियम 2(35) में दी गई परिभाषा थी। उक्त विनियम में खदान की परिभाषा खान में एक ऐसे स्थान के रूप में दी गई है, जहां किसी भी व्यक्ति की कानूनन पहुंच हो सकती है। उनके अनुसार निरीक्षण के लिए यह बहुत जरूरी है और इसलिए उन्होंने आगे कहा कि भले ही पहली शिफ्ट में गेलरी में पानी नहीं होता और उसका निरीक्षण किया जा सकता है, परन्तु दूसरी शिफ्ट में उसका निरीक्षण नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें पानी भरा होता है और वह 'त्यक्त' गैलरी बन जाती है। संभवतः यहां भी वे चरम स्थिति का उल्लेख कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश, 'डिस्यूजड' (त्यक्त) शब्द की परिभाषा विनियम में कहीं भी नहीं दी गई है फिर भी, इसमें 'डिस्यूजड (त्यक्त), अनयूजड (अप्रयुक्त) और 'डिसकन्टिन्यूड' (बंद) जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है।

11.27 विनियम 49(2)(क) सर्वेक्षक से संबंधित है, जो एक जिल्दबंद पुस्तक में रिकार्ड रखता है और यह कहा जाता है कि जब खोदने का कार्य खदान की चार-दीवारी या त्यक्त या पानी भरी खदानों के 75 मीटर के दायरे में पहुंच जाए तो उसे ये पूरे तथ्य इस पुस्तक में लिखने होते हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार अप्रयुक्त का अर्थ है जिसे प्रयोग में न लाया गया हो। यह बात ध्यान देने योग्य है कि विनियम 49 (2)(क) में पानी वाली खदानों को स्पष्ट रूप में त्यक्त खदानों की तरह ही माना गया है। यदि हम विनियम 146 को देखें उसमें गैस वाली खानों में बरते जाने वाले सामान्य पूर्वोपायों का उल्लेख मिलता है। उप-विनियम (9) के अनुसार मुख्य वायु धारा इतनी विखंडित और गतिक होगी कि उस वायुधारा से जो गोफ क्षेत्र में वायु संचार करती है चाहे वह क्षेत्र भरा हो या खाली हो या कोई त्यक्त खदान हमें क्षेत्रीय निरीक्षक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना सिवाय उस क्षेत्र के जिसके लिए उसमें व्यवस्था की गई हो किसी भी खदान में वायु-संचार नहीं किया जाएगा। यहां भी स्पष्ट रूप से 'त्यक्त' शब्द को 'प्रयोग में न लाई गई खदान' के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है।

11.28 यदि हम विनियम 6 को देखें, जिसमें इस बात की व्यवस्था है कि जब भी किसी खान या साम का परित्याग करने का इरादा हो या किसी विशेष अवधि के लिए उसके खदान-कार्य को रोकना हो, तो उसके लिए नोटिस दिया जाएगा। यहां पर 'डिस्कन्टिन्यू' (बंद करना) शब्द को 'एबेन्डन' (परित्याग करना) शब्द के साथ प्रयुक्त किया गया है। संभवतः दोनों शब्दों में यह फर्क है: परित्याग करने का अर्थ है कि कार्य को कभी भी या कम से कम लम्बी अवधि तक हाथ में न लेना; जबकि बंद करने का अर्थ है किसी कार्य को फिलहाल न करने से है। परन्तु उसे कुछ समय बाद हाथ में लिया जा सकता है। विनियम 6 और उपविनियम (2) के परन्तुक में भी 'एबेन्डन्ड' (परित्यक्त) और 'डिस्कन्टिन्यू 5' (बंद) शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया गया है।

11.29 विनियम 7 'फिर से खोलने के नोटिस' से संबंधित है और विनियम 6 की ही तरह इस विनियम के अनुसार भी जब कभी भी परित्याग और बंद करने के बाद खान या सीम को फिर से खोलने का इरादा हो तो उसे फिर से खोलने के लिए नोटिस देना आवश्यक है। मेरी राय में, 'एबेन्डनमेंट' (परित्याग) और 'डिस्कन्टिनुएंस' (बंद) शब्दों का वही अर्थ है जिनका विनियम 6 में उल्लेख किया गया है।

11.30 इसके बाद हम विनियम 61 पर विचार करते हैं। यह विनियम उन नक्शों और सेक्शनों के बारे में है जिन्हें खदान परित्यक्त करने और उस बंद के बाद पेश करना होता है। जिन शब्दों से हमारा संबंध है उनका वही संदर्भ है और इसलिए उनका प्रयोग स्पष्ट रूप में उसी

अर्थ में किया गया है जिस अर्थ में उनका पहले उल्लेख किया गया है ।

11.31 विनियम 59 में विभिन्न नक्शों के रख-रखाव के बारे में उल्लेख किया गया है । विनियम 59 के उपविनियम 1 (ख) में एक भूमिगत नक्शे का उल्लेख किया गया है और उप-विनियम 3(ख) में खदान के फर्श पर स्पाट लेबलों के दिखाए जाने का उल्लेख किया गया है । जहां तक उप विनियम 3(ख) के खंड (ii) का संबंध है, इसमें खदान सिरों पर उन स्पाट लेबलों को दिखाए जाने का उल्लेख मिलता है जिनमें अस्थायी या स्थायी तौर पर खदान-कार्य बंद कर दिया गया है । इसलिए 'डिस्कन्टिन्यूड'(बंद) का अर्थ ऐसी खदान का उपयोग न करने से है जिसे स्वेच्छा से बंद कर दिया गया हो, भले ही वह अल्पावधि के लिए हो या स्थायी तौर पर ।

11.32 "खान में खदान-कार्य" पर अध्याय में, विनियम 112 है जिसमें बाड़ लगाने का उल्लेख किया गया है । उप-विनियम 5(ख) में मालिक, एजेन्ट या प्रबंधक को निर्देश दिया गया कि वे किसी खान का परित्याग करने या खदान-कार्य बंद करने से पूर्व ऐसे निर्दिष्ट स्थानों के मुहानों और दरवाजों पर बाड़ लगाएं जिन पर बाड़ लगाने के लिए विशेष रूप से कहा गया हो । यहां भी, 'डिस्कन्टिन्यूड' (बंद) शब्द को खदान को बंद कर देने के संदर्भ में उसी प्रकार प्रयुक्त किया गया है जैसे कि 'एबेन्डन्ड' (परित्यक्त) को उन अर्थों के रूप में प्रयुक्त किया गया है जिन पर अब तक चर्चा की जा चुकी है ।

11.33 विनियम 143 में गैस के लिए अप्रयुक्त खदान के निरीक्षण के हेतु व्यवस्था की गई है । इसमें यह उल्लेख किया गया है कि सीलन किए गए ऐसे सभी अप्रयुक्त खदानों का निरीक्षण सक्षम व्यक्ति द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान किया जाएगा । यहां डिस्कन्टिन्यूड' (बंद) या 'डिस्यूज्ड' (त्यक्त) शब्दों की तुलना में 'अनयूज्ड' (अप्रयुक्त) शब्द के प्रयोग को अधिक तरजी दी गई है । संभवतः विनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट होता है कि 'अनयूज्ड' (अप्रयुक्त) शब्द ऐसे सभी प्रकार के स्थानों के लिए प्रयुक्त किया गया है जहां खदान-कार्य नहीं हो रहा है चाहे वे परित्यक्त हो, त्यक्त हों या बंद कर दिए गए हों ।

11.34 इस चर्चा के सारांश से यह जाहिर होगा कि त्यक्त खदान एक ऐसी खदान होगी जिसे प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है । यदि खदान का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो यह एक त्यक्त खदान है । यह कहना ठीक नहीं होगा कि किसी खदान का प्रयोग या प्रयोग न किया जाना इस बात से निश्चित किया जाएगा कि निरीक्षण के लिए वहां तक पहुंचा जा सकता है अथवा नहीं, हालांकि कई मामलों में यह एक अच्छा व्यावहारिक परीक्षण होगा । इस मामले में, प्रबंध-वर्ग द्वारा इस बात को बलपूर्वक कहा गया है कि विभिन्न लेबल और डिपों वाली संप को चाहे उसमें 27वें लेबल और डिप की ओर को भाग शामिल हो, अथवा 27वें लेबल शामिल न हो परन्तु उसमें डिप की ओर का भाग शामिल हो, उसे स्टोर के उद्देश्य से प्रयोग किया गया था और इसलिए यह मामला एक ऐसी खदान का है, जिसे प्रयोग में लाया जा रहा था । पानी निकाले जाने और पानी भरे जाने की निरन्तर प्रक्रिया पर बल दिया गया है । यही कारण कि वे यह कहते हैं कि संम्प त्यक्त खदान नहीं था । उनके अनुसार यदि यह भी मान लिया जाए कि यह पानी से भरी हुई खदान थी या ऐसा क्षेत्र था जो पानी से खाली नहीं था, तो मैं यह मानता हूं कि चूंकि यह त्यक्त खदान नहीं है, अतः इस पर विनियम 127 (3) लागू नहीं होगा ।

11.35 यह विचारणीय विषय है कि भूमिगत जलमग्नता से कामगारों की सुरक्षा के लिए बनाई गई सम्पूर्ण विनियम संहिता में विनियमन 127 ही एक ऐसा विनियम है जो इस पर लागू होता है । यह हमारे रिकार्ड पर है कि यह बहुत बड़ी क्षमता वाली सम्पत्ति है, अर्थात यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो अक्सर पानी से भरा रहता है । क्या यह माना जा सकता है कि विनियम के बनाने वाले इस प्रकार के क्षेत्र को पानी से होने वाले खतरे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में शामिल नहीं करना चाहते थे, या इस बात का संकेत नहीं देना चाहते थे कि इस प्रकार के क्षेत्र को पानी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष खतरा नहीं था? यह स्पष्ट है कि मुख्य डिप के पूर्व में लेबलों तथा गैलरियों की खुदाई पानी के विशाल भंडार की तरफ की जा रही है थी । यदि यह मान लिया जाता है कि उक्त विनियम में जो खतरे के मूल के रूप में उसे दूर करने के उद्देश्य से बनाया गया हो, ऐसा स्थिति पर विचार नहीं किया जाता है तो यह न्याय की विडम्बना होगी। प्रबंधक-वर्ग निर्विवाद रूप से इस बात को मानता है कि 28वें पूर्वी लेबल तथा 29वें पूर्वी लेबल सम्प के 60 मीटर के दायरे में थे ।

11.36 जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तव में बात यह थी कि टगर डिप के परे 28वें लेबल का ड्राइवेज इसलिए रोक दिया गया था ताकि संप को छेड़ा न जाए । कदाचित 29वें पूर्वी लेवल का ड्राइवेज भी इसी उद्देश्य से रोक दिया गया था । ऐसा प्रतीत होता है कि 27वें पूर्वी के दूसरे डिप का काम भी इसी प्रयोजन से रोक दिया गया था । अतः प्रबन्धक-वर्ग को इस बात का पूरा पता था कि जहां पानी जमा था उस दिशा में खुदाई की जा रही थी । वास्तव में, श्री कुमार प्रबन्ध गवाह 9 इस बात को स्वीकार करते हैं कि 29वें पूर्वी लेवल सम्प के 60 मीटर अर्थात् पानी के भंडार के 60 मीटर के दायरे में बनाया जा रहा था ।

अतः इस बात से कोई भी व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि पानी के भंडार के निकट खुदाई की जा रही थी। अब विचारार्थ विषय यह है कि क्या इस ड्राइवेज पर विनियम 127 का उपखंड (3) लागू होता है। यह मानते हुए कि सम्प एक खदान है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इसका पानी बाहर निकाला जा रहा है और उसे पुनः भरा जा रहा है, कोई भी व्यक्ति यह नहीं सोच सकता कि ऐसे मामले में वस्तुतः होता क्या है। यहां अनेक लेवल तथा डिप हैं जो पूर्वी-पश्चिमी तथा उत्तरी-दक्षिणी दिशा में फैले हुए हैं। पानी निकालने के लिए 90 हार्स पावर का एक पम्प लगाया गया था। मेरा यह निष्कर्ष है कि यह पम्प क्रास-कट डिप में 26वें लेवल के ठीक ऊपर लगाया गया था। इस विषय में यह मानते हुए भी कि 90 हार्स पावर का पम्प 27वें लेवल के ठीक ऊपर था, किसी पम्प की पानी निकालने की विशेष क्षमता होती है। इस मामले में सहायक इंजीनियर श्री खान प्रबन्ध गवाह 5 के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि चूषण पाइप में पांच पाइप बंधे थे अर्थात् उसकी लम्बाई 120 फुट थी। फुट वाल्व चूषण पाइप के सिरे में कहीं लगा होगा। इसके बावजूद की पम्प पूरी तरह काम करता है, फुट वाल्व के नीचे के पानी को कभी भी बाहर नहीं निकाला जा सकता। इस दृष्टि से यदि हम नक्शे प्रदर्श 19एए पर नजर डालते हैं तो इससे साफ जाहिर होगा कि पूर्वी क्रास-कट के 27वें पश्चिमी लेवल के परे चार डिपो में से किसी एक को भी पानी निकाल कर खाली नहीं किया जा सकता था। गैलरियों से पानी खत्म किया जा सकता था लेकिन फुट वाल्व के काफी नीचे का पानी नहीं निकाला जा सकता था और यह तो निश्चित था कि उपर्युक्त डिपो का पानी तो कतई ही नहीं निकाला जा सकता था; अतः इन डिपो के पास खदान के रूप में मानना पड़ेगा और खदान बिना पानी के हो नहीं सकती। गवाही में यह भी कहा गया है कि इन डिपो में हमेशा पानी भरा रहता था अन्यथा स्पाट लेबलों का पता किया जा सकता था और सर्वेक्षण द्वारा यह मालूम किया जा सकता था कि इन डिपो का सही विस्तार क्या था ?

11.37 यह निश्चित रूप से कहा जा सकता था कि ये डिप गैलरियां कीचड़, कूड़ेकरकट या बालू से भरी पड़ी थीं अतः इनमें पानी का नामोनिशान नहीं था। इस बात को न तो गवाही में कहा गया है और न ही सर्वेक्षक गनपति सिन्हा ने, जिन्होंने क्षेत्र का प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करने के बाद नक्शा प्रदर्श 19 तैयार किया था, इस उद्देश्य का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। नक्शे को देखकर ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति पर विचार नहीं किया गया था। निरीक्षण के समय भी, जांच न्यायालय ने डिप के बगल में कूड़ेकरकट आदि को नहीं दिखाया जो अंदर आते हुए पानी पानी के साथ बहकर चला गया होगा। इसके विपरीत, प्रदर्श 19 में चारों गैलरियों के विस्तार को दर्शाया गया है।

11.38 श्री वाते द्वारा श्री गनपति सिन्हा अदालती गवाह 6 के साथ की गई जिरह के दौरान उनसे यह विशेष प्रश्न पूछा गया कि क्या गवाह ने उस पानी पर ध्यान दिया था जो इन डिपों में था। श्री गनपति ने इसका उत्तर यह दिया कि प्रवणता को देखते हुए उन्होंने इन डिपों में शेष पानी को शामिल नहीं किया था। लेकिन इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि इन डिपो में हमेशा ही पानी भरा रहता था इसलिए, पूर्वी क्रास-कट के परे 27वें पश्चिमी लेबल के चारों अर्थात् पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे डिप को वैधरूप से पानीयुक्त त्यक्त खदान के रूप में माना जाना चाहिए। इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 29वें, 28वें तथा 27वें पूर्वी लेबलों की खुदाई पानीयुक्त त्यक्त खदान के 60 मीटर के दायरे में पहुंच चुकी थी। विनियमय 127 के अनुसार ऐसी खदान का विस्तार करने के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है और पहले से ही बोर छिद्र आदि की व्यवस्था करना जरूरी है। प्रबन्धकों ने स्वयं ऐसा कोई पूर्वोपाय नहीं किया। वे लगातार पानी के भंडार की तरफ बढ़ रहे थे। इस स्थिति में मैं निस्संदेह रूप से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कम से कम तीन डिपो अर्थात् 27वें पश्चिमी लेबल के दूसरे, तीसरे और चौथे डिपों पर विनियमन 127 (3) लागू होता है और जैसा कि उप-विनिमय (6) में विहित है, प्रबन्धक-वर्ग ने पूर्व अनुमति न लेकर तथा स्वयं कोई पूर्वोपाय न करके उक्त विनिमय का उल्लंघन किया है।

11.39 अगला विचारार्थ प्रश्न विनियम 127 के उप-विनियम (2) के लागू होने के संबंध में है। जलमग्नता न बचने के लिए पूर्वोपाय करने से संबंधित इस उप-विनिमय में विवेक्षित एक स्थिति यह है जब किसी अन्य साम या सेक्शन के नीचे किसी सीम या सेक्शन में काम किया जा रहा हो। इस मामले में स्थिति यह है कि 29वें में पूर्वी लेबल का तीसरे डिपो 27वें पश्चिमी लेबल के तीसरे डिप, जिसमें पानी भरा था, के ठीक नीचे था। दरार पड़ने के कारण निचले लेबल में पानी भरा गया और चारों ओर फैल गया। इस स्थिति पर यह स्पष्टतः विनियम 127 के उप-विनिमय (2) के खंड (1) में विचार किया गया है। इस घटना से प्रकट होता है कि हालांकि उप-विनियम में उल्लिखित पूर्वोपाय किये जाने चाहिए थे लेकिन प्रबन्धक वर्ग में ऐसे पूर्वोपाय कतई नहीं किए। इस दृष्टि से प्रबन्धक वर्ग ने विनियम 127 के उप-विनियम (2) का उल्लंघन किया है।

11.40 प्रबन्धक-वर्ग के लिए यह कहना बहुत आसान होता और वस्तुतः यह कहना भी यही चाहता था कि उसे इस बात का पता नहीं था कि 29वें लेबल ऊपरी

सेक्शन के ठीक नीचे चलता जा रहा है जिसमें 27वें पश्चिमी लेवल का काम किया गया है। यदि खदान-कार्य मुख्य डिपों के पूर्वी तरफ विभिन्न दिशाओं में चल रहा था तो प्रबंधक-वर्ग के लिए ऐसी घटना घटित होने के बारे में अनुमान लगा लेना तथा यह सोच लेना कोई कठिन कार्य नहीं था कि जब कथित क्षेत्र में एक सीम के नीचे दूसरी सीम का कार्य विभिन्न सेक्शनों में चल रहा है तब यदि यह दुर्घटना तीसरे डिप में नहीं होती तो दूसरे, पहले डिप या मुख्य डिप के पूर्वी क्रास-कट में तो इसके होने की पूरी संभावना थी। अतः इस बारे में जानकारी का न होना सर्वेक्षण एवं नक्शा संबंधी नियमों एवं विनियमों का पूर्णतः उल्लंघन करते हुए लापरवाही के बराबर था। चूंकि यह दुर्घटना कुल मिलाकर लापरवाही का ही परिणाम था अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रबन्धक-वर्ग विनियम 127 के उप-विनियम (2) का उल्लंघन का दोषी है।

11.41 इसके बाद हम विनियम 127 के उप-विनियम (1) के लागू होने के बारे में विचार करना चाहेंगे। उप-विनियम (1) में विशिष्ट शब्दों में यह विहित है कि खदान से पानी या अन्य तरल पदार्थ को रोकने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। जानकारी के न होने के दलील उस समय कमजोर पड़ जाती है जब हम इस उप-विनियम की प्रयोज्यता की दृष्टि से स्थिति पर विचार करते हैं। हुरिलाडीह कोयला खान के प्रबन्धक-वर्ग ने एक सम्प का नक्शा बनाया था। वस्तुतः प्रबन्धक गुप्ता, अदालती गवाह 3 और एजेन्ट देवेन्द्र सिंह, अदालती गवाह 5 की गवाही से हमें यह मालूम होता है कि वे सम्प खदान के पश्चिम में एक रोधिका बनाना चाहते थे। प्रबन्धक गुप्ता के अनुसार यह रोधिका 100 फुट मोटी बनाई जानी थी लेकिन लिखित बयान प्रदर्श 5 में प्रबन्धकों ने इस रोधिका की मोटाई 50 फुट बताई है। योजना चाहे जो रही हो लेकिन वास्तव में यह देखा गया है कि रोधिका पूरी तरह टूट चुकी है। यह तब हुआ जब 27वें, 28वें और 29वें पूर्वी लेवल बनाए जा रहे थे। प्रबन्धक भट्टाचार्यजी, प्रबन्ध गवाह 7 ने बताया था कि इन लेवलों का काम मेरे समय में शुरू किया गया था। गवाह मुखर्जी, प्रबन्धक गवाह 8 ने यह भी बताया कि 29वें पूर्वी लेवल का काम दुर्घटना से लगभग एक या डेढ़ महीने पहले शुरू किया गया था। लेकिन, जैसा कि पहले विचार किया जा चुका है, अब यह ड्राइवेज पानी भरा सम्प के 60 मीटर के दायरे में किया जा रहा था। इस ड्राइवेज का परिणाम यह हुआ कि योजनाबद्ध रोधिका पूर्णतः टूट गई।

11.42 यह हो सकता है कि पानी भरा रहने के कारण एकदम पूर्वी भाग में डिप का कार्य नहीं किया जा सकता था। इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि प्रबन्धक-वर्ग ने यह निश्चय किया होगा कि खंभा हटाने तथा डिप का कार्य साथ-साथ किया जाए जो कि विशेष पूर्वोपाय के बिना नहीं किया जाना चाहिए था। यह भी सही लगता है कि प्रबन्धकों ने यह निर्णय इसलिए लिया हो ताकि वह उत्पादन लक्ष्य न पिछड़ जाएं। लेकिन उसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि रोधिका टूट गई जो एक पूर्वोपाय के रूप में काम दे सकती थी। असल में बात यह है कि रोधिका के रहते हुए भी सीधे पानी के भंडार की ओर बढ़ते हुए वे पानी के 60 मीटर के दायरे में होते। यह केवल चर्चा का विषय है कि सम्प त्यक्त खदान है अथवा नहीं। जब हम उप-विनियम (1) की प्रयोज्यता के बारे में बात करते हैं तो इस उप-विनियम में उन सभी स्थितियों पर विचार किया गया है जिसमें पानी का खतरा होता है और मेरे विचार से और सम्प की तरह बढ़ने से पहले प्रबन्धकों द्वारा पर्याप्त पूर्वोपाय करने लाजिमी थे।

11.43 इस संबंध में हमें पश्चिमी तथा पूर्वी तरफ के लेवलों की सापेक्ष में स्थितियों 45 फुट (13.5 मी) की गलती पर भी विचार करना होगा। यह गलती 27वें पश्चिमी लेवल तथा 29वें पूर्वी लेवल के संबंध में है।

यह तर्क पेश किया गया है इसके स्थानान्तरण के कारण प्रबन्धक भ्रम में पड़ गए। यह तर्क ऊपर सही मालूम देता है लेकिन हमें समूचे मामले पर विचार करना होगा। यह स्पष्ट है कि सर्वेक्षण के दौरान जो गलती हुई उसका कारण भी यही था कि सर्वेक्षण कार्य से संबंधित विभिन्न विनियमों तथा पद्धतियों का पालन करने में लापरवाही की गई है। इसी कारण से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि विनियम 127 के उप-विनियम (1) का भी उल्लंघन किया गया था।

अध्याय—12

निष्कर्ष

12.1 सारांश के रूप में यह कहा जा सकता है कि, दुर्घटना का कारण मुख्य डिप क्षेत्र में 29वें पूर्वी लेवल तथा पूर्वी क्रास-कट डिप की पूर्वी त्यक्त खदान जिसका इस्तेमाल पानी की सम्प के रूप में किया जाता था, के बीच 45 घन मीटर की विभाजक दीवार का टूट जाना था। मिनटों में काफी मात्रा में पानी नीचे आना शुरू हो गया और सभी खदानों अर्थात मुख्य डिप के पूर्व में तीसरे, दूसरे और पहले डिप तथा 29वें पूर्वी लेवल के पूरे मुख्य डिप में भी भर गया। उसके बाद पानी 28वें लेवल के जोड़ के आस-पास तक चढ़ गया। पानी भरने के परिणाम-स्वरूप इस क्षेत्र में काम कर रहे 19 व्यक्ति डूब गए। यह जोड़ मुख्य डिप के पूरे 29वें पूर्वी लेवल के तीसरे डिप तथा 27वें पश्चिम लेवल की तीसरे उस डिपों के बीच लगाया गया था जिसमें पानी भरा रहता था और जो 29वें पूर्वी लेवल के तीसरे डिप के ठीक ऊपर था।

12.2 यह दुर्घटना अनेक परिस्थितियों में घटित हुई। प्रबन्धकों के अनुसार नक्शे की गलती के परिणामस्वरूप यह दुर्घटना हुई। इन बातों पर पहले ही विचार किया जा चुका है कि ये गलतियां कैसे हुईं। सर्वेक्षक वर्मा के समय से लेकर सर्वेक्षण तथा आलेखन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक बहुत बड़ा तर्क यह पेश किया गया कि 14वीं सीमा का पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण 1979 से जारी था और यदि दुर्घटना नहीं होती तो वह उसके बाद भी जारी रहता। अतः असल बात यह है कि पुनः सर्वेक्षण करने की कभी भी कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों की रिपोर्ट तथा एक प्रबन्धक की चार्ज रिपोर्ट में संयोग से जो सतर्कता बरतने को कहा गया था उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। सर्वेक्षण कार्य और सर्वेक्षण कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण नहीं रखा गया। यदि नक्शों पर हस्ताक्षर करके तथा खान सुरक्षा महानिदेशक को नक्शों की प्रतियां भेज कर विभिन्न विनियमनों का पालन किया जाता तो ऐसा नियंत्रण स्वतः हो जाता लेकिन उन नियमों का पालन न करके तथा लापरवाही, शिथिलता और अकर्मण्यता की प्रवृत्ति अपनाकर ऐसा नियंत्रण नहीं बरता गया। इसका परिणाम यह हुआ कि नक्शे गलत हो गए। इन सब बातों से यह प्रकट होता है कि नियमों की पूर्ण अवहेलना तथा उपेक्षा की गई है। लेकिन संबंधित परिस्थितियां केवल यही नहीं हैं। जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, जब एक विशाल सम्प अर्थात पानी का विपुल भंडार निकट था, तब साधारण पूर्वोपाय किये बिना सम्प की तरफ अंधाधुन्ध खुदाई की गई—विनियमों अथवा गैर विनियमों की तो बात ही छोड़ो। अतः मेरे विचार से विनियमों की अपेक्षा को भी एक परिस्थिति माना जाना चाहिए।

12.3 यदि इस रिपोर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति पर दोषारोपण करना है तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि गलती की शुरूआत सर्वेक्षण वर्मा से हुई। उनके बाद मुखर्जी भी सही कार्रवाई कर सकते थे किन्तु उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। इस गलती के किए वे भी उतने ही जिम्मेदार हैं। अन्य सर्वेक्षकों अर्थात असारा तथा अधिकारी को गलत नक्शा बनाने तथा प्रबंधकों को उन नक्शों को प्रमाणित करने के लिए समान रूप से दोषी ठहराया जाना चाहिए। प्रबन्धक भट्टाचार्यजी मौके के व्यक्ति थे—इसके लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मेरे विचार से एजेंट के ओहदे तक के उच्च-अधिकारियों को इस दोष से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एजेंट हुरिलाडीह में ही रहते थे और उन्हें कोयला खान की सम्पूर्ण स्थलाकृति की जानकारी रखते हुए दिन-प्रतिदिन के कार्य के बारे में प्रबंधकों का मार्ग दर्शन करना चाहिए था। इस विशेष मामले में एजेंट कुमार भूतपूर्व प्रबन्धक भी रह चुके थे जिनके कार्यकाल में ऐसी बहुत सी चीजें हुईं जिनके कारण यह दर्दनाक घटना हुई। चूंकि एक बार वे प्रबन्धक रह चुके थे अतः एजेंट के रूप में उनसे यह आशा की जाती थी कि प्रबन्धक के कार्य से सुपरिचित होते और उनका कुशलतापूर्वक पर्यवेक्षण करते तथा उनको समय से पूर्व संकेत देते ताकि यह दुर्घटना न होती।

12.4 एजेंट देवेन्द्र सिंह के पास एक बहाना है कि उन्हें कई कोयला खानों की देखभाल करनी पड़ती थी। लेकिन यह बहाना कुमार और प्रसाद के पास नहीं था। जिनके अधीन, जब ये गलतियां हुईं, केवल हुरिलाडीह का ही कार्यभार था।

12.5 अतः ये सभी व्यक्ति लापरवाही, शिथिलता तथा सांविधिक सुरक्षा उपायों का पालन न करने के दोषी हैं और इसलिए ये इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं जिसमें 19 निर्दोष व्यक्तियों की जानें गईं।

अध्याय-13

प्रेक्षण

13.1 खान अधिनियम की धारा 24 में, जिसके अधीन यह जांच न्यायालय बिठाया गया है, यह विचार किया गया है कि रिपोर्ट में वे प्रेक्षण दिए जा सकते हैं जिन्हें न्यायालय उचित समझे। अतः मैं उद्घाटित तथ्यों तथा पहले की गई चर्चा के आधार पर कुछ सिफारिशें करना चाहूंगा।

कोयला खान विनियम 127

13.2 सबसे अधिक लम्बा वादविवाद इस प्रश्न पर हुआ कि क्या इस मामले में विनियम 127 लागू होता है। इस विनियम में उन पूर्वापायों का उल्लेख किया गया है जो भूमिगत जलमग्नता के खतरे के संबंध में किए जाने चाहिए। तीन प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। उप-विनियम (1) में समूचा सामान्य विवरण दिया गया है। उप-विनियम (2) में उन तीन प्रकार की स्थितियों पर विचार किया गया है जिनके कारण भूमिगत जलमग्नता का खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन निरोधक कार्रवाई के लिए यह आवश्यक है कि पानी आदि के फूटने के संबंध में पर्याप्त पूर्वोपाय किए जाएंगे, उप-विनियम (5) का संबंध उस विशेष स्थिति से है जहां पानी का असाधारण रिसाव देखा जाए या यदि ऐसा कोई संदेह या शक हो जिसके बारे में खान सुरक्षा महानिदेशक को सूचित किया जाए तो आशा यह की जाती है कि संभावित कारणों तथा उपायों की दृष्टि से स्थिति की उचित जांच की जाएगी।

13.3 उप-विनियम (3) उन खदानों के परिसर में किए जा रहे ड्राइवेज से संबंधित है जो त्यक्त या परित्यक्त तथा जिनका निरीक्षण नहीं किया जाता है। 'त्यक्त' शब्द की व्याख्या करते समय लम्बे तर्क प्रस्तुत किए गए और

'बंद' तथा 'अप्रयुक्त' शब्दों से उसकी भिन्नता बताई गई। मैंने उन विभिन्न विनियमों पर विचार किया है जिनमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैंने उनका अर्थ समझने की कोशिश भी की है। विनियमों में 'त्यक्त' शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। इसके कारण संदेह पैदा हो सकता है और वर्तमान स्थितियों में उप-विनियम की प्रयोज्यता के बारे में तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। 'त्यक्त' 'अप्रयुक्त' और 'परित्यक्त' शब्दों की उपयुक्त परिभाषा देकर संदिग्धता को दूर किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 'त्यक्त' शब्द का अर्थ उन खदानों के संदर्भ में स्पष्ट हो सकता है जो त्यक्त नहीं हैं और जिनके लिए किसी खान कर्मचारी द्वारा उचित निरीक्षण के हेतु विनियम 113 में व्यवस्था है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए 'त्यक्त खदान' की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है—

'त्यक्त खदान' का अर्थ किसी खान में प्रत्येक स्थान से है—चाहे वह जमीन के अन्दर हो या बाहर और विनियम 113 के उप-विनियम (1) तथा उप-विनियम के खंड (ख) के अधीन किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा उसकी जांच करने की जरूरत नहीं होती है।'.

13.4 कदाचित् 'खदान' शब्द की परिभाषा देने की भी आवश्यकता है। यह भी ठीक होगा कि उप-विनियम (2) में उल्लिखित पर्याप्त पूर्वोपायों का कुछ ब्योरा दिया जाए ताकि उस संबंध में मार्गदर्शन मिल सके।

13.5 कुछ ऐसी दशाएं भी हैं जिनके कारण कभी-कभी भूमिगत पानी का खतरा पैदा हो जाता है और वे दशाएं हैं जब दो या अधिक गैलरियों का विस्तार डिप की तरफ किया जाता है। खतरा उस समय पैदा होता है जब संयोजक गैलरी की खुदाई पानी वाली डिप गैलरी से जोड़ने के लिए की जाती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विनियम में शायद इस बात का उल्लेख करना ठीक होगा कि जब किसी अन्य पानीयुक्त खदान की तरफ या उसके पांच मीटर के दायरे में कोई गैलरी बनाई जा रही हो तब तीन मीटर लम्बा एक बोर छिद्र रखा जाएगा और वह उस गैलरी के बीच रखा जाएगा जो बनाई जा रही है। कोयला खान विनियमन 60 अद्यतन नक्शों तथा सेक्शनों का प्रस्तुतीकरण।

13.6 जांच न्यायालय की कार्यवाही के दौरान यह मालूम हुआ था कि कोयला खान विनियम 60 का पालन नहीं किया जा रहा है जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ष खान सुरक्षा महानिदेशक को मुख्य नक्शों तथा खान के कार्यस्थलों के सेक्शनों की अद्यतन दो प्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। जब विनियम में यह उपबन्ध है कि नये नक्शे प्रस्तुत करने के बजाय किसी सम्बद्ध वर्ष में प्रस्तुत नक्शों तथा सेक्शनों को अगले वर्ष अद्यतन किया जाए तब इस उपबन्ध के पालन करने में लापरवाही बरतना एक आश्चर्य की बात है। यह ठीक है कि किसी खान के नक्शे की मात्र अध्ययन करने से खान के सभी प्रकार के खतरों का पता नहीं लगाया जा सकता फिर भी, खान सुरक्षा महानिदेशक के पास अद्यतन नक्शे का उपलब्ध होना वांछनीय है।

13.7 कुछ मजदूर संघों की ओर से यह कहा गया है कि प्रबन्धक-वर्ग ऐसे नक्शे प्रस्तुत करने के अपने कर्त्तव्यों की पूरी तरह अवहेलना करता रहा है और सुरक्षा को खतरा पैदा करता रहा है। यह भी कहा गया था कि खान सुरक्षा महानिदेशक ने विनियम 60 का पालन करवाने में खासी निष्क्रियता दिखाई है। वास्तव में, एक गवाह-निदेशक पी. सी. श्याम से जब संगत प्रश्न पूछे गए तब उन्होंने ऐसे नक्शों की जांच करने के बारे में न केवल अपनी असमर्थता व्यक्त की बल्कि यह भी बताया कि ये नक्शे स्टोर में पड़ रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि यदि विनियम का सख्ती से पालन किया जाता है तो कार्यभार खान सुरक्षा महानिदेशक के कार्यालय की क्षमता से बाहर हो जाएगा। उन्होंने यह भी सूचित किया कि खान सुरक्षा महानिदेशक ने इस अपेक्षा को हटाने के लिए सरकार को सुझाव दिया है। अगर ऐसी बात है तो मैं यह नहीं समझता कि खान सुरक्षा महानिदेशक इस संबंध में सही दिशा में कार्य कर रहे हैं।

13.8 विनियम 60 का मुख्य उद्देश्य शायद यह है कि उचित प्रक्रिया तथा (परित्यक्त खान नक्शा-विनियम 61) के पेश किए बिना खान बंद/परित्यक्त कर दी जाती है तो बाद के संदर्भ के लिए कम से कम कुछ तो अद्यतन खान नक्शे उपलब्ध होने चाहिए। ऐसी कोई प्रशंसनीय व्यवस्था (इस या अन्य स्थिति में) विद्यमान नहीं है जिसके अनुसार इन नक्शों तथा सेक्शनों की छानबीन खान सुरक्षा महानिदेशक करे। हालांकि ऐसी छानबीन की जानी उपयोगी सिद्ध होगी फिर भी, यह कार्य इस बात पर निर्भर करेगा कि खान सुरक्षा महानिदेशक के पास पर्याप्त स्टाफ हो। इस विषय पर बाद में चर्चा की गई है। लेकिन मेरे विचार से कोयला खान विनियम 60 का पालन किया जाना वांछनीय है। खान सुरक्षा महानिदेशक का कार्यालय शायद एक अधिसूचना जारी करके प्रबन्धकों को यह अनुमति दे सकता है कि वे नक्शों तथा सेक्शनों का सेट प्रस्तुत करते समय पिछले सेट को प्राप्त कर लें ताकि उसे अगले वर्ष अद्यतन बनाया जा सके और उसे प्रथम सेट के बदले खान सुरक्षा महानिदेशक के पास जमा किया जा सके। इस प्रकार खान सुरक्षा महानिदेशक के पास नक्शों आदि का एक अद्यतन सेट हमेशा रखा रहेगा।

13.9 यदि किसी विशेष नक्शे या सेक्शन को काफी महत्वपूर्ण समझा जाता है तो उक्त विनियम के पालन किए जाने से खान सुरक्षा महानिदेशक उसकी जांच कर सकेगा।

अन्यथा भी, ऐसे नक्शों तथा सेक्शनों से पिछली इन बातों को समझने में मदद मिलेगी कि किसी दुर्घटना के होने पर प्रबन्धकों ने क्या किया था और उन्हें क्या करना चाहिए था। ये आकस्मिक संदर्भ के लिए भी सुविधाजनक रहेंगे। इस उपबन्ध को समाप्त करना अवांछनीय होगा। इसके अलावा यदि खान सुरक्षा महानिदेशक को प्रतिवर्ष अद्यतन नक्शे तथा सेक्शन प्रस्तुत किए जाने हों तो इससे प्रबन्धक-वर्ग को कम से कम साल में एक बार संभावित गलतियों के लिए अपने नक्शों तथा सेक्शनों की जांच करने का मौका तो मिलेगा। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, इन नक्शों तथा सेक्शनों से खान सुरक्षा महानिदेशक को छानबीन के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो सकेगी हालांकि वर्तमान स्टाफ की संख्या को देखते हुए खान सुरक्षा महानिदेशक को ऐसी छानबीन करना कठिन होगा।

खान सुरक्षा महानिदेशालय के कर्मचारियों की संख्या

13.10 कदाचित यही उचित स्थिति होगी जिसमें खान सुरक्षा महानिदेशालय के कर्मचारियों की संख्या के प्रश्न पर विचार कर लेना चाहिए। ये बात सभी लोगों ने स्वीकार की कि कार्यों के उचित निष्पादन के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय के कर्मचारियों की संख्या एकदम अपर्याप्त है। पिछले बीस वर्षों में खान उद्योग का विस्तार कई गुना बढ़ा है लेकिन खान सुरक्षा महानिदेशालय के कर्मचारियों की संख्या लगभग उतनी ही रही है। अमेरिका की सी 'मुक्त' अर्थव्यवस्था में भी वार्षिक 90 करोड़ टन के उत्पादन के लिए 1400 से भी अधिक संघीय कोयला खान निरीक्षक है और वह भी जहां अधिकतर कार्य मशीनों के माध्यम से होता है। भारतीय स्थिति में, जहां अधिकांश कार्य शारीरिक होता है और श्रमिक भी अपनी सुरक्षा के बारे में सचेत नहीं होते हैं, गहन निरीक्षण की आवश्यकता है। अमेरिका के पैटर्न पर भी, खान सुरक्षा महानिदेशालय में कर्मचारियों की संख्या वर्तमान स्वीकृत संख्या लगभग 140 के मुकाबले कोयला खानों के लिए 270 या कुल मिलाकर 400 होनी चाहिए।

13.11 खान सुरक्षा महानिदेशालय में पदासीन अधिकारियों की संख्या भी कदाचित उस उद्योग की तुलना में जहां से ये अधिकारी इस विभाग के लिए जाते हैं, तुच्छ वेतनमानों या वृत्तिक संभावनाओं के कारण कम है। यह स्पष्ट है कि आजकल खान सुरक्षा महानिदेशालय प्रत्येक खान का हर वर्ष सामान्य निरीक्षण भी नहीं करवा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हाल में ही वेतनमानों में कुछ संशोधन किए गए हैं लेकिन इसी बीच कोल इंडिया के वेतनमानों में काफी परिवर्तन किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय तथा उद्योग के वेतनों में पहले की भांति गंभीर असमानता बनी हुई है। अतः वेतनमानों में संशोधन करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को अगले 8–10 वर्षों के दौरान खान सुरक्षा महानिदेशालय का प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत विस्तार करना चाहिए। केवल तभी इस संगठन को न्यूनतम वांछनीय स्तर तक मजबूत बनाया जा सकता है।

13.12 इस पहलू की उपेक्षा केवल खनिकों की सुरक्षा के महत्वपूर्ण हित को गंभीर खतरे में डाल कर ही की जा सकती है।

कोयला खान विनियम 58 (3)—खान नक्शे तथा त्रैमासिक सर्वेक्षण—कुछ सुझाव

13.13 जांच के दौरान सबसे अधिक परेशान करने वाली बात खान के नक्शों की स्थिति थी। खान के नक्शों से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं का उल्लेख विनियम 59 में किया गया है जिसके अनुसार सतह के नक्शे भूमिगत नक्शे तथा वातायन के नक्शे समेत पांच प्रकार के नक्शे रखे जाने आवश्यक हैं। विभिन्न पहलुओं यथा गैस, धूल, पानी आदि के खतरे से संबंधित खान की मौजूदा दशाओं के लिए विभिन्न प्रकार के ब्योरे दर्शाने के लिए खान के विभिन्न प्रकार के नक्शे अपेक्षित होते हैं। विनियम 58 के उप-विनियम के अनुसार प्रत्येक तिमाही में इस प्रकार के अद्यतन नक्शे तैयार करना एक प्रकार की सामान्य बाध्यता मानी जाती है। दुर्भाग्यवश हुरिलाडीह कोयला खान के नक्शे 30-6-82 को समाप्त तिमाही के बाद अद्यतन नहीं किए गए थे (प्रदर्श-62) यहां तक कि इस इंदराज पर भी प्रबन्धक ने प्रतिहस्ताक्षर नहीं किए थे। दूसरे शब्दों में, खान के नक्शे दुर्घटना की तारीख से कम से कम चार तिमाहियों तक अद्यतन नहीं किए गए थे। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि न तो प्रबन्धक ने इस गलती को दुरुस्त करवाने की परवाह की और न ही किन्हीं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने।

13.14 जांच के दौरान दी गई गवाही से यह प्रकट होता है कि सर्वेक्षक असांविधिक नेमी कार्यों यथा सिविल निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण, बिल तैयार करने आदि के कार्यों को करवाने में व्यस्त रहे। महत्वपूर्ण खान संबंधी कार्य यथा नवीन कार्य पैनल खोलने तथा मध्य एवं ग्रेड लाइनें देने के कार्य की प्रायः उपेक्षा की गई। खदानों के अन्त में स्पाट लेवलों की पैमाइश तो इस अवधि के दौरान कतई नहीं की गई। कार्य की इस शोचनीय स्थिति पर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए। इस संबंध में दो प्रश्न उठते हैं —

(i) कोयला खान पर अधिकांश समय कम से कम दो अर्हता प्राप्त सर्वेक्षकों के रहते हुए भी मध्य लाइनें देने, और उनका विस्तार करने तथा ग्रेड लाइनें देने और स्पाट लेवलों की पैमाइश करने तथा उनको रिकार्ड करने की महत्वपूर्ण खनन-अपेक्षाओं की पूर्णतः उपेक्षा क्यों की गई ?

(ii) दो वर्ष से भी अधिक समय से तिमाही सर्वेक्षण क्यों नहीं कराए गए ?

13.15 प्रश्न सं. (1) का उत्तर यह है कि सर्वेक्षण स्टाफ उत्पादन के आधार पर भुगतान संबंधी कार्यों में अत्यधिक व्यस्त था अतः उत्पादन-सुरक्षा संबंधी सांविधिक कार्यों की पूर्ण उपेक्षा की गई। इसके अतिरिक्त और कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। प्रश्न सं. (2) के संबंध में भी यदि सर्वेक्षक दिन-प्रति-दिन के महत्वपूर्ण कार्यों में अत्यधिक व्यस्त थे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तिमाही सर्वेक्षणों को बहुत ही कम महत्व दिया गया होगा।

13.16 इस संबंध में एक प्रश्न उठाया गया था कि खान उद्योग में अर्हता प्राप्त सर्वेक्षकों की अत्यंत कमी है। कदाचित यह ठीक है। फिर भी, यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्णतः राष्ट्रीयकृत क्षेत्रक कोयला उद्योग ने और अधिक प्रशिक्षित सर्वेक्षक नियोजित करने के संबंध में क्या किया है? इस समस्या को कम करने का एक तरीका यह है कि असांविधिक सर्वेक्षण कार्य सिविल के सर्वेक्षकों को सौंप दिए जाएं।

13.17 तिमाही सर्वेक्षण न करने के संबंध में जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह असंतोषजनक है। यह कहा जा चुका है कि यदि खान के पुराने नक्शों के सामान्यतः सही होने के बारे में संदेह किया गया था तो उनकी शुद्धता की जांच करना सबसे पहला काम था। लेकिन यह कार्य वर्षों तक नहीं किया गया और इसी बीच तिमाही सर्वेक्षण तो कतई नहीं किए गए। इस लापरवाही का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तिमाही सर्वेक्षणों में नई बनाई गई खदानों की सही स्थिति की उच्च जांच की जाती है लेकिन इस मामले में ऐसी जांच बिल्कुल नहीं की गई।

13.18 चूंकि खान के लिए नियुक्त सर्वेक्षक स्टाफ सदैव नेमी कार्यों में व्यस्त रहता है अतः राष्ट्रीयकृत उद्योग में यह वांछनीय प्रतीत होता है कि उसमें तिमाही सर्वेक्षण तथा अन्य जांच कार्य करने के लिए एरिया स्तर पर कर्मचारियों का एक अलग सेट नियुक्त किया जाए। इस पद्धति के अनुसार मुख्य खान नक्शों तथा सेक्शनों के दो सेट रखने होंगे एक खान में और दूसरा एरिया या ग्रुप कार्यालय में। इस प्रकार तिमाही सर्वेक्षण करने तथा अपने कार्यालय में अद्यतन नक्शों के सेट लाने की जिम्मेदारी एरिया या ग्रुप सर्वेक्षण दल की होनी चाहिए। नक्शों के इस अद्यतन सेट से खान कार्यालय में रखे नक्शों के सेट से विनिमय किया जाएगा तथा अगले तिमाही सर्वेक्षण में खान कार्यालय के नक्शों के सेट को अद्यतन किया जाएगा और उसका पुनः विनिमय किया जाएगा। इस पद्धति से दो लाभ होंगे:—

(क) खान में वे नक्शे सदैव रहेंगे जिन्हें प्रत्येक तिमाही में अद्यतन कर दिया गया है और

(ख) कोयला खान के सर्वेक्षकों के कार्य की जांच एक अलग सर्वेक्षण ग्रुप द्वारा प्रत्येक तिमाही में कर ली जाएगी।

बिंदु रेखाएं

13.19 तारीख सहित बिंदु-रेखाओं का प्रयोग प्रत्येक तिमाही में नक्शों को अद्यतन करते समय किया जाना चाहिए। लेकिन खान सर्वेक्षक प्रायः उस कार्यस्थल के संभावित विस्तार को दिखाने के लिए भी बिंदु-रेखाओं का प्रयोग कर लेते हैं जिसका वस्तुतः सर्वेक्षण नहीं किया गया है। चालू क्षेत्र में बंद सिरों द्वारा चिन्हित करके प्रगामी खदानों को तब तक नहीं दर्शाया जाता जब तक उनकी खुदाई अंतिम सीमा तक नहीं पहुंच जाती। यदि सर्वेक्षण के दौरान उन तक पहुंच न हो तो उन्हें बिंदु-रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है।

13.20 नक्शे-प्रदर्श 62 पर बिंदु-रेखाओं के संदर्भ में बिंदु-रेखाओं का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विभिन्न गवाहों से प्रश्न पूछे गए। सर्वेक्षण अधिकारी भट्टाचार्जी ने कहा कि पक्की रेखाओं के स्थान पर बिंदु-रेखाओं का प्रयोग तब किया जाता है जब सर्वेक्षण का पूरा ब्योरा नहीं दिया जा सकता। यदि गैलरी के सिरे पर बिंदु-रेखाएं हों तो वे इसकी व्याख्या इस प्रकार करेंगे—"गैलरी का विस्तार ज्ञात है लेकिन उसका ब्योरा नहीं" विस्तार का अर्थ लम्बाई से है। अदालती गवाह श्याम का कहना है कि जब किसी नक्शे पर बिंदु-रेखाएं दिखाई जाती हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि विस्तार और शुद्धता संदिग्ध हैं। सर्वेक्षक मुखर्जी ने डिप-गैलरियों को बिंदु-रेखाओं द्वारा इसलिए दर्शाया था क्योंकि उन्हें गैलरियां पानी से भरी मिली थी। अतः इसका अर्थ यह हुआ कि बिंदु-रेखाओं का इस्तेमाल तब किया जाता है जब खदान या गैलरी का सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता हो। सर्वेक्षण न किए जाने की वजह यह है कि या तो गैलरी में पानी भरा रहने के कारण या अन्यथा उसे रुका होने के कारण उसमें प्रवेश ही किया जा सकता। लेकिन नक्शे पर ब्यौरे को अनुरेखित नहीं किया जा सकता अतः उन्हें बिंदु-रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। दो आयामी खान नक्शों में, जो सामान्यतः हमारे पास आते हैं लेवलों तथा डिपों को दर्शाने के लिए रेखाएं खींची जाती हैं। वे ऊंचाई आदि नहीं दर्शाते। इसका उल्लेख कदाचित टिप्पणी या आरेखन द्वारा किया जाता है। ये प्रत्येक अवस्थिति की प्रवणता नहीं दर्शाते। सबसे ऊपर केवल सामान्य प्रवणता का उल्लेख कर दिया जाता है। इस दृष्टि से बिंदु-रेखाओं का सिरा बंद है या खुला है—इसका कोई महत्व नहीं है। इसका विस्तार केवल अनुमानित ही होता है। सर्वेक्षक ब्यौरों का सर्वेक्षण करने में असमर्थ होता है। यह आशा की जाती है कि यदि सर्वेक्षक एक तिमाही में ब्योरों की जांच नहीं करवा सकता तो उसे अगली तिमाही के लिए नक्शा तैयार करते समय यथास्थिति, रुकावट दूर करवा कर या गैलरी का पानी निकलवा कर वे ब्यौरे प्राप्त कर लेने चाहिए लेकिन इस मामले में यह पाया गया है कि स्पिट लेवल दिए बिना बिंदु रेखाएं तिमाही दर-तिमाही दिखाई जाती रहीं। यदि पक्की रेखाओं द्वारा सिरे को खुला दिखाया जाता है तो इससे यह जाहिर होगा कि काम चल रहा है और

यदि सिरा बंद दिखाया जाता है तो इससे यह जाहिर होगा कि खदान कार्य अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन यदि यह बिंदु-रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है तो इसमें भ्रम पैदा हो सकता है और यदि बिंदु-रेखाएं तिमाही-दर-तिमाही दिखाई जाती रहीं तो इसका मतलब यह नहीं है कि इतनी सारी तिमाहियों के दौरान सर्वेक्षक ब्योरों का सर्वेक्षण करने में असमर्थ था। अतः त्यक्त एक खदान बन जाती है और वह जल सारणी के नीचे होती है। ऐसी त्यक्त खदान में पानी का रिसाव होना जरूरी है। ऐसे लम्बे वाद-विवाद से बचने के लिए जैसा कि इस मामले में हुआ है, शायद यह कहना लाभदायक तथा सुविधाजनक होगा कि जब कभी भी किसी खदान को बिंदु-रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, तब तक यदि उसे अन्यथा न दिखाया गया हो, त्यक्त-खदान ही माना जाएगा। ऐसे संशोधन से समुचित तर्क-वितर्कों में कमी आएगी।

आंतरिक सुरक्षा संगठन

13.21 इस रिपोर्ट से अब तक यह जाहिर होता है कि दुर्घटना का मुख्य कारण प्रबंधकों द्वारा बरती गई लापरवाही है। विनियम 36 और 41 (क) के अनुसार प्रत्येक खान में एक सुरक्षा अधिकारी का रखा जाना अनिवार्य है। लेकिन यह पद केवल नाम के लिए ही सकता है। यह समझा जाता है कि अनेक कंपनियों तथा निगमों ने एक आंतरिक सुरक्षा संगठन का गठन किया है। खानों में सुरक्षा स्तर में सुधार करने के लिए उचित रूप से गठित आंतरिक सुरक्षा संगठन एक कारगर साधन बन सकता है।

13.22 लेकिन आंतरिक सुरक्षा संगठन को कारगर बनने के लिए इसके पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए अर्थात् यदि इस संगठन के विचार से किसी खान या उसका कोई भाग सुरक्षित न हो तो इसको मध्यस्थता करने का अधिकार ही नहीं बल्कि मध्यस्थता करने के लिए उससे अनुरोध भी किया जाना चाहिए। यदि इस संगठन को निम्नलिखित कार्य सौंपे जाएं तो इसकी भूमिका और अधिक उद्देश्यपूर्ण हो सकती है :—

(क) नए क्षेत्र में कार्य शुरु करने से पहले आंतरिक सुरक्षा संगठन से सुरक्षा निर्बाधता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। इसमें खंभा हटाने और कार्य प्रचालन तथा नए संस्थापन दोनों ही बात शामिल हो सकती हैं। हुरिलाडीह कोयला खान के विशेष मामले में यदि 29 वें पूर्वी लेवल क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने से पहले ऐसा निर्बाधता प्रमाण-पत्र ले लिया गया होता तो दाहिने और संप में पानी के खतरे की सूचना प्रायः प्रबंधक-वर्ग को विशेष रूप से दे दी गई होती।

(ख) सांविधिक अनुमतियां प्राप्त करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशक को संबोधित आवेदन-पत्र आंतरिक सुरक्षा संगठन के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इससे नए प्रस्तावों पर सुरक्षा समस्या की दृष्टि से उनकी गहरी छानबीन करने का अवसर मिलेगा।

आंतरिक सुरक्षा संगठन प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए उसे सामूहिक या मालिक के स्तर पर तैयार की गई स्पष्ट सुरक्षा नीति के माध्यम से एक विशिष्ट प्राधिकार दिया जाना चाहिए।

अध्याय—14

समापन

खर्च की वसूली

14.1 अब मैं खर्च की वसूली से संबंधित अंतिम प्रश्न पर विचार करता हूं। खान अधिनियम 1952 की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाई गई खान नियमावली के नियम 22 के अनुसार जांच न्यायालय संबंधित खान के मालिक से जांच से संबद्ध अन्य खर्चों सहित न्यायालय के खर्च की वसूली का निर्देश दे सकता है बशर्ते कि दुर्घटना प्रबंधक वर्ग की असावधानी या लापरवाही के कारण हुई हो। मेरी रिपोर्ट के अनुसार यह दुर्घटना नक्शे तैयार से संबंधित कार्यों, खान के कार्यचालन से संबद्ध कार्यों तथा कर्त्तव्यों की उपेक्षा करने तथा सुरक्षा पूर्वोपायों का पालन न करते हुए पूर्णतः प्रबंधक-वर्ग की लापरवाही के कारण हुई है। अतः जांच न्यायालय का पूरा खर्च प्रबंधन नामतः भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से वसूल करना होगा। अतः मैं एतद्द्वारा निर्देश देता हूं कि उपर्युक्त प्रबंधन इस जांच न्यायालय का पूरा खर्च अदा करें। मुख्य निरीक्षण अर्थात् खान सुरक्षा महानिदेशक उपर्युक्त खर्च का हिसाब लगाएं तथा उसकी वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इस खर्च में हुरिलाडीह जांच न्यायालय के लिए तथा उसकी ओर से किया गया खर्च, सरकार द्वारा नामित दो असेसरों का खर्च तथा बयान रिकार्ड करने और इस रिपोर्ट को तैयार करने के संबंध में खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा किया गया खर्च शामिल होगा।

14.2 समाप्त करने से पहले मैं प्रतिष्ठित असेसरों—श्री के. एस. त्रिवेदी और प्रोफेसर जी. एस. मरवाहा को उनके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण सहायता के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं प्रबंधकों की ओर से वकालत करने वाले वकील श्री सिरपुकर तथा वकील श्री एस. बी. सिन्हा तथा

यूनियनों के विभिन्न प्रतिनिधियों—सर्वश्री दाते, प्रसाद, चिन्मय मुखर्जी, दासगुप्ता, भट्टाचार्य, जानकी महतो, बख्शी तथा सिंह का भी उनके द्वारा दी गई ऐसा पर्याप्त सहायता के लिए धन्यवाद करूंगा जिसके बिना यह जांच इतनी आसानी से पूरी नहीं हो सकती थी। खान सुरक्षा महानिदेशक तथा उनके अधिकारियों ने न केवल अपने द्वारा एकत्र सामग्री प्रस्तुत करके बल्कि आवश्यकतानुसार हर प्रकार की सहायता के साथ लगे आकर जो पूरा सहयोग दिया है, उसके लिए में आभार व्यक्त करता हूं।

सी. टी. दिघे

अध्यक्ष

जांच न्यायालय

हुरिलाडीह कोयला खान दुर्घटना

तारीख जुलाई, 1984

मैं इस रिपोर्ट में दिए गए उन सभी प्रेक्षणों निष्कर्षों तथा सिफारिशों से पूर्णतः सहमत हूं जिन्हें मेरी पूरी सलाह से तैयार किया गया है।

मैं जांच के सभी पक्षों तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों को भी उनके सौजन्य, सहयोग तथा सहायता के लिए धन्यवाद करता हूं।

मुझे न्यायालय तथा असेसर साथियों का जो अविरत सौजन्य तथा सहयोग प्राप्त हुआ है मैं उसकी भी अत्यंत सराहना करता हूं।

चूंकि मैं खान अधिनियम के अधीन गठित तीन अन्य जांच न्यायालयों से पूर्णतः संबद्ध रहा हूं अतः उसके परिप्रेक्ष्य में मैं निम्नलिखित एक और विचार प्रकट कर रहा हूं। न्यायमूर्ति घेडि ने (1) प्रलेखों को सभी पक्षों से प्राप्त होने के बाद ही परिचालित करने, तथा (2) शुरु में ही गवाहों की सूची मांगने के संबंध में जो प्रक्रिया अपनाई थी उससे 'ढूंढ-खोज' का काम बहुत कम हो गया था। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने भी (3) शपथ पत्रों के रूप में प्रस्तुत मुख्य जिरह प्राप्त करने तथा (4) सम्पूर्ण रूप में (न कि प्रश्न-दर-प्रश्न रूप में) गवाहों के ऊपर लिखवाकर जो प्रक्रिया अपनाई थी उससे भी इस जांच को कम से कम समय में पूरा होने में काफी सहायता मिली है।

जी. एस. मरवाहा

असेसर

हुरिलाडीह जांच न्यायालय

नई दिल्ली, जुलाई, 1984

मैं इस रिपोर्ट में दिए गए उन सभी प्रेक्षणों, निष्कर्षों तथा सिफारिशों से पूर्णतः सहमत हूं जिन्हें मेरी पूरी सलाह से तैयार किया गया है।

मैं श्री मरवाहा द्वारा दिए गए प्रेक्षणों तथा उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से भी पूर्णतः सहमत हूं।

के. एन. त्रिवेदी

असेसर

हुरिलाडीह जांच न्यायालय

नई दिल्ली, जुलाई, 1984

परिशिष्ट-क

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय

श्रम विभाग

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1983

अधिसूचना

एस. ओ.—14 सितम्बर, 1983 को बिहार राज्य के धनबाद जिले की हुरिलाडीह कोयला-खान में दुर्घटना में कई जानें गई;

केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि दुर्घटना के कारणों और जिन परिस्थितियों में यह दुर्घटना हुई है, उनका पता लगाने के लिए एक औपचारिक जांच की जाए।

इसलिए, खान अधिनियम, 1952 (1952 के 35) के खंड 24 के उप खंड (1) में विनिर्दिष्ट शक्तियों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जस्टिस सी. टी. दिघे को इस दुर्घटना की जांच करने के लिए नियुक्त करती है और निम्नलिखित को इस जांच के लिए मूल्यांककों असेसरों के रूप में नियुक्त करती है :—

1. श्री के. एन. त्रिवेदी,
   प्रबंध सचिव,
   भारतीय राष्ट्रीय खान श्रमिक फेडरेशन,
   धनबाद।
2. श्री जी. एस. मारवाहा
   निदेशक,
   भारतीय खान विद्यालय,
   (इंडियन स्कूल आफ माइन्स)
   धनबाद।

[सं. एन.-11015/8/83-एम आई]

जे. के. जैन, अवर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. जस्टिस सी. टी. दिघे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, बंबई उच्च न्यायालय, द्वारा पीठासीन अधिकारी,

केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक ट्रिब्युनल सं. 1 सिटी आईस बिल्डिंग, (चौथी मंजिल) 298 पी, नारीमान स्ट्रीट, फोर्ट, बंबई।

2. श्री के. एन. त्रिवेदी, प्रबंध सचिव, भारतीय राष्ट्रीय खान श्रमिक फेडरेशन, धनबाद।

3. श्री जी. एस. मरवाह, निदेशक, भारतीय खान विद्यालय, धनबाद।

4. महानिदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद।

5. ऊर्जा मंत्रालय, (श्री वी. सरकार संयुक्त सचिव, कोयला विभाग), नई दिल्ली।

6. पत्र सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली।

7. विधि न्याय और कंपनी मामलों का मंत्रालय, (विधायी विभाग), नई दिल्ली

8. राजभाषा (विधायी) आयोग, भगवान दास रोड, नई दिल्ली-110002

9. पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद पुस्तकालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001

10. मंत्री राज्य मंत्री /सचिव/ अतिरिक्त सचिव के निजी सचिव।

हस्ताक्षर/-
जे. के. जैन, अवर सचिव

परिशिष्ट–ख

1 अक्तूबर, 1983

हुरिलाडीह जांच न्यायालय

निरीक्षण-टिप्पणी

जस्टिस सी. टी. दिघे, जांच न्यायाधीश ने दो असेसरों, पांचों संघों के एक-एक सदस्यों, कोयला खान प्रबंधक वर्ग के प्रतिनिधि तथा हुरिलाडीह कोयला खान के अधिकारियों के साथ पहली अक्तूबर को शाम को दुर्घटना स्थान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, कोयला खान कार्यालय में आसानी से उपलब्ध, अहस्तारित और अप्रामाणिक क्षेत्र-नक्शे की फेरो मुद्रण प्रति को मार्ग दर्शन के लिए इस्तेमाल किया गया। दुर्घटना 14वीं सीम में हुई थी, जो 30 फुट मोटी है। सीम में लगभग 8 ड्यु में एक लगभग एस 49° डब्लू की एक डिप थी।

2. दल, 477 फुट (142.0 मीटर गहरे, नीचे पूर्व) गहरे गड्डा संख्या 2 में, मुख्य ढुलाई डिप के पूर्व की ओर गए और तत्पश्चात सीधे नीचे की ओर डिप छोर तक गए जो 29वीं लेवल से 70-80 फुट आगे की ओर फैला हुआ था। (ऐसा कहा जाता है कि इस डिप से 10 शव मिले थे)। निरीक्षण के समय, इस डिप में पानी नहीं था जिसे पंप द्वारा निकाला जा रहा था। इसके बाद दल पुनः 29वें लेवल पर वापिस आ गया और पूर्व की ओर पहले पूर्वी कंपेनियन/टगर हालेज/डिप की ओर गया। लगभग 40 फुट के बाद डिप गैलरी खाली टबों से, बेतरतीब हो गए थे, बंद हो गई थी जिसके कारण दल और नीचे की ओर नहीं जा सका। फिर भी, दल कैम्प लैम्पों की सहायता से डिप के छोर के पास लकड़ी की मोटी टेक का ऊपरी हिस्सा देख सका। दल को बताया गया कि यह डिप 30वें लेवल से भी आगे तक फैला हुआ है, और 30वें लेवल पर पूर्व दिशा की ओर गैलरी बनाने का काम पहले से ही चालू कर दिया गया है। इस डिप से नौ लाशें मिलने की खबर दी गई थी।

दल पुनः 29वें लेवल पर वापिस आ गया और पूर्व में दूसरे डिप की ओर आगे गया जो 60-70 फुट तक फैला हुआ था; इसे भी पम्पों द्वारा पानी से मुक्त रखा गया था। दल 29वें लेवल पर वापिस आ गया तथा और भी पूर्व की ओर पंक्चर-स्थल तक गया। इस स्थान पर, ऊपरी परत से गहराई लगभग 98फुट थी।

3. यह पंक्चर 29वें लेवल और तीसरे पूर्वी छोर/डिप के जंक्शन के थोड़ा डिप की तरफ छत में था। नीचे से हम यह देख सकते थे कि पंक्चर के स्थान के पास विभाजक दीवार लगभग एक फुट बड़ी थी। दल ने सभी सूराखों के बचे हुए छोरों को भी देखने की कोशिश की। यह तीसरे पूर्वी डिप के मुहाने पर बने हुए दर्रे के दो-एक सूराख देख सका। इसने 29वें लेवल के मुहाने पर भी दर्रे के सूराखों के 6-7 साकेट भी देखें। इसने गैलरियों की तरफ या छत में बने हुए और कोई सूराख नहीं देखे। विशेष रूप से पूछताछ करने पर, श्री आर. कुमार (एजेन्ट) ने बताया कि इसमें पहले से कोई सूराख नहीं बनाए गए थे। दल ने देखा कि टगर डिप के मेन हालेज डिप और दूसरे पूर्वी डिप में भी कुछ कीचड़ (ज्यादा नहीं) था।

4. दल वापिस टगर डिप आ गया और इस सड़क-मार्ग से ऊपर की ओर 26वें लेवल तक गया। यहां से यह पूर्व

की ओर लगभग एक पिल्लर की लंबाई तक गया और सीम के नीचले भाग के निकट में (लगभग 10 लंबे कदमों के द्वारा) ऊपर की ओर ऊपरी भाग के निकट तक गया। सीढ़ियों की तह पर एक विभाजक दरवाजा (स्पष्टतः नए छोर पर) बनाया गया था। इस छोर पर लेबल-गैलरी का नंबर 25वां लेवल था—जोकि पूर्व छोर की ओर के पिल्लरों के अलग-अलग आकार के कारण है। 25वें पूर्व लेवल पर नीचे, इसके डिप के निकट दाईं ओर नीचे गया, जोकि पंक्चर का स्थान था।

पंक्चर वाले स्थान के थोड़ा ऊपर पानी के बहाव की मात्रा को मापने के लिए एक वी नोच (रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना के बाद) फिट किया गया था।

5. दल वापिस 25वें लेवल की ओर बढ़ा, और पूर्व की ओर लगभग तीन पिल्लरों की लंबाई तक गया और उस स्थान से लगभग एक पिल्लर तक पूर्वी क्रास कट हालेज डिप के नीचे की ओर गया जहां दुर्घटना से पूर्व 90 एच. पी. पंप लगाए जाने की रिपोर्ट है। इस पम्प का उद्देश्य यहां बनाए गए संप से जमा हुए पानी को रेत जमा करने के उद्देश्यों के लिए सतह पर (17वें लेवल मेन हालेज डिप के गौण मध्य संप और गड्ढे के तह पर लगे मुख्य पंप द्वारा) फेंकना था।

रिकवरी संक्रिया के दौरान, पंप को इस स्थान से हटा दिया गया। डिप सड़क का तल (पम्प के स्थान और उससे भी आगे तक) रेत से भरा हुआ था, जो जमा पानी से आ रहा था।

6. पंप स्थान को देखने के बाद, दल ने टगर स्थान की ओर गया, टगर डिप के नीचे एक पिल्लर की लंबाई तय करते हुए मेन हालेज डिप के दूसरी और 27वें लेवल तक गया और यात्रा सड़क मार्ग के साथ-साथ पश्चिम और पश्चिम क्रास कट (यात्रा सड़क मार्ग) की ओर बढ़ा। पूर्व से नम्बर 1 पिट तह तक आगे बढ़ा और उसके बाद शैफ्ट बाईपास से नंबर 2 पिट के पूर्व की ओर बढ़ा और गड्ढे तक बढ़कर सतह तक आ गया।

दल सायं लगभग 4.00 बजे नीचे गया था और रात लगभग 8.00 बजे सतह पर वापिस लौटा।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(सी. टी. दिघे)	(जी. एस. मरवाहा)	(के. एन. त्रिवेदी),

परिशिष्ट-ग

जांच न्यायालय-हुरिलाडीह कोयला खान दुर्घटना
सार्वजनिक सूचना

हुरिलाडीह कोयला खान के मालिक, एजेन्ट और प्रबंधक, 14 सितम्बर, 1983 को बिहार राज्य के धनबाद जिले में हुरियाडीह कोयला-खान में हुई दुर्घटना में घायल व्यक्तियों, दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के कानूनी प्रतिनिधियों, संबंधित श्रमिक संघों सहित सभी प्रभावित और संबंधित व्यक्तियों को एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि खान अधिनियम, 1952 के खण्ड 24 उप-खण्ड 1 के अन्तर्गत, भारत सरकार ने इस दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के आदेश दिए हैं और अधिसूचना सं० 11015/8/83-एम. आई दिनांक 22-9-1983 द्वारा मुझे इसकी जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है। मैं एतद्-द्वारा ऐसे संबंधित व्यक्तियों को जो इस जांच में भाग लेना चाहते हैं, अपने लिखित बयान दाखिल करने और गवाहों के नाम, यदि कोई हों तो, उनके पतों सहित भेजने के लिए आमंत्रित करता हूं ताकि मैं इसके बाद तिथियां निर्धारित करके दुर्घटना से संबंधित सभी उपलब्ध प्रमाणों को रिकार्ड कर सकूं। लिखित बयानों की 15 प्रतियां खान सुरक्षा महा-निदेशालय के कार्यालय (ग्राउन्ड फ्लोर पुराना भवन) धनबाद में स्थित जांच न्यायलय के कार्यालय में बृहस्पतिवार, 20 अक्तूबर, 1983 को या इससे पूर्व भजी जा सकती है।

हस्ताक्षर
(सी० टी० दिघे)
अवकाश प्राप्त जज,
बम्बई उच्च न्यायालय
एवं जांच न्यायालय

कैम्प : धनबाद (बिहार)

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 10th September, 1985

S.O. 4666.—In pursuance of Section 27 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby publishes the following report submitted to it under Sub-Section (4) of Section 24 of the said Act, by the Court of Inquiry appointed to hold an inquiry into the causes of and circumstances attending the accident which occurred on the 14th September, 1983, in the Hurriladin Colliery in Dhanbad District, State of Bihar :

[No. N-11015|3|84-MI]
L. K. NARAYANAN, Under Secy.

COURT OF INQUIRY

HURRILADIH COLLIERY ACCIDENT

Chairman	Justice C. T. Dighe, Judge, Bombay High Court (Retd.)
Assessors	Shri G. S. Marwaha, Director, Indian School of Mines, Dhanbad.
	Shri K. N. Trivedi, Organizing Secretary, Indian National Mines Workers' Federation, Dhanbad.

APPEARANCES

Sl. No.	Party	Represented by
1.	Bharat Coking Coal Ltd.	Shri R. Y. Sripurkar, Advocate Shri S. B. Sinha, Advocate
2.	Indian Mine Managers' Association.	Shri U. W. Datey
3.	All India Mine Personnel Association	Shri R. K. Prasad
4.	United Coal Workers' Union/ Indian Mine Workers' Federation/All India Trade Union Congress.	Shri Chinmoy Mukherjee
5.	Indian National Trade Union Congress/Indian National Mine Workers' Federation/Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.	Shri S. Dasgupta Shri L. N. Bhattacharya
6.	Indian National Mine Overmen, Sirdars and Shotfirers' Association.	Shri Janki Mahato
7.	All India Coal Workers' Federation/Colliery Mazdoor Sabha of India/Bihar Colliery Kamgar Union.	Shri S. K. Buxi
8.	Janta Mazdoor Sangh/Hind Mazdoor Sabha.	Shri K. B. Singh

CHAPTER I

INTRODUCTION

1.1 Dhanbad is having a unique position on the coal map of India. In Jharia Coal Field one of the finest qualities of coal exists even after it having been extracted for a number of years. The city's population is well accustomed to the polluted atmosphere surcharged with smoke, hazardous diseases among mine workers as well as minor accidents in mines taking place practically every day. A major accident making all the citizens panic stricken is a rarity. One such accident happened on 14th September, 1983 in Hurriladih Colliery when due to sudden in rush of water in the workings 19 persons were drowned.

1.2. Section 24 of the Mines Act, 1952 empowers the Government to appoint a Court of Inquiry in cases of accidents. Under Section 23, power for investigation of some other accidents, possibly minor in nature, is given to the Chief Inspector or the Director General of Mines' Safety. In this case quite immediately after the accident, on 22nd September, 1983, Government of India issued a Notification, Annexure 'A' to this Report, instituting a formal inquiry into the causes and circumstances attending the accident. I was appointed as the Presiding Officer of this Court of Inquiry, assisted by two Assessors—Shri K. N. Trivedi, Organising Secretary, Indian National Mine Workers' Federation, Dhanbad and Shri G. S. Marwaha, Director, Indian School of Mines.

1.3 On 1st October, 1983 along with the Assessors and the persons representing different Unions as well as in the presence of the representatives of the Management and the Director General of Mines' Safety, I inspected the site of the accident and a detailed note of inspection, Annexure 'B' to this Report, was made. Hurriladih Colliery is located between latitudes 23 43.5' and 23 44.2' North and longitudes 86 23.7' and 86 24.4' East covering an area of 1.6 sq. kms. The Colliery is bounded by Bhagora Colliery on the North, Standard Colliery on the east, Burragarh Colliery on the west and by Jamadoba and Bhutgoria Collieries on the south. It is approximately 12 kms. away from Dhanbad Railway Station.

1.4 From the undisputed facts it is gathered that the entire Jharia coalfield of which this colliery forms a part, is a sedimentary deposit consisting of about 25 coal seams. Hurriladih Colliery falls in South Central Zone of this coalfield and is transversed by igneous intrusions. The area is in a gently undulating ground. A streamlet flows east-west along the southern boundaries of the colliery.

1.5 Out of the 25 coal seams of Jharia coalfield, seams XI to XVIII from bottom have special significance inasmuch as they contain more than 95 per cent of the country's reserves of superior quality metallurgical coal forming hard coke, which is used in steel plants. Hurriladih Colliery now belongs to Bharat Coking Coal Limited (BCCL). It was taken over under the Coking Coal Mines Nationalisation Act, 1972 in a closed condition. Prior to nationalisation the mine belonged to M/s. Equitable Coal Company Limited and was managed by M/s. Macneill & Barry Limited. It was closed on 16-1-1967.

1.6 M/s. Bharat Coking Coal Ltd. was organised as a public sector company on 1st May, 1972 to manage, control and work the coking coal mines taken over on 17-10-71. Subsequently, in January, 1973 most of the coal mines in the country were taken over by the Government. It was on 1st June, 1973 that the Government handed over the entire Jharia coalfield including Hurriladih colliery, to Bharat Coking Coal Ltd.

1.7 The accident resulting in the taking away of the lives of 19 persons took place in the early hours of 14th September, 1983 at about 6 a.m. It had occurred underground in the XIV seam due to sudden in rush of water. The third shift was working in the development district. The workers were trapped and drowned in the area below the 20th level. The on-rush of water was caused by sudden puncture of the parting between the roof of the 3rd dip off 29th east level of the Main dip and the floor of the 3rd dip gallery off 27th level west of the East Cross-cut Main dip. The parting appeared to be so thin that possibly because of water pressure it burst causing the large water column overhead, differently estimated between 7 lacs to 9 lacs gallons, getting spread in different galleries.

1.8 Almost every concerned officer of the colliery and in addition, officials of allied institutions rushed to the spot for taking part in rescue operations. The area was dewatered by using large scale pumping. The first two pumps were started within 10 hours on 14th itself and all the 9 pumps were put into operation by the morning of 15th September, 1983.

1.9 The 29th level east of Main dip was cleared of water by mid-day of 16th September, 1983. The dewatering of dip

galleries continued and the first four bodies were recovered by about 6 a.m. on 17th September, 1983 from the Main dip. By mid-day of 17th September, 1983 four more bodies were recovered followed by the recovery of two more bodies by the evening of that day. Thus, from the main dip itself 10 dead bodies came to be recovered. The dewatering of east companion dip (tugger dip) continued and during the night of 17th September, 1983 another two bodies were located in that dip some time in the morning of 18th September, 1983. Remaining seven bodies were recovered from that place in the evening of 18th September, 1983.

1.10 Names of those who died and the place where their bodies were recovered are found on the plan (exh. 19) prepared by the Surveyor of the Office of the Director General of Mines' Safety. They are as follows :—

Sr. No.	Name of deceased person	Designation
1	2	3
	Main dip on 17-9-1983	
1.	Bhibhuti Bouri	Loader
2.	Ananta Mahato	Loader
3.	Madhu Bouri	Loader (working as bailing mazdoor)
4.	Mahabir Turi	Pump Operator
5.	Akhlu Bouri	Loader
6.	Sukhdeo Bouri	Loader
7.	Panchu Mahato	Loader
8.	Ananta Modi	Loader
9.	Subhas Roy	Loader
10.	Anil Bouri	Loader
	Tugger dip on 18-9-1983	
11.	Bachan Chamar	Loader
12.	Sonshahai Dhobi	Pump Operator
13.	Dharmu Chouhan	Mining Sirdar
14.	Ramji Chamar	Loader
15.	Bhangi Chamar	Loader
16.	Gurufekan Sao	Loader
17	Sanu Ram	Loader
18.	Mushafir Harijan	Loader
19.	Kali Sao	Loader

CHAPTER II

INSPECTION NOTE, PUBLIC NOTICE AND PARTIES TO THE PROCEEDINGS

2.1 The accident had occurred in XIV seam which is about 30-foot thick. It has a dip of about 1 in 8 to south 49 west. The inspecting party headed by me, went down No. 2 pit travelling east to the Main dip and went beyond the 29th level where ten bodies were reportedly recovered. At that time the 29th level was free of water. Coming back to the 29th level and going by the companion dip for about 40 feet the party noticed the gallery blocked with empty tubs. The party could not proceed further, but with the help of cap lamps they could see the top of a thick prop near the end of the dip.

2.2 Coming back to the 29th level, the group proceeded to the spot of puncture. It was noticed in a roof, a little to the dip side on the junction of 29th level and 3rd east dip. The parting appeared only a foot or so in thickness. A couple of shot holes were seen drilled in the 3rd east dip face and 6-7 sockets of shot holes were observed in the face of 29th level east. These were reportely not advance bore holes. A little muck was seen in the main haulage dip as well as in the tugger dip and the 2nd East companion dip.

2.3 Coming back to the tugger dip and travelling via the roadway to the 26th level, the group went to the top section. A littice door had been freshly constructed at the bottom of the steps. Proceeding to the dip end the site of puncture was visible. The group then walked back to the 25th level travelling east, went down the east cross-cut haulage dip and saw the site where reportedly a 90 horse power (h.p) pump was installed before the accident. The purpose of this pump was to pump out stowing water from the sump to the 17th level, from there it was pumped to the main sump at the pit bottom.

PUBLIC NOTICE

2.4 Immediately after completion of the inspection, on the very day, steps were taken to issue public notice, Annexure 'C' to this Report, inviting all persons affected and concerned in the accident together with legal representatives of those who died in the accident and the labour unions representing the employees in Hurriladih Colliery, to take part in the Inquiry by filing written statements and giving names of witnesses, if any. The written statements were to be submitted in the Office of the Court of Inquiry established in Dhanbad.

PARTIES

2.5 Audience was given to the parties genuinely concerned with the Inquiry who could contribute to the debate concerning the cause of accident as well as the circumstances leading to the accident. In all eight parties addressed the Court of Inquiry. Party No. 1 is the Management of Bharat Coking Coal Limited. Party No. 2 is the Indian Mine Managers' Association, shortly called 'IMMA'. Party No. 3 is All India Mining Personnel Association, shortly called 'AIMPA'. All these three parties represent the view point of the Management. As far as workers are concerned, unions affiliated to All India unions were allowed to conduct the proceedings only in the name of one party. Thus, party No. 4 is All India Trade Union Congress (AITUC), also representing United Coal Workers' Union and Indian Mine Workers' Federation. Party No. 5 is Indian National Trade Union Congress (INTUC) together with Indian National Mine Workers' Federation and Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh. Party No. 6 is Indian National Mines Overmen, Sirdars and Shotfirers' Association (INMOSSA) Party No. 7 is the Centre of Indian Trade Unions (CITU) with the affiliated association—Indian Coal Workers' Federation, Colliery Mazdoor Sabha of India and Bihar Colliery Kamgar Union. Party No. 8 is Janta Mazdoor Sangh affiliated to Hind Mazdoor Sabha.

2.6 In the present proceedings of the Court of Inquiry, it will be found that DGMS has not become a party. I am told that this is not for the first time that the DGMS has no association with the enquiry as a party. Much discomfort was noticed among the different unions representing the employees as to why the DGMS did not come forward to take part in the proceedings of the Court of Inquiry. There was, however, no material to hold that this was mala fide or in connivance with the Management. It was apparent that DGMS had adopted a neutral role, rendering all assistance to the Court by producing notes of evidence recorded, plans and documents seized and the plans and sections prepared by its departmental surveyors after the accident illustrating the accident in pursuance of the statutory duties of DGMS officers under section 23 of the Mines Act.

2.7 This enquiry was instituted even before the DGMS had made any formal report under section 23 of the Mines Act declaring any violation of the regulations or of the provision of law. After the Court of Enquiry set up under section 24 of the Mines Act started functioning, such report is redundant. It is said, when any report happened to be made before the appointment of a Court of Inquiry that had become a target of attack either from the Management side or from workers' unions depending upon the findings and conclusions favouring one party or the other. If the DGMS held the Management officials responsible, the Management tried to pick holes in the working of DGMS to save their skin. Similarly, when the findings absolved the Management of their responsibility, they were open to the charge of connivance with mine Management from the workers' unions. This helped diverting the attention of the parties from determining the cause and circumstances leading to the accident. In the process, the root cause of the accident sometimes got clouded. Even appreciating this line or

reasoning and appreciating the co-operation given by the organisation in the present proceedings the Court consider, that DGMS may also examine in each case submitting before a Court of Inquiry set up under section 24 of the Mines Act, other documents or other material as might be available in the previous records of the Office or within the knowledge of the DGMS that could possibly throw additional light for due appreciation of the cause of and circumstances attending the accident in proper perspective. That would require intelligent interest in the proceedings and would obviate any erroneous impression regarding the functions of DGMS.

CHAPTER III
THE KEY PLAN AND OTHER PLANS

3.1 Before taking a resume of the pleadings filed on behalf of the parties taking part in the proceeding, it would be necessary to make a reference to the different types of plans produced in this case. As soon as an accident takes place, it is the duty of the Directorate General of Mines' Safety to visit the spot and to attach documents including plans which are likely to be useful for determining the cause of accident. Such a list of documents taken possession of is given at exhibits 12 and 13 of the proceedings. The office of the Director General of Mines' Safety has also prepared some important plans either from some of the plans in the list or by actual surveying. Exhibit 14 in the proceedings is a working plan copied from the mounted paper plan now exhibited at Exh. 62. Exhibit 15 is a rescue plan. Exhibit 16 is a sectionalisation plan. Exhibit 17 is the underground drainage plan. Exhibit 18 is the working plan on tracing paper. Exhibits 19 and 19A are the plans prepared by the Office of the Director General of Mines' Safety after the accident. The sections are shown in Exh. 19A, while Exh. 19AA is the key plan a part of which near the accident has been resurveyed and plotted by the DGMS officials after the accident. The portion involved in the accident was very thoroughly surveyed and looked into for preparing Exh. 19. Exh. 19 is a detailed part plan illustrating the in-rush of water. Its reduced copy is annexed to this Report serving as a ready reference, marked Annexure 'D' to this Report. Similarly, a copy of the key plan, Exh. 19AA, is also important for understanding the discussion that is to take place. It is the key plan of XIV seam workings. Its reduced copy is Annexure 'F' to this Report.

3.2 Exh. 42 is the plan prepared by the management after the accident for showing the errors in the earlier plans. It is, however, in outlines and cannot be used without the tracing of the plan, Exh. 62. Exh. 43 is another working plan of 1983. Ehs. 63 and 64 are hand plans. Exh. 67 is the abandoned mine plan taken from the Office of the Director General of Mines' Safety. Exh. 70 is the plan prepared and submitted by the management while seeking permission for depillaring panel E of the XIV seam. Exh. 80 is the ventilation plan. Exh. 89 is the plan attached to the application made for allowing the management to cross under the District Board road site. Exh. 90 is the water danger plan. Exh. 101 is the plan prepared at the time of taking permission for solid blasting.

3.3 Although at various places in the discussion reference to different levels or dips would be made, at this introductory stage it may be of use to have a few observations based on the key plan, Exh. 19AA. The entire XIV seam shows different workings divided into panels A, B. C. D and E. We are in this inquiry more concerned with panel 'E', side-lined red in Exh. 19AA and a portion to the west which is east of the Main dip. Panel 'E' has two sub-districts, depillaring district to the east and a development district to the west. On the east side there is a cross cut and panel 'E' is situated both on the east side as well as the west side of the Main dip of that cross cut. The depillaring area lies to the east of this cross cut Main dip, while the spot of accident is towards the west of this east cross cut Main dip, though lying to the east of the Main dip. The accident has occurred in the development district which is situated to the east of the Main dip and west of the east cross cut. Some reference to the old workings on the west side of the Main dip have occurred in the evidence. but we are not concerned with that location. There may or may not be a good reason for naming one and the same level differently but there is no dispute that level no. 26 lying to the east of the Main dip, joins with level No. 25 lying to the west of the east cross-cut. In fact, it is one and the same level, but when we view it in co-relation with the cross cut, it has been called as 25th level west, whereas when we view it in co-relation with the Main dip, it is the 26th level east. The spot of the accident is seen as a red dot on the plan, Exh. 19AA. It is in the 3rd dip of 27th level west cross cut overlying the 3rd dip of the 29th level east of Main dip. Going to the dip side from the aforesaid 26th level, we find the 27th level east progressing from the Main dip to the companion tugger dip, from there to the 2nd dip extending a little further, but not getting connected with the lower level. The 27th level east has further progressed to the east, but not connected with the corresponding 26th level west of east cross cut. So far as the 28th level lying to the east of the Main dip is concerned, its progress stops with the companion dip, i.e. the tugger dip, although there is some extension eastwards which has been sometimes referred to in the evidence as the extension of the 28th level. However the corresponding 27th level west of the east cross cut has come westwards to have a fourth dip together with slight extension to the west of the level. Then further to the dip side is the 29th level having a dipward progress in the Main dip, a dipward progress in the companion dip and a dipward progress in the 2nd dip. The drivage of the companion dip is longer than that of the Main dip. The 1st companion dip has a slight eastward drivage to form the 30th level, but remaining only as small extension. The 2nd dip of the 29th level east extends substantially. The 3rd dip of the 29th level east is the offending gallery in which water rushed from the overlying 3rd dip of the 27th level west of east cross cut when the parting collapsed.

3.4 Looking from the cross cut dip side, the 25th level west has joined with the 26th level east of the Main dip as mentioned above and the 26th level west has joined with the 3rd dip of the 25th level west. So far as the 27th level west of the east cross cut is concerned, it has joined with the 3rd dip of the 26th level west and has also progressed dipwards to form the 3rd dip. This is the overlying offending gallery in which water existed as it was a part of the sump formed by the adjoining galleries. The sump was used to receive and provide for stowing water. The 27th level west has progressed further to have a 4th dip and has also extended westward Plan, Exh. 19, would show that the 29th level east has a twist towards rise (North) side. Evidence shows that the working on the east level face of this 29th level was stopped, but the dip face progress continued and it is while continuing this dipward progress that the water just above in the 3rd dip of the 27th level west of east cross cut, rushed inside through a collapse of the parting stone and spread in the dipside workings, drowning the persons working there.

CHAPTER IV

PLEADINGS AND PROCEDURE FOLLOWED

4.1 On behalf of the Management, statement is given as at Exh. 5. While speaking about the geology of the mine it has been stated in paragraph 3.4 and the following of the written statement that the entire zone is known for high water percolation in the workings of the mines. There is heavy percolation throughout the year and in particular during and immediately after the monsoon period. It is said that the colliery continued to have heavy seepage of water. It is pointed out that in pre-nationalisation days coal was extracted by caving method so that the stratum above was allowed to cave in, causing subsidence on the surface. That acts as a catchment zone during the monsoon and the water runs almost straight into the mines. The area of Hurriladih Colliery is said to be full of intrusions, most of which are igneous in nature. In fact, several complete seams like XV and XIII seams, have been burnt to form Jhama. The XI and XII seams are to also affected by these intrusions.

4.2 According to the Management's statement in paragraph 4.1 onwards. at the time of nationalisation, the Company inherited these coal seams in largely depleted condition. Most of the seams had been worked by caving method causing huge loss of coal. Seams XI to XVIII contain reserve of superior quality metallurgical coal in our country. XIV and XV seams perhaps contain the best quality metallur-

gical coal in India. The XV seam in Hurriladih is Jhama and XIV seam was standing on pillars. With a view to exploiting the balance coal, which was not obtainable by ;the XIV seam had a 'direct feed' quality coal. Consequently caving method used earlier, the Company decided to re-open that was standing on pillars. Records show that the working in the XIV seam was discontinued as long back as in 1933 and since then the seam had been flooded with water. XIV seam had been developed upto 25th level at the time of closure. It is stated that because of its recent closure and comparatively better knowledge of the conditions at the time of the closure, re-opening of Hurriladih Colliery appeared an attractive proposition, particularly when the XIV seam had a 'direct feed' quality coal. Consequently, BCCL prepared a report for re-opening in the year 1974. That report showed that in the XIV seam reserves were to the tune of 1.3 million tonnes standing on pillars and about 7 million tonnes in the XI seam, but the latter seam was decided to be included in Bhalgora project. The Hurriladih colliery was left to liquidate the XIV seam reserves standing on pillars as well as the small portion of serve which was virgin. It was also considered that without liquidating the XIV seam, coal from the lower XI seam could not be extracted by long-wall method with full mechanisation as proposed under the 1974 report.

4.3 By April, 1975 preliminary operations like fittings of winders, etc. in the shafts were completed. Dewatering operation of the XIV seam was completed towards the end of 1975 and work was taken in hand to support roadways, etc. The dip side development started in 1976 and continued till the year 1978. During this development, property from 20th to below 27th level towards east of the Main dip area was developed. However, difficulties were encountered. On and from September, 1978 the dip side area of the XIV seam was drowned and the development work was halted. They then decided to replace the development production with depillaring district in 'E' panel. After dewatering it was found that the roof here was very bad and needed extensive support. That was done by the recently developed rope stitching technique and certain lengths of roadways were also supported by brick wall. By the end of 1981 development of west side virgin area was completed. By 1982 only a small portion in the middle eastern property on the dip side was left for development. In order to obtain good percentage of extraction, it was necessary to fill the areas from which coal was extracted by hydraulic sand stowing. In this process sand is sent into the mine by mixing it with water at surface. The mixture flows through a pipe to the area of extraction. Temporary barriers of timber and bamboo matting area erected to retain sand after water percolates out through the bamboo matting. The percolated water flows down and is collected at the dip side from where it is pumped back to the surface for use again in the process of sand stowing. Depillaring permission was obtained from the Director General of Mines' Safety by the letter dated 10th August, 1978 and at the time of the accident final extraction was going on between 18th and 23rd levels and between 1st and 9th dips east of the Main cross cut dip. However, it is said that a small portion of the panel on the dip side was lying undeveloped and it was necessary to develop the same to enable complete extraction of the panel. This development was being done and that is the area where the accident took place.

4.4 As regards stowing water, it is said that water went down the 2nd dip of cross cut dip before it collected in the Main dip workings below the 27th level east. A 90 H.P. of 390 feet head and 400 gpm capacity was installed in the east cross cut main dip above the 27th level to pump out this water to the 17th level mid-sump from where it was repumped to pit bottom sump where two pumps of 275 H.P. and 150 H.P. were employed.

4.5 While emphasizing that the concerned officers were sufficiently senior and experienced, it is said that no pains were spared to see that the working continued free from danger including danger from any source of water, etc. In this connection it is said that BCCL is a three-tier organisation. The Headquarters' decides policy matters, the 'area' level provides coordination and support and the 'colliery' level is the production centre. Each area is headed by an experienced senior mining engineer designated as General Manager, having 5 to 9 mines under his jurisdiction. He is assisted by several senior executives for various functions. The collieries themselves are headed by Agents/Superintendents who are Agents for the purpose of the Mines Act, 1952. Under the Agent, there is a senior mining engineer designated as Colliery Manager under the Mines Act, 1952. Executives in the discipline of engineering and personnel and Assistant Managers, Safety Officer and Ventilation Officers are posted to carry out the managing operations effectively. For the two district working in the XIV seam there were 9 overmen and 21 mining sirdars and shotfirers to look after and supervise mining operations underground over the three shifts. There was a surveyor assisted by another surveyor and three chainmen to carry out all the survey connected with the colliery at underground and at surface. He was also given assistance from the area survey officer in respect of survey matters. There is also an Internal Safety Organisation at the headquarters headed by General Manager (Safety) who is assisted by senior executives of mining and electrical/mechanical disciplines.

4.6 It is said that after the accident a thorough examination by a senior officer was undertaken to search for the likely survivors, the likely source of water, the position of water levels, etc. After the 29th level east was cleared of water, a puncture in the roof of the 3rd dip off the 29th level east of Main dip was noticed through which water came into the dip side workings. The Management had appointed their own committee to inquire into the accident, but in view of the appointment of the Court of Inquiry by the Government that inquiry was not proceeded with. According to the preliminary investigations, it was found that accumulated water in the lodgement of stowing water caused in-rush after a puncture got established accidentally. The local colliery management had left a barrier of solid coal of sufficient thickness against a known patch of water (lodgement) on the basis of the survey plans available to them. In some of the plans, the offending old dip gallery has been shown in firm lines, giving the impression that the workings were surveyed and were away from the 29th level which, in fact, after the accident and dewatering of the workings, has been found to be incorrect.

4.7 Party No. 2, Indian Mine Managers' Association, filed their written statement at Exh. 7. It is said that this Association is a body of professional mine managers with over 61 years' standing. It says that the accident of 14th September, 1983 was a typical one resulting from sudden movement of water in underground workings. It then refers to the water going down the mine during monsoon and also otherwise, and speaks about the necessity of water reservoirs of capacity between 10,000 gallons to a few lakh gallons. It is said that some of these reservoirs are made in a planned way to act as sumps for pumping installations, while other reservoirs result due to mining operations themselves. Sudden flooding is said to be very rare when reservoirs are planned. The Jharia coalfield is said to be a saucer-shaped basin type structure so that the strata dip from all sides towards the centre. The sedimentary stratum forming the coal belt is very highly porous and affords easy movement of water. Due to the saucer shape the water has a natural tendency to move towards the centre so that the mines in the centre area of the basin get heavy seepage. Hurriladih colliery is said to be situated near the centre of this basin. Heavy pumping all round the year becomes necessary. In addition, it is said that seepage problems is aggravated where seams at shallower depths are extracted by caving method, so that voids are created without those getting filled up and resulting in subsidence on surface. This subsidence causes breaking up of the rock, appearance of cracks on the ground and lowering of general level so that more water percolated down. In Hurriladih the upper seams were caved long ago.

4.8 According to IMMA, the post-accident inspection of the site revealed that water entered the dip workings through a connection between the 2nd dip east of tugger dip of the 29th level and an extension of the 3rd dip off 27th level which perhaps was not known. The written statement observed that calculation of the volume of roadways in the area of sump shows that the sump had adequate capacity to hold much more than 70,000 gallons of water which entered the mine on a normal day due to stowing opera-

tions. The pump had adequate capacity to deal with this quantity of water in less than half a shift of operation. A surprise is expressed how half a million gallons of water, which is reported to have filled up the dip side workings, could come from the area. The sump below the 27th level was used to collect stowing water only. In conclusion, therefore, it is said that the evidence available does not clearly bring out the cause and circumstances leading to the unfortunate accident.

4.9 Party No. 3, All India Mining Personnel Association, which is also an organisation catering to a section of the Management, has filed its written statement at Exh. 23. Curiously enough, figures of death by road accidents have been given. Mining is said to be a hazardous profession and it is said that the present accident should be viewed in the context of other accidents which cause far more casualties. A list of four further accidents in mines caused by inundations subsequent to 14-9-1983 viz. 2-10-1983, 10-10-1983, 25-10-1983 and on an undated day at east Bhugatdih colliery, is given and it is suggested that the accident at Hurriladih colliery should be examined in line with the above-mentioned and such other cases and not in isolation. It is further pointed out that the Coal Mines Regulations, 1957 and the circulars issued by the Directorate General of Mines' Safety are based on the Mines Act, 1952, which was drafted on the lines of the British Mining Regulations, but the geological and mining environmental conditions of Jharia coalfield differ widely from the coalfields in the U.K. so that the relevance of those rules and circulars become debatable. It is further said that coal production is done by taking calculated risk and so even knowingly violating the Coal Mines Regulations. So long as nothing happens, it does not attract public attention, but once an accident involving life occurs, the Mine Manager and the members of the supervisory staff are condemned for their act of working the mine to produce coal for nation. While listing the causes for the accident, it is said that old plans maintained by the collieries, though certified to be correct, cannot be accepted as correct because prior to nationalisation coal mines had no suitable and standard survey instruments, nor full time surveyors. Limits of errors as specified in the Directorate General of Mines' Safety's circulars were not achieved. Plans were liable to shrinkage. There were to means to know the underground erosion, fall of roof, heaving of floor, sliding of strata along fault plans, no means to know natural changes in the vicinity and it is not possible to make fresh survey with existing survey instruments of all old galleries. Thus, without pinpointing any special cause, a general case, more for condonation of the faults of the Management, appears to have been made.

4.10 At Exh. 9 is the written statement given by party No. 4, United Coal Workers' Union, Indian Mine Workers' Federation and All India Trade Union Congress. After initially speaking about what happened in the accident, it is said that the colliery management was knowingly using the particular dip gallery for the purpose of stowing water. This establishes that the Management had full knowledge about the extent of drivage of the said dip gallery and the fact that the same was waterlogged. It is also pointed out that the parting left was not at all adequate and the Management failed to observe the primary duty to ensure safety of the mine and mine workers against any danger of inundation, particularly in places where water is allowed to accumulate in huge quantity. It is said that the Management knowingly put the workers in dangerous place without taking the statutory safety measures by storing water just above the 29th level where blasting and coal-getting operations were being carried on. It has been stated that some time before the accident there was heavy seepage of cold water from the roof of the gallery at the 29th level. The Management ignored indication of danger from seepage and did not take any steps to assess the thickness of the parting by driving advance bore holes. BCCL ventures to re-start the mining operations without taking necessary safety measures. As the mine was closed for long, it was incumbent on the Management as well as the Office of the Director General of Mines' Safety to undertake independent and thorough survey of the old working before restarting mining operations. Consequently it is said that the Management was fully responsible for the fatal accident which was caused due to utter negligence of the safety provisions under the Act and the Regulations. It is also said that the Department of the Director General of Mines' Safety is also responsible, as evidently it failed to exercise proper vigilance by conducting independent survey before granting permission to the Management and also in course of drivage of the 29th level.

4.11 Party No. 5, INTUC, with its allied Associations, has filed a written statement, Exh. 10. It is said that the accident was due to inrush of about 15 lakh gallons of water into the working places through a puncture point of 8 feet diameter. It says that after the accident it was revealed that due to the defective mine working/planning, the 2nd companion dip from the Main dip at the 27th level east was found driven to about 190 feet which is beyond the 29th level east face where puncture took place. The possible reasons for the puncture are given as (i) increase in the accumulation of water in the sump; (ii) vibrations caused by the blasting done in the dip faces; (iii) blasting done either on the 29th level east face; and (iv) knowing the existence of water nobody cared to inspect the site and know about the actual position of the dip gallery before driving any gallery below the same, i.e. along the 29th level east. It is, therefore, said that the Management has violated C.M.R. 127 as well as C.M.R. 64 as plans were not maintained as per the Regulations. They have also offered their suggestion to amend C.M.R. 127(3), and for appointment of Safety Officer in each colliery as well as workmen's inspector.

4.12 Party no. 6, Indian National Mine Overmen, Sirdars and Shotfirers' Association, filed its written statement at exh. 11. Mostly it speaks about the plans given to the Sirdar and overmen not showing all the things clearly. The position of galleries was not accurately shown. It is said that it is a matter of thinking that the 27th level east was stopped after development of two pillars and 28th level, east was developed for only one pillar from the Main dip in west section, but the 29th level and 30th level east were being developed regularly. It is thus suggested that the Management was possibly aware of the water lodgement near about and yet they had not taken adequate precautions while progressing the drivages in the 29th level. The plan was wrong in showing wrong projections and the Management had violated Regulations 64, 65, 104, 126 and 127. It assures the Court that the duties done by overmen, mining sirdar, shotfirers and other workers were very sincere and proper.

4.13 On behalf of the association affiliated to CITU, the written statement filed is at Exh. 8. By way of introduction it is said that in spite of different accidents and in spite of the reports of Courts of Inquiry constituted after the Jitpur, Chasnala, Kesbargara, Sudamdih and Khas Nirsa disasters, the recommendations made have never been implemented. It is only when there is loss of precious human life that attention is focussed. Accident in question could easily have been averted if the existing safety statutes and the recommendations made by the earlier Courts of Inquiry were implemented. While mentioning about the accident, it is said that the workers present at the time inside the mine had stated that water had been percolating from the roof of the working place some days before the inundation took place and the matter was reported to the superiors but no one cared to pay any heed. The workers claimed that seepage of water had always been excessive, particularly while driving the 29th level. It is thus said to be a man-made disaster. There was, in fact, no excessive rainfall and there were no floods of river or nala so that the water had accumulated in the cavities of the mine above the level 29 which was under the clear knowledge of the Management. It is said that the possibility of the plans not showing the correct depth of the gallery of the earlier levels could not be ruled out. The force with which the water entered lends support to the theory that the water must have accumulated upto much higher levels. Inundation was therefore not caused by geological reasons. Rules relating to mining around waterlogged area were not observed. CMR 127 is quoted to show how the Management had not been observing it. It is further stated that faulty ventilation system is also one of the numerous allegations made by the workers, which is ignored, thus showing the negligent attitude adopted by the Management towards safety. As regards the DGMS Office, it is said that the condition of the organisation is pathetic which shows callousness on the part of the Government towards safety in the most vital sector of our economy. When there are about 500 coal mines and 3600 non-coal mines, the total staff under the DGMS, according to the information, is only 844, including Class I and Class II Officers, for

inspection, head office work and Class III and Class IV employees. While the mine should be examined from the point of safety at least once in a quarter, the present staff is inadequate to inspect it even once a year. This very mine was not inspected by the DGMS Officers for the last six months due to shortage of staff. In listing the factors responsible for the disaster, it is said that there was gross negligence towards and non-implementation of the recommendations made by the earlier Courts, criminal violation of the Coal Mines Regulations, in particular Coal Mines Regulation 127, negligent and reckless working in the mines and inadequate supervision by the officials.

4.14 Exh. 6 includes two statements, one given by Janta Mazdoor Sangh and the other given by Koyala Ispat Mazdoor Panchayat and Hind Mazdoor Sabha, Bihar which are almost in similar terms. According to them, no notice or any prior information was given regarding any danger in the mine to the workers in the night shift. No care was taken to make daily inspection of the mines and the plan was not carefully studied. BCCL reopened the colliery without making effective safety regulations. The work was started in great hurry. The gross negligence of the Mines Department has greatly contributed to the fatal accident. For long time the thickness of the roof was quite inadequate. There was heavy percolation of water prior to the accident, which subsequently erodded the thickness, but this was all ignored. It is said that it was within the knowledge of the Management that more than 120 million gallons was stored in the upper seam along with sand and still they continued to work without taking any precaution. It is said that according to their information, the pump was out of order for 2-3 days before the accident and even when the workers reported to the Management to take steps for dewatering the upper seam, the Management failed to take any precaution or heed the advice. This organisation also states that the office of the Director General of Mines' Safety suffers from inadequate staff and inadequate remuneration and other facilities, as such there are no frequent inspections of the mines. While listing the causes, it is said that there was gross negligence in not observing the provisions of Coal Mines Regulations. Reckless working of the mine, inadequate supervision by the officials of the Department of Mines' Safety, non-implementation of the recommendations made by earlier Courts of inquiry, ignoring the complaints and suggestions of workers, not having proper survey of the working faces and failure to make bore holes were the factors that caused the accident.

4.15 At Exh. 24 is a rejoinder filed by the BCCL Management. In reference to the allegations that prior caution was not given to the workers, it is stated that no such danger was apprehended. They deny that the mine was not being inspected regularly. They deny that BCCL reopened the colliery without observing the safety regulations or that the mine was started in great hurry, or that there was heavy percolation or any seepage of water prior to the accident. It is said that the 27th and 28th levels east of the Main dip have been driven as per the projection drawn on the mine's plan. The allegations of non-implementation of the recommendations of the earlier Courts of Inquiry are denied. The Management has not suppressed anything. In particular, it is denied that in-rush of water was of 15 lakh gallons. The drivage of the 29th east gallery was stopped much before the accident, but the 3rd dip was being driven where accidentally the connection got established. They submit that coal barrier of adequate thickness was left between the 29th level east and the rise side stowing sump on the basis of the statutory mine plan available at the mines. According to them, CMR 127 is not attracted and therefore no permission of the Director General of Mines' Safety was necessary.

4.16 Even the All India Mining Personnel Association found it fit to file a rejoinder vide Exh. 25, stating that CMR 127 was not attracted, and that sufficient and adequate precaution to deal with underground water by three-stage pumping was taken in relation to Hurriladih colliery. It is said that in all old mines fresh survey of all the workings is not possible due to roof falls, water accumulation, mud and muck deposits, etc. It is denied that in mining accidents the responsibility lies with the mining engineer and the benefit of doubt goes to the prosecution. On no occasion any doubt was expressed about the length of drivage of the fateful dip gallery. It is not possible in old mines to dewater each gallery to clean muck and falls for resurvey. Reliance on old plans has therefore to be kept. It is also remarked that the Directorate General of Mines Safety are playing safe for themselves.

4.17 Rejoinder filed by party no. 4, at Exh. 27, shows that there was failure on the part of the Management to observe Regulation 65 dealing with accuracy of plans. It is pointed out that fresh detailed survey of all workings, including those that are inaccessible or waterlogged, was necessary. Spot levels have not been shown on the concerned plan. The plan is shown updated upto 30-6-1983, but, in fact, it was not so. The 27th level of the cross cut has been surveyed. In the west, the Main dip to the 26th level has already been shown. The offending 29th east level off the Main dip has not been shown at all, though it is now found that the puncture took place while working the 29th east level. The non-showing of the 29th level indicates that this dip was probably waterlogged at the time of survey. It is a pity that it never occurred to the higher Management and the Directorate General of Mines' Safety that the dotted dip gallery might have been driven much further to the dip than what has been shown in the working plan. Had the plan been maintained upto-date, it would have been clear that the drivage of the 29th east level could not be done beyond the tugger dip without advance bore holes as stipulated under CMR 127. The Management thus failed to foresee the danger of inundation and there was negligence to abide by the Regulations and circulars in this regard. Thus, it is said that the accident occurred because of this failure as well as the non-observance of other Coal Mines Regulations, and the plans maintained not having been upto-date, their accuracy remaining open to question.

4.18 Party No. 6 in their rejoinder at Exh. 28, has highlighted the fact that the accident did not occur due to geological disturbances. It is said that the statement filed by BCCL is almost a formality. In regard to the statement filed by CITU, it is said that it is vague. According to them, percolation of water was usual and normal. It is emphasized that no worker would risk his life and fail to report any percolation keeping the life of himself and his colleagues in danger. It is pointed out that the mining Sirdar Dharmu Chauhan, has lost his own life. It is stated that persons like him would not have failed to make report in case abnormal percolation was actually seen.

PROCEDURE FOLLOWED

4.19 After receiving the written statements, the method followed for recording evidence was asking the parties and their witnesses to file affidavits. These affidavits were to be filed simultaneously so as to exclude the scope of any witness or any party shaping his case after studying the affidavit filed by any other witness or party. It appears that while following this method, the possibility of shift in pleadings was minimised and the tendency to give evidence after looking into the version of others was curbed However, on receipt of the affidavits, a further chance was given to the parties to put in additional affidavits for further explaining their statements in the light of the affidavits filed by others. No additional affidavits were however actually received excepting in the case of two witnesses of the Management which were for explaining the survey made by the Management subsequent to the date of accident. That survey was made after the Court of Inquiry was instituted without intimating the Court about it. But no one has objected to this. The survey indicates the inaccuracy in old plan.

4.20 The affidavits so received were treated as examination-in-chief at the time of hearing. In other words, as soon as a witness entered in the box, he was asked whether the contents of the affidavit were correct and upon his admitting the contents, he was immediately offered for cross-examination.

4.21 Again the entire proceedings were viewed as between two opposing parties. One propounding the view point of the Management and the other opposing that view point. Therefore, at the time of cross-examination, the witnesses of the Management were first offered for cross-examination to those Unions who sided with the Management and thereafter the

Unions representing the employees took their turn. Similarly, when the witness was offered by the Union siding with the Management, between them the cross-examination was first complete and thereafter the witness was handed over to the opposing Unions representing employees. Only one Union, namely Indian National Mine Overmen & Sirdars' Association examined one witness. In that case the cross-examination was first restricted to the group of the Unions representing employees and the witness was thereafter offered to the other side.

CHAPTER-V

ORAL EVIDENCE

5.1 The Management was directed to lead evidence. In all nine witnesses have been examined by them. On behalf of the Indian Mining Personnel Association, siding with the Management, two more witnesses have been examined, and one employee was examined by the Employees' Association represented by the Indian National Mine Overmen, Sirdars and Shotfirers' Association. This was the all-told evidence in the case. Although there were several other unions taking part, they restricted themselves to cross-examining these witnesses. Therefore, the Court decided to examine the Manager and Surveyor of the old times when the relevant levels were driven and also the pump khalashi who was operating the pump at the time of the accident. Two senior officers and one surveyor of DGMS who had immediately gone to the spot, were also examined as Court witnesses. In all there were seven such witnesses.

5.2 Witnesses nos. 2, 3 and 4 on behalf of the Management are the loader, driller and shotfirer who had worked at the face some time immediately before the accident. Witness No. 1 is the Survey Officer who prepared the plan. Exh. 42, after the accident, locating the defects in the old plan which it is said, misled the Management in believing that they were at safe distance from water. They also examined the Electrical Engineer, the Executive Engineer, the Manager, the concerned Surveyor and the Agent as witness Nos. 5 to 9 respectively. It would be useful to have a brief summary of the evidence given by these witnesses before discussing their implications or finding out the concerted picture emerging out of it.

WITNESSES FOR MANAGEMENT

5.3 Witness no. 1 Surveyor Sunil Bhattacharjee, speaks about the closed circuit survey carried out of the mine working involved in the accident with coordinates of the XIV seam given to them by the Indian School of Mines, Dhanbad. In the result of this resurvey, the position of the 29th level in relation to the Main dip area was as per the plan available, but the area of the 27th level on the eastern side showed dipward shift of approximately 45 feet south of its actual position. According to this witness, the dotted line shown on the plan means that the extent of the gallery is known but its details are unknown.

5.4 Witness no. 2, Ghansham Mandal, a loader, was working on 13-9-1983 in the 3rd shift lasting from 1 a.m. to 9 a.m. His gang loaded 7 tubs from the 29th level east upto 4 p.m. When more work was asked for, Sirdar late Dharmu Chouhan advised his gang that roof condition in the 3rd dip was not good and directed them to the companion dip. One of his colleagues, Kalisha, went with Dharmu Chouhan to the tugger dip. A fencing was put between the 2nd and 3rd dips of the 29th level at about 5 or 5.30 a.m. Some time afterwards the witness had to go to pick up his basket and shovel from the 3rd dip face, but as he proceeded from the dip junction, he heard an unusual cracking sound and a source of water flowing out. He, therefore, shouted "Bhago, Bhago" and himself ran to safety along with others. He assures that when he went down the mine, there was no seepage of water noticed by him and the sirdar had tested the roof. According to him, the 29th level east was stopped 4-5 days before the accident.

5.5 The driller, Hari Pandit, witness No. 3 or the Management, had gone to the 3rd dip face of the 29th level east for drilling shot holes on 13-9-1983 in the third shift. But he returned without drilling as some coal was in balance. He went to other faces. Some time afterwards as per the orders of Dharmu Chouhan, six shot holes were drilled by him in the 3rd dip after the face was cleared of coal. That time there was no seepage of water. The face was perfectly alright and the 29th level east appeared normal. He did not see the roof falling, but he heard the shouts given by others. No holes were ever put for testing for water. Before the DGMS he stated of having seen some percolation of water and roof also having been bad.

5.6 Witness no. 4, Kaliprasad Mandal, is a mining sirdar-cum-shotfirer and was employed in the 3rd shift on 13-9-1983. After doing some work he was asked to charge six holes in the 29th level eastern-most dip. When he went there, he heard a cracking sound in the roof and flakes of coal 3/4" to 1" in thickness falling from the roof. Overman and the mining sirdar Dharmu Chouhan inspected the site and ordered erection of a fencing 50 feet west of the level face. Some time afterwards witness Ghansham Mandal raised and ordered erection of a fencing 50 feet west of the level water rushed above the 28th level in 1-1/2 to 2 minutes. Witness confirms that the 29th level east was stopped 4-5 days before the accident.

5.7 According to the witness, 90 h.p. pump was situated 3 to 3-1/2 pillars, i.e. 120 feet away from the tugger dip. It was installed neither at the floor level, nor at the roof level, but in the middle at a height of 7-8 feet. His evidence shows that till 12th September, 1983 the 29th level was being driven and then blasting was stopped.

5.8 Witness no. 5 for the Management Mohd. Mustak Khan, is the Asstt Engineer (Electrical and Mechanical) in-charge of the pump which was installed under his supervision. It was below the 26th level about 15—20 feet away from the 27th level and in working order. After the accident he took action to shift the pump to the main dip for dewatering at about 6.30 a.m. of 14-9-1983 as per his cross-examination. His estimate for dewatering the sump is one hour when there is no stowing operation and 4 hours while stowing is in progress. He puts the distance between the pump and the tugger dip approximately at 100 ft.

5.9 Witness no. 6 for the Management, Shri Katta Satyanarayan, is an Executive Engineer. He says that the pump had the capacity of 400 gallons per minute and was being operated by 90 h.p. motor. It was situated below the 26th level west side of the cross cut dip and the suction pipe was about 100 feet while the foot valve was 2-3 feet below. It was capable of dewatering nearly upto 27th level of the west side cross cut. Witness says that it took the whole of the 16th night for dewatering the main dip and, therefore, he estimates that about 9 lakh gallons of water including percolation of the intervening 3 days had been dewatered. He further says that the workings beyond the dip foot valve were always waterlogged.

5.10 Witness no. 7, Manager Sailesh Kumar Bhattacharya, took charge on 12-9-1982. He went underground and detected that the 3rd dip gallery had got connected accidentally with the stowing sump. He refers to the survey after the accident revealing that the offending dip gallery had been shown as 40 feet in length when it was found to be about 100 feet. According to the witness, the 90 h.p. pump was adequate to keep the sump free.

5.11 He refers to the decision to develop the dip side virgin area. Simultaneously with depillaring on the rise side in F District they decided to drive the 1st dip of the 29th level which was known to be away from the sump with adequate parting in between other drivages. This drivage was deviated so as to touch the floor of the seam and at the same time to facilitate tramming in future. There was no intention of joining with the 27th level west of the cross cut. Hence the drivage of the 29th level east was given up on the 9th or 10th of September and development of the 3rd dip of the 29th level was undertaken. But due to mistake in plotting only a thin parting was left.

5.12 In cross-examination he says that the working plan he used was on tracing cloth because the mounted paper working plan was under preparation. Tracing cloth plan is not before the Court. Witness says that while taking charge he had so suspicion that the plan was wrong because in the day-to-day working he found galleries connected as expected.

5.13 Witness admits that he was expected to sign the plan after every quarterly survey and adds, he must have so signed. Perhaps aware of the weakness of such a reply, he says, the surveyor had told him that he was plotting both on the working plan as well as on the mounted plan and the mounted plan was to be signed by him after the completion of the work. He says that he was told by the surveyor Shri S. S. Mukherjee some time in the end of July or August, 1983 that he was carrying out the new survey. He says, when he joined on 12th July, 1982 the re-survey was in progress. He also refers to the two levels, 25th level east of the Main dip and 25th level west of east cross cut, getting joined and in fact being one level.

5.14 Regarding 90 h.p. pump, he says, it was just below the 26th level west of the east cross-cut and the workings below the pump on the east rise district constituted the sump. According to the witness, the dotted line as shown on the plan means that the extent of the workings is fixed or known but other details are not known. Other details mean height and width. He also says that the XIV seam working is in one section. Proper horizon has not been maintained.

5.15 According to the witness, the 29th level was developed on the cast side of the Main dip about 360 to 380 feet, but on Exh. 43 it appears 200 to 220 feet. Witness mentioned that there was coal barrier of about 60 feet between the face of the 27th level east and sump working. 28th level was not driven more than 15 ft. beyond the tugger dip because on the other side they needed a sump; they feared that due to power failure there will be no opportunity to use the water pump to the extent necessary to deal with stowing water, so a large capacity sump was needed. He says that since there was adequate margin, CMR 127(1) did not apply and since lamp is not disused working, CMR 127(3) did not apply. He has said that levels 28th, 29th and 30th from the Main dip were driven in his time. 29th level was deviated slightly risewards to touch the floor. 28th level east face was stopped just before the tugger dip on 16-7-1983. He further says that no work of coal production was going on in the 2nd dip of the 27th level west of east cross cut. It was used as sump. There was no coal production from the 27th level west end. In the four dip galleries of the 27th level west of east cross out there was some water, mud, sand, etc. The 90 h.p. pump could not dewater them. The distance between the Main dip and the 4th dip is about 240 feet. The decision to stop the 27th level east and also the 29th level east was taken so that they did not connect the sump. The object of driving 29th level upto the point that had been driven was to develop the area upto the workings towards the dip side of the sump. According to the plan available to them, there was a safe barrier between the sump and the 29th level east.

5.16 Regarding the parting between the floor of the 3rd dip of the 27th level west and the 3rd dip of the 29th level east it varied from 5 feet to 9 inches as revealed after the accident. He says that the accident took place because of the double error, 100 feet drivage having been shown as 40 feet and the error of 60 feet in the shift, together making a total error of 100 feet. However, he says, CMR 104(2) does not apply as there was no intention to develop in two sections.

5.17 The make of water in September, 1983 excluding stowing water was according to him, 200 to 300 gallons per minute approximately. Witness says that when he inspected the site immediately after the accident there was not much water at the 27th level west of east cross cut. It was about 1 to 1-1/2 ft. high over the mud. Near the foot valve sump water used to remain, because of the blocking by mud and sand, but that was frequently removed by making a drain. There was no such drain for the 27th level and, therefore, the 27th level could not be made dry even in normal circumstances. He denied the suggestion that water coming at the time of accident was 9 lakh gallons. He sticks up to his estimate of 7 lakhs upto the 27th level. He says, sump is not waterlogged area because waterlogged area means area where water remains accumulated. He does not admit that the 27th level 3rd dip which is the offending gallery, was waterlogged area. He admits that the sump as existing on 13-9-1983 was capable of stowing 20 lakh gallons of water. He does not recollect whether during his tenure he submitted copies of the plans as required under CMR 60. He did not attempt to make dry the 1st, 2nd, 3rd and 4th dips of the 27th level west He had seen the 27th level dry, but full of muck and debris and presumed that the dips would also be so.

5.18 Witness No. 8 surveyor Shyam Mukherjee was attached to Hurriladih colliery in July, 1978. He refers to the survey made by Geodatic Research Branch of the Survey of India to establish control over the whole coal-field. He also refers to the post-accident survey revealing the 3rd dip 27th level west being 100 feet although shown 40 feet on the plan, and the shift being 45 feet to 50 feet. He admits that the plan, Exh. 43, is not listed in Exh. 58. According to him, serial No. 4 in Exh. 58 is the missing plan. He admits, he did not insist on taking signature on the plan and did not check the whole of Exh. 58 before signing. He says, he carried out the survey of the Main dip section of the 26th level and below. The 29th level east was started 1-1/2 months before the accident. Survey was done around 9th or 10th September, 27th level west of east cross cut was not surveyed by him.

5.19 He did not show the spot levels because firstly these workings were made before his joining and secondly, because they were full of sand and mud so that he could not go there. He had gone to the 3rd dip 27th level west two-three days before the accident. There was a fall at the western end of the 27th level west. The 3rd dip was full of muck which extended to the level also. He drew projection lines on the plan, Exh. 64. But he did not draw projection lines on the plan, Exh. 63. He admits the difference between the projection lines on Exh. 63 and Exh. 64 although they are common plans. He does not give any reason as to why he made an incorrect statement before the DGMS regarding dip galleries of the 27th level east cross-cut district having been shown in dotted lines because he found them waterlogged at the time of survey.

5.20 He puts the position of the 90 h.p. pump as 30 feet below the 26th level west, but cannot explain his statement before the DGMS that the water level used to vary between the 26th and 27th levels west. The 27th level and 28th level east were not driven further than what they appear now as they did not want them to connect with the sump. He disowns his statement before the DGMS that he has shown waterlogged dip galleries in dotted lines with ends closed in the main plan but in some other plans shows those galleries open. He admits that he did not do quarterly survey as required by CMR 58(3) as his time was spent in non-statutory duties.

5.21 Witness no. 9 for the Management, Shri Kumar, was the agent at the relevant time. He took charge in January, 1980 and was transferred in July, 1982. During the intervening time he worked as manager of Hurriladih colliery. From 1st October, 1982 he took charge of that colliery as agent. During July-September he was in Kustore area office as Superintendent of Mines. He refers to the depillaring permission obtained from the DGMS under letter No. 33/HU/P-100/78, dated 10th August, 1978 under which the work of depillaring with stowing was being done at the time of accident. He also refers to the error regarding the 3rd dip of the 27th level west actually being 100 feet, but having been shown as 40 feet only. He says that the projections shown on Exh. 14, i.e. Exh. 62, in respect of the 29th level 3rd dip, were made by him as manager and further projections were done by the then manager keeping him informed. On 5th September, 1983 the 29th level was being driven by solid blasting and it had come upto about 25 feet east

of the 2nd deep. Offending gallery, the 3rd dip west of the 27th level, was not driven in his tenure.

5.22 He does not admit that a sump working is water-logged. He admits that on exh. 62 where headings are closed, the spot levels are not shown. The position of the pump was below the 26th level. He does not remember when the 26th, 28th and 29th levels east of the Main dip were driven. The 4th dip of the 27th level west was being used as sump prior to his joining. The drivage of the 28th level east was stopped as it would have joined with the sump thereby losing its capacity. According to him, faulty plan was prepared during the period 197 7to 1978. He was sure of sufficient barrier to the sump in relation to the west dip. He says that spot levels could not be shown as headings were under water and could not be surveyed. Although these workings were not approachable because of water, he says, CMR 127(3) was not attracted, nor also to the 29th level east. The 3rd dip was containing water. He says, he signed the plan in connection with resurvey although the survey was not complete. He admits that the 29th level east was being driven within 60 metres of the sump. He cannot produce documents to show that quarterly surveys were done.

UNION WITNESSES-COLLIERY OFFICERS

5.23 Witness no. 1 for the Indian Mines Personnel Association, Shri Sahadeo Soren, Asstt. Manager, speaks of the faulty plans causing the accident. On 14-9-1983 he went underground in the 2nd shift at about 4 O'Clock in the evening. Water was upto 28th level east of the Main dip then. The percolation of water was normal. According to him, drivage of the 29th level east started in his time. He regularly observed the face. Further drivage o fthe 29th level was stopped in the 1st shift and the 3rd dip was started immediately after that. He does not know the reason why the drivage was stopped.

5.24 Witness no. 2 for IMPA, Madan Mohan Srivastav, Safety Officer, has curiously said that the puncture in the coal roof connected an old dip gallery of the 27th level which was earlier not known to exist through any available records. He proclaims that by studying the relevant plans they had no fear any surface water seoping inside. Water seen at the time of accident was far more than the sump. He cannot say from where it came. When stowing was in progress, water in the dip was not increasing except in rainy season. Some days before the accident he went to the 27th level west via 26th level east an dits 3rd dip. Stopping the drivage of the 28th level east was manager's decision as water from the sump would have entered into the dip workings in the event of power failure.

5.25 On 14-9-1983 at 7 p.m. water was near about the 28th level. He says that it is correct to say that the dip galleries to the 27th level were found full of water at the time of inspection. He adds, there was also sand and muck. He stated before the DGMS that in the plan, dip galleries were shown by dotted line. He cannot say how such a statement is made when in the affidavit he stated that the existence of the old gallery was not known. He then adds, the existence was known but not the extent. According to him, no drilling could be conducted along the 28th level east as drill rods did not work properly. Thus, virtually he gives two reasons; this is therefore another reason for stoppage of the 28th level.

UNION WITNESS-EMPLOYEE

5.26 Witness no. 1 for INMOSSA is Nirmal Kumar Singh, an overman working in the 3rd shift at the time of accident. According to him, at the start of the shift, roof was examined and found to be in order giving metallic sound. When shotfirer went for steming the holes, loose coal had fallen from the roof, therefore sirdar late Dharma Chouhan, stopped work and asked for fencing being made. When he went to the other side thereafter, alarm was heard. He heard the cracking sound. According to him, 90 h.p. pump was installed 30 feet below the 26th level west junction and the foot valve was 3-4 feet below the 27th level west. The 27th level west was full of muck and sand and bricks. The 29th level east was stopped around 11-9-1983 and the 3rd dip was started on the same day.

COURT WITNESSES-CONNECTED WITH COLLIERY

5.27 Court witness no. 1, Gokul Dusadh, was the pump operator at the time of accident. He says, the pump was installed just above the 26th level in straight line with the tugger. In the beginning it was shifted from level to level. On that day initially there was power failure, but the stowing operations started at about 5 a.m. An hour thereafter the reading showed zero and the wheel of the pump became free. He stopped the pump and proceeded to find out the cause just when he learnt about this accident. Water taken out by the pump was going to the 17th level. According to him, the 27th and 28th levels used to remain filled with sand, muck and water.

5.28 When he started his duty on 13th September he had made a mark on the suction pipe to show the level of the water of the sump and signed on the pipe by chalk putting the date. The distance between the pump and the point he signed was about 40 feet or two pipes. Water in west level was not observed at the point where he signed but it was about one pipe length below, which was about 10 feet above the foot valve.

5.29 Court witness no. 2, Akhileshwar Pd. Varma, was attached as surveyor to Hurriladih colliery. Depillaring in the XIV seam had just started and at that time he had made a closed circuit survey of the XIV seam. He was, however, transferred before the calculations were made or plotting was done. At that time the 27th level west was remaining full of water, but he does not admit it was discontinued working and, therefore, he did not show the spot levels. He pleaded ignorance whether spot levels were shown by earlier surveyor. He did not survey the 26th level east or 25th level west, nor had they joined then. He knew that the plan was to be prepared for the XIV seam and XI seam. He finished closed-circuit survey of the 20th level. He made entries in his filed book, but does not remember whether plans were sent as required under CMR 60. According to him, the 27th level west was not accessible. He refers to the missing tracing cloth plan which he had given in the office.

5.30 He refers to the mines getting drowned since last week of September. 1978 so that the work came to a standstill. He recognises the hand-writting of deceased surveyor Das in exh. 69 and reads the drivages of the 3rd dip noted by Das as 4 m i.e. 13 ft. x 12 ft. x 7 ft.=1092 cub. ft of the 4th dip as 5 m i.e. 16 ft. x 12 ft. 8 ft.=1536 cub. ft.; thus showing that the two dips were driven upto 13 ft. and 16 ft. respectively. On exh. 62 he notes that the 3rd dip is shown as 40 feet. In respect of exh. 80, ventilation plan he has a case that although his signature appears on it, it is a print of a plan bearing his signature which was only a hand plan. That in why there is no endorsement of quarterly inspection on it. He has conveniently stated that he has shown sport levels on the plan, not now before the Court, but admits that none of the plans, more than dozen attached by DGMS, shows any spot levels. He could not show a single plan prepared by Das where updating was done subsequent to 30-6-1978.

5.31 In respect of register, exh. 81, maintained by him, he has prevaricated to say on oath that the notings there are of water level though the heading above clearly indicates that the record is of progressive drivage. Witness Gupta, Manager has admitted that position. Apparently it is not convenient for Varma to admit the drivage as shown in exh. 81. Against the 3rd dip of the 27th west level the measurement is 70 ft., against the 1st dip/27th west level the entry is of 112 ft. and against the 2nd dip/27th west level the entry is of 97 feet.

5.32 Court witness no. 3 is Shri J. N. Gupta, Manager of Hurriladih colliery with effect from 3-5-1977 to 1-10-1978. At the time of his transfer the workings were in cross-cut section in the XIV seam. between the 26th and 28th levels east of the cross-cut. By his letter No. HRC/EA/78/F-11/1563-67, dated 10-11-1978 he has made a charge report, exh. 84, nothing therein that the previous survey seemed to be

wrong and hence plans could not be certified as correct. He says that the sump was planned in the lower most levels of east side of the east cross-out district between the 27th and 28th levels. The western side was to be developed till 30th level. They had planned a barrier of 100 ft. or so between the workings on the western side of the east cross-cut and the workings of the Main dip. It was to start from below the 23rd level. Regarding exh. 84 he says that the survey right from the 27th level upwards of the XIV seam as prepared by BCCL as well as erstwhile management was incorrect. He explains that inaccurates was found in the survey of the XI seam and hence he made the remarks about the XIV seam plan also.

5.33 According to him, the sump capacity planned was 10 to 15 lakh gallons and stowing capacity was 250 to 300 cub.m. of sand per day and was to be increased to 500 cub.m. per day. He also refers to the missing tracing cloth plan. He pleads loss of memory whether he observed CMR 60 and sent the plans to DGMS accordingly. Development work was being done almost through the middle section of the seam.

5.34 Court witness no. 5, Devendra Singh, was Agent at Hurriladih colliery from 19-4-1976 to 30-4-1980. According to him, they had planned to take water from the stowing area to the levels available on the dip- most portion on the eastern side and thus the sump was planned in the 27th and 28th dip-most levels east of the east cross-dip. At the time of stowing operation 500 gallons per minute of water was being released. He further says that when the XIV seam east cross-cut side development workings were drowned, that was replaced with depillaring district. He denies, it was necessary to maintain spot levels because he says that the XVI seam overlying the XIV seam was depillared in the past and was unapproachable.

5.35 Regarding the re-check survey of the XIV seam, it was made in his tenure but plotting, etc. was not done. In respect of the mistakes expressed in violation report, exh. 87, he says that they asked the Manager and the surveyor to rectify them, but he does not remember whether any reply was given to DGMS. He admits that the manager had the authority to change the projection lines until the same was exclusively given to General Manager by exh. 94, dated 1-6-1983. He is unable to point out the plan P-3/HURR/s mentioned in exh. 87. Development was planned in the middle lower horizon of the seam.

COURT WITNESSES—D.G.M.S. OFFICE

5.36 Court witness no. 4, Shri P. C. Shyam working as Director of Mines' Safety at Dhanbad, went to the spot of accident at about 8.30 a.m. on 14-9-1983. He seized the records from survey office and attendance room. On 16-9-83 he made detailed inspection by going underground, accompanied among others by Dy. Asstt. Surveyor. He inspected 'E' panel of east cross-cut section. In the 19th level he found four loaded tubs. He also found a foot valve of the pump between the 26th level and 28th level east cross-cut. The water level was near about the junction of the 28th level of east cross-cut. The 27th level itself was cleared, but difficult to walk through because of flowing of water. Proceeding further he noticed the puncture of about 6' in diametre. On the east cross-cut section, water level was about the 26th level. They made a V notch in the 3rd dip at the junction of the 27th level west with an angle of 35 degree. Height of water in the notch was 8 inches. The quantity of water flowing thus worked out to about 80 gallons per minute. According to him, the make of water during five hours between the accident and his visit would not more than 300 cub.m.

5.37 He refers to the general inspection carried out by witness Muzumdar on 28-12-1979 and the report, exh. 87, dated 20-1-1980, based on that inspection. The discrepancies were below the 26th level of main dip. He says, there was no immediate danger because of this incorrect plan. He further says that since his office learnt about the Management preparing a revised plan and as they were insisting on an accurate plan of the relevant area whenever any permission under any regulation was sought, they did not pursue the matter. He says that no plans under CMR 60 have been received for the last 2-3 years. About the previous years, he could not reply without referring to the record. Roughly speaking, the office of DGMS shall be receiving plans from 350 coal mines and 4400 metaliferrous mines and there was no agency to check them. He added that those plans were just stored and also said that they have made a proposal to the Government to delete Regulation 60.

5.38 According to him, all the inspections till March, 1983 were above the 26th level of the Main dip section. He does not know when the 27th level was created, but it was used as a sump since 1979. According to him, it is not the normal practice to work beneath the sump. If the work is vertically below water, 30-metre partition would be necessary. 10-mtr. parting shall be sufficient if the column of water overhead is about 40-45 metres. They got the impression that exh. 62 was the working plan. Referring to the permissions granted in March, 1982 under CMR 105 for crossing the road, he says that these workings were above the water line and there was no danger of inundation. According to him, regulation 104 would apply particularly for the junction where the two offending galleries have crossed. Seeing the plan, exh. 90 where offending old gallery is shown with dotted line and ends open, he says, dotted line means that the extent and accuracy is doubtful whether the ends are closed or not. Witness does not admit that on account of consistent pumping, sumps are not to be treated as waterlogged workings. He defines sump as standage of water from which water is pumped out by means of a pump. It is a permanent standage of water and not temporary. He would call it a waterlogged working with the fluctuating water level, and it would be disused working because nobody can go to the end of the working and see. It is abandoned working in the sense that there is no production.

5.39 He says, if the gallery is without water in the first shift and is filled with water in the second shift, it would be disused working because at that time nobody can go and use it and inspect it. Hence he says, regulation 127(3) is attracted. Logically, he admits that permission will be required for every shift unless the gallery is defatered first. But he had no occasion to grant such permission. According to him, galleries used for sump will not be galleries used because use means 'production or accessibility'. Witness does not agree that if the gallery is in use for any type, it is not disused or abandoned. Disuse and unuse are the same in that they are not in use. He says that when the area is drowned with water, spot levels cannot be measured but they can be measured from the gradient of the seam, if the gradient is constant and the working has followed the floor or the roof or a known horizon.

5.40 He enlightens that every statement taken by the officers of DGMS after the accident was explained in Hindi to the concerned person by an employee of the mine of the level of cashire or store keeper knowing English whose signature was taken on the statement in token of his explaining the contents. There was no difficulty in explaining mining terminology. He says that Regulation 58(4) was not complied with inasmuch as plan P/3/HURR/S to which referred has been made in the inspection report, exh. 87, was not entered in the register, exh. 58.

5.41 Court witness no. 6 is Ganapati Sinha, Head Surveyor in DGMS Office. He prepared the plan, exh. 19 showing the position of 90 h.p. pump before accident. At about 1.45 p.m. on 14-9-1983 he visited the spot where he found slippers arranged as temporary foundation of the pump. He found the foot valve at the spot shown in exh. 19. Some part of suction pipe was attached to it. He had carried his field book and all observations were noted in it. Water level shown on exh. 19 is the level as on 13-9-1983. He refuted that it could never be 36000 cub.m. In the calculations showing as 4,409 cub.m. of water, he has excluded the first, second, third and fourth dips of the 27th level to the extent of water level at the roof of the gallery. He assumed that the water level before the accident was at the chalk mark on the suction pipe. The suction pipe attached t othe foot valve was spread out, according to him, by reason of use in water. He has shown everything which he personally observed with the exception of the dead bodies which have been noted in exh. 19 at the instance of his supervising officer who had asked him to do so when the prepared plan was shown to that officer.

5.42 Court witness No. 7 is Mazumdar, Dy. Director of Mines' Safety. He was the group officer for Hurriladih colliery and in that capacity he had made general inspections, follow-up inspections and fatal accident enquiries, etc. Exh. 88 is the synopsis of such inspections. Every inspection, he says, is for a particular purpose and for doing so, particular route is followed and particular working place is inspected. He took charge in July, 1974. There were 11 coal mines under his charge. The schedule of inspections is prepared on the basis of accident characteristics, history of the mine, etc. He had no occasion to inspect the 27th level west of cross-cut. He had inspected panel 'E', but he had not seen the sump at that time. He did not go to the dip workings west of east cross-cut 27th level onwards. He does not know where the stowing water of that section was passing though he says it was expected to go to the dips. He had inspected the Main dip upto the 22nd level. He refers to his violation report and says that the plans did not bear the prescribed certificates showing the old number of the plan.

5.43 He says that they have not received any plans from Hurriladih Colliery under CMR 60. He suggested resurvey and says that for recheck of the XIV plan, 2-1/2 months would be required if one team consisting of a surveyor, assistant surveyor and three chainmen works for full time. According to him, remainders were given to submit compliance report regarding violations noticed at exh. 87 and it continued till the next inspection. Earlier he was informed that survey was in progress involving other agencies. He also assessed the magnitude of the work of survey. He was keeping in touch with the progress. No action was taken during that period as there was no development. For considering fresh proposals, they were insisting on an uptodate plan for that area. Referring to charge report, exh. 84, given by Manager Gupta, he says that in the context of doubt expressed therein, he visited the mine on 10-1-1979. Since there was no immediate danger, no action under Section 22 was taken.

5.44 He was not aware if the 27th level west of east cross-cut was used as sump. No officer of the mine told him that working was going on in the area lying on the east of the Main dip. They had told him about their proposal to cross the road 11 pillars below the 26th level Main dip. He says that the plans submitted under Regulation 60 are checked in the headquarters by a surveyor. In spite of deficiency having been pointed out in exh. 87, no water danger plan was maintained. Underground workings were not specifically inspected before granting permission under CMR 105. Some roof trouble was anticipated and, therefore, condition was put to leave some coal along the roof. Action under Regulation 65(3) was not undertaken as it is used for special circumstances and here the Management were on the job.

CHAPTER VI

ROOF FALL AND SEEPAGE

6.1. The case as disclosed from the evidence shows that in the early hours of 14-9-1983 when the 3rd shift was working underground the mine, there was cracking sound at the face of the 3rd dip of the 29th level, east of the Main dip and suddenly water from above started flowing down in great quantity drowning the 19 persons working in the nearby tugger dip and the Main dip. The 3rd dip of the 27th level west of east cross-cut from which water came, happened to be overlying the 3rd dip of the 29th level east; as the parting was so thin that the pressure of the water column caused the bottom to burst. The statement, exh. 5, given by the Management and the written statements of some unions refer to heavy seepage of water in Hurriladih colliery throughout the year and more so in monsoon. At times it was suggested that immediately before the accident such seepage did take place, but the Management ignored the same and as such, the tragedy was not averted in time the case of seepage in extensive quantity before the accident is not however borne out by the record. The first witness mentioning the accident witness no. 2 for the management, Ghanshyam Mandal. He is a loader. He was working in the third shift starting from 1.00 a.m. At about 4.00 a.m., after doing some loading work, he asked sirdar late Shri Dharmu Chouhan to provide for more coal. That time the sirdar advised his gang not to go to the 3rd dip face as the roof condition was not good. Instead they were asked to go to the companion dip. Shri Chouhan himself took one person of the gang and went towards the Tugger dip. Suddenly afterwards the alarm was heard when the witness was 15-20 feet away from the dip junction and learnt that water was coming in heavy quantity. It was thus the water which caused the persons working nearby to die.

6.2 In cross-examination he was specific that he was not knowing that the roof was bad. That night sirdar and overman had tested the roof before they were asked to do the loading works. The roof was found in order. He does not admit the suggestion that persons refused to go for work because there was seepage on the face.

6.3 He does speak of the sirdar, namely Shri Chouhan, directing persons to put fencing in the 29th level east between the 2nd and 3rd dips so that nobody could go to the 3rd dip. Working at that place was stopped but the witness is very clear that it was not because there was any heavy seepage.

6.4 Witness no. 3, Hari Pandit, is a driller. In the third shift of 13-9-1983 he had done some work. Thereafter late Dharmu Chouhan asked him to drill holes in the 3rd dip. He had accordingly drilled six holes after the face was cleared of coal. In cross-examination, he is clear that no hole was drilled near the roof. He says that the roof was tested although not by himself. He did not see any roof fall. No water had come out through the holes he drilled. He had heard the alarm. It will be apparent from the evidence of this witness that although he worked in the very face, which was the scene of tragedy a few minutes later, he had not received any advance idea about it. In his statement taken by the officers of the Director General of Mines' Safety immediately after the accident, he says that there was some percolation of water. Roof was also bid so he did not make holes. He is unable to give any reasons as to how he made that statement. It may be that either the present statement is wrong or the earlier one is wrong. Even the earlier statement could have been made in confusion. But it is clear that his substantaily evidence on oath is different and the previous statement made before the Director General of Mines' Safety cannot be accepted unless there is some corroboration anywhere. That corroboration is lacking.

6.5 Witness no. 4, Kaliprasad Mandal, says that after the holes were drilled by the previous witness, he was asked to charge those holes. He went for that purpose and at that time he heard a cracking sound in the roof and also found some flakes of coal 3/4″ to 1″ thick falling off the roof. This is, therefore, the nearest warning of the impending mishap. In cross-examination, he is very clear that although the roof flakes came out there was no indication of water coming out. He says, he reported the incident of falling of the roof flakes to sirdar Dharmu Chouhan who inspected the spot and asked for fencing to be erected, preventing entry to that place. Since no further action was taken by the sirdar who himself died in the accident, it is evident that he did not gather any impression that the situation was fraught with grave danger. He only stopped further working by fencing off the area. If he had felt that the matter was more serious, he was expected to report to him superiors for taking further immediate steps. On the contrary, he himself remained working near-about. Obviously, he did not feel that his own life or the life of anybody else was in danger and, therefore, remained satisfied after giving orders for putting up the fencing.

6.6 Witness Soren, Asstt. Manager on behalf of the Mine Personnel Association, as witness no. 1, also says that there was normal percolation. He had gone under-ground in the 2nd shift. Similarly, witness no. 2 for that Association, Madan Mohan Srivastava who is a Safety Officer, also speaks only of the roof falling and the fencing having been put. He has no case of any heavy seepage. Thus, the entire evidence on this point, particularly the immediate action of Dharmu Chouhan who himself died in the accident, shows that there was no advance warning of this collapse of the parting either by way of heavy seepage or by way of falling of roof although there was some trouble a few minutes before the accident in the face of the 3rd dip of the 29th level east. It has, therefore, to be held that the bursting was a sudden bursting. It appears that the layers of the sedimentary coal formation which served as the bottom of 3rd dip 27th level west and which was holding a large water column above, disintegrated due to weathering

effect and collapsed due to fatigue when they could not withstand the pressure of the water column above. There was no advance warning by substantial seepage possibly because the pores in the bottom were cemented by the silt collected along with floor of the offending old gallery.

CHAPTER VII

POSITION OF THE PUMP

7.1 During the arguments questions cropped up regarding the quantity of water flowing at the time of stowing and the capacity of the pump. In that connection great reliance was placed on behalf of the Management on the site of the 90 h.p. pump before the accident. According to their contention, the pump was just above the 27th level east cross-cut district. The place of the installation of the pump would show the water level that could be cleared by that pump and as such determining the position of the 90 h.p. pump becomes material.

7.2 Witness No. 5 for the Management, Asstt. Manager Khan says that the 90 h.p. pump was installed under his supervision. It was situated just below the 26th level on the date of accident. Witness no. 1 for Overman and Sirdars and Shotfirers' Association, Nirmal Kumar Singh, has said that the 90 h.p. pump was located 30 feets below the 26th level west and the foot value was 3 to 4 feet below the 27th level west. According to the Manager Bhattacharjee, witness no. 7 for the Management, it was below the 26th level west. Surveyor Mukherjee, witness no. 8 for the Management, says that the 90 h.p. pump was installed 30 feet below the 26th level west and water level varied below the 26th and 27th levels west. M.W. No. 9, agent Kumar, says that soon after the accident he found the pump installed below the 26th level and witness khan was dismantling the same.

7.3 The position so given is inconsistent with the position of the pump shown on the plan, exh. 19, and by Court witnesses Dusadh, P. C. Shyam and surveyor Ganapati Sinha. Dusadh, C.W. No. 1, is a pump khalashi. He was in the 3rd shift at the time of accident. His statement has been recorded by the officers of the DGMS, but he had to be called as court witness as no party to the proceeding cited him as a witness. In his deposition he says that at about 12.45 a.m. of the 3rd shift i.e. early morning of the date of accident, he started the pump. There was little water to be pumped out, but 15 minutes thereafter power went off. It came back after about one hour i.e. at about 2.00 a.m., but stowing operations started at 5.00 a.m. and the pump was, therefore, put in operation at that time. An hour thereafter the pump suddenly stopped. The reading on the meter was zero and to put it in his own words. "the wheel of the pump had become free". He could not see water. As he went to find out what had happened, he met other men from whom he learnt about the accident. His deposition further shows that the 90 h.p. pump was used for the first time about 7 years back. Originally water was at about the 23rd level. Dewatering that area the pump was installed near the dip workings at the 28th level; after that sand and muck collected in the dip workings and the pump was gradually shifted to its present position, above the 26th level. It follows, therefore, that since the last shifting the 27th level was remaining full of water.

7.4 According to him, when he started his duty in the night of 13th and 14th September water was found just below three lengths of the pipe. When he started his duty he made a mark on the suction pipe and signed on it by chalk giving the date. The distance between the place where the 90 h.p. pump was installed and the point where he signed was about 2 pipes i.e. 40 feet. Water level was about 10 feet above the foot value.

7.5 Court witness no. 6, Ganapati Sinha. the surveyor from DGMS Office, throws a good light on this point. He had gone underground at about 1.45 p.m. on 14-9-1983, some 8 hours after the accident, and under the direction of DDG (Central Zone) had prepared the plan after establishing survey stations and nothing everything he observed, in his field book. In exh. 19 he did not show anything he had not observed except the position of the dead bodies which he added on the instructions of DDG. According to the plan, the pump was above the 26th level. Witness found a temporary foundation of wooden slippers at the place and he also observed the chalk mark and blurred signature on the suction pipe. One discarded foot valve with same length of suction pipe attached to it was also found near the place. He denies the suggestion that he drew the plan keeping some pre-determined water level in his mind and, therefore, showed the location of the pump where it is found now in exh. 19. He depends upon the chalk mark and the letters W.L. written on it.

7.6 Even Director of Mines' Safety, C.W. No. 4 Shri P.C. Shyam, speaks about the finding of the foot valve. That foot valve was not correded; therefore it was in recent use before the accident. He cannot say whether the Management had changed the foot valve while shifting the pump after the accident.

7.7 It was vehemently argued on behalf of the Management that when every witness is giving a consistent story about the 90 h.p. pump having been below the 26th level, the version given by Sinha and Dusadh should not be accepted. But evidence is not be scanned on the basis of numbers. It is to be accepted by looking to its quality. Evidence of witness Sinha has a ring of truth in it, and is supported by circumstantial evidence of the temporary foundation, the finding of the foot valve and the chalk mark signature. Statement of Dusadh regarding his putting the signature and making the mark is not at all challenged. Men may lie but circumstances do not. Besides, the D.G.M.S. witness like surveyor Sinha and Director P.C. Shyam are independent witnesses having no axe to grind, whereas the witnesses produced by the Management are more likely to be propounding a case suitable to the Management. Therefore, the case about the 90 h.p. pump not having been just above the 27h level or below the 26th level looks to be true.

7.8 Apart from this, the observations made in the inspection note, exh. 3, are supporting the stand taken by the DGMS Officers. As per paragraph 5 of the inspection note, the inspecting group walked back to the 25th level travelled east by about 3 pillars' length and went down by about 1 pillar where "reportedly" a 90 h.p. pump was installed before the accident. During the recovery operations the pump had been shifted from the site. The floor of the dip road right upto the site of the pump and even beyond was full of sand coming with stowing water.

7.9 In view of the above discussion I conclude that the 90 h.p. pump was installed above the 26th level indicative of the sump capacity to include the 27th level.

7.10 This finding is supported by the evidence on record regarding the quantity of water reckoned at the time of accident, the quantity of water flowing during stowing operation and the evidence on the capacity of the pump.

7.11 Witness No. 7 for the Management, Shri Bhattacharjee, says that he made an estimate of the total quantity of water that may have entered in accident area immediately after the accident and his estimate is of 4.5 lakhs of gallons. He calculated it upto 29th level, but admits that water was increasing beyond the 28th level or so and taking into consideration that part, his revised estimate is of 7 lakhs of gallons including the 4-1/2 lakhs of gallons stated earlier. According to him, the sump as developed on 13-9-1983 was capable of storing 20 lakhs of gallons of water.

7.12 On this point witness no. 1 for the All India Mining Personnel Association, Sahadeo Soren, says that on 14-9-1983 he went underground in the 2nd shift. It was about 4 O'clock. He observed the water level upto the 28th level east of the main dip. On the west side of the main dip water was upto the level parallel to the 28th level. He possibly means the 27th level west of the cross-cut. From the plan, exh. 19, we gather that the level which is in line with the 28th level east of the main dip, is the 27th level west of the east cross-cut. Water level was therefore upto the 27th level west of east cross-cut. Surveyor Mukherjee, witness no. 8 for the Management, says that he was not going to the pump site regularly, but about 1-1/2 months before the accident the site was dry. However, he has stated before the officers of the DGMS that the water level used to vary between the 26th and 27th levels west of east cross-cut. He is not able to explain why that statement should be taken as incorrect.

7.13 It is already seen that Court Witness No. 1, pump Khalashi Dusadh, had found the water level about 10 feet above the foot valve somewhere above the 27th level west of east cross-cut. C.W. No. 3, Manager Gupta, says that the stowing capacity was 250—300 cub. mtrs. per day. Production planned was 100-150 tonnes with further increase in due course upto 200-250 tonnes per day in this context, he says that the pump capacity planned was 10—15 lakhs of gallons.

7.14 Then we come to the deposition of the agent Devendra Singh, C.W. No. 5, who worked at that time. He says that from the stowing operation, about 500 G.P.M. of water was being released although all this water coming during stowing operation was dewatered in 24 hours. They had made arrangements for retaining the water at higher level and pumping the overflow water from the dip workings.

7.15 From the above discussion it is clear that the sump was planned on a very large scale and its capacity was 10 to 15 lakh gallons. It should not, therefore, be surprising that at the time of accident, 9 lakh gallons of water had flowed in as said by some witnesses. On this background, we are to understand and appreciate the plan, exh. 19, and calculations made by the DGMS Surveyor Ganapati Sinha. Surveyor Sinha has noted on the plan, exh. 19, different positions of water. Position of water before the accident in east cross-cut dip from the 25th level towards dip (from west side of pillar corner) is 33 mtrs. Position of water after the accident in the tugger dip from the 28th level towards rise (from west side of pillar corner is 8 mtrs. The position of water after accident in the main dip from the 28th level towards rise (from west side of pillar corner) is 2.5 mtrs. and position of water after accident in west companion dip from the 28th dip level towards rise (from west side of pillar corner) is 5 mtrs. On these observations the calculations made show that the quantity of water in the main dip area was about 4180 cub. mtrs. i.e. about 9,18,000 gallons and the quantity of water in the east cross-cut area was 4409.709 cub-mtrs. or about 9,70,000 gallons.

7.16 In view of this evidence, the contention of the Management that the sump was of lower capacity or that the position of the pump would be indicating a lower sump capacity, looks untenable.

In the arguments four reasons are suggested for explaining the assumed excess of water than the capacity of the sump. First they speak of the increase being perhaps due to stopping of stowing pump after 6 a.m. on 14-9-1983 because of panic. But this would only indicate that for some time no pumping was done to lessen the quantity of water. It would not throw any light on the question as to what was the real capacity of the sump, i.e., how much quantity of water it would retain.

7.17 Another reason given is the addition of normal make of water, of about 12 hours, during which period there was no pump installed for starting the dewatering. The sump was designed after taking into consideration this factor of normal make of water. Consequently, this would be not outside the capacity of the sump and in any case, this would be only a marginal increase.

7.18 The third possibility suggested is of return of water from the mid-sump at the 17th level due to overflowing. Now this is a factual aspect. We have no information about the capacity of the sump at the 17th level. No such case was made out either in the pleadings or in evidence. The Management could not have forgotten this possibility if that was the real reason. We cannot act on presumpptions and hence this argument cannot be accepted.

7.19 The forth reason suggested is the accumulation of water in the depillared stowed area between the voids of the roof and the stowed area, such accumulated water being on the rise side, rushing by gravitation to the spot of inundation which was at the dipmost portion. Now this reason was suggested by Shri Datey also at the time of arguments. I had told him then that was more in the nature of conjecture than the actual happening. No data was established either to show that there were such voids or there was such accumulation of water or how and why it could get released exactly at the time of accident and not any time earlier in the past. No evidence has come forward that this had been happening. If such water was flowing almost frequently, it would account for the normal make of water. Hence this reason is also presumptive. Had such water flown from the depillaring area, it would have left trail in the nature of mud, silt, etc, regarding which no indications were seen either immediately after the dewatering of the levels or even at the time of the court inspection on 1-10-1983.

7.20 Consequently, all the suggested reasons cannot be accepted as the reasons for excess water in the sump. Evidence discloses that water to the tune of 9 lakhs of gallons flowed at the time of accident. In my opinion, there is no scope for holding that the sump was of lower capacity. This discussion thus lends support to the finding in respect of the position of the 90 h.p. pump as being above the 26th level before the accident.

CHAPTER VIII

27th Level and the Sump

8.1 The tragic accident has taken place by reason of the bursting of the bottom of the 3rd dip in the 27th level west and the water rushing inside the 3rd dip of the 29th level east which happened to be lying below the 3rd dip of the 27th level west. It would be therefore, useful to find out when and in what manner the 27th level west was driven and how the 3rd dip of the 29th level east happened to be lying down below.

8.2 Witness No. 3 for the Court is Manager Shri Gupta who worked in Hurriladih colliery from 3-5-1977 to 1-10-1978. C.W. No. 5 Devendra Singh was the Agent of this colliery from 19-4-1976 to 25-4-1980 and Surveyor Shri Varma, C.W. No. 2, was attached to the colliery as surveyor from July, 1978 and remained there till 21st of November, 1980. Witness Shri Gupta has stated that during the end of this stay they were working in the east cross-out section XIV seam between the 26th and 28th levels. It appears that earlier they had plans to develop the east side of east cross-out district as well as the west side of the main dip. However, since July, 1978 the dip side areas of east cross-out were drowned and he could not pursue their scheduled programme. The Management then decided to work on depillaring in 'E' panel, side by side, undertaking the development work in the area lying to the west of east cross-out. It is in these circumstances that the permission for depillaring was obtained in August, 1978. For stowing work in the depillaring district a sump was necessary. Even naturally the water by percolation was getting drained to the lowermost galleries of the east side. Witness says that the sump for depillaring district was planned in the lowermost level of east side of the east cross-out district. According to him, it was planned between the 27th and 28th levels. They had planned to keep a barrier of 100 ft or so between the workings on west side of the east cross-cut and the working in the main dip i.e. to say between the main dip workings and the present sump. He is clear that the 27th level of east cross-cut was driven during his tenure although he does not remember whether the first, second and third dips of that level were driven during his time. He has a say that the devlopment work during his tenure was being done almost from the middle section of the seam and the production was coming from that area.

8.3 Court witness no. 5 Shri Devendra Singh says that they had planned to take water to the levels which were available on the dipmost portion on the eastern side. Seeing Exh. 80 he says the sump was planned in the 27th and 28th dipmost levels east of the east cross-cut dip. While speaking as to why this depillaring work was started, he says that the XIV seam east cross-cut side developments were drowned and that was replaced with depillaring district. The small portion below the 22nd level east of the main dip and west of the east cross-cut was undeveloped and that was taken up for development. According to him, though the 27th level west was not developed as a sump, it started to be used as a sump during his tenure.

8.4 It follows, therefore, that the levels down below the 26th level dipwards were planned to be used as sump and

the 27th level west also came to be used as sump. Like witness Shri Gupta, Devendra Singh says that the development of the XIV seam was undertaken in the middel lower horizon of the seam and as far as the development regarding the main dip it was coming along with the gradient earlier available after meeting the Jhama. It is also clear from the evidence of these witnesses that the drivages in east cross-cut which were in the middle horizon, were in different section compared to the drivings in the main dip which were along the gradient. It was natural therefore to expect one of the section overlying another section in some place or the other.

8.5 According to witness Varma, the area was drowned since before July, 1978. Thereafter dipillaring in the XIV seam commenced. He had made a closed circuit survey of this seam. He was however transferred before he could make calculations or make plottings. He further says that throughout his working as Surveyor the 27th level was full of water. The 26th level east and the 25th level west were not joined during his tenure. The closed circuit survey he made was upto the 23rd level. The 27th level west was driven when he joined, but he says that it was not accessible.

8.6 In course of his cross-examination he was asked questions based on exh. 69 containing the handwriting of surveyor late Shri Das who worked before him. According to the measurement as shown in exh. 69, the 3rd dip of the 27th west level had drivage of 4 m. (i.e. 13 ft.) and the 4th dip was driven upto a length of 5m. (i.e. 16 ft.). He admits, however, that on the plan, exh. 62, corrected upto 30-6-1982, the 3rd dip is shown as 40 ft. in Length and on the plan Exh. 19, drawn after the accident, the actual lengths of the 3rd dip and the 4th dip of the 27th level west are bound to be 100 ft. and 68 ft. respectively.

8.7 Witness was asked question in relation to the record book, exh. 81, which he himself maintained. He prevaricated and tried to mislead the Court saying that he notings thereon were of water level although the sub-titles overhead speak of "total measurement", "previous" and "progress". In exh. 81 under the date 2-8-1978 the measurement shown against the 3rd dip of the 27th level is 70 ft. Witness Varma says that that represents the water level and is prepared to take the consequence that water had risen to that level in the dip which looks unbelievable. Similarly, he had to say that the measurements against the 2nd dip and the 1st dip of the 27th level shown as 112 ft. and 97 ft. represent water levels of these dips. Witness is thus unworthy of credit. However, he has been rightly believed in this respect by Manager Gupta who was asked to interpret those entries made in Exh. 81 by surveyor Varma and who said that they are the measurements of drivages. It is thus evident from exh. 81 that during Varm's regime, the 1st, 2nd and 3rd dips of the 27th level were progressing and that the 1st dip had been driven to a length of 112 ft., 2nd to the length of 97 ft., and the 3rd to the length of 70 ft. We are therefore, having a clear picture regarding how the development in this area came to be started between the period 1977 to 1978 and that by August, 1978 the 1st, 2nd and 3rd dips had been driven to a considerable length. It is therefore gathered from these witnesses that the area below the 26th level on both the sides of the east cross cut was used as a sump so that water was to be collected therefrom upward workings.

8.8 Witness no. 7 or the Management, Shri S. K. Bhattacharjee, Manager, says that the 28th, 29th and 30th levels east were driven during his tenure. According to him, the 29th level west could not be made dry even in normal circumstances. He had taken charge on 12-7-1982 and he is therefore, speaking of his time. According to him. the workings below the pump on the east rise district constituted the sump. Although a dispute was raised whether the 90 h.p. pump was installed slightly below the 26th level west of the cross-cut as said by some witnesses for the Management in the affidavit as also in cross-examination, or slightly above the 27th level west as contended at the time of arugments, or whether it was above the 26th level west as shown in the plan, exh. 19, which is now resolved by my giving the finding that the position of the pump was as shown in the plan, exh. 19, it is undisputed that from the 27th level dipwards was the area of the sump. Witness confirms that proper horizon was not maintained while working in the XIV seam. According to him, there was a coal barrier of about 60 ft. between the face of the 27th level east of the main dip and the sump working. He also says that levels 28, 29 and 30 from the main dip were driven more or less along the floor. No wonder therefore that one working would be overlying another working in the same section.

8.9 That these drivages were nearabout the area full of water which is called the sump, is also evident from the statements that he stopped the drivage of the 28th level east, further of the companion dip. In fact, he had also stopped the eastward drivages of the 27th level and 29th level, east and dipward drivage of the 26th level east after crossing the 27th level. (Management witness no. 4 Kalipada Mandal refers to the stoppage of east face of the 29th level, although he does not know the reason. Witness no. 8 for the Management, surveyor Mukherjee, speaks of stopping eastward drivages of the 27th as well as the 28th level east of the main dip. So also witness no. 1 of PAW, Asstt. Manager Soren, refers to the stoppage of the 29th level east a few days before the accident and the 3rd dip 29th level getting started immediately thereafter. Even witness no. 1 for Sirdara and Overmen Association says that the 28th level east was stopped. Manager Bhattacharjee and surveyor Mukherjee are clear in giving the reason for this stoppage, that they did not want to lose the sump, that is to say, they wanted the sump to be of large capacity as it existed. The statement of the manager that the 27th level west could not be made dry even in normal circumstances unless a drain was cut to drain out, has to be understood on this background. Surveyor Mukherjee says that no attempt was made any time to make dry the four dips of the 27th level. Witness no. 9 for the Management, the Agent, says that the 4th dip of the 27th level west was part of a sump. Similarly, the 3rd dip was also a part of the sump and was always under water. Witness was admitted that the 29th level east was driven within 60 metres of the sumps although according to him, sump cannot be taken as a waterlogged area.

8.10 The above discussion thus illustrate when and how the drivage of the 27th level west was taken in hand and how those workings came to be used as a sump. In fact, the dips of the 27th level were necessarily remianing full of water and no pains were taken to mark the spot levels.

CHAPTER IX

SPOT LEVELS

9.1 Showing spot levels on the floor affords good indication underground regarding the different levels at which the Work is progressing and could have been perhaps useful in some measure, to throw an alert in respect of the present accident.

9.2 Spot levels are required to be shown under the provision of Sub-Regulation (3)(b) of Regulation 59. One of the plans required to be maintained under Regulation 59 is the underground plan of the mine. Sub-Regulation 3(b) deals with the underground plan and lays down that the plan shall also show spot level on the floor of the working :—

(i) Aong all hauage road ways at every roadway junction except in roadways where tramming is done by manual means, where the spot levels may be shown at points not more than 150 metres apart, and

(ii) In the case of headings which have been discontinued either temporarily or permanently, also at the end of such headings.

9.3 It is no doubt true that the spot levels are to be marked when the workings are discontinued but the said regulation speaks of discontinuance whether temporary or permanent. It has come in the evidence of PAW 1 Soren that at the time of accident only 5 faces were working. They were main dip face, tugger dip face, the 3rd dip of the 29th, level east 30th level face off tugger dip and west companion dip. As far as ther areas are concerned, they could not be called working faces and as such the Regulation regarding showing of spot levels was attracted.

9.4 However, it is an admitted position that after the plan, exh. 62, was drawn and signed by the surveyor on 30-6-1982, no spot-levels were shown in any plan. Witness No. 8 for the Management, surveyor Mukherpee in his deposition, says that the spot levels were not shown because the 3rd dip off the 27th level west was full of muck which extended to the level also. In respect of this very level he has given a statement before the DGMS Officers that the dip galleries of the 27th level were found water-logged at the time of survey and therefore he showed them by dotted lines. Without giving any reason he says that the statement before the officers of the DGMS is incorrect. Now he says that he could not show spot-levels on the floor of dip side workings in the sump because workings were made before his joining and secondly, the area was full of sand, muck and water as a result of which he could not go there. Thus he admits the non-surveying but does not stick to the version that the 27th level was water-logged.

9.5 Witness no. 9 for the management, agent Kumar, admits that the spot levels are shown on the haulage road upto the 23rd level in exh. 62 and in the cross-cut dip upto the 27th level which is the last junction. He admits that wherever headings are closed the spot-levels are not shown though required under regulation 59. He has no explanation as to why they are not shown. Court witness no. 2, surveyor Varma who was there from July, 1978 to November, 1981, stated that on the missing working plan spot levels were shown, but he could not point out any other plans amongst the many plans now before the Court, to substantiate the attement that spot levels were so being shown. C.W. No. 3, Manager Shri Gupta, rests satisfied by saying that in this connection he had given general instructions and he does not know whether those instructions were followed.

9.6 Attention of C.W. No. 5 Devendra Singh was invited to condition no 7 in DGMS's letter of August, 1978. permitting depillaring and he was asked whether the spot levels were shown. He has a surprising reply that in spite of that condition it was not necessary to maintain the spot levels because the XVI seam which overlies the XIV seam, was depillared in the past and was unapproachable. But obviously he had not approached the DGMS for waiving that condition. In reply to a question to by Assessor Shri Marwaha, he says that Regulation 59(3)(ii) was not attracted to the situation when the 27th level west of east cross-cut and levels below got flooded. In other words, although these dips were full of water, the Management did not feel like de-watering the same by using a rotor pump, etc. and to mark the spot levels. In this connection, C.W. No. 4 Shri P. C. Shyam has stated that when the area is drowned with water, we cannot measure the spot levels but we can measure them from the gradient of the seam. Such spot levels can be calculated on the basis of the gradient if the gradient is constant and if the work has followed the floor or the roof or a known horizon.

9.7 From the above discussion it appears that so far as the dips of the 27th level west are concerned, no spot levels were ever measure. It is possibly suggested that the dips were used as sump and hence it was not thought fit to mark the spot levels. But the general picture is that in recent years no attention was paid to mark the spot levels.

CHAPTER-X

INACCURACIES IN THE PLAN AND LAPSES

10.1 The most proximate cause of the accident that wiped off the lives of 19 innocent people is the connection established between the 3rd dip. 27th level west and 3rd dip, 29th level east. Sump water contained in the overlying 3rd dip 27th level rushed below with force flooding the entire area. In written statement exh. 5. given by the Management, it is said that a puncture got established accidentally. They have not indicated how the two galleries could have got connected. In paragraph 11.6 it is said that some of the old plans gave the impression that the offending old gallery is away from the 29th level But on dewatering after accident. this was found to be incorrect. When the time for evidence came, they come out with the conclusion that the accident happened because the plan on which they worked was incorrect. Inaccuracy of the plan has been spoken to by every witness of the Management. They also propounded that the plan on which they worked which was on a tracing cloth, is missing and not before the Court. Witness no. 1 for Management, survey officer Sudhir Kumar Bhattacharjee by the additional affidavit, Exh. 41, speaks of his organising a survey of the XIV seam beginning from the shaft level where two stations transferred from surface to underground by the Indian School of Mines were available. He carried out a closed circuit survey for the portion of the mine comprising the area involved in the accident. This re-survey revealed that the correct position of the 29th level with relation to the main dip area was as per the plan available but the area of the 27th level on the eastern side showed that on the eariler plans it had shifted dipwise approximately 45 ft. north of its actual position. This shifting has been refered to also by other witnesses, namely Manager Bhattacharjee, MW7, surveyor Mukherjee, MW8 and Agent Kumar, MW9. In addition, these three witnesses say that the actual length of the 3rd dip 27th west level, namely the offending old dip. is 100 ft., whereas on the plan, Exh. 62. prepared from the working plan and the other plans, this has been shown as 40 t. only that is to say, there is an additional error of 60 ft. Consequently, it was the resulting error of 45 ft. plus 60 ft., that is 105 ft. That put them of guard as to where exactly they were working so that the unexpected and unanticipated connection of the two galleries took place.

10.2 According to witnesses Bhattacharjee, the Manager; Kumar, the agent and CW 2 Gupta, the old Manager, the missing mine plan drawn on the tracing cloth was used by them every day and projections were shown on that map. Every one says that the plan was lying in the office. Now that plan is not one of the plans attached by the DGMS. The same was not available to DGMS at the time of attachment although surveyor Mukherjee does say that it was listed in the list book, exh. 58. They have no case that the DGMS officers have suppressed that map. In fact, attachment of plans and documents is done under acknowledgement and hence that possibility is done be excluded, but then where has this plan gone? Obviously some one has removed it surreptiously with some ulterior motive possibly because that plan was in many ways defective and the Management would get exposed that they worked on such defective plan and hence the person removing it desired that the same shall not come to the notice of the Court. Whatever that may be, our effort would be to find out from the evidence recorded so far, whether the errors notice after the accident could have been detected by the Management with due diligence and whether they could have taken timely steps to rectify the same although, on the evidence which is given, we may not be able to pin-point as to who committed those errors.

10.3 As per the written statement, after nationalisation preliminary work for the purpose of development continued till the year 1978. In September, 1978 the mine was drowned and all the XIV-seam work was temporarily halted. This was replaced with depillaring district known as panel 'E' on the rise side of the property. Dip side developments in the main dip area could not be restarted without intensive support to the roof. After roof stitching development of west side virgin area was completed by 1981 and in 1982, middle eastern property on the dip side was taken up. This was simultaneously with the depillaring for which permission was obtained in August, 1978. However, as early as December, 1978 is was known that every thing was not satisfactory with Hurriladih colliery plans.

10.4 Witness no 7 for the Court, Tapan Mazumdar, Dy. Director had inspected the XIV seam along with other seams on 28-12-1978. His violation report, exh. 87, shows that the plans P. 2|Hurr|S and P-3|Hurr|S which were placed in his hand, did not carry the requisite certificate showing that the plans were copied from a particularly numbered old plans and were correct. Details of bench mark were not shown on the plan P-2/Hurr/S and were not within the knowledge of the surveyor. Underground spot levels were not shown at the required places on the plan P-3 Hurr|S. That plan was not upto-date and was last signed on 1-10-1977. Witness had directed that fresh co-relation

and underground survey should be done and fresh plan should be prepared.

10.5 This report if it were to be respected and meticulously followed, would have given a good opportunity to the Management to correct their plan so that the error now noticed could have been eliminated. The other caution came in the nature of charge report made by Manager Gupta, C.W. 3, on 6-11-1978. In this report, exh. 84, he has referred to the inaccuracy of the plan. After giving general information regarding all the seams, he wrote about the ventilation and thereafter while dealing with the subject of water danger, he has written two paragraphs which are as follows :—

"4. The previous survey seems to be wrong and hence, plans cannot be certified as correct. Fresh survey has to be made and fresh plans prepared. It seems survey has been nearly completed and could be plotted as soon as we receive the mounted papers, etc.

"5. As per the new survey another development projection plan has been prepared and approved by the Area Manager Technical and development onwards has to be done as this projection."

The plain reading of these observations shows that the then manager was not satisfied that the plans were correct. He wanted fresh survey, but the XI seams survey was nearly completed and further steps based on that survey were suggested.

10.6 From his oral evidence we gather that by the expression "previous survey" used in paragraph 4 of the charge report, exh. 84, he means survey right from the 27th level upwards of the XIV seam prepared by BCCL as well as by the erstwhile management. The doubt came to him after re-survey of the XI seam. Because of the inaccuracies found there he had similar doubts regarding inaccuracies in the XIV seam. It is a matter of regret that the statement in exh. 84 or the suggestion in exh. 87 were not taken seriously as they should have been, although these inaccuracies were not the ones which allegedly led to the sanguineness of the management.

10.7 Devender Singh, C.W. 5, who was the agent at that time, in this connection says that he did not think of closing of the mine as development was in progress. To a very specific question as to what he did to rectify the mistakes shown in exh. 87, he says he asked the manager and surveyor to rectify the defects. It is also said that re-survey had been taken in hand.

10. Much has been said in the arguments regarding the re-survey undertaken and it is sought to be shown that while on the work of bringing everything in order unfortunately the accident took place. It is thus said that the Management was deligent but the tragic happening took place in spite of their honest efforts. I do not get impressed by this argument. The so called re-survey of the XIV seam was not complete till September, 1983, although it was taken in hand as is said, some time before the close of the year 1979. It is unthinkable that the re-survey of the seam should last for nearly 4 years. In order to support the case that re-surveying was going on, it is argued on behalf of the Management that DGMS was knowing about it and hence they did not take any penal action. It is true that the officers of the DGMS had further occasions to inspect the mine as is disclosed in the synopsis, exh. 88. After the inspection of 28-12-1978 a large number of inspections have taken place, some of them partial and at least one general in the year 1981. It is also true that witness P. C. Shyam (C.W.4) and witness Mukherjee (C.W.7) replied that they did not purse the matter because they knew that the Management were on the job. However, these replies have to be appreciated with reservations. If re-survey had started some time immediately after the defects were made known, it should not have taken such a long time.

10.9 It is worthwhile noticing in this connection that the agent (C.W.5) says that the instructions regarding re-survey given to the manager were not in writing. C.W. 7 also says, re-check of the XIV seam plan, 2-1|2 months would be required if one team works full time. One team means, one surveyor, one assistant surveyor and three chainmen. It has been emphasized by some unions and it is also apparent from the way evidence was given by C.W. 7 that the DGMS office is over-burdened. It is said that the Management were on the job. But no material has come forward to convince the Court in that respect. There is nothing to show that the Management and the D.G.M.S. office were in regular correspondence on this topic of re-survey. No such letter is produced before me. It was within the cognizance of the Management as to how much progress in re-survey had taken place at a given time and from time to time. There ought to have been field books, rough plans, etc. maintained in this connection which would have given a graphic picture showing how the re-survey was progressing step by step. Nothing of that type has come forward. The court has only oral statements that the re-survey was in progress. When the end of the work was in sight is also not disclosed. The long and short of it is that, "re-survey in progress" is only used as a defence particularly knowing that the D.G.M.S. office which was silent, could not sound a discordant note. D.G.M.S. Office appears to have remained silent because the extent of work was beyond their capacity in view of the large number of mines required to be inspected. If for that reason they had no time to have stricker vigilance on the work of surveying in Hurriladih colliery the only reply they could give to the court would be of the nature given. But it cannot be advocated in the least that in the absence of control from D.G.M.S., persons working the mine would be having no responsibility. It is quite obvious that it is the primary duty of those persons to observe meticulously both in letter and spirit the statutory requirements for safety in the mines. It was their own independent responsibility to remain on the right side and vigilant to see that survey plans of the mines are corrected and there was no scope for any mishap to occur by reason of the same.

10.10 In this context it is useful to find out what emerges from the evidence on record regarding the manner in which surveying and allied matters were treated and carried out by the Maagement. In the written statement as well as in the oral evidence reference is made to correlation survey, but that was with a view to connecting all mine plan of Bharat Coking Coal Ltd. to the national grid and to have a common reference grid for proper orientation. This work was entrusted to Geodelite and Research Branch of Survey of India and as stated by witness No. 5 for the court, the work was over in 1980 when two stations were established on the surface. Evidently, this work was undertaken to correlate the entire Jharia coalfield. Underground survey of Hurriladih colliery was not to be carried out by the All Indian Organisation; that was the duty of the persons working in the mines. Surveyor Shri Varma, witness No. 2 for the court who was attached to the colliery during the years 1978 to 1981, says that he had made a closed circuit survey of the XIV seam, but before making a closed tions or plotting the results he was transferred. He further says that he finished closed circuit survey upto the 20th level. Incidentally, he also says that he was updating the plan. He made entries in his field book, exh. 69, which he handed over to the Management, but as regards compliance with C.M.R. 60 as to whether plans were sent to D.G.M.S regularly, he pleads lack of memory. According to him, the mines were drowned since July 29, 1978 and as soon as they were dewatered, development work started. His evidence then shows how the drivages progressed which is already seen while discussing the drivage of the 27th west level.

10.11 Witness No. 5 for the court, agent Devender Singh has also said that re-check survey of the XIV seam was made in his tenure, but plotting, etc., was not done in his time. He is specific that survey was done of all approachable portions. Manager Bhattacharjee witness No. 7 for the Management, in his deposition speaks of closed circuit survey having taken place of the west side. It was near the 20th or 23rd level west off the main dip. M.W.8, surveyor Mukherjee, says that during the period July, 1978 to November, 1981 he was associated with the survey work of the XIV seam underground. During that period main circuits were completed, calculations done and the plotting was done on the mounted paper plan which is now exh. 62 before the court. The survey work was done by surveyors Varma and Adhikari. After taking over as statutory surveyor in November, 1981,

he undertook the survey of development workings. This was of the 23rd level west main dip section and below. He further answers that he did not do the quarterly survey as stated in regulation 58(3) as his time was spent in non-statutory duties. He was not giving the gradient line as Jhama was encountered in the gradient line and the same could automatically get displaced.

10.12 It is clear therefore that a closed circuit survey was taken in hand some time after inaccuracy in the plan was twice notified, but the levels, viz. 29th level east and 27th level west with which we are concerned, do not appear to have been a subject of the closed circuit. Details regarding the 27th level west of the east cross-cut as to when the drivage started and when and how far the dips were driven, have already been discussed. Depillaring permission was granted in August, 1978 that time a plan was submitted showing the 'E' panel and it is a matter of assumption that a survey of that portion must have taken place them. But that time offending gallery or the level did not exist. The 29th level east as well as its 3rd dip also did not exist. The 29th level east and the other two levels, viz. 27th level east and 28th level east, were driven in the time of Manager Bhattacharjee. There is no clear picture as to when the 27th level cast was started. From the mouth of M.W. 7, Manager Bhattacharjee, we gather that the 28th level east was proceeding further to the east in his absence on leave. But as soon as he resumed duties, he stopped the drivage as they wanted the sump intact. We also know from MW-8 Mukherjee that the 29th level was started about a month or two before the accident and its extreme east face was stopped for not losing the sump.

10.13 Immediately after stopping that drivage, the 3rd dip of the 29th level east was taken in hand. There is thus a rough picture of the workings in that portion relating to the drivage of the three levels and their dips. Now we know that the 26th level east and the 25th level west were joined in the term of Manager Bhattacharjee. In fact, it is one and the same level. It seems to me that an excellent opportunity of closed circuit survey of the work in hand proceeding towards sump was lost in not undertaking such a closed circuit survey that time.

10.14 It would be useful to find out how much care and caution was bestowed by the Management while doing survey work. Witness Bhattacharjee says that he was expecting to maintain the plan every quarter as required by C.M.R. 59(3), but the surveyor had not made the plottings on the working plan as well as the mounted paper plan. He promised to bring the mounted paper plan after completion of the same but that does not seem to have happened and the witness also did not bother to have stricter vigilance or to get the work done more quickly. Apparently, he could not submit that plans as required under C.M.R. 60. Regarding exh. 43, which is dated 6-4-1983, he says that it is a copy of the working plan maintained on tracing cloth. According to the witness, exh. 62 is the underground plan as required by Regulation 59(10)(b), although he also says that the missing tracing cloth plan was listed in the book, exh. 58 as required by Regulation 63(4). Exh. 59 is the bound paged book maintained under Regulation 49(2), but there is no entry regarding the water by which the accident took place. He admits that the dotted lines showing the quarterly progress with date on it as provided by Regulation 59(b) are not shown on any of the Plans.

10.15 Similar is the case with surveyor Mukherjee. He was a surveyor along with Das, Mehta and Varma and from November, 1981 had become the statutory become surveyor. He says that the 27th level west of east cross-cut was not surveyed after his joining though the working was there. He speaks of the missing plan on the tracing cloth and refers to entry at serial No. 4, page 8 of exh. 58 as that plan. But he also admits that exh. 43 which is said to be working plan, is not entered in exh. 88. According to him, exh. 43, was prepared for day-to-day work and therefore is not entered in the register. On exh. 62 the mounted paper plan, 'restrictions', 'permissions', etc. are shown, but the signature of the person who made the plan is absent. According to the witness that is because at that time he was working as an assistant. After taking charge he was satisfied of the correctness and therefore he signed exh. 62 thereafter, but he immediately adds that he did not check the whole plan. He only checked the closed circuit between the 28th level west and the 23rd level east. Although there was plotting on the eastern side of the main dip bleow the 23rd level, he did not check it. The 26th level east of the main dip was surveyed and plotted by him. That was also not a closed circuit, but open circuit. He was concerned with the 28th level east of main dip which was started 1-1/4 months before the accident. Surveying was done around 9th or 10th September, 1982 Exh. 62 bears the signature of the surveyor as on 30-6-1982, but the Manager has not signed it. He says he was transferred in July, 1982.

10.16 As regards the missing plan on the tracing paper, his attention was drawn to Regulation 59(1)(d) providing that such plans maintained under that Regulation have to be kept in a flat position. But he has a case that he used to keep the tracing paper plan in flat position. The 29th level east had started in his time. But he did not make any record in the bound paged book as required by C.M.R. 49(2)(a). In the name of the missing plan he says that the dip of the 27h level west of east cross-cut were shown in firm line on that plan. In respect of Regulation 49(2) he has a case that he had no doubt and therefore no such entry was made in the bound paged book. His attention was drawn to the projection lines on the two plans, exh. 63 and 64. According to him, projection lines on exh. 63 are not made by him. He does not know who made them. But the projection lines on exh. 64 are made by him. He, however, does not admit the suggestion that in case development was done along with projection lines shown in exh. 63, no accident could have taken place.

10.17 Witness has given a statement to the officers of D.G.M.S. after the accident in respect of some of the planning work he did. Before D.G.M.S. he stated that he showed the dip galleries of the 27th level east cross-cut district in dotted lines because he found those water-logged when he surveyed the 27th level. He is now taking up the position that he did not survey the 27th level. He now says that they were full of sand mud and water, and denies that he had surveyed the same. He attributes the mistakes in the statement to his nervousness.

10.18 He has a case that he was preparing a separate sectionalised plan and therefore, he did not sign exh. 16. But such separate plan is not before the court. He has signed the rescue plan, exh. 15, on 30-6-1982, but in view of the reason for not signing exh. 16 it has to be inferred that possibly he did not find this plan important. Subsequent to 30-6-1982, even exh. 15 is not signed and there he speaks about his remaining busy in the preparations for the complete survey. In exh. 15 he had shown the 29th level east together with all its dips. But he says that he did not find it necessary to sign that Plan after showing those workings.

10.19 According to him, pencil markings were done about 6-7 days before the accident and also some 1-1|2 months before the accident. They were made in pencil as circuit was not closed. He has a specious plea that there was no special method for detecting the error in respect of the actual 100 ft. drivage when the plan showed it to be 40 ft.

10.20 He disowns his statement made to D.G.M.S. officers that he has shown water-logged dip galleries in dotted lines in the main plan, but in some other plans he has shown those galleries open also. He give no reason how incorrect statement came to be made. It was during his time that the 26th level east of the main dip and the 26th level west of cross-cut were joined. According to him, they were joined for the purpose of ventilation......and convenience of the inspection of the east side. Before the D.G.M.S. he had stated that that was done for checking water level. When his attention was invited to his statement before D.G.M.S. he adds that that was also one of the reasons for joining. Although those water levels were to be checked, he did not think it necessary to show the spot levels at the end of the headings below the 27th level west of east cross-cut which were stopped. Looking to the third reason he has given for joining the 25th and 26th levels, it appears that the same would have served a good opportunity to make a closed circuit survey as stated by me earlier. The Management then would have obtained a firm and convincing picture regarding the recent developments on the east of the main dip as well as west of main dip including the 29th level and the 27th level west where the accident took place. Had this been done immediately, the real state of affairs of the various levels and dips could have been seen and the situation that gave rise

to the accident could have perhaps been averted. Possibly the Management had no time or thought for such measures.

10.21 He admits that he did not do the quarterly survey provided in Regulation 58(3) and says that this was because his time was spent in non-statutory duties. Surely, he could have either complained about it or asked for accommodation from his superiors. But he has displayed a singularly complacent attitude not caring at all for his duties and allowing them to be neglected.

10.22 Let us now see what agent Kumar says in respect of surveying and the workings. His attention was invited to the projections on exh. 62 (a copy of which is (Ext. 14) east of main dip 29th evel 3rd dip. Before becoming the Agent he was the Manager of Hurriladih colliery. He says that projections were done by him upto tugger dip as Manager. Further projections were made by the concerned Manager keeping him informed about it. He says that he signed the plan in connection with re-survey of the XIV seam, although the survey was not complete. On 5th September, 1983 he had gone underground and the 29th level east was being driven by solid blasting. It had progressed about 25 ft. further off the 2nd dip. As we now know, its further progress to the east had been stopped. As Manager, he did not keep any record of the drivage. He depened upon the plans. He admits that the 29th level east was being driven within 60 metres of the sump working, that is, working including the 27th level west off the cross-cut. In other words, there is clear-cut admission that the level was heading towards the store of water and the distance was less than 60 metres. Obviously, no one bothered to take any precaution by having bore holes, etc. Whether or not Regulation 127 applied is being discussed separately. But a question could be raised at this stage whether it was wise to go ahead without any precautions when a sump of the capacity of about 9 lakhs of gallons was to be met with. It seems more carefulness was expected, but that was not resorted to.

10.23 Witness has answered that the quarterly surveys were made as per regulations, but he is unable to substantiate his statement by producing documents calculated to show that quarterly surveys were done after 30-6-1982. He says that when he became agent, that work was entrusted to the manager. To a further reply to the Assessor, he admits that it was his duty to see that the provision regarding quarterly survey was adhered to, but apparently he failed in performing it. He gives a non-committal answer that he does not remember when the drivage of the 27th, 28th and 29th levels east of main dip had started. But when asked about stoppage of the 28th level east, he says that the manager had consultation with him before stoppage. It is therefore clear that the manager was keeping high officials informed in respect of drivages. In our case, the drivages of the 29th level east and the 27th level west are more relevant, but there should be no hesitation to say that the higher officials were kept in the know of the developments by the Manager. Attention of the witness was invited to the projection on exh. 18. He admits that the accident took place because of inaccurate plans. Attention of the witness was invited to CMR 64(4) laying down that the agent or the manager is responsible if the surveyor fails or omits to show any part of the workings or allows the plans or sections to be inaccurate. Witness in outspoken terms agrees with it saying, it is a vicarious liability. Witness also stated that the 3rd dip of the 27th level off east cross-cut was never worked during his managership. Therefore he admits that the heading was discontinued and agreed that Regulation 59(3)(b) applied, but for not showing the spot levels, he gives the plea that the same was used as a sump.

10.24 That the marking of the spot levels was never taken seriously by the Management of Hurriladih colliery for a very long time has already been discussed by me. They also did not pay attention to observing many other regulations as will be seen from the foregoing paragraphs. It appears therefore that the work of planning and surveying was never done satisfactorily.

10.25 Particular attention of the witness was drawn to the D.G.M.S. circular, exh. 100 which required that a separate water danger plan should be maintained. A number of precautions have been provided therein to see that there is no scope for floodling. If the circular is meticulously followed, one feels, there will be no case of inundation in any mine whatsoever. It is worth remembering that as early as December, 1978 or January, 1979 alert and caution was given by the inspecting officer in his violation report, exh. 87, but nothing precious was done to remedy the situation on the specious plea that the general plan was wrong and re-survey was taking place. How long that re-survey would have continued is unknown and would remain unknown because no target period was fixed and no stages of progress appear to have been planned or anticipated. It is by the stroke of providence that the snail's progress in re-surveying was cut by reason of the fatal accident and the Management inspired to undertake a local survey that resulted in pinpointing the double error. Regarding the water danger plan, the D.G.M.S. officers did not pursue the matter. Witness Mazumdar, however, says that after-all midway preparation of the water danger plan would not have been the correct compliance as it had to be correlated with the survey plan which was not ready. But the result is the double misfortune of there being neither a water danger plan, nor an upto-date survey. This is certainly not a happy situation; what was wanted was an upto-date survey plan together with upto-date water danger plan.

10.26 In order to have a clear glimpse as to how survey work was attended to and how it progressed thoughtlessly, it looks useful to study a few plans before the court. It seems, the trail of error would be apparent from it. As pointed out earlier, there existed a closed circuit survey covering the working on the west side of the main dip. There was also survey of a portion of the cross-cut when permission for depillaring was asked for some time before it was granted in August, 1978, but there was no surveying done of the relevant levels, say, between the 26th and 29th levels east of the main dip and between the 25th and 27th levels west of the cross-cut. Excellent opportunity for doing the same was missed when the 26th level east and the 25th level west were joined.

10.27 The earliest available plan other than the abandonment plan now before the court, is Exh. 80. It is signed by surveyor Varma on 21-4-1979. It is called ventilation plan. Varma himself has a very different story in this respect. He says that the signature on Exh. 80 appearing as a print is his, but he did not sign the ventilation plan. When he signed, the plan was only a hand-plan without the title 'ventilation' plan as it appears now. On the plan he signed there was no necessity of showing the quarterly survey markings and as such on Exh. 80 the quarterly survey markings are not seen. What is however to be noticed in respect of the drawing of Exh. 80, be it the original plan prepared by Varma and not the ventilation plan, is that on the east of the main dip the portion with which we are concerned, there is a barrier or an undeveloped virgin portion; whereas the west side of the cross-cut 27th level has all the dips numbering, 1, 2, 3 and 4. These dips are shown with firm lines with ends open, thus indicating that the working was in progress. Unmistakably, therefore, on 21-4-1979, the date on which surveyor Varma signed the plan, those dips were in progress. Another important thing to be noted is that the 3rd dip in this plan appears 40 feet long. From the deposition of this very surveyor Varma we gather that on 3-6-1978 it measured 4 m. (i.e. 12 ft) as seen from Exh. 69 maintained by surveyor Das and it was 29.5 m (i.e. 96 ft.) on 19-6-1978 as seen from Exh. X now marked Exh. 108. At Exh. 81 Varma himself has noted that drivage as 70 ft. on 2-8-1978. To show that drivage as 40 ft. on 21-4-1979 is disastrous and indicative of the indolence of Varma in preparing and signing the plan, the original he prepared on 21-4-1979.

10.28 Thereafter we come to Exh. 16, dated 6-12-1979 It is a sectionalisation plan bearing the signature of surveyor Ansari who also worked along with Varma. In drawing and appearance it is just like Exh. 80, that is to say, regarding the east side barrier and the drivage of the 27th west level, as discussed above. The comments and criticism made in connection with Exh. 80 will apply with equal force to Exh. 16.

10.29 Then in point of time we come to Exh. 15 which is a rescue plan. It is updated from 14-6-1980 to 31-3-1982. All the endorsements on it are signed by surveyor Adhikari excepting the last two which are signed by surveyor Mukher-

jee. Mounted plan, Exh. 62, is also signed by the surveyor on 31-3-1982 and 30-6-1982, but Exh. 15 is different in look in respect of the joining of the 26th level east with the 25th level west of the cross-cut. In Exh. 62, the 26th level is shown not going straight to meet the 25th level, but proceeding in north-east direction in an inclined way. Again in Exh. 15, drivage of the 28th level east was absent, although the drivage of the 29th level which was undertaken in hand thereafter is seen on the plan.

10.30 The next in point of time is the plan, Exh. 89, dated 24-11-1981 prepared when permission for crossing District Board road was asked for under Reg. 105. It is signed by surveyor Mukherjee and the east side main dip portion with which we are concerned, is like a barrier or a virgin patch, that is to say, the 26th, 27th, 28th and 29th levels east are not shown on the plan. What is worth observing is that the 2nd dip and 3rd dip of the 27th level west are shown with dotted lines indicating that they could not be surveyed. The dips are also drawn copying the old lengths, thus showing the length of the 3rd dip as 40 ft. This is so in spite of the usual certificate that the plan is correct. Obviously, the certificate is attached without in the least bothering about reality. It is again a matter of appreciation as to why the dips of the 27th level which were so far shown with firm lines, suddenly came to be shown with dotted lines. The initial error in respect of showing the length of the dips particularly of the 3rd dip, was committed by Varma and the same was carried forward by others also. Incidentally, in connection with Exh. 89, it should be observed that although the crossing of the road was asked for at 4 points, actually it was crossed at more points as gathered from the evidence of witness P.C. Shyam.

10.31 Then we come to Exh. 90 signed by surveyor Mukherjee on 29-3-1982 and corrected upto 30-6-1982. It is a water danger plan. Here also the 3rd dip is shown in dotted lines, obviously not making any efforts any time till then to dewater it, measure it or even to take care of the old record showing its further drivage, but simply copying from the old plan.

1.32 Next in point of time is Exh. 43 which is a working plan bearing the signature of surveyor Mukherjee, of 6-4-1983. Regarding the workings in East panel, the two dips are shown dotted and short. This also does not represent the reality. On the basis of the discussions made above. the case made out by the Management that they suddenly realised after the accident that the plans showed short drivages and therefore they were helpless in avoiding the accident, is untenable. There appears to have been grave carelessness on their part in not executing their functions properly and not exercising strict control over their surveyors. So far as the length of the old offending dip is concerned, it would be apparent that right from the year 1979-80 surveyor Varma should not have shown the same as 40 ft. and in Mukherjee's regime there does not appear to be having any satisfactory reason for showing the dips in dotted lines. Although the Management was administered caution right from the year 1978, that the plans were inaccurate, they ignored that caution. The case in respect of the missing plan is also intriguing. No information is available whether the same was really accurate. When all other plans appear to be inaccurate at least in respect of the major factor of the shift of 45 ft. and the erroneous recording of 40 ft. length in place of 100 ft. the so-called plan prepared on the tracing cloth may also have been erroneous. Whether it was the plan used for regular working also looks doubtful inasmuch as it does not confirm with the statutory requirement that the same ought to be able to be kept in flat condition.

10.33 This interesting resume of the different plans gives ample insight into the errors committed and how the persons coming subsequently were equally careless in continuing the same. It is. therefore, possible to infer that they never cared to maintain good survey record which could have been done easily othervise with little diligence effective control The maintenance of survey records thus displays complete callousness, callousness amounting to criminal negligence.

10.34 It may be that this was because the Management was more production-minded. Correspondence embodied in Exh. 95 and 96 does show that there was high degree of persuasion for maintaining higher and higher production targets. Exh. 96 are the minutes of the meeting dated 26-2-1983. Exh. 95, dated 6-8-1983, incidentally a few days before the accident, is a letter from the General Manager, S. N. Jha, to Agen Kumar exhorting him to achieve the target at any cost. The appended table shows that the XIV seam had considerably lagged behind in maintaining the target from depillaring district and the same was sought to be made up by increasing beyond the average the output from the development district, clearly putting that district on pressure. It is certainly unsound to argue that the higher management insisted upon achieving the target disregarding the safety of the employees. But we must have a practical approach. The total atmosphere, the total environment in which the persons on the spot would find themselves in, has to be taken into account. Apprehensive of his own future if he were unsuccessful in satisfying his superiors, a person on the spot would be impelled to move with over-confidence, prepared to belittle risks, taking liberty with safety of the employees. It is futile to suggest that thereby safety was not endangered. The picture emerging out from the way in which this colliery was handled, surely does not suggest that the safety factory was not ignored.

10.35 In the arguments Advocate Sinha on behalf of the Management placed reliance on Sec. 87 of the Indian Mines' Act, 1952 which lays down that no prosecution or other legal proceedings whatsoever shall lie against any person for anything which is done in good faith or entitled to be done under this Act. Primarily, this protection appears to have been given to those who start any action under the Act. Assuming, however, that any person working in the mine or at any rate, the superior officers could take shelter under it, it is absolutely necessary that the act done was done in good faith. Merely saying that the act was done in good faith, would not make it an action in good faith. Good faith has to be inferred from the attending circumstances. The attending circumstances in this particular case are contra-indicative. Again, in legal parlance, good faith has a well-known connotation. Anything done without due care or caution cannot be said to have been done in good faith. A person who does not exercise ordinary diligence, Cannot claim to have asked in good faith. Even the definition of 'good faith' given in S. 52 of the Indian Penal Code shows that an act which is not done with due care and caution cannot be taken as having been done in good faith. Person or person who act thoughtlessly, who act negligently, who do not pay heed to any of the safety provisions, cannot be said to have acted in good faith. That is what has happened here and consequently the argument in the name of 'good faith' cannot stand.

CHAPTER-XI

COAL MINES REGULATION—REGULATION 127 IF APPLICABLE

11.1 It is now clear that the offending 3rd dip of the 29th level east as well as 29th level East itself have been driven near and towards the sump. At the time of driving these galleries, no permission under C.M.R. 127 was asked for. On behalf of the employees' Union it is contended that this lapse on the part of Management has jeopardised the lives of the employees. It is said that the Management very well knew that they were approaching a place full of water and therefore they ought to have taken permission from the Director General of Mines' Safety as required under Regulation 127 to carry out those working and observed the precautions laid down. This has been intentional breach. As against this, the learned Advocate Shri Sripurkar stoutly and vehemently argued on behalf of the Management that no such permission was at all necessary because the very purpose of Reg. 127 is different and that a sump cannot at all be considered as a water-logged working or a disused working. As such they were within their limits in not asking for any such permission. In this connection, they also relief upon the judgment of Madhya Pradesh High Court in Criminal Appeal No. 222 of 1965 (S.D. Prasad vs. Shri Seth Haji Mullla Akbar Ali & Ors.), a copy of which is given to me at the time of arguments. It is the contention of the Management that according to that judgment, if a working is simply water-logged, Reg. 127 (3) is not applicable. They are further contending that Regulation 127 (1) and (2) would

not also apply. Regulation 127 to the extent relevant runs as follows:—

"Danger from underground inundation

(1) Proper provision shall be made in every mine to prevent irruption of water or other liquid matter from the working of the same mine or an adjoining mine.

(2) Where work is being in—

(i) any seam or section below another seam or section or

(ii) any place in a seam approaching a fault passing through an upper seam or section which contains other liquid matter,

Acquate predesutions shall be taken against an irruption of water or other liquid matter into working.

(3) No working which has approached within a distance of 60 metres of any disused or abandoned working (not being working which have been examined and, found to be free from accumulation of water or other liquid matter) whether in the same mine or in an adjoining mine, shalll be extended further except with permission in writing of the Chief Inspector and subject to such conditions as he may specify therein.

Explanation : For the purpose of this sub-regulation the distance between the said working shall mean the shortest distance between the working of the same or between any two seams or sections as the case may be, measured in any direction whether horizontally, vertical or inclined."

11.2 Regulation 127 appears in the Chapter entitled 'Precautions against Danger from Fire, Dust, Gas and Water", which covers Regulations 116 to 129 (both inclusive). So far as the precautions against danger from water are concerned in all there are four regulations, namely, Regs. 126 to 129.r The sub-title of Regulation 126 is dange from surface water', that of Reg. 127 is 'danger from underground inundation', of Reg. 128 'intentional flooding' and of Reg. 129 'construction of water dam, etc.'. It will thus be seen that it is Reg. 127 alone which deals with underground inundation. This factor has to be kept in mind while interpreting the various sub-clauses.

11.3 Sub-Regulation (1) appears in general terms providing for precautions to be taken to prevent irruption of water and other liquid matter. It is left to the discretion and efficiency of the Management or the persons working in the mine to decide what steps should be taken Sub Regulation (2) envisages three situations in respect of a working underlying any other working which could be a source of danger. The situations are, when any seam or section lies below any other seam or section or when any place in a seam or section is at a lower level than any other place in a lower seam of section or when any place in a seam is approaching a fault, etc. According to the sub-regulation, adequate precautions have to be taken against an irruption of water or liquid matter obviously coming from upper seam, sections or the levels. Here also precautions are not listed. But they have been left to the good sense and efficiency of the persons working the mine.

11.4 Third sub-regulation, however is of a different character. It speaks of taking prior permission in writing from the Chief Inspector for extending the working which has aproched within a distance of 60 metres of any other working. The gist of the matter is that as soon as a working approaches within a distance of 60 metres from any disused or abandoned working prior permission of the Chief Inspector would be necessary and the work carried out observing the conditions given in sub-regulation (6). How one exception has been made to the taking of such prior permission and that is when the working towards which the working is to be extended has been examined and found to be free from accumulation of water or other liquid matter. In other words, when the disused or abandoned working towards which the extension is to be made has been examined and is seen free from water or other liquid matter, permission would not be necessary and sub-regulation (6) would not apply. Obviously if it is not examined, permission would be necessary That is to say, responsibility is cast upon the persons working the mine to make sure that the possibility of accumulation of water or other liquid matter is excluded by actual examination and then they are absolved of taking any premission.

11.5 At the time of arguments attention was invited to the history of Regulation 127. In the year 1926 there were two Regulation—Regulation 74 and 75—Covering such positions. In the year 1957, Regulation 127 existed almost in its present form, but by an amendment of 19th March, 1980 more sub-clauses were added. Regulation 74 of 1926 provided for the prohibited distance of 100 feet and it said that the approch should have been to any place containing or likely to contain" accumulation of water or other liquid matter. That Regulation also referred to disused or abandoned working and the bracketed portion now found also existed then. Without the words which contains or may contain "accumulation of water" used in Regulation 75 that Regulation is embodied in the present sub-regulation (2) of Regulation 127. What precautions should be taken was left to the persons working the mine in both Regulations 74 and 75.

11.6 The part relating to the disused working is made more specific in the present sub-regulation (3) than in Regulation 74 by adding the word abandoned'. So far as the amendment of March, 1980 is concerned, proviso to sub-regulation (3) relating to seepage of water is delated and converted into a separate sub-regulation (5), Earlier sub-regulations (4), (5) and (6) have been exhaustively reproduced with some additional requirements in the new sub-regulations (4), (6), (7) and (8). The 1980 amendment is of no consequence in interpreting sub-regulation (3) with which we are concerned and the question to be decided in the present case is whether or not the working was within prohibited distance of a disused or abandoned working not being working which has been examined and found to be free from accumulation of water and other liquid matter.

11.7 The debate has centralised on the question whether a sump is a water-logged working. Bhattacharjee, Witness no. 7 for the Management, while replying to the question to regulation 127 said that in his opinion for driving the 29th level east no permission was needed under Reg. 127 because as per plan available to him he had kept adequate margin. That is why Reg. 127 (1) did not apply. Regulation 127 (3) did not apply as a sump, he says sump is a reservoir wherefrom water is taken out, again collected and again tagen out, again collected and again taken out; whereas accumulated". Witness Kumar, MW-9, the agent of the mine, also says that Reg. 127 (3) is not attracted for workings in the 29th level east of main dip, although he categorically admitted the 29th level east was being driven within 60 metres of the sump workings including 27th level west". He does not agree that sump working is water-logged. C.W. No. 2, surveyor Varma, has also said in his deposition that the 27th level west off east cross-cut was full of water. But he does not admit that therefore it should be called discontinued working.

11.8 As against this, Court witness no. 4 Shri P. C. Shyam Director of Mines' Safety has a very different say. He has been cross-examined in detail giving different positions and situations. To the question put by Sri Sirpurkar, learned Advocate for the Management, witness answered that he did not admit that the sumps are not treated as water-logged workings. Giving definition of a sump he says, a sump is a standage of water from which water is pumped out by means of a pump. He does not admit that it is a temporary standage of water. He called it a permanent standage of water. According to him it is an area full of water. He would call it a water-logged working with water level which can never be lower than the foot value. According to him, it would be disused water-logged area bacause nobody can go to the end of the workings and see. In his opinion, it is an abandoned working in the sense that there is no production. He does not admit that disused or abandoned nature cannot be inferred from the mere fact of water-logging. He was cornered with the question whether if the gallery is without water in the first shift and if the same gallery is full of water in the second shift, it would be a disused gallery. Witness answered that it can be called disused gallery because at

that time nobody can go and use it and inspect it. He was, however, unable to say whether therefore permission would be required for every shift unless it is dewatered first. He himself had no occasion to grant such permission. Witness clearified that use means production or accessibility. He would call the gallery used for sump as unused, disused and not used. He does not admit that if a gallery is used for any type of user it is not a disused or abandoned gallery. Disused or unused are the same as not used.

11.9 In answer to a question by Assessor Shri Trivedi he says that the 3rd dip of the 27th level was always water-logged irrespective of the position of 90 h.p. pump in cross-cut district and, therefore, it was a disused or abandoned working in the true sense of the words because the working cannot be examined and found to be free from accumulation of water or other liquid matter. Witness thus relies upon two tests, accessibility of the workings and the presence or absence of production. The user, according to him, is producing coal and it is the accessibility or the availability for inspection which determined the dispute eve nif it be water-logged area.

11.10 The effort on behalf of the Management is to highlight the concept of water-logging in interpreting Regulation 127 (3) and, therefore, Shri Sirpurkar wants to rely upon the definition of a sump. Sump is not defined in the Coal Mines Regulation and therefore, was are to depend upon mining practice. Shri Sirpurkar referred to the Dictionary of Mining by A. Nelson and quoted the following definition-

> Sump : A waterlodge or catchbasin that receives the gravity drainage and supplies the pump inlets. It also serves as a settling basin to remove sludge and sand from the water before it enters the pumps. may be interposed between drainage ditches sumps to extract wood and trash from the water, A sump should provide a sufficient settling capacity with baffles to still the water

He also depended upon the definitions of 'sump' as given in Law Lexicon & Legal Maxims' by Venkataramaiya which run as follows:

> Sump: Sumping—The terms "sump" has been used to designate a pit dug in the lower part of a coal mine to catch the drainage of the mine-Coal Run Coal Co. vs. Jones. 19 Ill App. 365; a pit beneath the cages of a shaft—Dallas Coal Co. v. Ratenberry. 107 S.W. 997; 85 Ark. 237; a rule well or cistern in which the water in a mine is trained to collect and from which it is pumped out of the mine by the steam engine which moves the cars in the shaft-woodward Lion Co. vs. Jones a 80 Ala: 123.

11.12 A number of definitions are given in the 'Dictionary of Mining & Mineral and Related Terms' at page 1102. Among the eighteen citations one relates to the definition as given by Nelson and quoted by Shri Sirpurkar. Other relevant definition would be the following:

> "An excavation made underground to collect water from which water is pumped to the surface or to another sump nearer the surface. Sumps are placed at the bottom of a shaft near the shaft on a level or at some interior point. Lewis p. 21."

11.13 Here we are not concerned with any type of sump which can well be described as a cistern or a tank or a pit. Here the sump was formed by galleries themselves so that the water lying right from floor to roof in all the galleries cutting and crossing each other was taken as a sump. That water was carried to the pit top through intermediate pump at the 17th level, the main sump at pit bottom, and was ultimately used for the purpose of stowing.

11.14 Looking to the definitions referred to above and the situation with which we are concerned, we must bear in mind that the sump in the instant case is an excavation made underground in a mine having a gradient and covering the dips of the workings. It was also a water-lodge in terms of the definition given by Nelson.

11.15 Shri Sirpurkar, the learned Advocate for the Management, then relied upon the judgment of the Madhya Pradesh High Court extensively quoting from the same. It was a criminal prosecution launched for breach of Regulation 127 sub-regulations (1), (3) and (5) read with Regulation 190 punishable under Section 74 of the Mines Act. Several persons working underground in a gallery were drowned due to sudden irruption of water. After quoting sub-regulation (3) as it then existed with the proviso which is not material for the case under discussion, the learned Judges of the High Court have observed that the permission for extension is required after two conditions co-exist, namely, (1) the workings towards which extension is being made are disused or abandoned workings; and (2) the workings are water-logged. The learned Judges have further observed that if there be no water-logging in the workings, no permission is required even if they are disused or abandoned workings. According to the learned Judges, water-logging is a condition additional to and independent of the working being discontinued or abandoned so that the 'disused' or 'abandoned' cannot be interpreted from the very fact of water-logging. The learned Judges have finally concluded that if the extension is towards the working which is merely water-logged, no such permission would be necessary.

11.16 Depending on this interpretation Shri Sirpurkar has contended that the sump with which we are concerned, even if it be a water-logged working, no permission would be necessary in so far it is not a disused or abandoned working and that is because water from the sump is being constantly used for stowing. In the first place, it is incorrect to say that all the water taken to the surface is brought back into the mine for the purpose of stowing. In actual fact only a part of it is used for stowing surplus being discharged in the surface stream. Therefore to that extent the sump contained water which is not used.

11.17 Besides, it may have to be noted that the word 'water-logged' which, in my opinion, has a different shade of meaning than the words 'not free from water', is not used in the Regulation. Therefore, the two conditions for the application of sub-regulation (3) would be (a) that there is disused or abandoned working, ad (b) that the same is not free from water. A disused working may become disused for two reasons. either because of accumulation of water which prevents it from being used as a working or because it is otherwise inaccessible because of fall of roof or any other obstruction. It appears that an abandoned working is a working abandoned by volition; whereas the disuse may be either voluntary or non-voluntary so that as soon as the cause of the disuse is removed, the working may again be put in use.

11.18 Taking into consideration the geological aspect, water would always percolate into mine workings if they are below the natural water level of the area. If these workings are in the dip side, this water would remain there if not pumped out or otherwise drained. In the rise side however it will flow dipwards. But even then the working on the rise side may be disused if they are not otherwise in use. It can therefore be said that all dip side workings below the water level are both water-logged and disused; while the workings on the rise side though not water-logged, could be disused or in use depending upon the situation.

11.19In the light of the above discussion and going by the plain reading of the words it appears clear that the framers of the regulation had in view the normal percolation of water in the abandoned working or in the disused working so that contingently that being a source of danger, provision has been made for precaution to be taken against the same. The meaning of the sub-regulation can be clearly understood first without looking to the portion in the brackets and then we can take into consideration the bracketed portion. In that way sub-regulation (3) would show that a prior premission of the Chief Inspector is necessary for extending if the working in hand has approched within the distance of 60 metres of any disused or abandoned working. In other works, as soon as the approch is towards the abandoned working or towards the disused working, permbission would be necessary. It is taken for granted that in normal circumstance such abandoned working or such disused working would be containing water so that the obligation to take permission and to observe the conditions for granting permission are to be complied with by the persons working towards such disused or abandoned working.

11.20 In practice however it may happen that the abandoned working or the disused working is quite well known to the person working the mine and before heading towards it they examine it and find it or make it free from accumu-

lation of water or other liquid matter. In that event the main purpose for which the regulation is made is served that is there is no lurking danger from accumulation of water or any other liquid matter and as such liberty is given to continue the working even without permission.

11.21 In my opinion this is the plain meaning of the words used in sub-regulation. It also would conform to the intention of the statute. In this connection we can usefully refer to "Craise on Statute law" seventh edition by S.G.G. Ledger. The citation in Chapter 5 paragraph 2 under the heading. 'Construction according to intention runs as follows", "The cardinal rule for the construction of Acts of Parliament is that they should be construed according to the intention expressed in the Acts themselves. If the words of the statute are themeselves precise and unambigous, then no more can be necessary than to expound those words in their ordinary and natural sense. The words themselves alone do in such a case best declare the intention of the lawgiver.". The tribunal that has to construe an Act of a legislature, or indeed any other document, has to determine the intention as expressed by the words used. And in order to understand these words it is natural to inquire what is the subject-matter with respect to which they are used and the object in view". In 1955 Lord Goddard CJ said. "A certain amount of common sense must be applied in construing statues. The object of the Act has to be considered."

11.22 The judgement reported in 1983 p. 716 (Azimuddin Ansari vs. the State of Bihar) a copy of which has been handed over to me, can also be useful. On the question of interpretation of statute it has been held that it is permissible to interpret a clause by removing the bracket. The following observations in paragraph 9 of the judgment are material—

> "No special significance can be attached to the bracket, as Lord Esher M.R. observed in the case of Duke of Devonshire vs. O' Connor. (1890) 24 Q.B.D. 468 at 478. "In an act of Parliament there are no such things as stops". It is permissible to read a clause with brackets removed". "It appears to be established that punctuation marks are not to be treated as forming part of a statute and that they must therefore, be disregarded for the purpose of consturing it." (Halsbury Vol. 44. 4th edn. para 820). However some judges and law Lords in England have drifted a little from the said position by observing "not to take account of punctuation disregards the reality." (Hanlon v. Law Society, 1980 (2) A.E.R. 199 at p. 221 Lord Lowry (H.L.)."

11.24 It is, therefore, possible to ignore the bracket and read the sub-regulation as a whole. Therefore, the words "not being workings which have been examined and found to be free from accumulation of water or other liquid matter", would qualify 'workings' which are denoted by the adjectives 'disused or abandoned'. In short, therefore, the working to which an approch is to be made should be primarily a disused working or an abandoned working and the same is not free from accumulation of water or other liquid matter.

11.25 The question for consideration therefore. would be whether a sump is disused or abandoned working. Reasonably there should be no difficulty in accepting the definition of 'sump' given by the Management witness no. 7 Bhattacharjee that the sump is a reservoir where from water is taken out. again collected and again taken out. Similarly, what C.W. No. 4 Shri Shyam had stated that a sump is a standage of water from which water is taken by means of a pump also appears reasonable. Witness Shyam does not admit that it is a temporary standage of water. According to him, it is a permanent standage of water. Whatever it is, a sump of the type we are discussing would be having a fluctuating water level depending upon how much water is pumped out from the sump. Even if we conceive that the pump throws out water to its utmost capacity, could it be conceived that the sump would be absolutely empty and dry? It would not be so. May be that such a position may continue for a short period only because again the water would start coming and filling up the sump and again it would be pumped out.

11.26 Witness Shyam had two tests: accessibility for inspection and use for producion. According to him, if there is no production, apparently of coal then the working is a disused working. Perhaps that is a very extreme position and one not likely to be correct. He has, however, spoken about the test of seeing the working or inspecting the working. He had obviously in mind the definition given in Regulation 2(35) where working place' is defined as a place in a mine to which any person has lawful access. This is what he feels necessary for inspection and therefore, he proceeds to say that even if a gallery is without water in the first shift and could be inspected, but could not be so inspected in the second shift because it is full of water, that become disused gallery. Here also possibly he is taking an extreme position. Unfortunately the word 'disused' has not been defined anywhere in the Regulation. We do however come across the words disused, unused and discontinued.

11.27. Regulation 49 (2) (a) relates to the surveyor making a record in a bound-paged took and it is said that he has to record the full facts when the workings have approched 75 metres from the mine boundary or from disused waterlogged workings. Derivatively disused would mean not used. It is worth noting that in the Regulation 49 (2) (a) waterlogged workings are apparently considered ejus dem generis with disused workings. If we turn to the Regulation 146 it speaks of general precautions to be taken in a gassy mine sub-Regulation (4) says that the main air current shall be so split and coursed that an air current which ventilates a goaved out area, whether packed or unpacked or any disused working, shall not except with he prior permission in writing of the Regional Inspector, ventilate any workings except as provided therein. Now here also obiously the word 'disused' has been used to show a 'not used working.'

11.28 Now if we turn to Regulation 6, it provides that, when it is intended to abandon a mine or seam or to discontinue the working thereof for the period specified, a notice will have to be given. Now there the word 'discontinue' is used along with the word 'abandon'. Possibly the difference between the two is that abandoning means not to be taken in hand any time or at least for a very long time; while discontinuing means not in use just presently, but may be taken in hand some time not so remote. The proviso to Regulation 6 as well as sub-regulation (2) also use the words 'abandoned' and 'discontinued' with the same meaning.

11.29 Regulation 7 relates to "Notice of Re-opening' and as in the case of Regulation 6, it speaks of giving notice of re-opening whenever it is intended to re-open the mine or seam after abandonment or after discontinuance. The words 'abandonment' and 'discontinuance' would, in my opinion, be having the same meaning as discussed in Regulation 6.

11.30 Then we come to Regulation 61 which is in respect of Plans & Sections to be submitted after abandoment or discontinuance. The words with which we are concerned, have the same context and therefore they are used obviously with the same meaning as earlier discussed.

11.31 Regulation 59 specifies maintaining of different plans. An underground plan is referred to in sub-regulation 1(b). of Regulation 59 and sub-regulation 3(b). enjoins the showing of spot levels on the floor of the working. So far as clause (ii) of this sub-regulation 3(b) is concerned, it provides for the showing of such spot levels in the case of headings which have been discontinued either temporarily or permanently. The word 'discontinued' therefore means not making use which is stopped voluntarily, may be for a short period or may be permanently.

11.32 In the Chapter on 'Mine Workings', there is Regulation 112 speaking about fencing. Sub-regulation 5(b) directs the owner, agent or the manager to cause the top or entrance of the places specified to be fenced before a mine is abandoned or the working thereof is discontinued. Here also the word 'discontinued' is used in the context of stopping the work as in the case of 'abandoned' with the meanings so far discussed.

11.33 In Regulation 143, provision has been made for inspection of unused working for gas. It lays down that all unused workings not sealed off shall be inspected in the period specified by a competent person. The word 'unused' is used here in preference to the words 'discontinued' or 'disused'. Possibly looking to the purpose of the Regulation it appears that the word 'unused' is used to cover all types of non-working places whether they are abandoned, disused or discontinued.

11.34 A resume of this discussion would show that a disused working would be a working not in use. If no use is made of the working, then it is a disused working. It may not be correct to say that the use or the disuse is to be determined on the basis of its accessibility for inspection, though in many cases that would be a good practical test. It is vehemently contended by the Management in our case that the sump consisting of different levels and dips, either inclusive of the 27th level and the portion dipwards or excluding the 27th level but covering the dipwards portion, was used for stwoing purposes and therefore, it is a case of working in use. Emphasis is laid on the continuous process of taking out water and the filling up of the water. It is for this reason that they say that the sump was not a disused working. According to them, even assuming that it could be called a water-logged working or an area free from water, the expression I prefer. Regulation 127 (3) would not be applicable in the absence of it being a disused working.

11.35 It is a matter for consideration that in the entire code of Regulation made for safety of the workers, from underground inundation, Regulation 127 is the only Regulation stipulated. We have it on record that this was a sump of large capacity, that is to say, a large area often very much full of water. Can it be conceived that the framers of the Regulation did not want to include such an area in the area under danger from water or to indicate that such an area cannot be the subject of latent or patent source of danger from water? Most obiously, we find the levels and galleries in the east of the main dip proceeding towards a large store of water. It could be a travesty of justice if it is held that such a situation is out of consideration of any Regulation enacted for the purpose of averting it as a source of danger. The Management in this case does not dispute that the 28th level east and the 29th level east within 60 metres of the sump.

11.36 In fact, as stated earlier, drivage of the 28th level east further off tuger dip was stopped so that the sump was not disturbed. Perhaps the drivage of the 29th level east was also stopped for the same purpose. The 2nd dip of the 27th level east also seems to have been stopped for that purpose. The Management was therefore, fully aware of their proceeding in the direction of the storage of water. In fact, witness Kumar, MW 9, admits that the 29th level east is driven within 60 metres of the sump, that is to say, within 60 metres of store of water. Therefore, one would be entitled to infer that the drivage was known to be near the store of water. The precise point for consideration would be whether such drivage falls within sub-clause (3) of Regulation 127. Granting that the sump is a working and is in use because water is being taken out and again filled up, one has to pause for consideration as to what exactly happens in such a case. Here are several levels and dips spread out in east-west direction and north-south direction. For dewatering a 90 h.p. pump was installed. I have given a finding that it was installed just above the 26th level in the cross-cut dip. Even assuming for the present discussion that the 90 h.p. pump was just above the 27th level, a pump has specific dewatering capacity. Evidence of Shri Khan, Asstt. Engineer, M. W. 5 in the present case, shows that the suction pipe consisted of 5 pipes' lenght, that is to say, about 120 feet. The foot valve would be somewhere at the end of the suction pipe. Even after the pump works fully, water below the foot valve can never by emptied out. In this light, if we look to the plan, exh. 19AA, it would be clear that none of the four dips off the 27th level west of east cross-cut could be dewatered. Water would be finished from the galleries, but not down below the foot valve and surely the dips mentioned above could not be dewatered. Therefore, these dips have to be looked upon as disused working and disused working not free from water. It has also come in evidence that at no time these dips were free from water, otherwise spot levels could have been noted and the exact extent of these dips could have been known by survey.

11.37 It might be contended that these dips galleries were full of mud, muck or sand so that there was no trace of water in it. Such a distinction has not been made out in the evidence, nor is there any supporting evidence for this purpose elicited from the mouth of Ganapati Sinha, Surveyor who prepared the plan, exh. 19 after physically traversing the area. From the plan such a situation does not seem to have been observed. Even at the time of inspection muck, etc. was not noticed by the Court of Inquiry in the dip side working where it should have gone along with the inrushing water. On the contrary, in exh. 19 the extent of all the four galleries has been noted.

11.38 In the cross-examination of CW 6 Ganapati Sinha carried out by Shri Datey, a specific question was asked whether the witness had taken into consideration the water that would be lying in these dips and he replied that looking to the gradients he had excluded the water remaining in those dips. But that does illustrate that these dips were full of water all along. Therefore, these four dips, i.e. the 1st, 2nd, 3rd and 4th dips, of the 27th level west off east cross-cut are legitimately to be taken as disused workings having water in them. It cannot be denied that the drivages of the 29th, 28th and 27th levels east had proceeded within 60 metres of that disused working not free from water. Regulation 127 requires that for extending such workings prior permission is required and there is necessity of having advance bore holes, etc. No such precaution was taken by the Management on their own also. All along they were approaching the store of water. As it stands, I have no hesitation in coming to the conclusion that in relation to at least three dips, namely, 2nd, 3rd and 4th, of the 27th level west Regulation 127(3) was applicable and the Management has committed a breach in not taking permission and not taking precautions on their own, as laid down in Sub-Regulation (6).

11.39 The next point for consideration would be in respect of application of sub-regulation (2) of Regulation 127. One of the situations contemplated in this sub-regulation providing for precautions to be taken against water inundation, is when the workings are done in a seam or section below another seam or section. Now as the situation has turned out in this case, the 3rd dip of the 29th level east happened to be exactly below the 3rd dip of the 27th level west which was containing water. The lower level got flooded by the breach and the flooding water spread everywhere. This situation is precisely contemplated by clause (i) of sub-regulation (2) of Regulation 127. The happening of the events demonstrates that though precautions conceived by the sub-regulation ought to have been taken, the Management miserably failed in observing the precautions. In that light they must be said to have committed breach of sub-regulation (2) of Regulation 127.

11.40 It would be very easy for the Management to say and, in fact, they did contend that they were not knowing that the 29th level was proceeding just below the upper section in which the workings of the 27th level west have been made. When the workings were proceedings on the east side of the Main dip in different horizons, it should not have been very difficult for the Management to contemplate such a happening and to conceive that in the area the seam was being worked in two different sections, one below the other, so that such happenings would have taken place if not under the 3rd dip then under the 2nd dip or 1st dip or east cross-cut Main dip. Ignorance about it is therefore as good as carelessness in working in utter disregard of rules and regulations in respect of the survey and mapping. It is the combined result of this type of negligence therefore that I would be inclined to say that the Management is guilty of the breach of sub-regulation (2) of Regulation 127.

11.41 Then we might consider the applicability of sub-regulation (1) of Regulation 127. In specific terms it lays down that proper provision shall be made to prevent irruption of water or other liquid matter from the working of the mine. The plea of ignorance becomes weak when we consider the situation from the angle of the application of this sub-regulation. The Management of Hurriladih colliery had planned a sump. In fact, from the evidence of Manager Gupta, CW 3 and Agent Devendra Singh, C. W. 5 we gather that they had intended to keep a barrier towards the west of the sump working. According to Manager Gupta, the barrier planned was of 100 feet thickness; whereas in the written statement, exh. 5, the Management has given the extent of that barrier as 50 ft. Whatever be the planning, in reality it is noticed that the barrier has been completely eroded. That happened when the 27th, 28th and 29th levels east were driven. Manager Bhattacharjee, MW

7. had said that these levels were started in his time. Witness Mukherjee, MW 8, has further stated that the 29th level east was driven about a month or one and a half months before the accident. Now this drivage as has been observed earlier, was within 60 metres of the sump containing water. This drivage resulted in doing away with the planned barrier altogether.

11.42 It may be that the dip workings in the eastern-most panel were not workable by reason of waterlogging. It may be because of this that they decided to simultaneously go ahead with depillaring programme as well as with the development in the dip-side which should not have been done without special precautions. It is understandable that the decision may have been taken so that they do not lag behind the production target. But the direct resultant effect was the disappearance of the barrier which could have been a precaution. Actually speaking, even with a barrier they would have been within 60 metres of water, heading directly towards the storage of water. Whether a sump is a disused working or not becomes an academic discussion. When we speak about the application of sub-regulation (1), every sort of situation which would be a source of danger from water, is contemplated in this sub-regulation, and it was according to me, incumbent upon the Management to take sufficient precautions before driving towards the sump.

11.43. In this connection we must also take into consideration the error in the relative positions of the levels on the west and east sides, to the extent of 45 ft. (13.5 m). This error is in respect of the 27th level west and the 29th level east. It is argued that because of this shift, the Management was misguided. This argument is plausible, but we must take an overall view of the matter. It is evident that the mistake in surveying is also due to negligence in observing the various regulations and practices relating to the carrying out of survey work. It is because of this that I am to conclude that there was a breach of sub-regulation (1) of Regulation 127 as well.

CHAPTER XII

CONCLUSIONS

12.1 By way of summary it can be said that the cause of the accident was the collapse of the parting of 45 cub. mtrs. between the 29th level east in the Main dip district and the old workings west of the east cross-cut dip which were used as water sump. Within a matter of minutes large quantity of water started coming down and inundated all the dip workings namely, the 3rd, 2nd and 1st dips east of the Main dip and the Main dip itself off the 29th level east. The water then started rising about the 28th level junction. As a result of inundation 19 persons working in that area were drowned. This connection was established between the 3rd dip of the 29th level east off the Main dip and the 3rd dip of the 27th level west containing watre which happened to lie just above the 3rd dip of the 29th level east.

12.2 A number of circumstances were attending the accident. According to the Management, inaccuracy in the plan resulted in the accident. It has already been discussed how those inaccuracies crept in. Right from the time of surveyor Varma no heed was paid to the surveying and the plottings. A very specious argument was made that re-survey of the XIV seam was continuing. That was continuing from the year 1979 and would have continued even after the accident if that accident had not taken place. In effect, therefore, no serious effort was ever made to have the re-survey done. Caution fortuitously dropped in that connection in the nature of the report of D.G.M.S. officers and in the nature of the charge report of a Manager was thrown to the winds. There absolutely no control kept over the survey work and the surveying personnel. Whenever such control would have been automatic by reason of observing various regulations such as signing the plans and sending copies of the plans to D.G.M.S., that control was given up by not following those rules and displaying a very casual, complacent and indolent attitude. This has resulted in inaccurate plans. All this added together shows callous disregard and negligence of high order. But these are not the only attending circumstances. As discussed earlier, when a sump of large extent, a storage of water containing extensive quantity was near about, reckless drivages towards the sump were made without taking even ordinary precautions leave aside the regulation or no regulations. That disregard is also, in my opinion a circumstance to be reckoned with.

12.3 To point an accusing finger if that s what is expected by this report, I would have no hesitation in saying that initially the error started from the Surveyor Varma. Surveyor Mukherjee who came on the same, could have easily taken corrective measures, but he failed to do so. He is also equally responsible. Other Surveyors, that is, Ansari and Adhikari, in plotting erroneous plans as well as the managers certifying those plans are equally to be blamed. Manager Bhattacharjee is the man on the spot upon whose shoulders the responsibility must come. But I do not think the higher-ups at least upto the rank of the Agent can be excluded from blame because the Agent residing at the same place, Hurriladih, has to guide the Manager in his day-to-day working remaining conversant with the entire topography of the colliery. In this particular case Agent Kumar also happened to be the earlier Manager in whose regime many things happened which have led to the tragic occurrence. Once having been the Manager, as agent he was expected to be far more conversant and diligent to supervise the working of the Manager and give him timely hints so that the accident would not have occurred.

12.4 Agent Devendra Singh has an excuse that he was to look after many collieries. But that defence is not available to Kumar or to Prasad who were incharge of Hurriladih colliery alone at the time the errors were committed.

12.5 All these persons are, therefore, guilty of negligence, latches, non-compliance with statutory safeguards and, therefore, are responsible for the accident in which 19 innocent lives were lost.

CHAPTER-XIII

OBSERVATIONS

13.1 Section 24 of the Mines' Act 1962 under which this Court of Inquiry is instituted, contemplates that the report may contain any observations which the Court may think fit to make. I would, therefore, like to take the opportunity to make a few recommendations on the basis of facts disclosed and the discussions made earlier.

COAL MINE REGULATION 127

13.2 The longest debate centered round the question whether Regulation 127 was attracted in this case. This Regulation specifies precautions to be taken in respect of danger from underground inundation. Three types of provisions have been made. Sub-regulation (1) merely makes a general overall statement. Sub-regulation (2) envisages three types of situations which can give rise to danger of underground inundation. But the preventive action is still confined to the requirement that adequate precautions shall be taken against an irruption of water, etc. Sub-regulation (5) is concerned with the special situation where abnormal seepage of water is noticed, or if there is any such suspicion or doubt in which case, Director General of Mines Safety is to be informed, the expectation being that the situation would be suitably investigated for likely causes and possible remedies.

13.3 Sub-regulation (3) relates to drivages being made in the vicinity of workings which are disused or abandoned and are not inspectable. Long arguments were addressed in interpreting the word 'disused' and the same was contrasted with the words 'discontinued' and 'unused'. I have dwelt upon various Regulations where those words are used indicating also my understanding of their meaning. The word 'disused' has not been defined in the Regulations. This has provided scope for doubt and arguments as to the applicability of sub-regulation (3) in a given set of conditions. The ambiguity can be removed by suitably defining the words 'disused', 'unused' and 'abandoned'. It appears that the meaning of the word 'discused' can be brought out in co-relation with workings which are not disused and for which there is provision in Regulation 113 for suitable inspection at the

hands of a mining employee. Taking a que from that situation the definition of the term 'disused working' is proposed as follows :—

> 'Disused working' means every place in a mine, whether below ground or opencast which is not required to be examined by the competent person under sub-regulation (1) and clause (b) of sub-regulation (3) of Regulation 113.

13.4 Perhaps the word 'workings' also needs to be defined. It will also appear that the adequate precaution mentioned in sub-regulation (2) can be spelt some details so as to provide guidance in that respect.

13.5 There is another set of conditions which sometimes leads to danger from underground water, and that is when two or more galleries are being simultaneously extended dipwards. The danger arises when a connecting gallery is driven to connect with a dip gallery which contains water. To provide for this situation, it may perhaps be advisable to specify in the regulation that whenever a gallery is being driven towards and within five metres of any other development working which contains water three metre long bore hole shall be placed and maintained in the centre of the gallery that is being driven.

C.M.R. 60-Submission of upto-date Plans and Sections

13.6 During the proceedings of the Court of Inquiry it was brought out that CMR 60 which requires submission to the Director General of Mines' Safety every year of two upto-date copies of the main plans and sections of the mine workings was not being complied with. When the regulation enables the plans and sections submitted in a given year to be brought upto-date next year, in lieu of submission of a new set of plans, negligence in complying with this provision was somewhat a surprise. While it is perhaps true that all types of danger in the mine cannot be identified just by the study of a mine plan, the availability of upto-date plan with the Director General of Mines' Safety is desirable.

13.7 It was argued on behalf of certain workers' Unions that the Management was completely ignoring their duties of submitting such plans and endangering safety. It was also said that the Director General of Mines' Safety had singularly displayed a very complacent attitude in not securing compliance with Regulation 60. In fact, when one of the witnesses Director P. C. Shyam, was asked relevant questions, he not only expressed inability about the checking of such plans, but also indicated that they would just remain stored. He has expressed that in case the regulation is strictly observed, the work-load will be beyond the capacity of the Office of the Director General of Mines' Safety. He also informed that the Director General of Mines' Safety has suggested to the Government for deletion of this requirement. I do not think that the Director General of Mines' Safety is proceeding on the right lines in this respect.

13.8 The main purpose behind Regulation 60 is perhaps that if a mine is closed/abandoned without due process and without submission of an AMP (Abandoned Mine Plan-Regulation 61), at least some reasonably upto-date mine plan of the mine is available for later reference. There is no complimentary provision (either at this stage or at other stage) that these plans and sections must be scrutinised by DGMS. While it would be useful for such a scrutiny to be made, this would be dependent on the adequacy of DGMS staffing, which issue has been discussed later. I consider however, that compliance with CMR 60 is very desirable. The DGMS Office can perhaps by notification, permit the management while submitting one set of plans and section, to collect the earlier set which can then be brought upto-date next year and lodged with the DGMS, in exchange of the first set. In this way, one upto-date set would always remain with DGMS.

13.9 This compliance will enable the DGMS, if it finds a particular plan or section to be of sufficient importance, to scrutinise it. Even otherwise such plans and sections would provide good link for retrospective consideration as to what the management had done or should have done in the event of an accident or for the convenience of any contingent reference. Doing away with this provision will be very undesirable. Also, if upto-date plans and sections are to be submitted annually to DGMS, it would provide an occasion for the management to check their plans and sections at least annually for possible errors. As mentioned above, these plans and sections could also provide good material to DGMS for scrutiny although perhaps, with the present level of staffing it may be difficult for the DGMS to do so.

13.10 This is perhaps the proper stage to discuss the issue of the staff strength of D.G.M.S. It has been accepted by all that the staff strength of DGMS is far too inadequate for proper discharge of its functions. While the mining industry has expanded several-fold over the past 20 years, the DGMS staff strength has remained more or less static. Even in a 'free' economy like that of U.S.A. there are over 1400 federal coal mine inspectors for an annual production of 900 million tonnes —and this in a situation where work is highly concentrated through mechanisation. The need of the Indian situation where work is much more manual and workers much less safety-conscious, is for closer inspection. Even on the U.S.A. pattern, DGMS should have a staff strength of 270 for coal mines or 400 in all as against its current sanctioned strength of 140 or so.

13.11 The number of Officers in position is even less, perhaps because of the inferior pay-scales and career prospects, compared to the industry from which Officers are to be drawn. It is evident that at present the DGMS cannot carry out even one general inspection per year of every mine. It appears that some improvements in salary-scales have recently been made, but in the meanwhile, Coal India salary structure has undergone a major change—with the result that the grave disparity in emoluments in DGMS and the industry continues as before if not accentuated. There is, therefore, need for review of the same. Besides, the Government of India should set itself the target of a 20% annual expansion of DGMS over the next 8-10 years; only thus can the Organisation be strengthened to the minimum desirable level.

13.12 This aspect can be neglected only at the risk of grave damage to the important cause of miners' safety.

CMR 58(3)—Mine Plans and Quarterly Surveys—Some Suggestions

13.13 One of the most disquieting features to emerge in the enquiry was the state of mine plans. The statutory requirements in respect of mine plans are embodied in Regulation 59 which speaks of maintaining five types of plans including the Surface Plan, the Underground Plan and the Ventilation Plan. Different types of mine plans are required to show different types of details to bring out the current status of the conditions in the mine in respect of different aspects such as danger from gas, dust, water, etc. Sub-regulation (3) of Regulation 58 imposes a general obligation to make these plans upto-date every three months. In Hurriladih colliery unfortunately, the mine plans had not been brought upto-date after the quarter ending 30-6-1982, (Exh. 62). Even this entry was not countersigned by the Manager. In other words, mine plans had not been brought upto-date for at least four quarters before the date of the accident. It is surprising that neither the Manager cared to get this rectified nor any of the other senior officials.

13.14 From the evidence adduced in the enquiry, it appears that the surveyors remained busy in carrying out routine non-statutory works such as supervising civil works, making bills, etc. Important mine jobs such as opening of new development faces and giving centre and grade lines were by and large neglected. Spot level at the end of workings were not measured at all during this period. This sorry state of affairs deserves special consideration. Two questions arise —

(1) Why is it that though there were at least two qualified surveyors at the colliery most of the time, the important mining requirements of giving and extending centre and grade lines and the measuring and recording of spot levels were totally neglected ?

(2) Why were the quarterly surveys not carried out for over a year ?

13.15 The answer to question (1) is that the survey staff was much too busy in production-payment related jobs, to the utter neglected of production-safety-related statutory jobs. There can be no other explanation. In regard to question (2) also if the surveyors were too busy to attend to important day-to-day jobs, there is no wonder that quarterly surveys received, an even further back seat.

13.16 A point was made in this context that there is acute shortage of qualified surveyors in the mining industry. This is perhaps correct. It is not clear however, as to what a fully-nationalised sector like coal industry has done in getting more mine surveyors trained. One way of mitigating the probelm is to allocate non-statutory survey jobs to civil surveyors. There is no evidence that anything of this type was done.

13.17 The explanation given for not carrying out quarterly surveys is as unsatisfactory. It has been contended that doubts having been raised about the general accuracy of the old mine plans, the first priority was to check this accuracy. The job however has lingered on for years and, in the meanwhile, quarterly surveys were given a total go-bye. There is no explanation for this serious neglect. Quarterly surveys provide a highly desirable check on the correctness of the position of newly made workings; in this case this check was totally lacking.

13.18 As mine located survey staff is always likely to remain busy in routine jobs, it would appear desirable in a nationalised industry, to have a separate set of staff, say at the Area level, to carry out quarterly (and other check) surveys. The system would involve keeping two sets of main mine plans and sections, one at the mine and the other in the Area or Group office. It should then be the responsibility of the Area or Group Survey Team to carry out quarterly surveys and bringing upto-date the set of plans in their office. This upto-date set of plans would then be exchanged with the set of plans kept at the mine office; the latter set would then be brought upto-date in the next quarterly survey and again exchanged. Such a system would have two advantages—

(a) The mine would always have plans which have been brought upto-date at quarterly intervals, and

(b) the work of the colliery surveyors will get checked every quarter by a separate survey group.

Dotted Lines

13.19 Dotted lines are required to be used with dates, while updating the maps quarterly. However, mining surveyors have often taken recourse to dotted lines to show the possible extent of working which has not been actually surveyor. In a running district the progressing faces are never shown with closed ends till they reach their final limits of drivages. They are shown in dotted lines if not approachable during survey.

13.20 Referring to dotted lines on the plan, Exh. 62, questions were asked to different witnesses to bring out the meaning of the dotted lines. Survey Officers Bhattacharjee said that in place of firm lines dotted lines are used when all the details of the survey cannot be made. With end of the gallery in dotted lines he would interpret it as "the extent of the gallery is known, but not the details". Extent means length. Court Witness Shyam says that when dotted lines are shown on a plan, it means that the extent and accuracy are doubtful. Surveyor Mukherjee showed the dip galleries with dotted lines because he found them waterlogged. It follows, therefore, that dotted lines are used when the working of gallery cannot be surveyed. This is because of its inaccessibility either because it is filled with water or it is otherwise blocked. But the details cannot be traced on the plan and, therefore, they are shown in dotted lines. On the two dimensional mine plans which we generally meet with, lines are drawn to show levels and dips. They do not show any heights, etc. except perhaps by mentioning it by note or by drawing. They do not show the gradient at each location, only the general gradient is indicated at the top. In this light whether the end of dotted lines is closed or the end is open, it is of no significance. Ex-hypothesi the extent is approximate; the surveyor is unable to survey the details. It is expected that if the surveyor is unable to get the details checked in one quarter, he should be able to get those details while drawing the plan for the next quarter either by removing the blocking or by dewatering the gallery as the case may be. But in this case, it is found that the dotted plotting continues to be shown quarter after quarter, without giving the spot levels. With firm lines if the end is open, it would indicate that the work is in progress; if the end is closed, it would indicate that the heading is not presently proceeding. But when it is accompanied with dotted lines it may create confusion and if the same dotted lines are shown quarter after quarter, it does mean that the surveyor was unable to survey the details for so many quarters'. The working, therefore, becomes a disused working and being below the water table, such a disused working is bound to get percolation water. In order to avoid long debate as has taken place in the present case, it will perhaps be useful and convenient to say that whenever any working is shown with dotted lines, it will be presumed to be a disused working until shown otherwise. Such an amendment would curtail unreasonable contentions.

Internal Safety Organisation

13.21 From the report so far it would be seen that negligence by the Management is the prime factor for causing this accident. It is compulsory to have a safety officer in every mine as per Regulations 36 and 41(a). That post however, may have a tendency to be ornamental. It is understood that many of the mining companies and corporations have set up an internal safety organisation. A properly structured ISO can be an effective tool for improving safety standards in mines.

13.22 For ISO to be effective however, it must have some "teeth", in that it should be empowered, even required, to intercede if it finds that a mine or a part of it is not safe in some specific regard. Its role could also become more purposeful if it could be assigned the following functions :—

(a) ISO could be asked to issue safety clearance before work in new district is commenced; this could cover both depillaring and development operations as well as new installations. In this particular case of Hurriladih colliery, if the start of development in the 29th level east area had been subject to such a clearance, the lurking danger from water in the sump on the rise side would most probably have been specifically brought to the notice of the Management.

(b) Applications to DGMS for grant of statutory permissions could be routed through ISO; this would provide another occasion for the safety implications of the new proposals to be subjected to a closer scrutiny.

To enable the ISO to function effectively, it must be given a specific authority through a clear safety policy formulated at the corporate or at owner level.

CHAPTER XIV

FINALE

Recovery of expenses

14.1 This brings me to the last question of making an order in respect of recovery of expenses. Rule 22 of the Mines Rules, 1955 made in exercise of the powers conferred by Section 53 of the Mines' Act, 1952 enables the Court of Inquiry to direct the recovery of the expenses of the Court including any other expenses connected with the inquiry to be made from the owner of the mine concerned if the accident is due to carelessness or negligence on the part of the Management. My report discloses that the accident has taken place entirely due to the negligence of the Management in disregarding the functions connected with the preparation of the plans, the functions and duties connected with the working of the mine and not observing safety precautions. It follows, therefore, that the entire expenses of this Court of Inquiry shall have to be recovered from the Manage-

ment, namely, Bharat Coking Coal Limited. I do hereby direct that the above noted Management do pay the entire expenses of this Court of Inquiry. The Chief Inspector, i.e. the Director General of Mines' Safety do, calculate the above expenses and take necessary steps for its recovery. The expenses will include the expenses incurred for and on behalf of Hurriladih Court of Inquiry, two Assessors nominated by Government as well as the expenses incurred by the Directorate General of Mines' Safety for recording depositions and for preparation of this Report.

14.2 Before concluding, I must record my deep thanks to the valuable help given by eminent Assessors, Shri K. N. Trivedi and Prof. G. S. Marwaha. I must also thank the Advocates appearing on behalf of the Management, Counsel Shri Sirpurkar and Counsel Shri S. B. Sinha as well as the different representatives of the Unions, Sarvashri Datey, Prasad, Chinmoy Mukherjee, Dasgupta, Bhattacharya, Janki Mahato, Boxi and Singh for their unstinted help without which this Inquiry could not have been finished so smoothly. I must also acknowledge the deep co-operation given by the Director General of Mines' Safety and his officers not only in producing the material they had collected, but also by coming forward with every type of assistance whenever necessary.

Dated : July, 1984.

C. T. DIGHE, Chairman,
Court of Inquiry
Harriladih Colliery Accident

I fully agree with all observations, conclusions and recommendations made in the Report which has been prepared in full consultation with me.

I would also like to join him in thanking all parties to the enquiry and D.G.M.S. Officers for their consistent courtesy, co-operation and help.

I would also like to take this opportunity to recall my deep appreciation of the unfailing courtesy and the consideration received from the Court and my Assessor colleague at all times.

In the context of my entire association with the three other Courts of Inquiry constituted under the Mines Act I must make another observation.

The procedure adopted by Justice Dighe : (i) in circulating documents only after they had been received from all parties, and (2) in asking for the list of witnesses right in the beginning, had the very desirable effect of cutting down the scope for 'fishing' Expeditions. This, coupled with the procedure adopted by the Court, (3) in getting the examination-in-chief submitted in the form of Affidavits and (4) in dictating witness-answers in a comprehensive manner, and not question by question, helped very considerably in getting the enquiry completed in the shortest possible time.

New Delhi;
July,—1984.

G. S. MARWAHA, Assessor.
Hurriladih Court of Inquiry.

I fully agree with all observations, conclusions and recommendations made in the Report which was prepared in full consultation with me.

I also fully agree with the observations made and the sentiments expressed by Shri Marwaha.

New Delhi;

July, 1984.

K. N. TRIVEDI, Assessor,
Hurriladih Court of Inquiry.

ANNEXURES

ANNEXURE—A

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, the 22nd September, 1983

NOTIFICATION

S.O. 4667.—Whereas an accident occurred in the Hurriladih colliery in District Dhanbad of Bihar State on 14th September, 1983 causing loss of lives;

And whereas the Central Government is of the opinion that a formal inquiry into the causes of and the circumstances attending the accident ought to be made;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) the Central Government hereby appoints Justice C.T. Dighe, Retired Judge of Bombay High Court, to hold such inquiry and also appoints the following persons as assessors in holding the inquiry, namely :—

1. Shri K. N. Trivedi,
Organising Secretary,
Indian National Mine Worker's Federation,
Dhanbad.

2. Shri G. S. Marwaha,
Director, Indian School of Mines,
Dhanbad.

[No. N-11015|8|83-MI]
J. K. JAIN, Under Secy.

ANNEXURE—B

Dhanbad the 1st October, 1983

Hurriladih Court of Enquiry

Note of Inspection

The Court of Enquiry, Justice C. T. Dighe, accompanied by the two Assessors, one member from each of five unions, a representative of the Colliery management, and officials of Hurriladih Colliery, inspected the site of the accident in the afternoon of 1st October. An unsigned unauthenticated ferroprint of the district plan, readily available in the Colliery Office, was used for guidance during the inspection. The accident had occurred in 14 seam, which is 30 ft thick. The seam has a dip of about 1 in 8 due about S49°W.

2. The group went down No. 2 pit, 477 ft (143.0 metres deep, downcast), travelled east to the Main Haulage Dip and then straight down to the dipend which had gone about 70-80 feet beyond the 29th level, (10 bodies had reportedly been recovered from this dip). At the time of inspection, the dip was free of water which was being dealt with by pump.

The group then came up back to the 29th level and travelled east to the 1st East Companion|Tugger Haulage Dip and went down this Dip. After about 40 ft the dip gallery was blocked with empty tubs turn topy-turvey, and the group could not proceed further down. With the help of caplamps, however, the group could see the top of a thick prop near the end of the dip. The group was informed that this dip had extended beyond 30th level, and in east gallery had already been started at the 30th level. Nine bodies had reportedly been recovered from thie Dip.

The group came back to the 29th level and travelled further east to the II dip which had progressed about 60—70 ft. this also was kept free of water by pumping. The group came back to 29th level and travelled further east to the site of the puncture. At this place, the depth from surface would be about 900 ft.

3. The puncture was in the roof a little to the dip side of the junction of 29th level and the III East|Dip. From the bottom we could see that, at the site of the puncture, the parting was only about a foot or so thick. The group tried to look for remnant ends of all holes. It could see a couple of short-holes drilled in the III East Dip face. It also saw 6-7 sockets of short-holes in the face of 29th level. It did not see any other holes driven eitheir in the sides of the

gallieries or in the roof. On the specific enquiry made, Shri R. Kumar (Agent) stated that no advance bore holes had been driven. The group noted that there was a little muck (not much) in the Main Haulage Dip, in the Tugger Dip and also in II East Dip.

4. The group retraced its steps back to the Tugger Dip and travelled up by this roadways to the 26th level. From here it travelled east for about a pillar-length and went up (through about 10 long steps) from near the bottom section of the seam to near the top section. A brattice door had (apparently freshly) been constructed at the bottom of the steps. The level gallery on this side was numbered 25th level due to the different size of pillars on the East side. Immediately after getting up into the 25th East Level, the group went down the dip gallery for about three pillar-length, right down near its dip and which was the site of the puncture. This dip gallery was dry because of the new puncture opening.

A V-Notch had been fitted just above the site of the puncture (reportedly after the accident) to measure the quantity of waterflow.

5. The group walked back up to the 25th level and travelled east by about three pillar-lengths and went down the East Cross-cut Haulage Dip by about one pillar to the site where reportedly a 90 hp pump was installed before the accident. The purpose of this pump was to pump out stowing water from the sump created here, to the surface (via an auxiliary middle sump at 17th level of Man Haulage Dip and the Main Pump at the Pit Bottom) for sand stowing purposes.

During the recovery operations, the pump had been shifted from this sits. The floor of the Dip road (right up to the site of the pump and even beyond) was full of sand, coming with the stowing water.

6. After seeing the Pump-site, the group retraced its steps to the site of the Tugger, went down the Tugger Dip for one pillar length to 27th level off Main Haulage Dip and travelled west along with the Travelling Roadway and up the West Cross-cut (Travelling Roadway). Travelled east to No. I Pit Bottom, then through the shaft bye-passes to the east of No. 2 Pit, and up the Pit to the surface.

The group had gone down around 4.00 p.m. and returned to the surface around 8.00 p.m.

Sd/- (C. T. DIGHE)

Sd/- (G. S. MARWAHA)

(K. N. TRIVEDI)

ANNEXURE—C

COURT OF INQUIRY—HURRILADIH COLLIERY ACCIDENT

PUBLIC NOTICE

Public Notice is hereby given to all persons affected and concerned, including the Owner, Agent and Manager of Hurriladih Colliery, the persons who were injured in the accident which took place in Hurriladih Colliery in District Dhanbad of Bihar State on 14th September, 1983, the legal representatives of those who died in the accident the concerned Labour Unions that under Section 24, sub-section 1 of the Mines Act, 1952, the Government of India have ordered an inquiry into the cause of and the circumstances attending the accident and by Notification No. N-11015|8|83-MI dated 22-9-1983 I have been appointed to hold that inquiry. I hereby invite the concerned persons who desire to take part in this inquiry to file their written statement and also to submit the names of witnesses, if any and their addresses to enable me to record all available evidence relating to the accident on the dates to be fixed hereafter. The statements in writing with 15 copies be submitted in the office of the Court of Inquiry at the office of the Director-General of Mines Safety. (Ground floor, Old Building) at Dhanbad on or before Thursday the 20th October 1983.

Sd|-

C.T. DIGHE, Retired Judge, Bombay High Court & Court of Inquiry

Camp : Dhanbad (Bihar)

Dated the 1st October 1983

Annexure 'D'

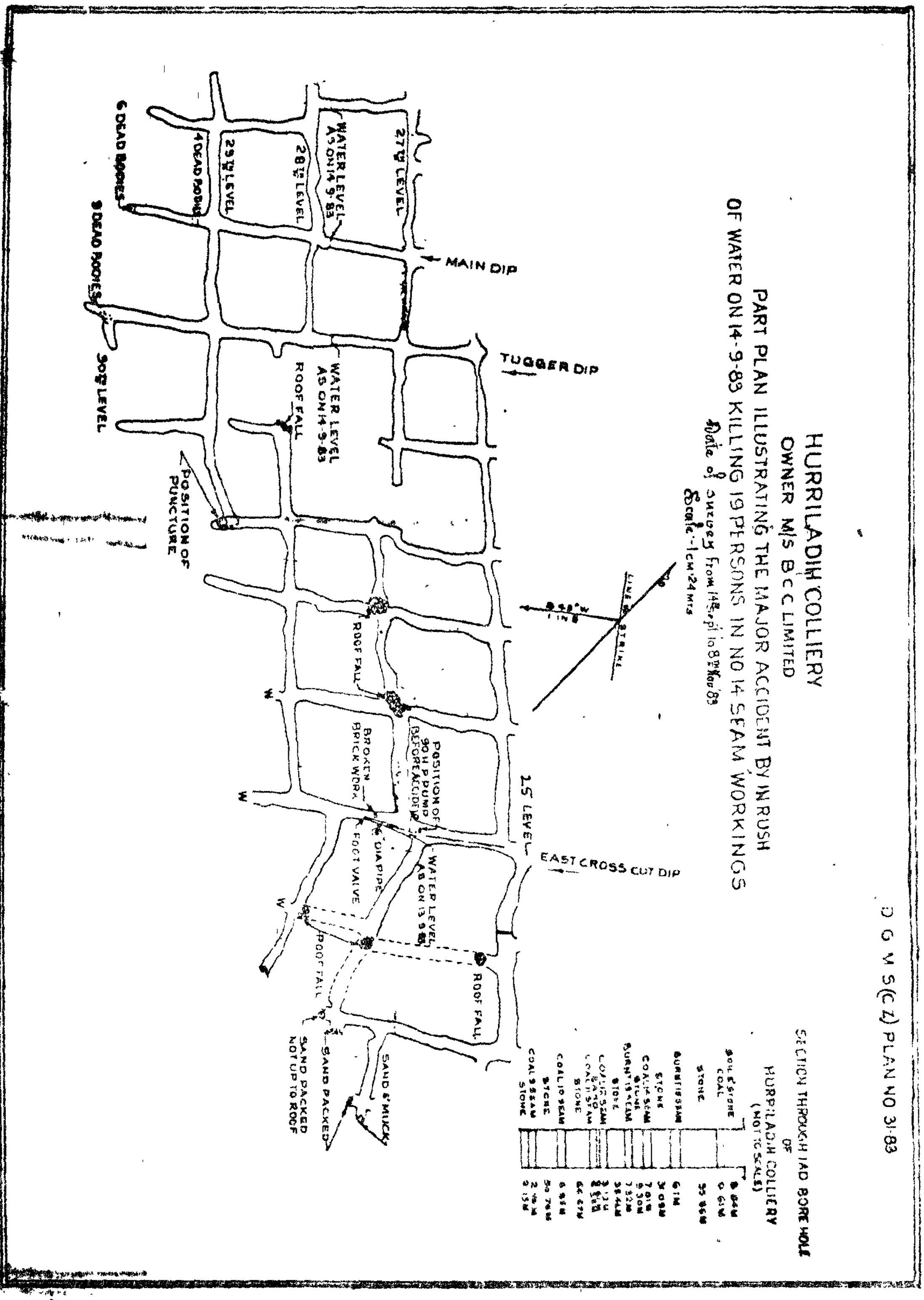
HURRILADIH COLLIERY
OWNER M/S B C C LIMITED
PART PLAN ILLUSTRATING THE MAJOR ACCIDENT BY INRUSH
OF WATER ON 14-9-83 KILLING 19 PERSONS IN NO 14 SEAM WORKINGS
D G M S (C Z) PLAN NO 31-83
SECTION THROUGH IAD BORE HOLE
OF
HURRILADIH COLLIERY
(NOT TO SCALE)
27th LEVEL
28th LEVEL
29th LEVEL
30th LEVEL
25 LEVEL
MAIN DIP
TUGGER DIP
EAST CROSS CUT DIP
WATER LEVEL AS ON 14-9-83
WATER LEVEL AS ON 13-9-83
ROOF FALL
POSITION OF PUNCTURE
6 DEAD BODIES
4 DEAD BODIES
9 DEAD BODIES
POSITION OF 90 H.P. PUMP BEFORE ACCIDENT
BROKEN BRICK WORK
FOOT VALVE
SAND & MUCK
SAND PACKED
SAND PACKED NOT UP TO ROOF

Annexure 'E'

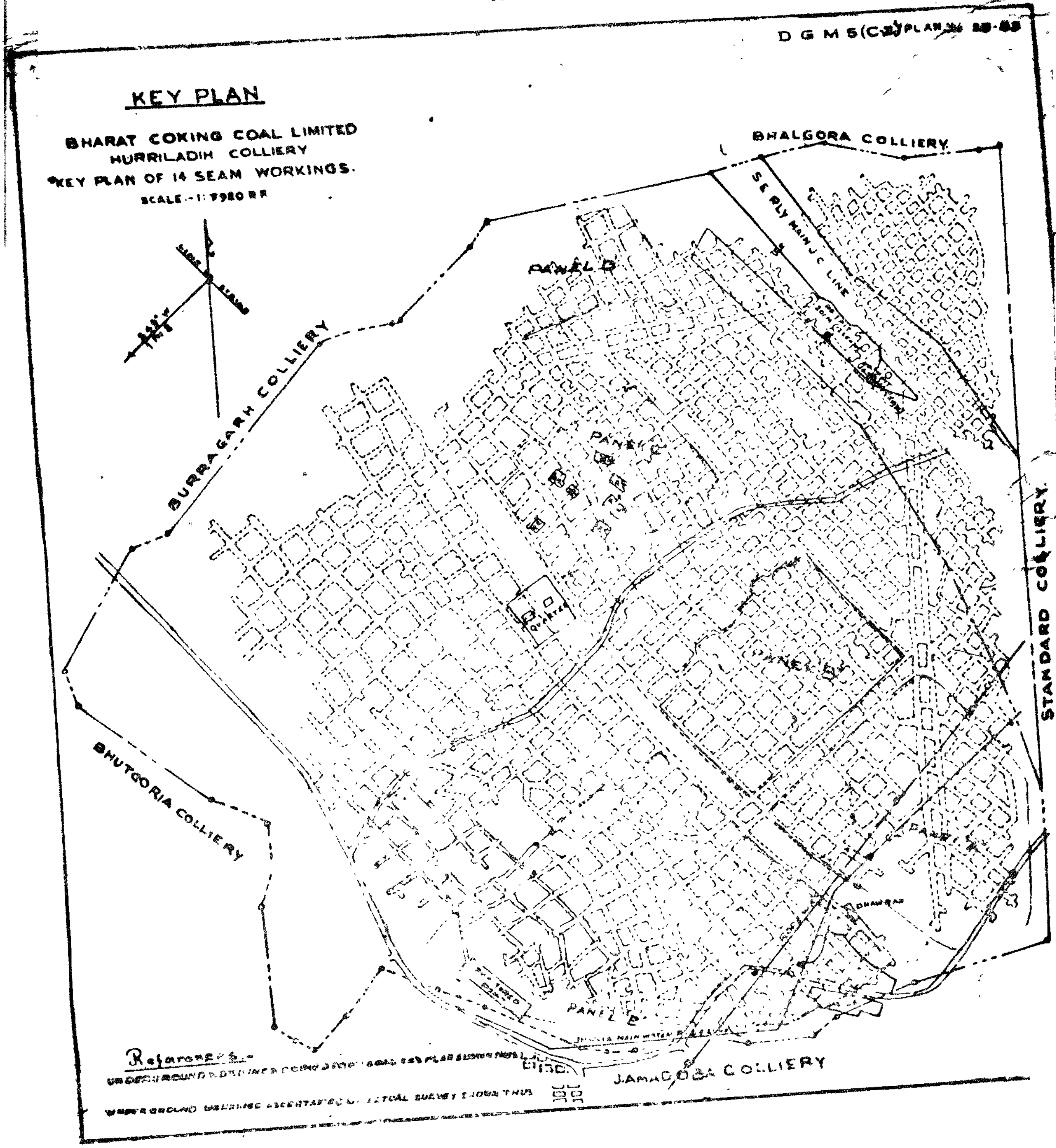

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110064, 1985